IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

October 2021
Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

हिंदी

IN NEW AVATAR

Revamped With Revolutionary Aspects

- Easy To Remember Tabular Format
- Practice Mcq's At The End
- Top Editorial Summaries Of The Month
- A Comprehensive Compendium Of News Sourced From More Than 5 Reputed Sources

IAS BABA

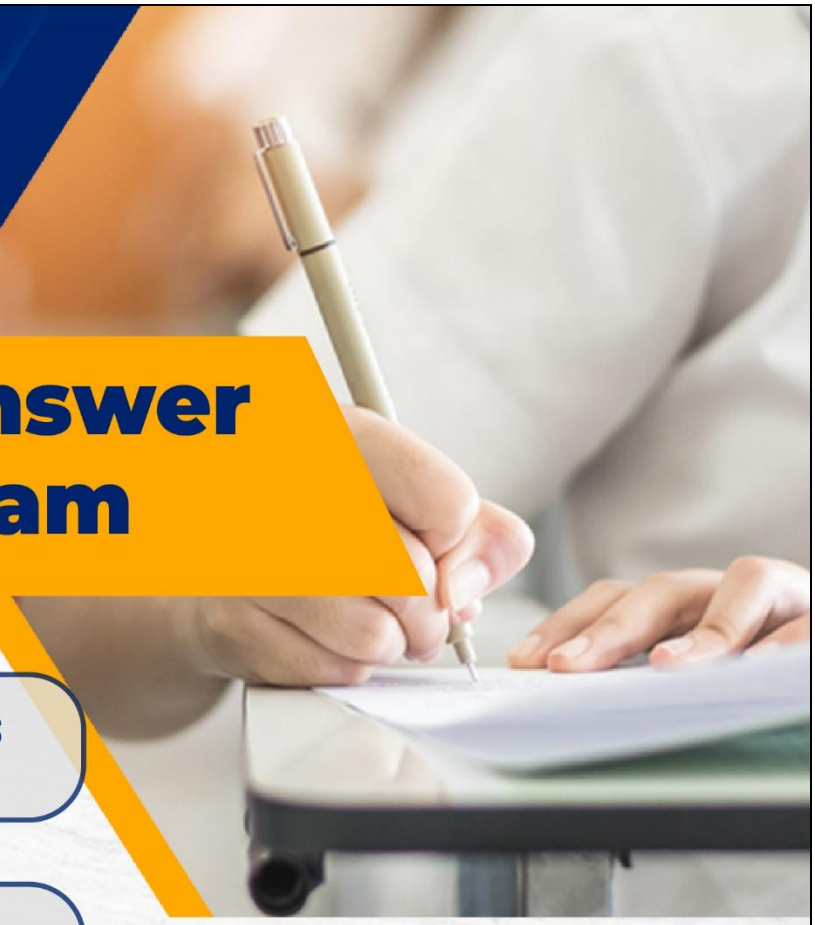

TLP+ Mains Answer Writing Program

- **22 UPSC Level Mocks**
  (8 Sectional, 6 Essay, 2 FLT's)
- **1:1 Mentorship**
- **Discussion Classes After Test**
- **Detailed Synopsis**
- **Flexible Tests**
- **Mainspedia –**
  Access Important Issues Of Last 1 Year In Answer Writing Format At One Place

Toppers Recommended

Scan here to know more

REGISTER NOW

विषय वस्तु

राज्यव्यवस्था एवं शासन

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)
- OCI उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में उपस्थित हो सकते हैं
- जमानत मांगने का अधिकार संविधान में निहित: सुप्रीम कोर्ट
- भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रकिया का सरलीकरण
- असम समझौते को लागू करने के लिए पैनल गठित होगा
- सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को RIMC प्रवेश में शामिल होने की अनुमति दी
- ई-श्रम पोर्टल
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
- ई-वोटिंग
- अंशकालिक कर्मियों को नियमितीकरण का हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- अग्रिम जमानत
- आदर्श आचार संहिता (MCC)
- नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोष
- पुरुषों को भूमि अधिकार देगा मातृवंशीय मेघालय
- पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की
- मुल्लापेरियार बांध मुद्दा
- UIDAI ने डेटा बिल से छूट की मांग की
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD), 1969

अर्थव्यवस्था

- मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट (MeghEA)
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ
- इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA)
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना
- जल जीवन मिशन
- बिजली नियम
- सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग
- मसौदा बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2021
- बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020
- औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट 2.0
- खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन-तेल पाम (NMEO-OP)
- 'पीएम मित्र' पार्क
- स्वामित्व योजना
- G-Sec अधिग्रहण कार्यक्रम
- मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन
- बांस की व्यावसायिक खेती की शुरुआत
- अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021
- भारत की अक्षय ऊर्जा
- कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC)

- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)
- दूरसंचार उत्पादों के लिए PLI योजना शुरू की गई
- ई-श्रम पोर्टल
- कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
- विदेशी अंशदान संबंधी नए दिशा-निर्देश
- पीएम मित्र पार्क योजना
- डि-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)
- नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)
- ग्रीन डे अहेड मार्केट (GDAM)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
- जीएसटी मुआवजा
- भारत, ADB ने 251 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

पर्यावरण

- इथेनॉल उत्पादन
- स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG)
- अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला
- मुंबई अंधी ईल
- 'भारत के आर्द्रभूमि' पोर्टल का शुभारंभ
- सरकार का वन अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव
- मैड्रिड प्रोटोकॉल और अंटार्कटिक संधि
- उत्तर प्रदेश PM2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक: CEEW
- ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क रिपोर्ट
- छत्तीसगढ़ में भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व
- मध्य हिमालयी क्षेत्र में एरोसोल के स्रोत
- पराली जलाना
- Google जलवायु इनकार विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाएगा
- जावन गिब्बन
- भारत ने जलवायु लक्ष्यों को अपडेट करने को कहा
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) पर SC
- संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन
- स्वच्छ भारत कार्यक्रम
- क्लाइमेट रेजिलिएशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग (CRISP-M)टूल
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रिपोर्ट
- चौथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा
- भारत का जैव-आर्थिक हब
- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति
- जिओरिसा मावस्माईन्सिस
- 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दशकीय औसत से ऊपर
- अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस
- मुदुमलाई टाइगर रिजर्व

- जहरीले पटाखों की बिक्री
- चीन ने संयुक्त राष्ट्र को नई जलवायु योजना सौंपी
- CO_2 को मीथेन में बदलना

भूगोल और समाचारों में स्थान

- भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)और COVID मुआवजा
- कावेरी नदी विभिन्न प्रदूषकों की वजह से हो रही प्रदूषित: आईआईटी मद्रास
- पाक खाड़ी योजना
- भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र

संस्कृति और इतिहास

- लाल बहादुर शास्त्री
- लंगा मांगणियार (Langa Manganiyar) विरासत
- ब्रह्मपुत्र विरासत केंद्र
- श्यामजी कृष्ण वर्मा
- राम वन गमन पर्यटन सर्किट
- अभिधम्म दिवस
- आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ

विज्ञान प्रौद्योगिकी

- नासा का लुसी मिशन बृहस्पति के रहस्यमय ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की जांच करेगा
- डिजी सक्षम का शुभारंभ
- मधुमेह (डायबिटीज)
- मेनिन्जाइटिस शोथ
- विक्रांत दूसरे चरण के परीक्षणों के लिए रवाना होंगे
- तापमान और स्पर्श पर काम के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार
- एक्स मिलन: भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास
- आई-ड्रोन(i-Drone)
- आयुष्मान भारत संशोधित
- इंटरपोल ने ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया
- भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2021
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की
- रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा
- हरा-भरा अभियान
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)
- भारतीय सेना यूके के साथ अभ्यास करेगी
- पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली: भारत, क्रोएशिया सहयोग करेंगे
- आर्यभट्ट पुरस्कार
- भारतीय अंतरिक्ष संघ
- वन हेल्थ कंसोर्टियम (One Health Consortium)
- यूफिल (UFill)

- व्यायाम युद्ध अभ्यास 2021
- 1000 मेगावाट घंटे की परियोजना के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)
- 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट: WHO
- सुपारी (Arecanut)
- ई-संजीवनी
- पहली बार मानव शरीर में लगाया गया सूअर का गुर्दा
- MES का वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल (WBPMP)
- मास्टिटिस रोग
- अटल इनोवेशन मिशन डिजी-बुक इनोवेशन फॉर यू
- पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम
- इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF)
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)
- स्पंदित सफेद बौना (Pulsating White Dwarf)
- निपुण भारत मिशन
- पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत मोबाइल अस्पताल
- भारत का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- AY4.2 भारत में 'अनियमित': INSACOG
- भारत ने ADB, AIIB से वैक्सीन ऋण मांगा
- अग्नि-5
- न्यूमोकोकल 13-वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV) ड्राइव लॉन्च

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- क्वाड पहल में शामिल हो सकता है चीन
- CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार
- भारत अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्थन देता है
- भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक सुरक्षा
- स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट: यूनिसेफ
- भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन (HAC) में शामिल हुआ
- समझौता ज्ञापन: कपड़ा मंत्रालय और GIZ
- प्रतिबंध अधिनियम (CAATSA) के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला
- परमाणु नियामक आयोग (NRC)
- रोहिंग्या संकट
- OECD/G20 समावेशी फ्रेमवर्क टैक्स डील
- 3rd इंडिया - यूके एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप - मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता
- उत्तर पश्चिमी यूरोप सहकारी आयोजन
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स: भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर
- सीमा संबंधी वार्ता में तेजी लाने के लिए चीन और भूटान के बीच समझौता
- भारत-इजरायल के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू
- लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज (LMDC)
- पाकिस्तान फिर से FATF की 'ग्रेलिस्ट' पर बरकरार
- वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021

- अफगानिस्तान में 'पीपुल्स इकोनॉमी' के लिए यूएन फंड
- इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (IPRD)
- अफ्रीकी संघ
- डेटा प्रकटीकरण ढांचा
- 15वां भारत-इजरायल संयुक्त कार्य समूह
- 18वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन

विविध

- 01 अक्टूबर: अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
- 'राज्य पोषण प्रोफाइल' (एसएनपी)
- वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार
- गेमिंग विकार और रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICD)
- मिहिदाना
- गुडूची (Guduchi)
- साहित्य में नोबेल पुरस्कार
- पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम
- नोबेल शांति पुरस्कार 2021
- डॉ. तीजन बाई ने 'गोल' कार्यक्रम के मेंटर्स और मेंटीज़ को प्रेरित किया
- 177 संभावित जनजातीय उत्पादों के लिए जीआई टैग
- डाक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
- केरावन केरल परियोजना
- भारत ने 100 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक को पार किया
- सक्षम केंद्र
- ढोल (Dhole)

मुख्य फोकस (MAINS)

- पार्टियों को संवैधानिक बनाना
- गांधी जी एक दार्शनिक के रूप में
- आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) को भंग किया गया
- MSP मांग और संभावित समाधान
- पटाखा निर्माताओं पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा
- शहरों द्वारा जलवायु कार्रवाई को अपनाना
- कोयला संकट
- डीप ब्रेन स्टिमुलेशन
- भारतीय कृषि में डेटा क्रांति
- PRIs और आपदा प्रबंधन
- जलवायु विज्ञान के लिए पहला नोबेल
- शरणार्थी कानून
- 'अर्ध-संघीय' लोकतंत्र पर विचार
- इंडो-पैसिफिक में एक 'ताइवान फ्लैशप्वाइंट'
- वन संरक्षण अधिनियम और प्रस्तावित संशोधन
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण

- जलवायु संकट से निपटना
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पर विवाद
- गति शक्ति योजना
- प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतें
- भारत-श्रीलंका: कोलंबो पोर्ट
- COP26 जलवायु सम्मेलन
- भवन जल सुरक्षा
- हंगर: GHI का विश्लेषण
- अक्टूबर में असामान्य भारी बारिश
- अन्य क्वाड
- COP26 पर कार्बन मार्केट्स पहेली
- लिथियम सुरक्षित करने के लिए भारत की रेस
- भारत का मध्य एशियाई आउटरीच
- भारत को नेट जीरो पर साइन ऑन क्यों नहीं करना चाहिए?
- चीन का नया भूमि सीमा कानून और भारतीय सरोकार
- खरीद सुधार (Procurement Reforms)
- आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
- फ्रीबी कल्चर (Freebie Culture)
- पेगासस केस
- म्यांमार संकट

प्रैक्टिस MCQs

उत्तर कुंजी

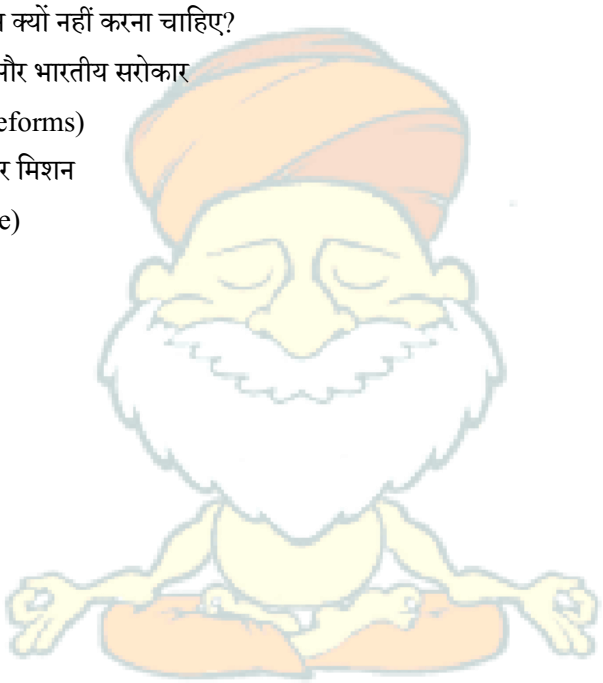

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA)	**संदर्भ :** गृह मंत्रालय (MHA) ने गैर सरकारी संगठनों के लिए अपने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) पंजीकरण प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) क्या है?** • भारत में व्यक्तियों के विदेशी वित्त पोषण को FCRA अधिनियम के तहत नियंत्रित और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। • अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिए ऐसा योगदान प्राप्त किया गया है। • इस अधिनियम के तहत संगठनों का पंजीकरण पाँच वर्ष के लिये वैध होता है, लेकिन सभी मानदंडों का पालन करने के बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। • पंज़ीकृत संघ/संगठन सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिये विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं। **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020** • **विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर रोक:** अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है। • **विदेशी अंशदान का अंतरण:** अधिनियम विदेशी अंशदान को स्वीकार करने के लिए पंजीकृत किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। • **पंजीकरण के लिए आधार:** अधिनियम एक पहचान दस्तावेज के रूप में, विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाता है। • **FCRA खाता:** विदेशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दिल्ली की उस शाखा में ही प्राप्त किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। • **प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग में कमी:** अब कोई भी गैर-सरकारी संगठन (NGO) विदेशी अंशदान की 20 प्रतिशत से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्च पर नहीं कर सकता है। FCRA 2010 में यह सीमा 50% थी। • **प्रमाण पत्र का समर्पण:** अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर करने की अनुमति देता है।
OCI उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में उपस्थित हो सकते हैं	**संदर्भ :** सुप्रीम कोर्ट ने भारत के प्रवासी नागरिकों (OCI) के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में NEET-UG 2021 काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि OCI को सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने का आदेश केवल 2021-2022 शैक्षणिक वर्ष तक ही सीमित है। **पृष्ठभूमि** • गृह मंत्रालय ने NEET के उद्देश्य से OCI उम्मीदवारों को अनिवासी भारतीयों (NRIs) के समान व्यवहार करने का निर्देश दिया था। • इसका मतलब यह होगा कि सफल OCI उम्मीदवारों को भारत में मेडिकल सीटों के लिए एनआरआई को उच्च शुल्क का भुगतान करना होगा। **NRI और OCI में क्या अंतर है?** • NRI को भारतीय पासपोर्ट के साथ भारत के नागरिक को आवासीय दर्जा प्रदान करने के लिए दिया जाता है जो काम/व्यवसाय, या शिक्षा के उद्देश्य से विदेश में रहता है। • OCI एक आप्रवास स्थिति है जो भारतीय मूल के एक विदेशी नागरिक को दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप

	में प्रदान की जाती है जिसकी भारतीय संविधान द्वारा अनुमति नहीं है।
जमानत मांगने का अधिकार संविधान में निहित: सुप्रीम कोर्ट	**संदर्भ :** सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जमानत की अर्जी दाखिल करने का अधिकार संविधान में निहित एक "व्यक्तिगत अधिकार" है। • दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439, 438 और 389 में एक अभियुक्त, एक विचाराधीन कैदी या सजा के निलंबन पर जमानत लेने के लिए अपील अदालत के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे एक दोषी व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी गई है। • यदि इन आवेदनों को सूचीबद्ध करने पर पूर्ण प्रतिबंध है, यहां तक कि कम सजा वाले अपराधों के लिए भी, यह प्रभावी रूप से जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने के लिए स्वतंत्रता चाहने वालों के लिए पहुंच को अवरुद्ध कर देगा और हिरासत में रखने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देगा। • इस तरह के आदेश में अस्थायी रूप से वैधानिक प्रावधानों को हटाने का प्रभाव भी होता है। **पृष्ठभूमि** • राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मार्च में महत्वपूर्ण मामलों की श्रेणी में जमानत, अपील, अपीलों में सजा के निलंबन के लिए आवेदनों और संशोधनों को सूचीबद्ध नहीं करने का आदेश पारित किया था।
भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रकिया का सरलीकरण	**प्रसंग:** गृह मंत्रालय (MHA) ने अपनी नागरिकता को त्यागने के इच्छुक भारतीयों के लिये प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। नागरिकता त्यागने संबंधी इस नई प्रकिया के तहत आवेदकों को ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा दी जाएगी और साथ ही इस समस्त प्रकिया को 60 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रावधान है। **नागरिकता के बारे में** • भारत में, संविधान का अनुच्छेद 5-11 नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। नागरिकता शब्द का अर्थ किसी भी ऐसे राज्य की पूर्ण सदस्यता का आनंद लेना है जिसमें एक नागरिक को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। • नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति तीन तरीकों से संभव है। • **स्वैच्छिक त्याग:** यदि भारत का कोई नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक भी है, निर्धारित तरीके से एक घोषणा के माध्यम से अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। • **समाप्ति:** यदि कोई नागरिक जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता अपनाता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। • **सरकार द्वारा वंचित किया जाना:** भारत सरकार कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। यह केवल उन नागरिकों के मामले में लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण, देशीयकरण, या केवल अनुच्छेद 5 (c) द्वारा नागरिकता हासिल की है।
असम समझौते को लागू करने के लिए पैनल गठित होगा	**प्रसंग:** असम सरकार ने 1985 के असम समझौते के सभी खंडों के कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और जांच करने के लिए एक आठ सदस्यीय उप-समिति का गठन किया है। • उप-समिति को राज्य के सर्वांगीण विकास की क्षमता के अलावा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, बाढ़ और कटाव के मुद्दों, शहीदों के परिवारों और असम आंदोलन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अद्यतन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने और जांच करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है। **असम समझौता क्या है?** • यह 1985 में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता था। • समझौते पर हस्ताक्षर करने से छह साल के आंदोलन का समापन हुआ, जिसे 1979 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें असम से अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग की गई थी। • यह असम में अवैध विदेशियों का पता लगाने के लिए 24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि की एक कट-ऑफ निर्धारित करता है।

	• हालांकि, 1951 के बाद अवैध रूप से असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों का पता लगाने और निर्वासन की मांग की गई थी। **क्या आप जानते हैं?** • असम समझौते के खंड-6 के अनुसार, असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत के संरक्षण, रक्षा और प्रोत्साहन के लिए यथोचित संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को RIMC प्रवेश में शामिल होने की अनुमति दी	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिसंबर में होने वाली राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (RIMC) की प्रवेश परीक्षा देने के लिए लड़कियों को अनुमति देना का निर्देश दिया है। • हाल ही में, SC ने सशस्त्र बलों से महिलाओं को नवंबर 2021 में भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने को कहा था। **RIMC के बारे में** • राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) भारत में दून घाटी, देहरादून में स्थित लड़कों के लिए एक सैन्य स्कूल है। • इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। • RIMC राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और बाद में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक फीडर संस्थान है।
ई-श्रम पोर्टल	**सुर्खियों में:** 3 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। • श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoLE) द्वारा • यह असंगठित कामगारों (NDUW) का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए वेब पोर्टल है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। • यह लगभग 398-400 मिलियन असंगठित कामगारों को पंजीकृत करने और उन्हें 12 अंकीय विशिष्ट संख्या वाला ई-श्रम कार्ड जारी करने की इच्छा रखता है। • पोर्टल पर पंजीकरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 2 लाख रुपये प्रति वर्ष के दुर्घटना कवरेज का और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये के पात्र होंगे। **ई-श्रम पोर्टल का महत्व - असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW)** • पोर्टल असंगठित कामगारों के लाभ के लिये उपलब्ध सभी सामाजिक कल्याण योजनाओं को एकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। • पोर्टल अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को उनकी अवस्थिति पर ध्यान दिये बिना कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। • असंगठित क्षेत्र के कामगार बीमा कवरेज, मातृत्त्व लाभ, पेंशन, शैक्षिक लाभ, भविष्य निधि लाभ, आवास योजनाओं आदि के रूप में उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। **मुद्दे** • **जटिल प्रक्रिया:** प्रत्येक कार्यकर्ता को पंजीकृत करने की विशाल प्रकृति को देखते हुए, यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। • **डेटा सुरक्षा मुद्दे:** कड़े डेटा संरक्षण कानून के अभाव में, पोर्टल की प्रमुख चिंताओं में से एक डेटा-सुरक्षा और इसका संभावित दुरुपयोग है क्योंकि यह एक वृहत आकार का डेटाबेस है। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ डेटा साझा करना होगा जिनकी डेटा सुरक्षा क्षमता अलग-अलग है। • **निश्चित मुद्दे:** ईपीएफ और ईएसआई द्वारा कवर किए गए श्रमिकों को छोड़कर, लाखों अनुबंध और निश्चित अवधि के अनुबंध श्रमिकों को यूडब्ल्यू के ब्रह्मांड से बाहर रखा जाएगा। • **बदलती पहचान:** असंगठित की जटिल और हमेशा बदलती पहचानें हो सकती हैं जहां वे औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच चलती हैं। • **गिग श्रमिक -** हालाँकि श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 'गिग' कामगारों (Gig Workers) को इस प्रक्रिया में शामिल किया है, अन्य तीन श्रम संहिताएँ उन्हें कामगार के रूप में शामिल नहीं करतीं, न ही सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) उन्हें विशेष रूप से शामिल करती हैं, जब तक कि वे 'self-employed' या 'wage workers' घोषित नहीं हों। • **संघीय चुनौतियाँ:** संघ योजना बनाता है लेकिन राज्यों को इसे लागू करना होता है। राज्य की क्षमताओं में

	अंतर कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। • **भ्रष्टाचार :** भ्रष्टाचार को लेकर भी एक चिंता है क्योंकि इंटरनेट प्रदाता जैसी मध्य-सेवा एजेंसियां ई-श्रम कार्डों को पंजीकृत करने और उनका प्रिंट लेने के लिये अत्यधिक शुल्क वसूल कर सकती हैं। **आगे की राह** • भ्रष्टाचार के मुद्दों के समाधान के लिए निगरानी एजेंसियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। • पंजीकरण प्रणाली की दक्षता का आकलन करने के लिए सरकार को पंजीकरण के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए। • एक राष्ट्र-एक-राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड (विशेष रूप से बैंक खाता सीड) और चुनाव आयोग कार्ड का ट्रिपल लिंकेज, कुशल और रिसाव-रहित वितरण के लिए किया जा सकता है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	**संदर्भ :** हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने कश्मीरी पंडितों के अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकों की लक्षित हत्याओं के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?** • NHRC की स्थापना 1993 में हुई थी। • यह 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाए गए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। • **स्थिति:** यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है। • मुख्यालय: नई दिल्ली। **कार्य:** • यह **मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच के उद्देश्य** से **केंद्र सरकार या राज्य सरकार** के किसी अधिकारी या जाँच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग करने के लिये **अधिकृत** है। • मानवाधिकारों के बारे में शोध करना, विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाना और गैर सरकारी संगठनों के काम को प्रोत्साहित करना। **संयोजन:** • यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, वह अध्यक्ष होता है। • **नियुक्ति:** NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल हैं: ○ प्रधान मंत्री (अध्यक्ष) ○ गृह मंत्री ○ लोकसभा में विपक्ष के नेता ○ राज्यसभा में विपक्ष के नेता ○ लोकसभा अध्यक्ष ○ राज्य सभा के उपसभापति • राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या वे 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकता है।
ई-वोटिंग	**संदर्भ :** पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों (CEC) ने ऑनलाइन वोटिंग और रिमोट वोटिंग के विचार के बारे में कई तरह की चिंताओं को उठाया है, ऐसे समय में तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग (SEC) एक ई-वोटिंग प्रयोग करने के लिए तैयार है और चुनाव आयोग भारत (EC) भी रिमोट वोटिंग की संभावनाएं तलाश रहा है। • राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि तेलंगाना SEC 20 अक्टूबर को स्मार्टफोन ऐप-आधारित ऑनलाइन वोटिंग प्रयोग करेगा। • दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने पिछले साल कहा था कि वह उन मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग के विकल्प पर विचार कर रहा है, जो उन मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां वे पंजीकृत हैं।

	चिंताएं • मतपत्रों की गोपनीयता बनाए रखना मुश्किल होगा। • यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि सरलतम तकनीक पर आधारित है, अभी भी कानूनी विवादों का मामला है, तो यह बहुत संभव है कि ऐप-आधारित वोटिंग फुलप्रूफ न हो। • यह स्पष्ट नहीं था कि मतदाता पहचान का सत्यापन, मुक्त मतदान का माहौल बनाए रखने और मतपत्रों की गोपनीयता को कैसे बनाए रखा जाएगा। • इसे राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। • बाहरी मतदाताओं के लिए प्रचार भी किया जाएगा।
अंशकालिक कर्मियों को नियमितीकरण का हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अंशकालिक कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि वे सरकार में किसी भी स्वीकृत पद पर काम नहीं कर रहे हैं। • नियमितीकरण केवल राज्य/सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार हो सकता है और "कोई भी अधिकार के रूप में नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता"। • कोई पद न होने पर स्थायीता का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। • काम उपलब्ध होने की अवधि के दौरान हर साल मौसमी काम जारी रखना एक स्थायी स्थिति का गठन नहीं करता है।
अग्रिम जमानत	**प्रसंग :** सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक बेहतर अदालत अग्रिम जमानत के आदेश को रद्द कर सकती है यदि यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सामग्री हो कि अपराध की गंभीरता और अपराध में आरोपी की भूमिका जैसे कारकों पर निचली अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया था। **अग्रिम जमानत की अवधारणा क्या है?** • अग्रिम ज़मानत का प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 में किया गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय विधि आयोग ने अपने 41वें प्रतिवेदन में इस प्रावधान को दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करने की अनुशंसा (सिफारिश) की थी। • अग्रिम ज़मानत (Anticipatory bail) न्यायालय का वह निर्देश है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने के पहले ही ज़मानत दे दी जाती है अर्थात् आरोपित व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। • **समय सीमा:** सुशीला अग्रवाल बनाम NCT राज्य दिल्ली (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फैसला सुनाया कि अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) के लिये कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है और यह मुकदमे के अंत तक भी जारी रह सकती है। • यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। **ऐसी सुरक्षा की क्या आवश्यकता है?** • एक आरोपी परिवार का प्राथमिक देखभाल करने वाला या एकमात्र कमाने वाला भी हो सकता है। उनकी गिरफ्तारी उनके प्रियजनों को भुखमरी और उपेक्षा की स्थिति में छोड़ सकती है। • वर्ष 1980 में गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि धारा 438 (1) की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये।
आदर्श आचार संहिता (MCC)	**भाग :** प्रीलिम्स और मेन्स जीएस-द्वितीय- शासन, चुनाव **सुर्खियों में:** यदि निर्वाचन क्षेत्र राज्य की राजधानी / महानगरीय शहरों / नगर निगमों में शामिल है, तो MCC निर्देश केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में लागू होंगे। **आदर्श आचार संहिता (MCC)** • मुख्य रूप से भाषणों, मतदान दिवस, मतदान केंद्रों, विभागों, चुनाव घोषणापत्र, जुलूस और सामान्य आचरण के संबंध में चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के संचालन के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक सेट। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार है, जो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। • **फिलॉसोफी:** पार्टियों और उम्मीदवारों को अपने विरोधियों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, उनकी नीतियों और कार्यक्रमों की रचनात्मक रूप से आलोचना करनी चाहिए, और कीचड़ उछालने और व्यक्तिगत हमलों का

	सहारा नहीं लेना चाहिए। MCC का उद्देश्य चुनाव अभियान को सार्वजनिक नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद करना और सभी दलों तथा उम्मीदवारों के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है। • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता के लिए आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद लागू होता है। लोकसभा चुनाव के समय, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें MCC के अंतर्गत आती हैं। • MCC कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोष	**संदर्भ :** हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सिफारिश की है कि 'मादक पदार्थों के नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष' का उपयोग केवल पुलिसिंग गतिविधियों के बजाय नशामुक्ति कार्यक्रमों के संचालन हेतु किया जाना चाहिये। **अन्य सम्बंधित तथ्य** • यह कोष 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस' (NDPS) अधिनियम, 1985 के प्रावधान के अनुसार बनाया गया था, जिसमें 23 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। • उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने या उनके दुरुपयोग को नियंत्रित करने, धारा 71 के उपायों के संबंध में किए गए व्यय को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निधि का उपयोग किया जाएगा। **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के बारे में** • इसे NDPS एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। • यह किसी भी व्यक्ति को उत्पादन, खेती, बिक्री, खरीद, परिवहन, भंडारण या किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के सेवन से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है। **साइकोट्रोपिक्स और नारकोटिक्स के बारे में** • चिकित्सा की दृष्टि से, साइकोट्रोपिक्स उन रासायनिक पदार्थों को नामित करता है जो मन पर कार्य करते हैं, जो कि किसी व्यक्ति के चेतन या अचेतन मानसिक जीवन पर होता है। • नारकोटिक्स में ऐसे पदार्थ शामिल हैं जो स्तब्ध हो जाना (बेहोश), मांसपेशियों में छूट और संवेदनशीलता में कमी या उन्मूलन का कारण बनते हैं।
पुरुषों को भूमि अधिकार देगा मातृवंशीय मेघालय	**संदर्भ :** मातृवंशीय मेघालय माता-पिता की परंपरा को बदलने का फैसला किया है, माता-पिता की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा खटदुह को सौंपता है, जिसका अर्थ खासी भाषा में सबसे छोटी बेटी है। • मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (KHADC) ने घोषणा की है कि वह 'खासी उत्तराधिकार संपत्ति विधेयक, 2021' पेश करेगी। इस बिल का उद्देश्य खासी समुदाय में भाई-बहनों के बीच पैतृक संपत्ति का "समान वितरण" करना है। • यदि प्रस्तावित विधेयक लागू होता है, तो यह मातृवंशीय खासी जनजाति की विरासत की सदियों पुरानी प्रथा को संशोधित करेगा। • विधेयक में किसी गैर-आदिवासी से शादी करने वाले और अपने पति या पत्नी की संस्कृति और परंपरा को स्वीकार करने वाले किसी भी वार्ड को संपत्ति के हिस्से से वंचित करने का भी प्रावधान है। **खासी की परंपरा के बारे में** • मेघालय की तीन जनजातियाँ- खासी, जयंतिया और गारो, विरासत की एक मातृवंशीय प्रणाली का अभ्यास करती हैं। इस प्रणाली में वंश और वंश का पता माता के वंश से चलता है। • यहां, बच्चों को अपनी मां का उपनाम मिलता है, पति अपनी पत्नी के घर चले जाते हैं, और सबसे छोटी बेटियों को पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है। • खासी का इस्तेमाल मेघालय में कई उपसमूहों को संदर्भित करने के लिए एक छत्र वाक्यांश के रूप में किया जाता है, जिनकी अलग-अलग भाषाएं, संस्कार, समारोह और आदतें हैं, लेकिन की हिन्न्यू ट्रेप (Ki Hynniew Trep)(द सेवन हट्स) के रूप में एक जातीय पहचान साझा करते हैं।
पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की	**प्रसंग :** सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यक्तियों के "पवित्र निजी स्थान" में राज्य की शक्ति पूर्ण नहीं है। • इस प्रकार, इसने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर.वी. रवींद्रन ने आरोपों की जांच करने के लिए कहा कि केंद्र ने नागरिकों की जासूसी करने के लिए इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया। • कोर्ट ने यह भी कहा है कि कानून के शासन वाले लोकतांत्रिक देश में पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों के बिना

	अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ○ राज्य द्वारा निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग साक्ष्य आधारित होना चाहिए। **पेगासस (Pegasus) क्या है?** ● यह एक प्रकार का मैलेशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर है जिसे स्पाइवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ● पेगासस को इज़राइली फर्म NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है जिसे वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। ● स्पाइवेयर लोगों के फोन के जरिए उनकी जासूसी करता है। ● पेगासस एक शोषण लिंक भेजकर काम करता है, और यदि लक्षित उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है, तो उपयोगकर्ता के फोन पर मैलवेयर या निगरानी की अनुमति देने वाला कोड इंस्टॉल हो जाता है। ● एक बार पेगासस स्थापित हो जाने पर, हमलावर के पास लक्षित उपयोगकर्ता के फोन तक पूरी पहुंच होती है। **पेगासस क्या कर सकता है?** ● पेगासस "लोकप्रिय मोबाइल मैसेजिंग ऐप से पासवर्ड, संपर्क सूची, कैलेंडर ईवेंट, टेक्स्ट संदेश और लाइव वॉयस कॉल सहित लक्ष्य के निजी डेटा को वापस भेज सकता है"। ● निगरानी के दायरे का विस्तार करते हुए, फ़ोन के आस-पास की सभी गतिविधियों को कैप्चर करने के लिए लक्ष्य के फ़ोन कैमरा और माइक्रोफ़ोन को चालू किया जा सकता है।
मुल्लापेरियार बांध मुद्दा	**संदर्भ :** सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्लापेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। **पृष्ठभूमि** ● सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2014 में मुल्लापेरियार बाँध से संबंधित सभी मुद्दों की देख-रेख के लिये एक स्थायी पर्यवेक्षी समिति का गठन किया था। यह बाँध तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद का एक स्रोत है। **मुद्दा क्या है?** ● केरल ने कहा कि जल स्तर 139 फीट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, जैसा कि अदालत ने 24 अगस्त, 2018 को आदेश दिया था, जब राज्य बाढ़ की चपेट में था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर बांध में पानी का स्तर बढ़ा तो 50 लाख लोगों की जान को खतरा होगा। ● हालांकि, तमिलनाडु ने 2006 और 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए इस फैसले पर आपत्ति जताई, जिसमें अधिकतम जल स्तर 142 फीट तय किया गया था। ● पर्यवेक्षी समिति की नवीनतम अनुशंसा ● पर्यवेक्षी समिति ने सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश की कि मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ● तमिलनाडु यह कहता है कि इसका जल स्तर 137 फीट है। ● हालांकि, केरल यह कहते हुए उसकी राय से सहमत नहीं था कि इसकी अंतिम रिहाई से बाढ़ का खतरा होगा और केरल में लाखों लोगों के जीवन को खतरा होगा। **तमिलनाडु क्या कहता है?** ● तमिलनाडु का दावा है कि हालांकि उसने बांध को मजबूत करने के उपाय किए हैं, केरल सरकार ने जलाशय के जल स्तर को बढ़ाने के किसी भी प्रयास को अवरुद्ध कर दिया है - जिसके परिणामस्वरूप मदुरै के किसानों को नुकसान हुआ है। **केरल के तर्क क्या हैं?** ● हालांकि, केरल भूकंप की आशंका वाले इडुक्की जिले में नीचे की ओर रहने वाले निवासियों द्वारा तबाही की आशंकाओं को उजागर करता है। ● वैज्ञानिकों का तर्क है कि यदि इस क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर छह से ऊपर की तीव्रता वाला भूकंप आता है, तो 30 लाख से अधिक लोगों की जान को गंभीर खतरा होगा। **मुल्लापेरियार बाँध** ● यह मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बना एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है।

	• हालांकि बांध केरल में स्थित है, यह तमिलनाडु द्वारा 999 वर्षों (पेरियार झील लीज समझौता) के लिए 1886 लीज इंडेंट के बाद संचालित किया जाता है, जिस पर त्रावणकोर के महाराजा और पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए भारत के राज्य सचिव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। • इसका निर्माण 1887 और 1895 के बीच हुआ था। • यह नदी को अरब सागर के बजाय बंगाल की खाड़ी की ओर बहने के लिए पुनर्निर्देशित किया और मद्रास प्रेसीडेंसी में मदुरै के शुष्क वर्षा क्षेत्र को पानी प्रदान किया।
UIDAI ने डेटा बिल से छूट की मांग की	**संदर्भ :** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India – UIDAI) ने कानूनों के दोहरेपन से बचने के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (Personal Data Protection – PDP) कानून से छूट की अपील की है। • डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति के साथ बातचीत में, UIDAI के पदाधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण पहले से ही आधार अधिनियम द्वारा शासित है और कानूनों का दोहराव नहीं हो सकता है। **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (PDP) कानून के बारे में** • यह कानून का एक व्यापक हिस्सा है जो व्यक्तियों को इस बात पर अधिक नियंत्रण देने का प्रयास करता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्र, संग्रहीत और उपयोग किया जाता है। • बिल इसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की भी स्थापना करता है। **विधेयक की उत्पत्ति** • इस विधेयक की उत्पत्ति न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्ण द्वारा हुई । • निजता के अधिकार के मामले (जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। **विवादास्पद धारा 35** • यह भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और राज्य की सुरक्षा का आह्वान करता है ताकि सरकारी एजेंसियों के लिये केंद्र सरकार को इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान को निलंबित करने की शक्ति प्रदान की जा सके। **UIDAI के बारे में** • यह आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई, 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। • UIDAI को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की विशिष्ट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करना अनिवार्य है। • UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। • **मंत्रालय:** इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD), 1969	**संदर्भ :** केंद्र ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है जो इसे "राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस को बनाए रखने" में सक्षमता करेगा। • अभी तक, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्यों द्वारा नियुक्त स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। **अन्य संबंधित तथ्य** • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (नागरिकता अधिनियम, 1955) और चुनावी रजिस्टर (निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960) तथा आधार (आधार अधिनियम, 2016), राशन कार्ड (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013), पासपोर्ट (पासपोर्ट अधिनियम) एवं ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस [मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019] को अद्यतन करने हेतु। **केंद्र द्वारा प्रस्तावित संशोधन** • यह प्रस्तावित है कि मुख्य रजिस्ट्रार (राज्यों द्वारा नियुक्त) राज्य स्तर पर एक एकीकृत डेटाबेस बनाए रखेंगे और इसे भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RJI) (गृह मंत्रालय के तहत) द्वारा बनाए गए 'राष्ट्रीय स्तर' पर डेटा के साथ एकीकृत करेंगे। संशोधनों का अर्थ होगा कि केंद्र डेटा का समानांतर भंडार होगा।

	● "विशेष उप-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति, आपदा की स्थिति में उनकी किसी या सभी शक्तियों और कर्तव्यों के साथ मृत्यु के पंजीकरण तथा उसके उद्धरण जारी करने के लिये निर्धारित की जा सकती है।"

मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट (MeghEA)	**संदर्भ :** हाल ही में, मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट (MeghEA) का शुभारंभ किया गया है। ● इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और शासन में सुधार करना है। ● एंटरप्राइज़ आर्किटेक्चर (EA) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए IT (सूचना प्रौद्योगिकी) बुनियादी ढांचे को मानकीकृत और व्यवस्थित करते हैं। **अन्य संबंधित तथ्य** ● MeghEA पहल के तहत वर्ष 2030 तक मेघालय को एक उच्च आय वाला राज्य बनाने हेतु 6 स्तंभों अर्थात् शासन, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण पर आधारित है। ● 2030 तक मेघालय को उच्च आय वाला राज्य बनाने की परिकल्पना की गई है। ● MeghEA की परिकल्पना निम्नलिखित डिजिटल सरकारी लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए की गई है: ○ एक नियोजित राज्य सरकार परिवर्तन पहल जो रणनीतियों, नीतियों, प्रक्रियाओं, सेवाओं और संगठनात्मक क्षमता के बीच कुशल समन्वय की मांग करती है। ● बेहतर समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए सभी ICT पहलों को एक छत्र के नीचे समन्वयित करना। ● मल्टी-चैनल सेवा वितरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की प्रक्रिया पुनर्रचना को लागू करना और ICT सक्षम बनाना। ● यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के एप्लिकेशन और सिस्टम अंतिम उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं ● रोजगार और विकास के लिए ICT का लाभ उठाकर साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ	**संदर्भ:** SBM-U 2.0 और AMRUT 2.0 को हमारे सभी शहरों को 'गैसबेज फ्री (Gasrbage Free)' और 'वाटर सिक्योर' बनाने की आकांक्षा को साकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रमुख मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का संकेत देते हैं और सतत विकास लक्ष्यों 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मदद करेंगे। **स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के बारे में** ● सभी शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाएं और अमृत के अंतर्गत आने वाले शहरों को छोड़कर सभी शहरों में दूषित और काले पानी का प्रबंधन सुनिश्चित करना। ● साथ ही इसके तहत सभी शहरों के स्थानीय निकायों को ओडीएफ+ और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले को ओडीएफ++ के रूप में तैयार करने की योजना है। ● यह मिशन ठोस कचरे के स्रोत पृथक्करण के लिए 3R के सिद्धांत पर काम करेगा, ये तीन R (रिड्यूस (कम करें) रीयूज (पुन: उपयोग), रिसाइकल (पुर्नचक्रण)) हैं इसके तहत शहरी ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डंपसाइट के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा **अमृत 2.0 के बारे में** ● इस योजना का लक्ष्य 4,700 शहरी स्थानीय निकायों में सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति करना है तथा इसके तहत इन शहरों में 2.64 नल कनेक्शन और 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज होगा। इससे शहरी क्षेत्रों में करीब 10.5 करोड़ लोगों को लाभ होगा। ● अमृत 2.0 में सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को अपनाएगा और यह सतह और भूजल निकायों के संरक्षण और कायाकल्प को बढ़ावा देगा। ● यह मिशन नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकियों और कौशल का लाभ उठाने के लिए जल प्रबंधन और प्रौद्योगिकी उप-मिशन में डेटा आधारित शासन को बढ़ावा देगा। ● योजना के तहत शहरों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए 'पेयजल सर्वेक्षण' शुरू किया जाएगा। इस योजना पर 2.87

	लाख करोड़ रुपए है।
इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA)	• यह एक ऐसा ढांचा है जो पूरे भारत में सभी सरकारों और उनकी एजेंसियों द्वारा समान मॉडल और मानकों के अनुरूप स्वतंत्र रूप से तथा समानांतर में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के विकास और कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है। • इसे अक्टूबर 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा ई-गवर्नेंस मानक के रूप में अधिसूचित किया गया था। • IndEA का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सरकारों में राज्य सरकारों, मंत्रालयों और विभागों को उनके उद्यम वास्तुकला के विकास के लिए एक संरचित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करना है। 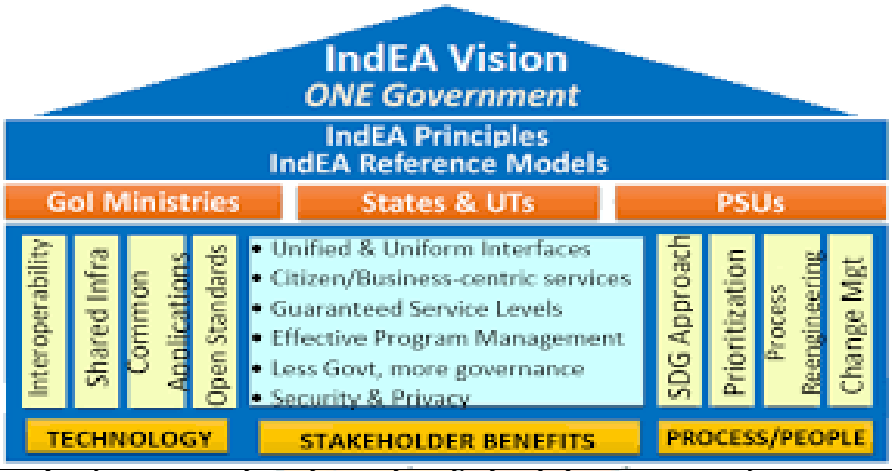
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना	**संदर्भ :** मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना, जो छात्रों को गर्म भोजन प्रदान करती है, का नाम बदलकर राष्ट्रीय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया है। **पीएम पोषण योजना में प्रमुख प्रस्ताव** • **पूरक पोषण:** नई योजना में आकांक्षी ज़िलों और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चों के लिये पूरक पोषण का भी प्रावधान है। • **राज्य आहार तय करना :** यह गेहूँ, चावल, दाल और सब्जियों के लिये धन उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार के स्तर पर मौजूद सभी प्रतिबंध और चुनौतियों को समाप्त करता है। • वर्तमान में यदि कोई राज्य मेनू में दूध या अंडे जैसे किसी भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है, तो केंद्र सरकार अतिरिक्त लागत वहन नहीं करने संबंधी प्रतिबंध को हटा लिया गया है। • **न्यूट्री-गार्डन:** बच्चों को "प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव" देने के लिए उन्हें स्कूलों में विकसित किया जाएगा। • **महिलाएं और FPOs:** योजना के कार्यान्वयन में किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय रूप से निर्मित जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। • **सोशल ऑडिट:** जमीनी स्तर पर निष्पादन के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा "निरीक्षण"। • **तिथि-भोजन:** त्योहारों आदि पर बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए समुदायों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। • **स्कूल को DBTs:** राज्यों से कहा जाएगा कि वे खाना पकाने की लागत के नकद हस्तांतरण को अलग-अलग स्कूल खातों में नकद हस्तांतरण और रसोइयों तथा सहायकों के बैंक खातों में भत्तों का हस्तांतरण करें। • **समग्र पोषण:** स्कूल पोषण उद्यान के साथ-साथ स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। **मध्याह्न भोजन योजना के बारे में** • प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE) 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। • **उद्देश्य:** नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों में पोषण स्तर में सुधार करना। • 2001 में यह पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बन गया।

- इस योजना में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) और सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत समर्थित मदरसों / मकतबों में पढ़ने वाले कक्षा I-VIII के बच्चे शामिल हैं।
- यह विश्व का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है।
- यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आता है।

जल जीवन मिशन

संदर्भ : 2019 में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से पांच करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

- लगभग सवा लाख गांवों में अब नल का पानी हर घर में पहुंच रहा है।
- जल जीवन मिशन ऐप भी हितधारकों के बीच जागरूकता में सुधार लाने और मिशन के तहत योजनाओं की अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिए लॉन्च किया गया है।
- राष्ट्रीय जल जीवन कोष भी शुरू किया गया है, जहां कोई भी व्यक्ति, संस्था या परोपकारी, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने में मदद करने के लिए योगदान दे सकता है।

जल जीवन मिशन क्या है?

- ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।
  - इसमें 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
  - इसमें स्कूलों, आंगनबाडी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन भी शामिल है।
- यह कार्यक्रम अनिवार्य तत्वों के रूप में स्रोत स्थिरता उपायों को भी लागू करेगा, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन: उपयोग।
- JJM स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह मिशन पानी के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यह पानी के लिए एक जन आंदोलन बनाना चाहता है, जिससे यह सभी की प्राथमिकता बन जाए।
- यह नकद, वस्तु और श्रम तथा स्वैच्छिक श्रम में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदायों के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देता है और सुनिश्चित करता है।
- **मुख्य मंत्रालय:** पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- **फंडिंग पैटर्न:** केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है।
- राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर योजना का चार स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी आदि।

बिजली नियम	**सुर्खियों में:** बिजली (ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग, इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन चार्ज का विकास और रिकवरी) नियम 2021 के लॉन्च ने ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग के ओवरहालिंग का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे बिजली क्षेत्र की उपयोगिताओं को देश भर में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क तक आसान पहुंच प्रदान की जा सके। ट्रांसमिशन प्रणाली बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में उत्पादन और मांग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। नियम होगा- ● ट्रांसमिशन प्रणाली में निवेश की योजना, विकास और वसूली की प्रक्रिया को कारगर बनाना। ● नियमों का उद्देश्य उत्पादन और पारेषण क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। ● यह नियम देश को अधिक (deeper) बाजार विकसित करने में सक्षम बनाएंगे। ● यह इस बात को रेखांकित करता है कि "विद्युत ट्रांसमिशन योजना इस तरह से बनाई जाएगी कि ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता की कमी विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर ब्रेक के रूप में कार्य न करे और जहां तक संभव हो, ट्रांसमिशन प्रणाली को नियोजित और विकसित किया जाए। उत्पादन और भार की वृद्धि के साथ मेल खाते तथा योजना बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई फालतू निवेश न हो।
सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग	**संदर्भ :** रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने COVID-19 से जोखिमों में कमी का हवाला देते हुए भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को "नकारात्मक" से "स्थिर" में बदल दिया है ● इसने भारत की रेटिंग को Baa3 पर स्थिर रखा, जो निम्नतम निवेश ग्रेड रेटिंग को दर्शाता है। ● मूडीज एक Baa3 या उच्चतर रेटिंग को निवेश ग्रेड का मानता है और Ba1 तथा उससे नीचे की रेटिंग को "जंक" ग्रेड माना जाता है। ● यह उम्मीद करता है कि 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि दर्ज की जाएगी, इसके बाद अगले वर्ष 7.9% की वृद्धि होगी। ● विकास अनुमानों में कमजोर बुनियादी ढांचे, श्रम, भूमि और उत्पाद बाजारों में कठोरता सहित संरचनात्मक चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है, जो निजी निवेश को बाधित करना तथा महामारी के बाद के आर्थिक संकट में योगदान करते हैं। **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग:** ● सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश या संप्रभु इकाई की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है। ● यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम सहित किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। ● सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की भूमिका विदेशी ऋण बाज़ारों में बाण्ड जारी करने के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण है। ● आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग पद्धति को अधिक पारदर्शी, कम व्यक्तिपरक और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करने का आह्वान किया गया है। ● भारत में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के तहत पंजीकृत छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे- CRISIL, ICRA, CARE, SMERA, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग। **भारत का वर्तमान परिदृश्य** ● भारत में कर्ज का बोझ ज्यादा है और कर्ज वहन करने की क्षमता कमजोर है। ● हालांकि, भारत के संकीर्ण चालू खाते के घाटे और ऐतिहासिक रूप से उच्च विदेशी मुद्रा भंडार ने देश की कमजोरियों को बाहरी झटके में कम कर दिया है।
मसौदा बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2021	**संदर्भ:** बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2021 का मसौदा हाल ही में प्रकाशित किया गया था। **नए नियमों का अवलोकन** ● वितरण लाइसेंसधारियों को सभी उपभोक्ताओं को 24×7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि डीजल जेनरेटिंग (DG) सेट चलाने की कोई आवश्यकता न हो। ● बिजली नियामक आयोग वितरण कंपनी के लिए एक अलग विश्वसनीयता शुल्क पर विचार कर सकता है, अगर उसे बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए धन की आवश्यकता होती है। ● वितरण कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में राज्य विद्युत नियामक आयोग को भी दंड का

	प्रावधान करना चाहिए।
बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020	• ये नियम उपभोक्ताओं को उन अधिकारों के साथ "सशक्त" बनाने का काम करते हैं जो उन्हें गुणवत्ता, विश्वसनीय बिजली की निरंतर आपूर्ति तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। • नियमों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में मीटरिंग व्यवस्था शामिल है; बिलिंग और भुगतान; आपूर्ति की विश्वसनीयता आदि। **प्रमुख प्रावधान** • राज्यों को इन नियमों को लागू करना होगा और बिजली के कनेक्शन प्रदान करने तथा नवीनीकरण में देरी जैसे मुद्दों के लिए डिस्कॉम को अधिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। • वे बिजली मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी बाध्य हैं। • अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार दंड लागू करेगी जो उपभोक्ता के खाते में जमा की जाएगी। • इन नियमों के कुछ अपवाद हैं, विशेषकर जहां कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग का संबंध है। **क्या आप जानते हैं?** • बिजली एक समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) का विषय है और केंद्र सरकार के पास इस पर कानून बनाने का अधिकार और शक्ति है।
औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट 2.0	**सुर्खियों में:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट में 41 औद्योगिक पार्कों को 'अग्रणी' (Leaders) श्रेणी के रूप में आंका गया है। • 90 औद्योगिक पार्कों को 'चैलेंजर' (Challenger)श्रे णी के तहत आंका गया है, जबकि 185 की रेटिंग 'आकांक्षियों' के रूप में की गई है। • ये रेटिंग प्रमुख मौजूदा मानकों और बुनियादी सुविधाओं आदि के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इनमें से लगभग 98% पार्क पश्चिमी (महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात) तथा उत्तरी (उत्तराखंड) क्षेत्रों से हैं। • औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली को औद्योगिक पार्क की प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए 4 स्तंभों के आधार पर विकसित किया गया है - आंतरिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, बाहरी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, व्यावसायिक सेवायें और सुविधायें तथा पर्यावरण और सुरक्षा प्रबंधन। • यह रिपोर्ट भारत औद्योगिक भूमि बैंक का एक विस्तार है, जिसमें निवेशकों को निवेश के लिए उनके पसंदीदा स्थान की पहचान करने में सहायता करने के लिए एक जीआईएस-सक्षम डाटाबेस में 4,400 से अधिक औद्योगिक पार्क शामिल है। • यह रेटिंग प्रमुख वर्तमान मानकों तथा अवसंरचना सुविधाओं आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है। • IPRS प्रायोगिक प्रक्रिया 2018 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर में औद्योगिकीकरण को सक्षम करने के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचे की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना तथा नीतिगत विकास का समर्थन करना था।
खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन-तेल पाम (NMEO-OP)	**संदर्भ:** अरुणाचल प्रदेश ने खाद्य तेल-तेल पाम (NMEO-OP) पर राष्ट्रीय मिशन को जल्द ही 1.33 लाख हेक्टेयर में लागू कर दिया है। • इसके अलावा, एकीकृत तेल पाम विकास फर्म 3F ऑयल पाम ने असम और अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल की खेती में 1,750 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है। • दोनों राज्यों में पाम ऑयल की खेती अगले पांच वर्षों में लगभग 31 गुना बढ़कर 62,000 हेक्टेयर हो जाएगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। **NMEO-OP योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?** • **उद्देश्य:** खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना। • **लक्ष्य:** घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को 10.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 18 मिलियन टन करके 2024-25 तक आयात निर्भरता को 60% से 45% तक कम करना, जो 70% विकास लक्ष्य है। • किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज से लेकर प्रौद्योगिकी तक सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। • पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह मिशन हमारी अन्य पारंपरिक तिलहन फसलों की खेती का भी विस्तार करेगा।

	ऐसी योजनाओं की क्या जरूरत है? ● भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ● भारत का पाम तेल आयात इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 60% है। ● हाल ही में, महंगे आयात पर भारत की निर्भरता ने खुदरा तेल की कीमतों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ● भारत में, 94.1% पाम तेल का उपयोग खाद्य उत्पादों में किया जाता है, खासकर खाना पकाने के लिए। इस प्रकार, पाम तेल भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ● **शीर्ष उपभोक्ता:** भारत, चीन और यूरोपीय संघ (ईयू)। **क्या आप जानते हैं?** ● NMEO-OP के पूर्ववर्ती तिलहन और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन थे।
'पीएम मित्र' पार्क	**सुर्खियों में:** हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय से सात 'मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल' (पीएम मित्र) पार्कों की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है। ● 'पीएम मित्र' पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में एक 'विशेष प्रयोजन इकाई' (SPV) द्वारा विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। ● विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा। ● एक स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करेगा ● 'मित्र' पार्क के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 1 लाख रोज़गार सृजित होने और परोक्ष रूप से 2 लाख रोज़गार सृजित होने की उम्मीद है। ● **पार्क में होगा -** ○ **कोर इंफ्रास्ट्रक्चर:** इनक्यूबेशन सेंटर और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री साइट, सड़कें, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल प्रणाली, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और सीईटीपी तथा अन्य संबंधित सुविधाएं जैसे- डिजाइन केंद्र, परीक्षण केंद्र आदि। ○ **सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर:** वर्कर्स हॉस्टल और हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग, मेडिकल, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट सुविधाएं **'5F' फॉर्मूला में शामिल हैं -** फार्म टू फाइबर; कारखाने के लिए फाइबर; फैशन के लिए कारखाना; फैशन टू फॉरेन।
स्वामित्व योजना	● एक्रोनिम स्वामित्व गांवों के सर्वेक्षण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मैपिंग के लिए स्टैंड्स है। ● यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (केंद्र सरकार द्वारा 100%) है जो केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। ● इसका उद्देश्य गांव के घरेलू मालिकों को "अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना और गांवों में निवास ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करने के लिए हैं।" ● सरकार का उद्देश्य देश भर के हर गांव में अगले तीन से चार वर्षों में प्रत्येक घर में ऐसे संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। ● यह योजना ड्रोन का उपयोग करके सभी ग्रामीण गुणों का सर्वेक्षण करना और प्रत्येक गांव के लिए जीआईएस आधारित मानचित्र तैयार करना है।
G-Sec अधिग्रहण कार्यक्रम	**संदर्भ:** रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि यह G-Sec अधिग्रहण कार्यक्रम (GSAP) के तहत अपनी बॉन्ड खरीदारी को मना कर रहा था। ● GSAP पर्याप्त तरलता और वित्तीय बाजारों को स्थिर करने में सफल रहा था। **सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (GSAP) क्या है** ● सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) मूलतः एक व्यापक आकार का बिना शर्त 'संरचित ओपन मार्केट ऑपरेशन' (OMO) है। ● **उद्देश्य:** अर्थव्यवस्था में तरलता के प्रबंधन के साथ-साथ 'यील्ड कर्व' का एक स्थिर और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना। ○ एक यील्ड कर्व एक ऐसी रेखा है जो बांडों की पीढ़ी (ब्याज दरें) बराबर क्रेडिट गुणवत्ता होती है लेकिन अंतर परिपक्वता तिथियां होती हैं।

	○ यील्ड कर्व एक ऐसी रेखा है, जो समान क्रेडिट गुणवत्ता वाले, लेकिन अलग-अलग परिपक्वता तिथियों वाले बॉण्ड की ब्याज़ दर को दर्शाती है। ● मुद्रा आपूर्ति शर्तों को समायोजित करने के लिये RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (g-sec) की बिक्री या खरीद के माध्यम से OMO आयोजित किये जाते हैं। **सरकारी प्रतिभूतियां क्या हैं?** ● एक G-Sec केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य उपकरण है। ● ऐसी प्रतिभूतियां अल्पकालिक या दीर्घकालिक हैं। ● G-Sec व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट रूप से कोई जोखिम नहीं लेते हैं, इसलिए, जोखिम मुक्त गिल्ट-एज यंत्र कहा जाता है।
मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन	**सुर्खियों में:** स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन (NMCG) ने शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में अधिकारियों की सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए जल, स्वच्छता और स्वच्छता संस्थान (WASH संस्थान) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ● **उद्देश्य:** भारतीय कस्बों और शहरों में FSSM (मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन) और अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए तैयारियों को कुशलतापूर्वक संबोधित और सुधारना करना। ● इस परियोजना को USAID द्वारा वित्त पोषित और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित किया जाएगा। **पृष्ठभूमि** ● भारत में, अनुपचारित मल कीचड़ और शहरी सीवेज जल प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत हैं, खासकर गंगा के आसपास के शहरों में। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल स्वच्छ भारत मिशन के तहत 62 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। इनमें से आधे शौचालय ऑन-साइट स्वच्छता प्रणाली (OSS) पर निर्भर हैं। इन शौचालयों से एकत्रित कचरे का प्रबंधन भारत के लिए अगली बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार, शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के अधिकारियों, STP/FSTP ऑपरेटरों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों के पेशेवरों और FSSM क्षेत्र में शामिल अन्य हितधारकों के कौशल और ज्ञान के निर्माण के लिए पूरे भारत में व्यवस्थित क्षमता निर्माण की पहल करने की आवश्यकता है। **क्या आप जानते हैं?** ● FSSM समाधानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2017 में FSSM पर राष्ट्रीय नीति बनाई। ● 24 से अधिक राज्यों ने इसे अपनाया है और उनमें से 12 अपनी नीतियां लेकर आए हैं। ● 66 लाख घरेलू शौचालयों और 6 लाख से अधिक सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ शहरी भारत में शौचालयों की सार्वभौमिक पहुंच हासिल की गई। ● 'खुले में शौच-मुक्त' (ODF) के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, भारत अब ODF+ और ODF++ बनने की ओर बढ़ गया है। ● ये लक्ष्य स्वच्छता तक पहुंच की अवधारणा से परे हैं और शौचालय कचरे के पर्याप्त उपचार और सुरक्षित निपटान के साथ सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का लक्ष्य रखते हैं।
बांस की व्यावसायिक खेती की शुरुआत	**संदर्भ :** सुपारी के बड़े इलाकों में पीली पत्ती की बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के किसानों ने अब छोटे तरीके से बांस की व्यावसायिक खेती शुरू कर दी है। **पीली पत्ती रोग के बारे में** ● पत्ती के ऊतकों का असामान्य पीलापन क्लोरोसिस कहलाता है। ● पत्तियों में आवश्यक हरे वर्णक क्लोरोफिल की कमी होती है। संभावित कारणों में खराब जल निकासी, क्षतिग्रस्त जड़ें, संकुचित जड़ें, उच्च मिट्टी pH और पौधे में पोषक तत्वों की कमी शामिल हैं। **बांस रोपण के बारे में** ● बांस का उपयोग 1,500 विभिन्न तरीकों से किया जाता है, जिसमें भोजन, लकड़ी, भवन और निर्माण सामग्री, हस्तशिल्प तथा कागज के विकल्प शामिल हैं।

	• मोनोकल्चर वृक्षारोपण की तुलना में बांस का लाभ कई गुना है। • रोपण के बाद, बांस छोटी जोत में कृषि वानिकी अभ्यास का हिस्सा बन सकता है। • बांस के नए बागान लकड़ी के विकल्प के रूप में काम करके वनों की कटाई के दबाव को कम कर सकते हैं। इसकी बहुमुखी प्रकृति और कई उपयोगों के कारण, इसे 'गरीब आदमी की लकड़ी' भी कहा जाता है। • इसे गंभीर रूप से खराब हुए स्थलों और बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। • यह अपने अजीबोगरीब झुरमुट गठन और रेशेदार जड़ प्रणाली के कारण एक अच्छा मिट्टी बांधने वाला होता है इसलिए यह मिट्टी और जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। • यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली छतरी नुमा होता है, जो पेड़ों की तुलना में 35% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। • ऐसे अध्ययन हैं जो बताते हैं कि बांस प्रति हेक्टेयर से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है। • हालांकि यह एक पेड़ की तरह लंबा होता है, यह घास परिवार से संबंधित है।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2021	**संदर्भ :** अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री डेविड कार्ड को शोध के लिए दिया गया था जिसमें दिखाया गया • इनमें से एक ने साबित किया कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की नियुक्ति में कमी नहीं आती है और प्रवासियों के चलते मूल निवासी श्रमिकों का वेतन कम नहीं होता। • इसके अलावा दो अन्य अर्थशास्त्रियों ने इस तरह के सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करने का तरीका बताने के लिए नोबेल सम्मान प्राप्त किया। **अन्य संबंधित तथ्य** • नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अर्थशास्त्रियों में बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड कार्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जोशुआ डी. एंग्रिस्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के गुइडो इम्बेन्स शामिल हैं। कनाडा में जन्मे कार्ड ने अपने शोध में बताया कि न्यूनतम मजदूरी, आव्रजन और शिक्षा श्रम बाजार को कैसे प्रभावित करते हैं। • अन्य आधे हिस्से को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जोशुआ एंग्रिस्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डच में जन्मे गुइडो इम्बेन्स द्वारा उन मुद्दों के अध्ययन के लिए साझा किया गया था जो पारंपरिक वैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। • अन्य नोबेल पुरस्कारों के विपरीत अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में स्थापित नहीं किया गया था बल्कि स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा 1968 में उनकी स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें पहले विजेता को एक साल बाद चुना गया था। यह प्रत्येक वर्ष घोषित नोबेल का अंतिम पुरस्कार है।
भारत की अक्षय ऊर्जा	• भारत की स्थापित क्षमता का 39% गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों से है। 2022 तक भारत 40% के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। • भारत ने 2021 में 100 GW मील के पत्थर (बड़े जलविद्युत को छोड़कर) को पार कर लिया। • भारत ने अक्षय ऊर्जा के लिए विशाल क्षमता का केवल एक अंश का उपयोग किया है और इसलिए भारत ने 2030 तक 450 GW RE स्थापित क्षमता का लक्ष्य बढ़ाया है। • ग्रीन कॉरिडोर चरण 2 को लॉन्च करना और आम तौर पर उन जगहों से अक्षय ऊर्जा निकासी के लिए सिस्टम लगाने के लिए ट्रांसमिशन का विस्तार करना जहां विकिरण अधिक है, या हवा की गति अधिक है। • भारत कई क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन विकसित कर रहा है; प्रारंभ में 2030 तक लगभग 1 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। • बैटरी भंडारण के लिए सरकार बोलियां ला रही है। अक्षय ऊर्जा का रुक-रुक कर होना पूरी दुनिया के लिए एक और चुनौती है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि वर्तमान में प्रति यूनिट बैटरी भंडारण अधिक है और इसे कम करने की आवश्यकता है। बैटरी स्टोरेज के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पहले से ही मौजूद है और स्टोरेज की कीमतों को कम करने के लिए मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है। • भारत सरकार ने हाल ही में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। भारत को अगले पांच वर्षों में 10 गीगावाट सौर पीवी विनिर्माण क्षमता जोड़ने की उम्मीद है।

	• निवेशकों के लिए उभरते अवसरों के तीन नए क्षेत्र - हरित हाइड्रोजन, अपतटीय पवन और सौर पीवी निर्माण। अनिवार्य खरीद दायित्वों का उद्देश्य उर्वरक, पेट्रोलियम शोधन और शहरी गैस वितरण जैसे क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन का उपयोग बढ़ाना है।
कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC)	**संदर्भ :** खाद्य तेलों में लगातार उच्च मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए, सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज के तेल को सीमा शुल्क से छूट देने का फैसला किया है, और अक्टूबर 14 से 31 मार्च 2022 तक उनके आयात पर लगाए गए कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) को घटा दिया है। **अन्य संबंधित तथ्य** • कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज के तेल के आयात पर 2.5% का मूल सीमा शुल्क और 20% का AIDC लगता है। • यह सीमा शुल्क को शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज के तेल के लिए उपकर को घटाकर 5% कर दिया गया है। कच्चे पाम तेल के मामले में, AIDC उपकर को मूल 20% के बजाय घटाकर 7.5% कर दिया गया है। • **लाभ:** इस फैसले से खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अंतिम उपभोक्ताओं पर कीमतों का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। **कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) क्या है?** • कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) को बजट 2021-22 में प्रस्तावित किया गया था। • **उद्देश्य:** न केवल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बल्कि कृषि उत्पादन को कुशलतापूर्वक संरक्षित और संसाधित तथा मदद करने के उद्देश्य से कृषि बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने के लिए धन जुटाना। • नया उपकर 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा, जिनमें सोना, चांदी, आयातित सेब, आयातित शराब (बीयर को छोड़कर), आयातित दालें, आयातित पाम तेल, आयातित यूरिया और ब्रांडेड सहित पेट्रोल/डीजल आदि प्रमुख है। • यह केवल सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क में कमी की भरपाई करेगा और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए कर भार नहीं बढ़ाएगा। **क्या आप जानते हैं?** • संविधान के अनुच्छेद 270 और 271 से शक्ति प्राप्त करते हुए, केंद्र उपकर एकत्र करता है और इसे भारत की संचित निधि में जमा करता है। • हालांकि, धन को विशिष्ट उद्देश्यों को उपयोग किए जाने के लिए एक अलग फंड में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)	**संदर्भ :** GST नेटवर्क ने कहा है कि उसने माल और सेवा कर के तहत पंजीकृत 66,000 व्यवसायों के 14,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को अवरुद्ध कर दिया है। **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्या है?** • ITC करों के कैस्केडिंग से बचने के लिए एक तंत्र है। करों का कैस्केडिंग, सरल भाषा में, 'टैक्स ऑन टैक्स' है। • इनपुट टैक्स क्रेडिट से तात्पर्य उस कर से है जो किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं की खरीद के समय पहले ही चुकाया जा चुका है और जो देय कर से कटौती के रूप में उपलब्ध है। • सरल शब्दों में, इनपुट क्रेडिट का अर्थ है आउटपुट पर कर का भुगतान करते समय, आप इनपुट पर पहले से चुकाए गए 'कर' को कम तथा शेष राशि का भुगतान कर सकते हैं। • **अपवाद:** कंपोजीशन स्कीम के तहत एक व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकता है। व्यक्तिगत उपयोग या छूट प्राप्त सामानों के लिए ITC का दावा नहीं किया जा सकता है। **इसके दुरुपयोग पर चिंता** • वर्तमान में ITC दावे और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए करों के साथ उनका मिलान करने के बीच एक समय अंतराल है। केवल टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए नकली चालान बनाकर व्यवसायों द्वारा प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना हो सकती है। • कुल GST देनदारी का जितना 80% ITC द्वारा निपटा कर केवल 20% नकद के रूप में जमा किया जाता है। • वर्तमान व्यवस्था के तहत, इनपुट के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पहले ही भुगतान किए गए करों के साथ ITC दावों के वास्तविक समय के मिलान का कोई प्रावधान नहीं है।

दूरसंचार उत्पादों के लिए PLI योजना शुरू की गई	**सुर्खियों में:** भारत महत्वाकांक्षी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन या PLI योजना के तहत चार वर्षों की अवधि में 31 घरेलू और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लगभग 3,300 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त करने के लिए तैयार है, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में 40,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने की उम्मीद है। • वृद्धिशील निवेश को प्रोत्साहित करके दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। • देश में विश्व स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और समर्थन के साथ दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के आयात के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। • नए उत्पादों के विकास के लिए अपने राजस्व का 15% खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध कंपनियों के साथ स्थानीय स्तर पर अनुसंधान और विकास (R & D) गतिविधियों को बढ़ावा देगा। **विवरण** • योजना के तहत सहायता पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी, अर्थात वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक। • योजना और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, लगभग 31 कंपनियों, जिनमें 16 MSME और 15 गैर-MSME शामिल हैं, को पात्र पाया गया है, उन्हें PLI योजना के तहत मंजूरी दी जा रही है। • अनुमानित वृद्धिशील उत्पादन लगभग Rs.1.82 लाख करोड़। • दूरसंचार क्षेत्र के लिए योजना में शामिल हैं- • ट्रांसमिशन उपकरण का निर्माण, • अगली पीढ़ी (4जी और 5जी) रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण, • ग्राहक आधार उपकरण (CPE), एक्सेस डिवाइस, राउटर और स्विच।
ई-श्रम पोर्टल	**सुर्ख़ियों में:** असंगठित श्रमिकों पर भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। • पंजीकरण की उच्चतम संख्या: ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। • सबसे अधिक संख्या में श्रमिक कृषि और निर्माण क्षेत्र से पंजीकृत हैं। • ई-श्रम में पंजीकरण से असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। • 4.09 करोड़ श्रमिकों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 50.02% लाभार्थी महिलाएं हैं और 49.98% पुरुष हैं। **ई-श्रम पोर्टल** • यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित कामगारों, जैसे निर्माण मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना है। • कामगारों को ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा, जो आगे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करने में मदद करेगा। **ई-श्रम पोर्टल का महत्व - असंगठित श्रमिकों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW)** • असंगठित कामगारों की लक्षित पहचान एक बहुत ही आवश्यक कदम था और पोर्टल जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं का राष्ट्रीय डेटाबेस होगा, कल्याणकारी योजनाओं को उनके दरवाजे तक ले जाने में मदद करेगा, जो हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। • लक्षित वितरण और अंतिम मील (mile) वितरण, भारत सरकार की योजनाओं का एक प्रमुख केंद्र रहा है और असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (ई-श्रम पोर्टल) उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	**संदर्भ :** उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 20 अक्टूबर को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। • इस हवाईअड्डे से श्रीलंका, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर आदि के पर्यटकों को निर्बाध प्रदान करेगा। • पहले परिवार के एक सदस्य के नेतृत्व में श्रीलंकाई दल भी इस जगह के ऐतिहासिक महत्व के कारण मौजूद रहेगा।

	उपहार के प्रतीक के रूप में भित्ति चित्र ● इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, श्रीलंका कोलंबो के पास एक लोकप्रिय बौद्ध मंदिर, केलनिया राजामहा विहार में प्रसिद्ध श्रीलंकाई कलाकार सोलियास मेंडिस द्वारा चित्रित दो भित्ति चित्रों (Mural Paintings) की तस्वीरें भारत को प्रस्तुत करेगा। ● एक भित्ति चित्र में सम्राट अशोक के पुत्र अरहत भिक्षु महिंदा को श्रीलंका के राजा देवनामपियातिसा (Devanampiyatissa) को बुद्ध का संदेश देते हुए दर्शाया गया है। ● दूसरे भित्ति चित्र में सम्राट अशोक की पुत्री 'थेरी भिक्षुणी' संघमित्रा को पवित्र बोधि वृक्ष (जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसके नीचे ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी) के पौधे के साथ श्रीलंका में आगमन करते हुए दर्शाया गया है। **कुशीनगर का महत्व** ● कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र है, जिसमें लुंबिनी, सारनाथ और गया के तीर्थ स्थल शामिल हैं। ● बौद्ध तीर्थयात्री कुशीनगर को एक पवित्र स्थल मानते हैं, जहां उनका मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया और 'महापरिनिर्वाण' या मोक्ष प्राप्त किया।
विदेशी अंशदान संबंधी नए दिशा-निर्देश	**संदर्भ:** केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि गैर सरकारी संगठनों को बिना नियमों के अनियंत्रित विदेशी योगदान प्राप्त करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ● केंद्र ने कहा कि संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए थे कि विदेशी धन का उपयोग भारत में संसदीय संस्थानों, राजनीतिक संघों और अन्य संगठनों के कामकाज में बाधा डालने के लिए नहीं किया गया था। ● यह 2020 में विदेशी योगदान विनियम कानून में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का जवाब दे रहा था। **पृष्ठभूमि** ● याचिकाओं में तर्क दिया गया था कि संशोधनों ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा उनकी गतिविधियों के लिए विदेशी धन के उपयोग को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ● उन्हें यह बोझिल लगा कि नए कानून से 23,000 गैर सरकारी संगठनों को अपने विदेशी धन प्राप्त करने के लिए राजधानी में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मुख्य शाखा में खाते खोलने की उम्मीद है। **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) क्या है?** ● भारत में व्यक्तियों के विदेशी वित्त पोषण को FCRA अधिनियम के तहत नियंत्रित कर गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ● अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिए ऐसा योगदान प्राप्त किया गया है। ● पंजीकृत NGOs पांच उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं - सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020** ● **विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर रोक:** अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है। ● **पंजीकरण के लिए आधार:** संशोधन के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन (NGOs) या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों और संगठनों के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों एवं अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिये आधार (Aadhaar) को एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज़ बना दिया गया था। ● **FCRA खाता:** विदेशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दिल्ली की उस शाखा में ही प्राप्त किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी। ● **प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग में कमी:** प्राप्त कुल विदेशी निधियों का 20% से अधिक प्रशासनिक खर्चों के लिए चुकाया नहीं जा सकता है। FCRA 2010 में यह सीमा 50% थी। ● **प्रमाण पत्र का समर्पण:** अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सरेंडर करने की अनुमति देता है।
पीएम मित्र पार्क	**संदर्भ:** कपड़ा मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2021 को 7 'व्यापक एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान' (पीएम मित्र) पार्क (Mega

योजना	Integrated Textile Region and Apparel: PM MITRA Parks) की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की है, जैसा कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में घोषित कर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। ● संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 ("लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना") को प्राप्त करने में भारत की मदद करने के लिए पीएम मित्र पार्क की परिकल्पना की गई है। ● इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है। ● 'पीएम मित्र' प्रधानमंत्री के 5एफ (5F) विजन से प्रेरित है। '5एफ' फॉर्मूला में- 'फार्म टू फाइबर; फाइबर टू फैक्ट्री; फैक्ट्री टू फैशन; फैशन टू फॉरेन' (Farm to fibre; fibre to factory; factory to fashion; fashion to foreign) शामिल हैं। ● यह योजना कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के लिए है। यह लॉजिस्टिक लागत को कम करेगा और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा। ● यह योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी। ● इन पार्कों को ऐसे स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिनमें कपड़ा उद्योग के फलने-फूलने के लिए अंतर्निहित ताकत है और सफल होने के लिए आवश्यक संबंध हैं। ● शाम 7 बजे मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड / ब्राउनफील्ड साइटों पर स्थापित किए जाएंगे। ● अन्य कपड़ा संबंधी सुविधाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ 1,000+ एकड़ के सन्निहित और भार-मुक्त भूमि पार्सल की उपलब्धता के साथ राज्य सरकारों के प्रस्तावों का स्वागत है। ● ग्रीनफील्ड पीएम मित्रा पार्क के लिए, भारत सरकार विकास पूंजी सहायता ₹500 करोड़ की सीमा के साथ परियोजना लागत का 30% होगी। ● ब्राउनफील्ड साइटों के लिए, मूल्यांकन के बाद, विकास पूंजी सहायता शेष बुनियादी ढांचे की परियोजना लागत का @30% और अन्य समर्थन सुविधाओं को विकसित और 200 करोड़ रुपये की सीमा तक सीमित किया जाना है। राज्य सरकार के समर्थन में विश्व स्तरीय औद्योगिक संपदा के विकास के लिए 1,000 एकड़ भूमि का प्रावधान शामिल होगा। ● पीएम मित्र पार्क में कपड़ा निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए प्रत्येक पीएम मित्र पार्क को 300 करोड़ रुपये की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (CIS) भी प्रदान की जाएगी। ● पीएम मित्र पार्क को एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा विकसित किया जाएगा जिसका स्वामित्व सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा। ● मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा बल्कि रियायत अवधि के दौरान इसका रखरखाव भी करेगा। इस मास्टर डेवलपर का चयन राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर होगा।
डि-अमोनियम फॉस्फेट (DAP)	**संदर्भ :** हरियाणा में डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) की भारी कमी के कारण हताश किसान पुलिस पर पथराव और विरोध में सड़कों को अवरुद्ध कर रहे हैं। **DAP किसानों के लिए क्यों जरूरी है?** ● DAP यूरिया के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। ● DAP में 46% फास्फोरस, 18% नाइट्रोजन पाई जाती है जो किसानों के लिये फास्फोरस का पसंदीदा स्रोत है। ● यह अत्यधिक घुलनशील है और यह मिट्टी में जल्दी से घुल जाता है जिससे पौधे के लिए उपलब्ध फॉस्फेट और अमोनियम निकल जाता है। ● DAP की एक उल्लेखनीय संपत्ति क्षारीय pH है जो घुलने वाले दाने के आसपास विकसित होती है। ● रबी फसलों के लिए एक बुनियादी पोषक तत्व होने के कारण, सरसों और गेहूं जैसी फसलों की बुवाई के समय DAP उर्वरक का छिड़काव करना पड़ता है।

	• इसकी आपूर्ति में किसी भी तरह की देरी से फसलों की बुवाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। **गैर-कृषि उपयोग** • DAP अग्निरोधी के रूप में भी कार्य करता है। उदाहरण के लिए, जंगल को जलने से रोकने के लिए DAP और अन्य अवयवों के मिश्रण को आग से पहले फैलाया जाता है। आग का खतरा टलने के बाद यह पोषक तत्व का स्रोत बन जाता है। • DAP का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है, जैसे धातु परिष्करण।
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)	**भाग :** प्रारंभिक और जीएस III - विमानन उद्योग **संदर्भ:** संयुक्त राज्य अमेरिका के विमानन प्रहरी, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA)) ने भारत के सुरक्षा नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) का पांच दिवसीय ऑडिट शुरू किया। **अन्य संबंधित तथ्य** • इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट (IASA) प्रोग्राम के तहत, FAA यह निर्धारित करता है कि क्या किसी अन्य देश की अपनी एयरलाइनों की निगरानी जो यूएस में संचालित होती है या जिनका यूएस एयरलाइन के साथ कोडशेयर समझौता है, वैश्विक एविएशन वॉचडॉग इंटरनेशनल सिविल एविएशन संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हैं। **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के बारे में** • यह भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारतीय केंद्र सरकार का एक वैधानिक निकाय है। • इसका गठन विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 के तहत किया गया था। • **कार्य:** यह विमानन दुर्घटनाओं की जांच करता है, विमानन से संबंधित सभी नियमों को बनाए रखता है और लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है।
ग्रीन डे अहेड मार्केट (GDAM)	**सुर्ख़ियों में:** भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा विद्युत बाज़ार है, जिसने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा हेतु 'ग्रीन डे अहेड मार्केट' (जीडीएएम) प्रारंभ किया है। • यह पारंपरिक 'डे-अहेड मार्केट' के साथ एकीकृत तरीके से कार्य करेगा। • यह एक्सचेंज अलग-अलग 'बिडिंग विंडो' के माध्यम से बाज़ार सहभागियों के लिये पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों हेतु एक साथ बिडिंग का प्रावधान प्रस्तुत करेगा। • अगर बाज़ार सहभागियों की 'बिडिंग' क्षमता हरित बाज़ार में ही समाप्त हो जाती है फिर भी यह तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा विक्रेताओं को पारंपरिक खंड के अंतर्गत बिडिंग की अनुमति देगा। • यह तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा विक्रेताओं को पारंपरिक खंड में बाद में बोली लगाने की अनुमति देगा, अगर उनकी बोलियां हरित बाजार में समाप्त हो जाती हैं। पारंपरिक और नवीकरणीय दोनों के लिए अलग-अलग मूल्य खोजें होंगी। • GDAM के आरंभ से एक दूरगामी प्रभाव (डोमिनो इफेक्ट) उत्पन्न होने की संभावना है जो पीपीए आधारित अनुबंध से बाजार-आधारित प्रतिरूप में क्रमिक परिवर्तन की ओर अग्रसर करेगा जो कि अगले स्तर तक बाजारों का निर्माण और गहन करेगा, भारत के लिए अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य, 2030 तक 450 गीगावॉट हरित क्षमता को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। • हरित बाजार को गहरा करेगा और प्रतिस्पर्धी मूल्य संकेत प्रदान करेगा, इसके अलावा बाजार सहभागियों को हरित ऊर्जा में सबसे पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से व्यापार करने का अवसर प्रदान करेगा। • ग्रीन डे अहेड मार्केट का शुभारंभ हरित बाजार को गहरा करेगा और प्रतिस्पर्धी मूल्य संकेत प्रदान करेगा, इसके अलावा बाजार सहभागियों को सबसे पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धी और कुशल तरीके से हरित ऊर्जा में व्यापार करने का अवसर प्रदान करेगा। • बाजार आधारित प्रतिस्पर्धी कीमतें अक्षय उत्पादकों को बिजली बेचने के साथ-साथ भारत को एक स्थायी और कुशल ऊर्जा अर्थव्यवस्था के रूप में बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की दिशा में अक्षय क्षमता वृद्धि में तेजी लाने का एक और विकल्प प्रदान करेगी। • हरित ऊर्जा की कटौती को कम करना, अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता को खोलना, RE जनरेटरों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करना अर्थात डिलीवरी के दिन ही। • **ऊर्जा संक्रमण सक्षम करना:** दुनिया भर में ऊर्जा संक्रमण हो रहा है और भारत जीवाश्म ईंधन से गैर-जीवाश्म ईंधन

	में ऊर्जा संक्रमण के लिए भी प्रतिबद्ध है। तदनुसार, विद्युत बाजार की गतिशीलता बदल रही है। खरीदार का व्यवहार लंबी अवधि के अनुबंधों से अल्पकालिक अनुबंधों और विद्युत बाजार की ओर भी स्थानांतरित हो रहा है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)	**संदर्भ:** अपने स्वयं के वित्तीय विवरण के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना 8,686 करोड़ रुपये का नकारात्मक शुद्ध संतुलन दिखाती है। ● केंद्र की प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना वित्तीय वर्ष के आधे रास्ते से ही समाप्त हो गई है, और अनुपूरक बजटीय आवंटन अगले संसदीय सत्र के शुरू होने पर कम से कम एक और महीने के लिए बचाव में नहीं आएगा। **अन्य सम्बंधित तथ्य** ● इस योजना का 2021-22 का बजट मात्र रु. 73,000 करोड़ है। ● केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया कि देशव्यापी तालाबंदी समाप्त हो गई, और यदि धन समाप्त हो गया तो अनुपूरक बजटीय आवंटन उपलब्ध होगा। ● हालांकि, 29 अक्टूबर को देय भुगतान सहित कुल व्यय पहले ही रु. 79,810 करोड़ हो गया। ● 21 राज्यों ने नकारात्मक शुद्ध संतुलन दिखाया, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे खराब स्थिति में हैं। ● महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) क्या है? ● महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 2005 में अधिसूचित किया गया था। ● **लक्ष्य :** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा में सुधार करना। ● यह एक सार्वभौमिक योजना है जो मांग व्यक्त करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देती है। ● इसका उद्देश्य 'काम के अधिकार' की गारंटी देना है। ● प्रत्येक पंजीकृत परिवार को अपने पूरे किए गए कार्य को ट्रैक करने के लिए एक जॉब कार्ड (JC) प्राप्त होता है। ● यह योजना ग्राम पंचायत द्वारा क्रियान्वित की जाती है। ● नौकरी के आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर रोजगार के प्रावधान की विफलता के परिणामस्वरूप नौकरी चाहने वालों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा। ● रोजगार एक आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर उपलब्ध कराया जाना है। ● मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।
जीएसटी मुआवजा	**संदर्भ:** वित्त मंत्रालय ने जीएसटी मुआवजे के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 44,000 करोड़ रुपये जारी किए। **अन्य संबंधित तथ्य** ● 1,15,000 करोड़ रुपये की पूर्व रिलीज को ध्यान में रखते हुए, GST मुआवजे के बदले चालू वित्त वर्ष में बैक-टू-बैक ऋण के रूप में जारी की गई कुल राशि 1,59,000 करोड़ रुपये है। ● यह रिलीज सामान्य GST मुआवजे के अतिरिक्त है जो वास्तविक उपकर संग्रह से प्रत्येक 2 महीने में जारी किया जाता है। **पृष्ठभूमि** ● 28 मई 2021 को आयोजित 43वीं GST परिषद की बैठक के बाद, यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार 1.59 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी और इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विधायिका के साथ बैक-टू-बैक आधार पर जारी करेगी ताकि मुआवजे की संक्षिप्त रिलीज के लिए संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके। **GST मुआवजे के बारे में** ● GST से पहले, राज्यों के पास आर्थिक गतिविधियों पर कुछ अप्रत्यक्ष कर लगाने की शक्ति थी। इसलिए GST शासन शुरू होने के बाद (2017 में), केंद्र ने राज्यों को पहले पांच वर्षों के लिए गारंटीकृत मुआवजे का वादा किया था, जो कि पहले की प्रणाली से बदलाव के बाद हटाए गए राजस्व के लिए था। ● 2015-16 को आधार वर्ष के रूप में देखते हुए तथा पाप और विलासिता के सामानों पर मुआवजा उपकर लगाकर मुआवजे की गणना 14% की वृद्धि दर पर की जाती है।

भारत, ADB ने 251 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए	**सुर्ख़ियों में:** भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चेन्नई में जलवायु संतुलन, एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए 251 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि चेन्नई शहर को बाढ़ के प्रभाव को रोकने के कार्य को मजबूत किया जा सके। ● चेन्नई-कोसास्थलैयार बेसिन के निवासियों की लगातार बाढ़ के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद करेगा, जिन्होंने हाल के वर्षों में संपत्ति और आजीविका को नष्ट कर दिया है। ● आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के निर्माण से समुदायों को तेज बारिश, समुद्र के उच्च स्तर में वृद्धि और चक्रवातों के कारण होने वाले तूफान से निपटने में मदद मिलेगी और जीवन, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की रक्षा होगी। ● एकीकृत शहरी नियोजन और उन्नत नगरपालिका संसाधन जुटाने के साथ परियोजना द्वारा प्रचारित जलवायु-लचीला बाढ़ प्रबंधन के लिए अभिनव डिजाइन और हस्तक्षेप अन्य भारतीय शहरों के लिए व्यापक रूप से दोहराया जा सकता है जो जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति संवेदनशील हैं। ● सामुदायिक ज्ञान और बाढ़ जोखिमों तथा प्रभावों के बारे में जागरूकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवरेज और जल निकायों की सुरक्षा के साथ संबंधों को बढ़ाकर बाढ़ की तैयारी में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य है।

इथेनॉल उत्पादन	**संदर्भ :** पिछले सीजन (अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021) के दौरान लगभग दो मिलियन टन (MT) चीनी को इथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्ट किया गया था। **इथेनॉल और इसके उत्पादन के बारे में** ● इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से किया जा सकता है, जिनमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। ● भारत में, इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के शीरे से किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। ● विभिन्न मिश्रण बनाने के लिए इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है। ● चूंकि इथेनॉल अणु में ऑक्सीजन होता है, यह इंजन के ईंधन को पूरी तरह से दहन करने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप कम उत्सर्जन होता है और इस तरह पर्यावरण प्रदूषण की घटना को कम करता है। ● चूंकि इथेनॉल का उत्पादन पौधों से होता है जो सूर्य की शक्ति का उपयोग करते हैं, इथेनॉल को अक्षय ईंधन के रूप में भी माना जाता है।
स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG)	**सुर्खियों में:** चाचा चौधरी ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया। ● गंगा और अन्य नदियों के प्रति बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से तैयार की जाने वाली सामग्री। बिहार में गंगा के बाढ़ क्षेत्र की आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन का प्रस्ताव: ● इस परियोजना के प्रमुख घटक वेटलैंड इन्वेंट्री और मूल्यांकन, वेटलैंड प्रबंधन योजना, वेटलैंड की निगरानी और क्षमता विकास और आउटरीच होंगे। ● बिहार में गंगा के 12 जिलों में बाढ़ के मैदानी आर्द्रभूमि के प्रभावी प्रबंधन के लिए ज्ञान का आधार और क्षमता बनाने का उद्देश्य आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के निरंतर प्रावधान और जैव विविधता आवासों को सुरक्षित करना सुनिश्चित करना है। ● **कल्पवास (Kalpvas):** सिमरिया घाट कल्पवास के लिए लोकप्रिय है, एक प्राचीन परंपरा जिसमें भक्त घाटों पर रहते हैं, गाते हैं और माघ मेले के दौरान ध्यान करते हैं।
अलीबाग के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला	**प्रसंग:** अलीबाग (Alibag) के प्रसिद्ध सफेद प्याज (white onion) को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया, जो इसके अनूठे मीठे स्वाद, बिना आंसू के कारक, साथ ही इसके औषधीय गुणों को दुनिया भर में पहचान दिलाता है। ● अलीबाग, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के दक्षिण में एक तटीय शहर है। ● स्थानीय किसानों ने दो शताब्दियों से अधिक समय से बीज को संरक्षित किया है। 1883 में प्रकाशित एक सरकारी गजट में भी प्याज का उल्लेख है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● अलीबाग तालुका की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम होती है। ● प्याज में उच्च एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों (क्वेरसेटिन) के अलावा कम तीखापन, मीठा स्वाद, 'नो टियर' फैक्टर, कम पाइरुविक एसिड, उच्च प्रोटीन, वसा और फाइबर सामग्री होती है। ● यह प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, अनिद्रा, रक्त की सफाई, रक्तचाप और गर्मी से संबंधित बीमारियों में मदद करता है। **जीआई टैग क्या है?** ● यह एक संकेत है जो एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए निश्चित है। ● इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है। ● सामान को उस क्षेत्र में उत्पादित या संसाधित या तैयार करने की आवश्यकता होती है। ● उत्पाद में एक विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ● सामान के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में GI सामान का पंजीकरण और सुरक्षा प्रदान करता है। ● भारत के लिए भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। ● एक पंजीकृत जीआई टैग किसी तीसरे पक्ष को ऐसे उत्पादों का उपयोग करने से रोकता है।

	• GI एक सामूहिक बौद्धिक संपदा अधिकार है और इस प्रकार परिभाषित GI क्षेत्र के भीतर सभी उत्पादकों के स्वामित्व में है। • पेटेंट और ट्रेडमार्क किसी व्यक्ति या व्यावसायिक इकाई के स्वामित्व में होते हैं।
मुंबई अंधी ईल	**संदर्भ :** मुंबई के एक कुएं से स्वैम्प ईल की एक नई प्रजाति की खोज की गई। **अन्य संबंधित तथ्य** • ईल को रक्थमिच्थिस मुंबा, मुंबई ब्लाइंड ईल कहा जाता है। • यह जीनस रक्थैमिक्थिस से संबंधित है जो भारत के लिए स्थानिक है। • यह भारत से वर्णित होने वाली जीनस की पांचवीं प्रजाति है। • पनियल सांप नुमा दिखने वाला यह जीव मछलियों की श्रेणी में आता है और अंधा होता है। • यह पहली पूरी तरह से अंधी भूमिगत मीठे पानी की मछली प्रजाति है जिसका वर्णन महाराष्ट्र और उत्तरी पश्चिमी घाट से किया गया है। *Rakthamichthys mumba* sp. nov.
'भारत के आर्द्रभूमि' पोर्टल का शुभारंभ	**संदर्भ:** गांधी जयंती के अवसर पर और MoEFCC (4-10 अक्टूबर 2021) के आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह की शुरुआत करते हुए, एक वेब पोर्टल - 'वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल' (http://indianwetlands.in/), दे रहा है देश के आर्द्रभूमि पर विवरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। • पोर्टल आर्द्रभूमि से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल बिंदु पहुंच है - क्षमता निर्माण सामग्री, डेटा भंडार, वीडियो और छात्रों के लिए जानकारी। • प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया गया है ताकि पोर्टल तक पहुंच बनाई जा सके और इसे अपने प्रशासन में आर्द्रभूमि की जानकारी के साथ रखा जा सके। • यह परियोजना अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल (IKI) के तहत पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा (BMU) के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। **अन्य संबंधित तथ्य** **वेटलैंड्स** • वे अत्यधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र हैं जो दुनिया को अपनी मछली की फसल का लगभग दो-तिहाई हिस्सा प्रदान करते हैं। • वे वाटरशेड की पारिस्थितिकी में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। • वे जीवों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करते हैं जो खाद्य जाल का आधार बनते हैं और जलीय जंतुओं की कई प्रजातियों को खिलाते हैं। • वे कार्बन पृथक्करण (वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने) में मदद करते हैं। • वे जानवरों और पौधों के लिए आवास प्रदान करते हैं और पौधों तथा जानवरों का समर्थन करते हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते हैं।

	• वे भूजल पुनर्भरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। • आर्द्रभूमि छह प्रकार की होती है: 1. समुद्री या तटीय आर्द्रभूमि जिसमें तटीय लैगून, चट्टानी तट और प्रवाल भित्तियाँ शामिल हैं 2. डेल्टास, ज्वारीय और मैंग्रोव दलदलों सहित एस्टुअरीन आर्द्रभूमि 3. झीलों से जुड़ी लैकुस्ट्रिन आर्द्रभूमि 4. नदियों और नालों के किनारे नदी की आर्द्रभूमि 5. पलुस्ट्रीन आर्द्रभूमि 6. मानव निर्मित आर्द्रभूमि जैसे मछली, झींगा (shrimp) और फार्म पॉन्ड्स (farm ponds), सिंचित कृषि भूमि, नमक के बर्तन (salt pans), जलाशय, बजरी के गड्ढे और नहरें। **आर्द्रभूमि के लिए खतरा** **शहरीकरण** • **कृषि:** बड़ी संख्या में जलाशयों, नहरों और बांधों के निर्माण ने संबंधित आर्द्रभूमि के जल विज्ञान (hydrology) को बदल दिया है। • **प्रदूषण:** औद्योगिक स्रोतों से पारे के कारण • **जलवायु परिवर्तन:** हवा के तापमान में वृद्धि; तूफान, सूखा और बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि; समुद्र के स्तर में वृद्धि • **ड्रेजिंग (Dredging) और रेत खनन:** नदियों के ड्रेजिंग से आसपास की पानी की मात्रा कम हो जाती है और आसन्न आर्द्रभूमि सूख जाती है। • **विदेशी प्रजातियां:** विदेशी पौधों की प्रजातियां जैसे जलकुंभी और साल्विनिया जलमार्गों को रोकते हैं और देशी वनस्पतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
सरकार का वन अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव	**भाग :** प्रारंभिक और जीएस II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस-III - पर्यावरण **संदर्भ :** केंद्र सरकार ने मौजूदा वन संरक्षण अधिनियम (FCA) में संशोधन के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं और सीमा अवसंरचना परियोजनाओं में शामिल एजेंसियों को केंद्र से पूर्व वन मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है। • यह प्रस्ताव मौजूदा वन संरक्षण अधिनियम (FCA) में संशोधन का एक हिस्सा है। संशोधन मसौदे का दस्तावेज़ 15 दिनों के लिए सार्वजनिक चर्चा के लिए खुला है जिसके बाद इसे कैबिनेट और संसदीय अनुमोदन के लिए बढ़ाया जा सकता है। • FCA पहली बार 1980 में पारित हुआ था और 1988 में संशोधित किया गया था। अधिनियम को ऐसी अनुमति की आवश्यकता होती है। **हाल के प्रस्ताव क्या हैं?** • इस दस्तावेज़ में 1980 में एफसीए के लागू होने से पहले रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों द्वारा अधिग्रहित भूमि को छूट देने के लिए एक योजना भी है। • आज की स्थिति में एक भूमिधारक एजेंसी (रेल, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, आदि) को इस अधिनियम के तहत अनुमोदन लेने और ऐसी भूमि जो मूल रूप से गैर-वन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी उसके निर्धारित प्रतिपूरक शुल्क जैसे कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी), प्रतिपूरक वनीकरण (सीए), आदि का उपयोग करने की आवश्यकता है। • पर्यावरण मंत्रालय ने संशोधित अधिनियम के तहत अपराधों को एक वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास के साथ दंडनीय बनाने और इसे संज्ञेय और गैर-जमानती बनाने के लिए एक खंड जोड़ने का प्रस्ताव किया है। • पहले से हुई क्षति की पूर्ति के लिए दण्डात्मक मुआवजे का प्रावधान। • दस्तावेज़ में "गैर-वानिकी" गतिविधियों की परिभाषा से चिड़ियाघर, सफारी, वन प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को हटाने का भी प्रस्ताव है। **वन संरक्षण अधिनियम (FCA) क्या है?** • वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (FCA, 1980) वन और उसके संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करता है।

	• यह भारत के वनों के चल रहे कटाई को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। • यह 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ जिसमें पांच खंड थे। • यह अधिनियम राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पहले निर्णय लेने के लिए प्रतिबंधित करता है। • यह अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को पूर्ण अधिकार देता है। • यह अधिनियम FCA के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दंड लगाता है। • इसमें एक सलाहकार समिति होगी जो वन संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार की मदद करेगी।
मैड्रिड प्रोटोकॉल और अंटार्कटिक संधि	**संदर्भ:** अंटार्कटिक के वातावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने संकल्प पर जोर देते हुए, भारत ने अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। • भारत ने पहले ही हवा की व्यवहार्यता के साथ प्रयोग करके हरित ऊर्जा पहल को अपनाया था। ऊर्जा उत्पादन और प्रायोगिक आधार पर पवन ऊर्जा जनरेटर (WEG) के मध्यम उत्पादन को स्थापित किया। • अंटार्कटिक में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारती स्टेशन के लिए कंबाइंड हीट एंड पावर (CHP) का चुनाव भी पर्यावरण की रक्षा के लिए भारत की प्रतिज्ञा को बढ़ावा देता है। • भारत अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और इस समय निम्नलिखित का दावा करता है: 1. भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में ATCM में अपनाए गए सभी निर्णयों, संकल्पों और उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना। 2. दोनों भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशनों में हरित वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली का उपयोग; मैत्री और भारती जैसे सौर पैनल और पवन ऊर्जा जनरेटर धीरे-धीरे जीवाश्म ईंधन के उपयोग से समझौता कर रहे हैं और वैकल्पिक हरित ऊर्जा के साथ स्टेशन को कुशल बना रहे हैं। 3. वाहनों और मशीनरी का उपयोग करके कार्बन पदचिह्नों को कम करना, जब अधिकतम आवश्यकता हो। 4. अंटार्कटिका में मानव संसाधन, सामग्री और मशीनों को पहुंचाने के लिए साझा आपूर्ति जहाज का उपयोग करना। 5. अंटार्कटिका में किसी भी तरह से या वेक्टर ट्रांसफर के माध्यम से गैर-देशी प्रजातियों के प्रवेश पर नियंत्रण करना **भारत और अंटार्कटिक संधि** • भारत ने 19 अगस्त, 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए और एक महीने बाद परामर्शी दर्जा प्राप्त किया। • मैड्रिड प्रोटोकॉल पर भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए जो 14 जनवरी, 1998 को लागू हुए। • भारत अंटार्कटिक संधि के 29 सलाहकार पक्षों में से एक है। • भारत राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम (COMNAP) के प्रबंधक परिषद और अंटार्कटिका अनुसंधान की वैज्ञानिक समिति (SCAR) का भी सदस्य है। ये सभी अभ्यावेदन अंटार्कटिक अनुसंधान में शामिल देशों के बीच भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाते हैं। • अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल पर 4 अक्टूबर 1991 को मैड्रिड में हस्ताक्षर किए गए थे और 1998 में इसे लागू किया गया था। यह अंटार्कटिका को "शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व" के रूप में नामित करता है। **अंटार्कटिका में भारत** • भारत में दो सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं; मैत्री (1989 में कमीशन) शिरमाकर हिल्स में, और भारती (2012 में कमीशन) अंटार्कटिका में लारसेमैन हिल्स में। • भारत ने अब तक अंटार्कटिका में 40 वार्षिक वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किए हैं। • Ny-Alesund, स्वालबार्ड, आर्कटिक में हिमाद्री स्टेशन के साथ, भारत अब उन राष्ट्रों के कुलीन समूह से संबंधित है जिनके पास ध्रुवीय क्षेत्रों के भीतर कई शोध केंद्र हैं।

उत्तर प्रदेश PM2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक: CEEW	**संदर्भ:** ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (CEEW) द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार, उत्तर प्रदेश PM2.5 का सबसे बड़ा उत्सर्जक है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक माना जाने वाला पार्टिकुलेट मैटर का वर्ग है। **अन्य सम्बंधित तथ्य** ● उ.प्र. से उच्च उत्सर्जन बड़े पैमाने पर घरों में ठोस-ईंधन के उपयोग से PM2.5 उत्सर्जन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के कारण थे और भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के कारण, इस प्रकार के ईंधन पर निर्भर परिवारों का अनुपात अधिक था। ● **अन्य शीर्ष प्रदूषक:** महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान। ● सामान्य प्रदूषक जिनका विश्लेषण किया गया: PM2.5, PM10, NOx (नाइट्रस ऑक्साइड), SO2 (सल्फर डाइऑक्साइड), CO (कार्बन मोनोऑक्साइड), NH3 (अमोनिया) और NMVOC (गैर-मीथेन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक)। **भारत सरकार की पहल** ● भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित करते हुए 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) शुरू की है। इसमे शामिल है: ○ **राष्ट्रीय सौर मिशन:** देश भर में इसकी तैनाती के लिए नीतिगत शर्तें बनाकर भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। ○ **उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन:** नवीन नीतियों और प्रभावी बाजार साधनों को बढ़ावा देकर ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को बढ़ावा देना। ○ **सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन:** जलवायु परिवर्तन की समझ, इसके अनुकूलन और शमन, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देना। ○ **राष्ट्रीय जल मिशन:** जल का संरक्षण, अपव्यय को कम करना और इसका अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना। ○ **हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन:** हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का लगातार आकलन करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय क्षमता विकसित करना। ○ **हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन:** रक्षा करना; भारत के घटते वन क्षेत्र को बहाल करना और बढ़ाना। ○ **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन:** एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण के तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। ○ **जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन:** एक जीवंत और गतिशील ज्ञान प्रणाली का निर्माण करना जो पारिस्थितिक तथा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई को सूचित और समर्थन करेगी।
ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क रिपोर्ट	**संदर्भ :** ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क (GCRMN) द्वारा विश्व में प्रवाल भित्तियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। ● 13 वर्षों में प्रकाशित अपनी तरह की इस पहली रिपोर्ट में वैश्विक तापन के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित किया गया है। तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करके प्रवाल भित्तियों को बचाया जा सकता है। **रिपोर्ट की मुख्य बातें** ● नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में लगभग 14% प्रवाल भित्तियों का ह्रास हुआ है। ● **खतरे:** महासागर-अम्लीकरण, गर्म समुद्र का तापमान और स्थानीय तनाव जैसे कि अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण, अस्थिर पर्यटन और खराब तटीय प्रबंधन। ● **ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव:** दुनिया भर में प्रवाल भित्तियाँ जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले वार्मिंग से लगातार तनाव में हैं। समुद्र की सतह के ऊंचे तापमान (SST) में वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन की घटनाएं प्रवाल हानि के लिए जिम्मेदार थीं।

	• **कठोर प्रवाल आवरण का नुकसान:** 1978 के बाद से पिछले चार दशकों में कठोर प्रवाल आवरण में लगातार कमी आई है, जब दुनिया ने अपने मूंगों का नौ प्रतिशत खो दिया था। यह कमी चिन्ताजनक है क्योंकि सजीव कठोर प्रवाल आवरण प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य का सूचक है। • **शैवाल खिलना:** मूंगे की लकीरों पर शैवाल का खिलना संरचनाओं पर दबाव का संकेत है। 2010 के बाद से, दुनिया के प्रवाल भित्तियों पर शैवाल की मात्रा में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। **हमें मूंगों का संरक्षण क्यों करना चाहिए?** • प्रवाल समुद्र तल के एक प्रतिशत से भी कम हिस्से पर रहते हैं लेकिन एक अरब से अधिक लोग सीधे भित्तियों से लाभान्वित होते हैं। • प्रवाल भित्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्रति वर्ष $2.7 ट्रिलियन होने का अनुमान है। इसमें कोरल रीफ पर्यटन में 36 अरब डॉलर शामिल हैं। • विश्व की प्रवाल भित्तियों का शुद्ध आर्थिक मूल्य लगभग दसियों अरब डॉलर प्रति वर्ष हो सकता है। **विरंजन क्या है?** • विरंजन तब होता है जब स्वस्थ मूंगे समुद्र के तापमान में बदलाव के कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिससे वे अपने ऊतकों में रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जो उनके जीवंत रंगों को खत्म कर देता है। • विरंजन पहली बार 1998 में चट्टान पर देखा गया था - उस समय, रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष - लेकिन जैसे-जैसे तापमान के रिकॉर्ड में गिरावट आई, इसकी आवृत्ति बढ़ गई है, जिससे मूंगा को ठीक होने में कम समय मिला।
छत्तीसगढ़ में भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व	**संदर्भ :** राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी। • मूल रूप से संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा, गुरु घासीदास पार्क को 2001 में राज्य के अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में एक अलग इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। **अन्य सम्बंधित तथ्य** • यह मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। • यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व (उदंती-सीतानदी, अचानकमार, इंद्रावती) है। • वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V(1) के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। **महत्व** • गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत में एशियाई चीता के अंतिम ज्ञात निवास स्थान के रूप में महत्वपूर्ण है। • वन्यजीव कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि गुरु घासीदास को टाइगर रिजर्व में परिवर्तित करना एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह मध्य प्रदेश और झारखंड को जोड़ता है और बाघों को पलामू और बांधवगढ़ रिजर्व के बीच जाने के लिए एक गलियारा प्रदान करता है। • दूसरी ओर, भोरमदेव छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण** • यह दिसंबर 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद स्थापित किया गया था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में कई टाइगर रिजर्व के पुनर्गठित प्रबंधन के लिए गठित किया गया था। इस संविधान के लिए 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया था। • यह लुप्तप्राय बाघों की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
मध्य हिमालयी क्षेत्र में एरोसोल के स्रोत	**स्रोत:** खनिज धूल, जैव पदार्थों (बायोमास) का जलना, द्वितीयक सल्फेट और द्वितीयक नाइट्रेट उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान से दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर, थार रेगिस्तान और अरब सागर क्षेत्र, एवं और लंबी दूरी तक वायु संचरण में सक्षम समुद्री मिश्रित एरोसोल मध्य हिमालय में एरोसोल के मुख्य स्रोत हैं। • धूल का यह परिसंचरण और वनों की आग विशेष रूप से मानसून-पूर्व की उस अवधि (मार्च-मई) में कुल निलंबित कणों (TSP) के मुख्य स्रोत हैं, जब इस क्षेत्र में TSP की सांद्रता अपने चरम पर होती है। • वसंत और गर्मियों में खनिज धूल और सर्दियों में जैव पदार्थों (बायोमास) जलने और माध्यमिक सल्फेट की प्रबलता थी।

	• परिवहन किए गए समुद्री मिश्रित एरोसोल स्रोत मुख्य रूप से गर्मी के मौसम के दौरान दक्षिणपंथी मानसून वायु द्रव्यमान से जुड़े थे। • घरेलू ताप और उथली मिश्रण परत के कारण इंडो गंगा के मैदानों और हिमालय पर जैव पदार्थों (बायोमास) जलने की तीव्रता के कारण सर्दियों में कार्बोनेसियस एरोसोल (ऑर्गेनिक कार्बन (OC) और एलिमेंटल कार्बन (EC)) सबसे अधिक थे। **पृष्ठभूमि** एशियाई जलवायु में एक अनूठी भूमिका के साथ, हिमालयी क्षेत्र को एक संवेदनशील वातावरण माना जाता है। पिछले दशक के दौरान पश्चिमी और मध्य हिमालयी क्षेत्रों में कार्बनयुक्त एरोसोल और अकार्बनिक प्रजातियों के लिए कई रासायनिक प्रजाति अध्ययन किए गए हैं, जो भारत-गंगा के मैदानों से परिवहन किए गए एरोसोल प्लम के प्रभुत्व की रिपोर्ट करते हैं।
पराली जलाना	**संदर्भ :** वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा गठित आयोग ने एक बयान में कहा कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान की खेती के तहत क्षेत्र में कमी और धान की किस्मों से दूर होने से इस साल पराली जलाने में कमी देखी गयी। **अन्य सम्बंधित तथ्य** • केन्द्र सरकार और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारें फसलों में विविधता लाने के साथ-साथ धान की पूसा-44 किस्म के उपयोग को कम करने के उपाय कर रही हैं। • फसल विविधीकरण और पूसा-44 किस्म के स्थान पर कम अवधि तथा अधिक उपज देने वाली किस्में पराली जलाने के मामले में नियंत्रण हेतु रूपरेखा और कार्य योजना का हिस्सा हैं। • हरियाणा, पंजाब और यूपी के आठ एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) जिलों में कुल धान क्षेत्र में 7.72% की कमी आई है। • इसी तरह, चावल की गैर-बासमती किस्म से कुल धान की पराली के उत्पादन में 12.42% की कमी होने की संभावना है। • यह चावल की गैर-बासमती किस्म है, जिसका डंठल रहता है, जिसे आमतौर पर किसान गेहूं की बुवाई से पहले जला देते हैं। **पराली जलाना क्या है?** • पराली जलाना फसल के अवशेषों को अगली फसल बोने के लिए खेत से निकालने के लिए आग लगाने की क्रिया है। • पंजाब और हरियाणा में सर्दियों की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए चावल की भूसी को साफ करना एक पारंपरिक प्रथा है। • यह अक्टूबर के आसपास शुरू होता है और नवंबर में चरम पर होता है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ मेल खाता है। • 10 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
Google जलवायु इनकार विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाएगा	**संदर्भ:** Google झूठे जलवायु परिवर्तन दावों को बढ़ावा देने वाले डिजिटल विज्ञापनों को अन्य सामग्री के पास में प्रदर्शित होने से प्रतिबंधित करेगा। • प्रतिबंध ऐसी सामग्री के विज्ञापनों पर रोक लगाएंगे जो जलवायु परिवर्तन के बारे में अच्छी तरह से स्थापित वैज्ञानिक सहमति का खंडन करती हैं। • यह जलवायु परिवर्तन से इनकार करने वालों के लिए राजस्व को सीमित करने और इसके प्लेटफार्मों पर गलत सूचना के प्रसार को रोकने में मदद करेगा। • नई नीति YouTube पर भी लागू होगी, जिसने पिछले सप्ताह टीके की गलत सूचना पर व्यापक कार्रवाई की घोषणा की थी।
जावन गिब्बन	**संदर्भ:** इंडोनेशिया जावन गिब्बन (Hylobates moloch) के आवास की रक्षा के लिए कदम उठा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन और मानव अतिक्रमण से संकटग्रस्त है। • इनका शिकार माँस और व्यापार दोनों के लिये भी किया जाता है।

	जावन गिब्बन के बारे में ● सिल्वर गिब्बन, जिसे जावन गिब्बन के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राइमेट है। यह आमतौर पर दो की जोड़ी के समूहों में पाए जाते हैं। ● यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप का स्थानिक है, जहाँ यह 2,450 मीटर की ऊँचाई तक वर्षा वनों में रहता है। ● यह बीजों को फैलाकर वन वनस्पति को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। ● लगभग 4,000 जावन गिबन्स बचे हैं। ● इसे IUCN वर्ष 2004 में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घोषित किया गया था, लेकिन अब यह लुप्तप्राय की श्रेणी में आ गया है। हालाँकि नवीनतम IUCN अनुमान से पता चलता है कि उनकी जनसंख्या घट रही है। ● **आवास:** जावा, इंडोनेशिया। ● **सुरक्षा की स्थिति:** ○ IUCN: लुप्तप्राय (EN) ○ साइट्स: परिशिष्ट I
भारत ने जलवायु लक्ष्यों को अपडेट करने को कहा	**सन्दर्भ :** U.K. ने भारत से कुछ हफ्तों में ब्रिटेन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले "अधिक महत्वाकांक्षी" राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की घोषणा करने का आग्रह किया है। ● आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में, यूके सभी देशों से अगले कुछ दशकों के लिए जलवायु लक्ष्यों को दर्शाने के लिए अपने NDC को अद्यतन करने के लिए कह रहा है। ● यूके ने यह भी नोट किया कि भारत पहले से ही नवीकरणीय प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणी है। **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) क्या है?** ● राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) गैर-बाध्यकारी राष्ट्रीय योजनाएं हैं, जो जलवायु परिवर्तन के जवाब में सरकार द्वारा लागू की जाने वाली जलवायु क्रियाओं को उजागर करती हैं और पेरिस समझौते में निर्धारित वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान के रूप में हैं। 193 देशों ने अपना पहला NDC दाखिल किया, लेकिन अभी तक केवल 19 ने ही उन्हें अपडेट किया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) पर SC	**संदर्भ:** सर्वोच्च न्यायालय ने 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' (NGT) को एक 'विशिष्ट' मंच के रूप में घोषित करते हुए कहा कि वह देश भर में पर्यावरणीय मुद्दों को उठाने हेतु 'स्वत: संज्ञान' (Suo Motu) लेने की शक्तियों से संपन्न है। **सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें** ● आवेदनों की प्राप्ति से NGT द्वारा शक्ति का प्रयोग सीमित नहीं है। ● जब पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं और मामला दीवानी प्रकृति का होता है और वे अधिनियम से संबंधित होते हैं, तो एनजीटी, आवेदन के अभाव में भी, सुधार की दिशा में या नुकसान की रोकथाम के लिए कार्रवाई स्वयं को प्रज्वलित कर सकता है। ● नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' की भूमिका केवल न्यायनिर्णयन तक सीमित नहीं है, ट्रिब्यूनल को कई अन्य महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ भी निभानी होती हैं, जो प्रकृति में निवारक, सुधारात्मक या उपचारात्मक हो सकती हैं। ● 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' के पास विशेष मंच के रूप में सभी पर्यावरण संबंधी बहु-विषयक मुद्दों से निपटने के लिये 'मूल' एवं 'अपीलीय' क्षेत्राधिकार मौजूद है। **एनजीटी क्या है?** ● यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार 2010 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ● यह एक विशेष न्यायिक निकाय है जो केवल देश में पर्यावरणीय मामलों के न्यायनिर्णयन के उद्देश्य से विशेषज्ञता से लैस है। ● NGT के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। ● यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। ● ट्रिब्यूनल के आदेश बाध्यकारी हैं और इसके पास प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे और हर्जाने के रूप में राहत देने की शक्ति है।

संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन	**संदर्भ :** संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन (UN Biodiversity Summit) 12 अक्टूबर, 2021 को चीन में शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को जैव विविधता की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। COP-26 जलवायु सम्मेलन से पहले प्रदूषण से निपटने और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने को रोकने के लिए देशों के बीच बैठक की पृष्ठभूमि में यह शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। **अन्य संबंधित तथ्य** ● बीजिंग दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है। ● इसने हाल के वर्षों में पर्यावरण के मुद्दों पर विश्व नेता के रूप में खुद को स्थापित करने की मांग की है। ● ऑनलाइन शिखर सम्मेलन अप्रैल 2022 में आमने-सामने बैठक करेगा। ● यह 2030 तक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए नए लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए जैविक विविधता (CBD) पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों को देखेगा। ● यह 2030 तक 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित दर्जा देने की "30 बाई 30" योजना पर भी बहस करेगा। ○ यह उपाय राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन द्वारा समर्थित है। प्लास्टिक कचरे के निर्माण को रोकने के लिए भी सदस्य देश लक्ष्य निर्धारित करेंगे। **जैविक विविधता पर कन्वेंशन (CBD)** ● इसे अनौपचारिक रूप से जैव विविधता सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, यह एक बहुपक्षीय संधि है। ● सम्मेलन के तीन मुख्य लक्ष्य हैं: ○ जैव विविधता (या जैव विविधता) का संरक्षण; ○ इसके घटकों का सतत उपयोग; ○ और आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। ● **उद्देश्य:** जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना। ● इसे अक्सर सतत विकास के संबंध में प्रमुख दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। ● 5 जून 1992 को रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए सम्मेलन खोला गया और 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ। ● इसके दो पूरक समझौते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल।
स्वच्छ भारत कार्यक्रम	**सुर्ख़ियों में:** भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष की पूर्व संध्या पर राज्य सरकारों के सहयोग से स्वच्छ भारत कार्यक्रम शुरू किया। ● **प्रमुख गतिविधियां:** संग्रह अभियान और घर-घर जाकर कचरे का संग्रह और निपटान अभियान, ग्राम सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत स्थलों, सामुदायिक केंद्रों, युवा मंडलों / महिला मंडलों, स्कूल और पंचायत भवनों आदि के लिए रखरखाव सौंदर्यीकरण अभियान और पारंपरिक जल स्रोत : कार्य शिविरों के माध्यम से जल निकायों की सफाई और रखरखाव। ● पूरे देश में 744 जिलों को कवर करते हुए 75 लाख किलो कचरे का संग्रह और निपटान मुख्य रूप से प्लास्टिक कचरे का प्रति जिले औसतन 10,080 किलोग्राम कचरा एकत्र किया जाएगा और तदनुसार प्रति गांव औसतन 30 किलोग्राम कचरा एकत्र कर उसका निपटान किया जाएगा।
क्लाइमेट रेजिलिएशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग (CRISP-M) टूल	**सुर्ख़ियों में:** भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत क्लाइमेट रेजिलिएशन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग (CRISP-M) टूल लॉन्च किया। ● भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित वाटरशेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए। ● जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए हमारे ग्रामीण समुदायों के लिए नई संभावनाएं खोलें - जलवायु परिवर्तन से निपटने और उन्हें मौसम संबंधी आपदाओं से बचाने के लिए।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रिपोर्ट	**संदर्भ:** वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में अब तक 70% और हरियाणा में 18% की कमी आई है। ● हालांकि, यह एक प्रारंभिक विश्लेषण है क्योंकि कटाई अभी भी चल रही है और आग की संख्या में दिन-प्रतिदिन भिन्नता बहुत अधिक है।

	महत्वपूर्ण तथ्य ● पराली जलाने को कम करने के लिए कई पहलें की गई हैं जैसे हैप्पी सीडर [कटाई उपकरण] का बढ़ता उपयोग और जैव-डीकंपोजर का उपयोग लेकिन परिणाम दिखने में समय लगेगा। ● वर्षों से यह देखा गया है कि धान की कटाई के लिए तैयार होने और गेहूं की बुवाई के सही समय के बीच बहुत कम समय होने पर आग लगने की संख्या बढ़ जाती है। ● इस वर्ष, उत्तर भारत में अत्यधिक नमी के कारण व्यापार के लिए बाजारों के खुलने में देरी, किसानों के लिए फसल और बुवाई के लिए उपलब्ध समय को और कम कर सकती है, जिससे उन्हें अपने खेतों में आग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। **पराली जलाना क्या है?** ● पराली जलाना फसल के अवशेषों को अगली फसल बोने के लिए खेत से निकालने के लिए आग लगाने की क्रिया है। ● पंजाब और हरियाणा में सर्दियों की बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने के लिए चावल की भूसी को साफ करना एक पारंपरिक प्रथा है। ● यह अक्टूबर के आसपास शुरू होता है और नवंबर में चरम पर होता है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के साथ मेल खाता है। ● 10 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
चौथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा	**सुर्खियों में:** ISA की चौथी सभा में विचार-विमर्श होगा ● OSOWOG पहल के संचालन के आसपास की प्रमुख पहलें, ● 2030 के लिए $1 ट्रिलियन सौर निवेश रोडमैप ● मिश्रित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण सुविधा का अनुमोदन ● अगले पांच वर्षों के लिए ISA की रणनीतिक योजना पर चर्चा करना जिसमें एक देश भागीदारी ढांचा, निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रणनीति और ISA की सदस्यता में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किफायती वित्त की सुविधा के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना जैसी पहल शामिल है। ● LDCs और SIDS को तकनीकी और वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए ग्लोबल एनर्जी एलायंस (GEA) के साथ साझेदारी पर चर्चा करना। **भारत द्वारा प्रस्तावित 'वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड' (OSOWOG) पहल** ● भारत द्वारा वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव जिसका उद्देश्य परस्पर जुड़े अक्षय ऊर्जा संसाधनों का एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिसे आसानी से साझा किया जाता है। ● देशों और क्षेत्रों के बीच समय क्षेत्रों, मौसमों, संसाधनों और कीमतों के अंतर का लाभ उठाते हुए, दुनिया भर में सौर ऊर्जा साझा करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय ऊर्जा ग्रिड के निर्माण और स्केलिंग की कल्पना करता है। ● ऊर्जा उत्पादन को कार्बन मुक्त करने में मदद करना , जो आज वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। ● भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विश्व बैंक और ISA द्वारा OSOWOG पर त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ, यह पहल दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय उत्प्रेरक हो सकता है। यह ऊर्जा उत्पादन और संचरण में पैमाने की अभूतपूर्व अर्थव्यवस्थाओं को अनलॉक कर सकता है। ● कठोर आकलन और मॉडलिंग ने पहल की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की है, जिससे एक मजबूत व्यावसायिक मामला बनता है। ● विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता को और बढ़ाया गया है, जो सौर ऊर्जा की लागत को कम करके बाजार बनाने में मदद कर रहे हैं।
भारत का जैव-आर्थिक हब	**संदर्भ:** पूर्वोत्तर (Northeast) क्षेत्र को भारत के जैव-आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि "पूर्वी हिमालयी (Eastern Himalayan) क्षेत्र मेगा-जैव विविधता

	समृद्ध क्षेत्रों में से एक है और दुनिया के 34 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक है।" • जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने क्षेत्र के लिए विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने और सामाजिक उत्थान के लिए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के रूप में स्थानीय समुदाय पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव संसाधनों का एक आनुवंशिक खजाना है। • उत्तर पूर्वी क्षेत्र के फाइटो-फार्मास्युटिकल मिशन का उद्देश्य पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं के प्रलेखन, वैज्ञानिक सत्यापन और मूल्यांकन को बढ़ावा देना है - पूर्वोत्तर के विशाल संयंत्र संसाधनों और विविध पारंपरिक स्वास्थ्य प्रथाओं के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। • स्थानीय जैव-संसाधनों के साथ उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण पारंपरिक ज्ञान-आधारित चिकित्सीय एजेंटों के विकास में मदद करेगा जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ-साथ पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सकों को लाभ होगा। • DBT ने शूट-टिप ग्राफ्टिंग प्रोद्यौगिकी के माध्यम से गुणवत्ता रोपण सामग्री का उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण फ्रूट क्रॉप खासी मंदारिन में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने का कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य परियोजना की तीन साल की अवधि के दौरान खासी मंदारिन और स्वीट ऑरेंज के चार लाख प्रमाणित रोग मुक्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन करना और क्षेत्र में कम से कम 1,000 किसानों का क्षमता निर्माण करना है। • DBT ने बागवानी अनुसंधान स्टेशन, असम कृषि विश्वविद्यालय (एएयू), काहिकुची में एक बायोटेक-किसान केंद्र स्थापित किया है। इसका उद्देश्य मालभोग केले की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। इस केले की असम राज्य में बहुत मांग है। • भारत की जैव-अर्थव्यवस्था 2025 तक मौजूदा 70 बिलियन डॉलर से 150 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है और 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में प्रभावी योगदान देगी।
जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति	**संदर्भ :** केंद्र सरकार ने अभी तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के वैज्ञानिकों के एक शोध प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया है, जो पारंपरिक ट्रांसजेनिक तकनीक की आवश्यकता के बिना पौधों को आनुवंशिक रूप से संशोधित करने की अनुमति देगा। **बेहतर गुणवत्ता वाले चावल की किस्म** • IARI के वैज्ञानिक जीन संपादन तकनीकों का उपयोग करते हुए लचीली और उच्च उपज वाली चावल की किस्मों को विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, जिन्हें पहले ही कई देशों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। • उन्हें उम्मीद है कि 2024 तक चावल की ऐसी किस्में भारतीय किसानों के हाथ में आ जाएंगी। • यह तकनीक पारंपरिक प्रजनन विधियों के बराबर है, क्योंकि इसमें किसी भी विदेशी डीएनए को सम्मिलित नहीं किया जाता है। • हालांकि, प्रस्ताव लगभग दो वर्षों से जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के पास लंबित है। **लाभ:** • उनका उद्देश्य CRISPR जैसे जीन एडिटिंग टूल का उपयोग करके प्रजनन प्रक्रिया में सटीकता और दक्षता लाना है। • यह प्राकृतिक उत्परिवर्तन या पारंपरिक प्रजनन विधियों की तुलना में बहुत तेज़ और कहीं अधिक सटीक है जिसमें परीक्षण और त्रुटि और कई प्रजनन चक्र शामिल हैं। **जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति क्या है?** • GM फसलों के अनुमोदन के लिए नियामक ढांचा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति सर्वोच्च निकाय है जो भारत में GM फसलों की व्यावसायिक रिलीज की अनुमति देती है। • जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा मूल्यांकन और पर्यावरण रिलीज सहित GM फसलों के विनियमन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र प्रदान करता है।

	क्या आप जानते हैं? ● IARI ने पहले गोल्डन राइस पर काम किया है, जो एक पारंपरिक GM किस्म है जिसने चावल के पौधे में अन्य जीवों के जीन डाले, लेकिन कृषि संबंधी मुद्दों के कारण पांच साल पहले परीक्षण समाप्त हो गया।
जिओरिसा मावस्माईन्सिस	**संदर्भ :** हाल ही में, शोधकर्ताओं ने मेघालय (Meghalaya) के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मावस्माई गांव में चूना पत्थर की गुफा के भीतर सूक्ष्म घोंघे (snail species) की एक नई प्रजाति मिली है। जिसका नाम 'जियोरिसा मावस्माएंसिस' है। **घोंघे की नई प्रजातियों के बारे में** ● ये घोंघे आकार में इतने छोटे होते हैं कि एक वयस्क की लंबाई 2 मिलीमीटर से भी कम होती है। ● इसकी खोज 170 साल बाद हुई है। ● यह 1851 में था कि नवीनतम खोज के रूप में एक ही जीनस के सदस्य, जिओरिसा सरिता को चेरापूंजी के पास मुस्माई (मौसमई आज) घाटी से एकत्र और वर्णित किया गया था। ● जिओरिसा जीनस के सदस्यों को व्यापक रूप से अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में वितरित और रिपोर्ट किया जाता है। ● हालांकि, वे चूना पत्थर की गुफाओं या चूना पत्थर के विघटन से बने कार्स्ट परिदृश्यों से युक्त सूक्ष्म आवासों तक ही सीमित हैं। ● जिओरिसा तराई के उष्णकटिबंधीय वनों के साथ-साथ उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों या कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतहों पर मिट्टी या भूमिगत आवासों में पाया जाता है। ● नई प्रजाति पहले की तुलना में खोल के आकार में भिन्न है। इसके अलावा, जियोरिसा सरिता में सात की तुलना में खोल के शरीर के झुंडों पर इसकी चार बहुत ही प्रमुख सर्पिल पट्टियां हैं। ● अब तक मेघालय की गुफाओं से घोंघे की पांच प्रजातियां पाई गई हैं। **मौसमाई गुफा** ● यह मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी (सोहरा) से लगभग चार किमी दूर मौसमई के छोटे से गांव में स्थित है। ● खासी भाषा में 'मौसमई' शब्द का अर्थ 'शपथ पत्थर' है। ● खासी लोग गुफा के लिए स्थानीय शब्द 'क्रेम' का प्रयोग करते हैं। ● मावसई गुफा परोक्ष रूप से पूर्वी खासी पहाड़ियों से निकलने वाली किंशी नदी की धाराओं से प्रभावित है।
2020 में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दशकीय औसत से ऊपर	**संदर्भ:** विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 से 2020 तक कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि 2018 से 2019 की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन पिछले दशक की औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक थी। हालांकि, यह पिछले एक दशक में औसत वार्षिक वृद्धि दर से अधिक है। अद्यतन आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 में महामारी के व्यवधान ने समग्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण रूप से सेंध नहीं लगाई। **मुख्य निष्कर्ष** ● नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) वार्षिक ग्रीनहाउस गैस इंडेक्स (एजीजीआई) से पता चलता है कि 1990 से 2020 तक, लंबे समय तक रहने वाली ग्रीनहाउस गैसों (एलएलजीएचजी) द्वारा विकिरण बल (वार्मिंग प्रभाव) में 47% की वृद्धि हुई, जिसमें सीओ2 लगभग 80 के लिए जिम्मेदार था। इस वृद्धि का%। ● **मीथेन:** मीथेन के लिए, 2019 से 2020 तक की वृद्धि 2018 से 2019 तक की तुलना में अधिक थी और पिछले दशक की औसत वार्षिक वृद्धि दर से भी अधिक थी। ● **नाइट्रस ऑक्साइड:** नाइट्रस ऑक्साइड के लिए भी, वृद्धि अधिक थी और पिछले 10 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि दर से भी अधिक थी। ● **कार्बन डाइऑक्साइड (CO2):** सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 2020 में 413.2 भाग प्रति मिलियन (Parts Per Million: PPM) तक पहुंच गई, जो पूर्व-औद्योगिक स्तर का 149% है।

	• मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित CO2 का लगभग आधा हिस्सा आज वायुमंडल में बना हुआ है। शेष आधा भाग महासागरों और भूमि पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा लिया जाता है। **चिंताएं उठाईं** • WMO ने चिंता व्यक्त की है कि भविष्य में भूमि पारिस्थितिक तंत्र और महासागरों की 'सिंक' के रूप में कार्य करने की क्षमता कम प्रभावी हो सकती है, इस प्रकार CO2 को अवशोषित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है और बड़े तापमान में वृद्धि के खिलाफ एक बफर के रूप में कार्य करता है। • इसने यह भी बताया है कि ग्रीनहाउस गैस सांद्रता में वृद्धि की वर्तमान दर पर, हम इस सदी के अंत तक पेरिस समझौते के पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से कहीं अधिक तापमान में वृद्धि देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस	**संदर्भ:** हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस (International Snow Leopard Day) मनाया जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में 12 स्नो लेपर्ड रेंज देशों (अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कज़ाखस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान) द्वारा बिश्केक घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए थे। **हिम तेंदुए के बारे में** • **पर्यावास:** हिम तेंदुए उत्तरी और मध्य एशिया के ऊँचे पहाड़ों (हिमालय क्षेत्र सहित) के विशाल क्षेत्र में रहते हैं। • अब जंगल में केवल 3,920 और 6,390 हिम तेंदुए बचे हैं। • संरक्षण की स्थिति: हिम तेंदुए की IUCN स्थिति "असुरक्षित" है। इसे 2017 में "संकटग्रस्त" से "कमजोर" में बदल दिया गया था। • भारत लगभग 450-500 हिम तेंदुओं का घर है, जिन्हें देश के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। **भारत द्वारा संरक्षण के प्रयास** • भारत प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (PSL) के माध्यम से हिम तेंदुओं और उनके आवासों का संरक्षण करता रहा है। • भारत 2013 से ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन (GSLEP) प्रोग्राम का भी हिस्सा रहा है। • भारत ने तीन बड़े भू-दृश्यों की पहचान की है, अर्थात् लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हेमिस-स्पीति; नंदा देवी - उत्तराखंड में गंगोत्री; और खांगचेंदज़ोंगा - सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तवांग। • पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए हिम तेंदुआ 22 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में है। • **सुरक्षित हिमालय:** उच्च ऊंचाई वाली जैव विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF)-UNDP द्वारा अनिर्धारित। • यह परियोजना अब चार हिम तेंदुओं की श्रेणी वाले राज्यों - जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में परिचालित है। • हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम "हिमाल रक्षक"। **वैश्विक संरक्षण के प्रयास** • 2013 में, बिश्केक घोषणापत्र ने 2020 तक व्यवहार्य हिम तेंदुओं की आबादी के साथ कम से कम 20 हिम तेंदुओं के परिदृश्य की रक्षा करने का लक्ष्य निर्धारित किया। • इसने ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP) के गठन का नेतृत्व किया। **संरक्षण के लिए चुनौतियां** • आवास की कमी और गिरावट में वृद्धि। • अवैध शिकार। • समुदायों के साथ संघर्ष।
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व	**संदर्भ:** मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में वन्यजीव बचाव एवं पुनर्वास केंद्र खोलने के लिए स्टेप उठाए जाएंगे। • **स्टेप का कारण:** नीलगिरी में हाल ही में पकड़े गए या बचाए गए जानवरों को इलाज के लिए चेन्नई के अरिग्नार अन्ना प्राणी उद्यान या मैसूर चिड़ियाघर में ले जाने की आवश्यकता थी। **मुदुमलाई टाइगर रिजर्व**

	• मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरि ज़िले में तीन राज्यों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) के त्रि-जंक्शन पर स्थित है। • यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व) के साथ पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (केरल), उत्तर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक), दक्षिण में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली का एक हिस्सा है। • वनस्पति: ○ इस रिजर्व में लंबी घास है, जिसे आमतौर पर 'हाथी घास' कहा जाता है। ○ विशाल किस्म का बाँस, मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियाँ जैसे सागौन, शीशम आदि। ○ स्थानिक वनस्पतियों की कई प्रजातियां हैं। • **जीव:** प्रमुख प्रजातियां: बाघ और एशियाई हाथी। **तमिलनाडु में अन्य टाइगर रिजर्व** • अनामलाई टाइगर रिजर्व (ATR) • कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व (KMTR) • सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (STR)
जहरीले पटाखों की बिक्री	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी राज्य में प्रतिबंधित किस्म के पटाखों का इस्तेमाल होता है तो मुख्य सचिव और शीर्ष प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। **अन्य संबंधित तथ्य** • SC ने कहा कि किसी को भी दूसरों के जीवन के साथ खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के जीवन के साथ। ○ केवल उन पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले होते हैं। • राज्य सरकारों/राज्य एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। • यदि यह पाया जाता है कि किसी भी प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण, बिक्री और उपयोग किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है, तो राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और क्षेत्र के पुलिस आयुक्त, क्षेत्र के जिला पुलिस अधीक्षक और थाने के प्रभारी एसएचओ/पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। • अदालत ने जहरीले तत्वों के बिना बने 'हरे' या पर्यावरण के अनुकूल पटाखों के उपयोग की अनुमति दी थी। **क्या आप जानते हैं?** • पटाखे दहन प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइज़र का उपयोग करते हैं, और परिणामी विस्फोट सामग्री को अत्यधिक गर्म अवस्था में फैला देता है। विस्फोटक मिश्रण में धातु के लवण 'उत्तेजित' हो जाते हैं और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। • कई अध्ययनों से पता चलता है कि पटाखों का जलना प्रदूषण का एक असामान्य और चरम स्रोत है, जो कणों और गैसों से बना है। • पटाखों से होने वाला प्रदूषण लोगों और जानवरों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और भारतीय शहरों में पहले से ही खराब परिवेशी वायु गुणवत्ता को बढ़ाता है। • इसके परिणामस्वरूप अदालती मामलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है, और अदालत ने अंततः उपयोग किए जाने वाले रसायनों के प्रकार के साथ-साथ उनकी मात्रा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।
चीन ने संयुक्त राष्ट्र को नई जलवायु योजना सौंपी	**संदर्भ:** चीन, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, ने 2030 से पहले कार्बन प्रदूषण को चरम पर पहुंचाने के वादे के साथ अपनी उत्सर्जन कटौती योजना को नवीनीकृत किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** • संयुक्त राष्ट्र में चीन के नए सबमिशन ने 2060 से पहले कार्बन तटस्थता हासिल करने और अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 65% से अधिक कम करने के अपने लक्ष्य की पुष्टि की।

	○ चीन सभी मानव निर्मित उत्सर्जन के एक चौथाई से अधिक के लिए जिम्मेदार है, और पहले वादा किया था, 2015 पेरिस जलवायु समझौते द्वारा गति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत, 2060 तक शुद्ध-शून्य तक पहुंचने के लिए। ○ पेरिस जलवायु समझौते के तहत, राष्ट्रों को प्रत्येक पांच साल में नए सिरे से उत्सर्जन-कटौती प्रतिज्ञाओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है - जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDC के रूप में जाना जाता है। ● चीन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की अपनी योजनाओं को नवीनीकृत करने में अनिच्छुक था, और यह आशा की गई थी कि उसके नए सबमिशन से ग्लासगो में विलंबित COP26 शिखर सम्मेलन से पहले गति मिल सकती है, जो रविवार से शुरू हो रहा है। **चीन के नए सिरे से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** ● अपने नवीनीकृत NDC के अनुसार, यह प्राथमिक ऊर्जा खपत में गैर-जीवाश्म ईंधन के अपने हिस्से को पहले से गिरवी रखे गए 20% से बढ़ाकर 25% कर देगा। ● यह 2005 के स्तर की तुलना में अपने वन स्टॉक को छह बिलियन क्यूबिक मीटर बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। ● पवन और सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता को 2030 तक 1.2 बिलियन किलोवाट से अधिक तक पहुंचाएं।
CO2 को मीथेन में बदलना	**संदर्भ:** हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) को मीथेन (CH4) में परिवर्तित करने के लिये एक प्रकाश उत्प्रेरक (Photocatalyst) विकसित किया है। ● प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा शुरू की गई एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। **प्रमुख बिंदु** ● वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक पॉलिमर को इस तरह से डिज़ाइन किया है जो दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में भी सक्षम होगा। ● अधिकांश उत्प्रेरकों में विषैले और महँगे धातु प्रतिरूप उपस्थित होते हैं। इसलिये वैज्ञानिकों ने इस कमी को दूर करने हेतु एक धातु मुक्त तथा संरंध्रयुक्त (Porous) कार्बनिक बहुलक तैयार किया है। ● CO2 के न्यूनीकरण की यह प्रकाश-रासायनिक विधि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। ● **महत्व:** ○ मीथेन के महत्त्वपूर्ण उपयोगों के साथ-साथ यह सबसे स्वच्छ ज्वलनशील जीवाश्म ईंधन के रूप में मूल्यवर्द्धित उत्पादों में से एक हो सकता है और सीधे हाइड्रोजन वाहक के रूप में ईंधन कोशिकाओं में उपयोग किया जा सकता है। ○ यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी है और इसमें बिजली उत्पादन के लिये कोयले की जगह लेने और नवीकरणीय उत्पादकता को सुदृढ़ करने की आपूर्ति क्षमता है। **मीथेन क्या है?** ● मीथेन गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। ● यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिसमें एक कार्बन परमाणु और चार हाइड्रोजन परमाणु (CH4) होते हैं। ● मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। यह ज्वलनशील है, और इसका उपयोग दुनिया भर में ईंधन के रूप में किया जाता है। ● मीथेन गैस कार्बनिक पदार्थों के टूटने या क्षय से उत्पन्न होती है और इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा वातावरण में उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे कि आर्द्रभूमि में पौधों की सामग्री का क्षय, भूमिगत जमा गैस का रिसाव या मवेशियों द्वारा भोजन का पाचन या मानव गतिविधियाँ जैसे- तेल और गैस उत्पादन, चावल की खेती या अपशिष्ट प्रबंधन। ● मीथेन को 'मार्श गैस' भी कहा जाता है क्योंकि यह दलदली जगहों की सतह पर पाई जाती है।

भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली	**संदर्भ:** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (CSIR-NGRI) ने हिमालयी क्षेत्र के लिये 'भूस्खलन और बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली' विकसित करने हेतु एक 'पर्यावरण भूकंप विज्ञान' (Environmental Seismology' Group) समूह की शुरुआत की है। यह प्रणाली उपग्रह डेटा, संख्यात्मक मॉडलिंग और भू-आकृति विश्लेषण सहित घने भूकंपीय नेटवर्क के साथ वास्तविक समय की निगरानी पर आधारित होगी। ● यह कई घंटे पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी को सक्षम करेगा, जो भविष्य में ऐसे आयोजनों के दौरान बहुमूल्य मानव जीवन और संपत्ति को बचाएगा। **जलवायु परिवर्तन - भूस्खलन और बाढ़ का कारण** ● भारत के उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन आम हैं, विशेष रूप से वर्तमान मानसून के मौसम में जब भारी बारिश से पृथ्वी और चट्टानें नीचे गिरती हैं। ● जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है, जिससे मानसून अधिक अनिश्चित हो गया है और पहाड़ों में ग्लेशियरों का पिघलना अधिक हो गया है। ● क्षेत्र में सड़कों का रखरखाव भी अक्सर खराब रहता है। **भूस्खलन और बाढ़ के बारे में** ● भूस्खलन को एक ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान की गति के रूप में परिभाषित किया गया है। ● एक उच्च जल स्तर जो एक धारा के किसी भी हिस्से के साथ प्राकृतिक किनारों से बह जाता है, बाढ़ कहलाता है। इस प्रकार, बाढ़ आमतौर पर एक धारा या नदी से जुड़ी होती है। **क्या आप जानते हैं?** ● राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक घटक अनुसंधान प्रयोगशाला है। ● इसकी स्थापना 1961 में पृथ्वी प्रणाली की अत्यधिक जटिल संरचना और प्रक्रियाओं तथा इसके व्यापक रूप से परस्पर जुड़े उप-प्रणालियों के बहु-विषयक क्षेत्रों में अनुसंधान करने के मिशन के साथ की गई थी।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना	**संदर्भ:** केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना कर दिया है। 1995 में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पका हुआ भोजन दिए जाने के लिए मध्याह्न भोजन की शुरूआत की गई थी। **पीएम पोषण योजना में प्रमुख प्रस्ताव** ● **पूरक पोषण (Supplementary nutrition):** आकांक्षी जिलों के बच्चों और एनीमिया के उच्च प्रसार वाले बच्चों के लिए पूरक पोषण। ● **राज्य आहार तय करना :** यह केंद्र की ओर से केवल गेहूं, चावल, दाल और सब्जियों के लिए राशि उपलब्ध कराने के प्रतिबंध को दूर करता है। ● वर्तमान में, यदि कोई राज्य मेनू में दूध या अंडे जैसे किसी भी घटक को जोड़ने का निर्णय लेता है, तो केंद्र अतिरिक्त लागत वहन नहीं करता है। अब वह प्रतिबंध हटा लिया है। ● **न्यूट्री-गार्डन:** बच्चों को "प्रकृति और बागवानी के साथ प्रत्यक्ष अनुभव" देने के लिए उन्हें स्कूलों में विकसित किया जाएगा। ● **महिलाएं और FPOs:** स्थानीय, महिला स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए गायन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ● **सोशल ऑडिट:** जमीनी स्तर पर निष्पादन के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा "निरीक्षण"। ● **तिथि-भोजन (Tithi-Bhojan):** त्योहारों आदि पर बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए समुदायों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ● **स्कूल को DBTs:** राज्यों से कहा जाएगा कि वे खाना पकाने की लागत के नकद हस्तांतरण को अलग-अलग स्कूल खातों में नकद हस्तांतरण, रसोइयों और सहायकों के बैंक खातों में भत्तों का हस्तांतरण करें। ● **समग्र पोषण:** स्कूल पोषण उद्यान के साथ-साथ स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के उपयोग को

	प्रोत्साहित किया जाएगा। **मध्याह्न भोजन योजना के बारे में** ● प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NSPE) 1995 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। ● **उद्देश्य:** नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों में पोषण स्तर में सुधार करना। ● 2001 में यह पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना बन गया। ● इस योजना में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (STC) और सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत समर्थित मदरसों / मकतबों में पढ़ने वाले कक्षा I-VIII के बच्चे शामिल हैं। ● यह विश्व का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है। ● यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और COVID मुआवजा	**संदर्भ:** केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए कोरोना से मौत का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। ● बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत COVID-19 से मरने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) क्या है?** ● NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। ● NDMA का गठन औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार किया गया था। ● **संरचना:** प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष और नौ अन्य सदस्यों के रूप में, और ऐसे एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना है। ● **जनादेश:** इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वय करना और आपदा समाधान तथा संकट प्रतिक्रिया में क्षमता निर्माण के लिए है। ● यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने वाली शीर्ष संस्था भी है ताकि आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। ● **विज़न:** एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना जिसमें सभी हितधारक शामिल हों और रोकथाम, तैयारी तथा शमन की संस्कृति को बढ़ावा दें।
कावेरी नदी विभिन्न प्रदूषकों की वजह से हो रही प्रदूषित : आईआईटी मद्रास	**संदर्भ:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के बाद कहा है कि कावेरी नदी औषधीय प्रदूषकों, निजी देखभाल से संबंधित उत्पादों, अग्निशामकों, भारी धातुओं और कीटनाशकों सहित विभिन्न प्रदूषकों की वजह से प्रदूषित हो रही है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● यह दवा प्रदूषकों के लिए नदी और उसकी सहायक नदियों की नियमित रूप से निगरानी करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ● यह प्रदूषक विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि भारत दूसरा सबसे बड़ा दवा निर्माता है। ● **हानिकारक प्रभाव:** दवा के यौगिक, जब छोटी मात्रा में भी जल निकायों में छोड़े जाते हैं, तो लंबे समय में मानव और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ● अध्ययन ने मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर इस तरह के प्रदूषकों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। **कावेरी नदी के बारे में** ● कावेरी नदी (कावेरी) को 'दक्षिण भारत की गंगा' या 'दक्षिण की गंगा' के रूप में नामित किया गया है। ● कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु (कूर्ग) के चेरंगला गांव के पास ब्रह्मगिरी रेंज पर तालकावेरी से निकलती है। ● यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और बड़े झरनों की एक श्रृंखला में पूर्वी घाट से नीचे गिरती है। ● तमिलनाडु के कुड्डालोर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, नदी बड़ी संख्या में वितरिकाओं में टूट जाती

	है, जिससे एक विस्तृत डेल्टा बनता है जिसे "दक्षिणी भारत का उद्यान" कहा जाता है। ● यह नदी पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में संकरे पर्वत (ridges) मौजूद हैं, जो इसको कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बेसिन से अलग करती हैं।
पाक खाड़ी योजना	**संदर्भ:** पाक खाड़ी योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार गहरे समुद्र में मत्स्यन (मछली पकड़ने) वाले जहाजों की इकाई लागत में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ताकि इसे मछुआरों के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। ● अभी तक, 80 लाख रुपये की मूल इकाई लागत मछुआरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अपर्याप्त थी। **पाक खाड़ी योजना के बारे में** ● इसे जुलाई 2017 में प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ● इसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लाभार्थी की भागीदारी के साथ वित्तपोषित किया जा रहा है। ● इसमें राज्य के मछुआरों को तीन साल में 2,000 जहाजों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है ताकि उन्हें नीचे की ओर ट्रॉलिंग को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। **बॉटम ट्रॉलिंग क्या है?** ● बॉटम ट्रॉलिंग का अर्थ है समुद्र तल में महाजाल के उपयोग द्वारा मछली पकड़ना। ● यह मत्स्यन (मछली पकड़ने) की एक प्रणाली है जो समुद्र तल के साथ जाल खींचकर लक्ष्य प्रजातियों, अधिकांशतः मछलियों को एकत्रित करती है एवं प्रग्रहित करती है। ● तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका अत्यंत व्यापक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह मत्स्यन-पश्च मृत्यु दर, नितल (बेंथोस) में परिवर्तन एवं प्रवाल भित्तियों को हानि पहुंचाता है।
भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र	**सुर्ख़ियों में:** नीति आयोग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से नीति आयोग द्वारा भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया गया है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने भी इस प्लेटफॉर्म को विकसित करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। ● देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की एक समग्र तस्वीर प्रदान करता है जो 27 विषयगत परतों के माध्यम से ऊर्जा प्रतिष्ठानों के दृश्य को सक्षम बनाता है- ● नक्शा किसी देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों और उनके परिवहन / प्रेषण नेटवर्क की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद करेगा। ● इस मंच को कई संगठनों में बिखरे हुए ऊर्जा डेटा को एकीकृत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ● वेब-जीआईएस प्रौद्योगिकी और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर में नवीनतम प्रगति का लाभ उठाता है ताकि इसे इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके। ● यह मैप योजना बनाने और निवेश संबंधी निर्णय लेने में उपयोगी होगा। ● ऊर्जा संपत्तियों की GIS मैपिंग भारत में ऊर्जा क्षेत्र की अन्योन्याश्रयता (interdependence) और बड़े भौगोलिक वितरण को देखते हुए वास्तविक समय और एकीकृत योजना सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

लाल बहादुर शास्त्री	**सुर्ख़ियों में :** प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। • भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। • ये महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। • 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए • 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होनें देश का नेतृत्व किया **ईमानदार व्यक्ति (The man of integrity)** • लाखों भारतीयों की तरह, शास्त्री ने भी महात्मा गांधी से प्रेरणा ली और जब वे किशोरावस्था में थे तब स्वतंत्रता संग्राम में आये। • साठ साल से भी पहले, शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का परिचय दिया था। • तमिलनाडु के अरियालुर में एक ट्रेन दुर्घटना के बाद, जिसमें 140 से अधिक लोग मारे गए थे, उन्होंने इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। • उनकी ईमानदारी के लिए प्रशंसा करते हुए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वह उनका इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह संवैधानिक औचित्य में एक उदाहरण स्थापित करेगा, हालांकि शास्त्री इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं थे। • जब उन्होंने 1928 में शादी की, तो ससुराल वालों के दहेज लेने के आग्रह पर उन्होंने एक चरखा और कुछ खादी का कपड़ा लिया। यहां तक कि जब उनका निधन हो गया, तब भी उनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी ये कुछ किताबें और धोती-कुर्ता छोड़ गए थे। उदाहरण, जब वे बचपन में स्कूल जाते थे तो उनको नदी पार कर (गरीब परिवार के पैसे बचाने के लिए नाव में नहीं बैठते थे) जाना होता था। • चूंकि बच्चों को उनके पिता के प्रधानमंत्री होने पर स्कूल जाने के लिए आधिकारिक कार का उपयोग करने की शायद ही कभी अनुमति दी जाती थी, परिवार ने एक फिएट कार रुपये में खरीदने का फैसला किया। 12,000. रुपये के लिए एक बैंक ऋण 5,000 लिया गया, जिसे शास्त्री की विधवा को उनकी अचानक मृत्यु के बाद, उनकी पेंशन से निकालना पड़ा। प्रधानमंत्री के रूप में एक कपड़ा मिल के दौरे पर, जब मालिक ने उन्हें महंगी साड़ियाँ उपहार में देने की पेशकश की, तो शास्त्री ने केवल उन्हीं के लिए खरीदने और भुगतान करने पर जोर दिया जो वह खरीद सकते थे। उन्होंने अपने बेटे के पलट जाने के लिए एक अनुचित पदोन्नति भी की थी। **एक तर्कसंगत और नैतिक व्यक्तित्व** • उन्होंने बहुत कम उम्र में एक व्यापक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया और सातवीं कक्षा में होने पर अपना जाति-आधारित उपनाम छोड़ दिया। • उनका प्रगतिशील रवैया तब सामने आया जब उन्होंने दहेज के रूप में खादी का कपड़ा और चरखा मांगा। • 1964 में उनका पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उस समय था। • शास्त्री ने कहा: "हम दुनिया में सम्मान तभी जीत सकते हैं जब हम आंतरिक रूप से मजबूत हों और अपने देश से गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर सकें। सबसे बढ़कर हमें राष्ट्रीय एकता की जरूरत है। सांप्रदायिक, प्रांतीय और भाषाई संघर्ष देश को कमजोर करते हैं। इसलिए हमें राष्ट्रीय एकता बनानी होगी। मैं सभी से राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने और हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए एक सामाजिक क्रांति की शुरूआत करने की अपील करता हूं। अंतिम विश्लेषण में, देश की ताकत केवल उसके भौतिक धन में ही नहीं है। इसके लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे लोगों की जरूरत है। इसके लिए चरित्र बल और नैतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूं कि वे अपने अंदर अनुशासन पैदा करें और देश की एकता और उन्नति के लिए काम करें। • चरित्र और नैतिक शक्ति पर उनका जोर आज विशेष महत्व रखता है, जब हम विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यों का चारो ओर का पतन देखते हैं। **जय जवान, जय किसान नारा** • 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान, शास्त्री ने "जय जवान, जय किसान" का अमर नारा दिया, जो आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। • अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, जो दुर्भाग्य से उनकी असामयिक मृत्यु से समाप्त हो गया था, शास्त्री ने

	भारत को पाकिस्तान पर जीत के लिए नेतृत्व करके राष्ट्र का मनोबल बढ़ाया। • खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के उनके दृष्टिकोण ने हरित क्रांति के बीज बोने और श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। • देश का उन पर कोई छोटा-मोटा कर्ज नहीं है कि आज हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। • स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा: "राष्ट्र आराम नहीं कर सकता। भविष्य में हमारे लिए क्या मायने रखता है, यह कहना मुश्किल है। पाकिस्तान ने अभी तक अपनी आक्रामकता की नीति को नहीं छोड़ा था। इसलिए राष्ट्र का कर्तव्य स्पष्ट है। देश की सुरक्षा को मजबूत करना होगा। लोगों को रक्षा को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। साथ-साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना होगा। खाद्य आत्मनिर्भरता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी एक मजबूत रक्षा प्रणाली। इसी वजह से मैंने 'जय जवान, जय किसान' का नारा लगाया। किसान उतना ही जवान है जितना कि सिपाही"। • कई साल बाद, पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी वाजपेयी ने भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों की सराहना करने के लिए शास्त्री के नारे में "जय विज्ञान" जोड़ा। **देश हित पहले** • शास्त्री जी ने देश के हितों को सबसे ऊपर रखा। • यद्यपि वह शांति के सिद्धांतों के प्रति समर्पित थे, शास्त्री ने दिखाया कि जब भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात आती है तो वह अधिक कठोर थे। • भारतीय सशस्त्र बलों को पाकिस्तान की अकारण आक्रामकता के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का आदेश देने में उनकी प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक थी। • शास्त्री का मातृभूमि के प्रति प्रेम तब स्पष्ट हुआ जब उन्होंने 16 साल की छोटी उम्र में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के आह्वान का जवाब दिया। • उसके जीवन की एक घटना दर्शाती है कि वह कर्मठ व्यक्ति थे। खाद्यान्न की कमी को देखते हुए देशवासियों से सप्ताह में एक बार भोजन न करने की अपील करने से पहले उन्होंने अपने घर पर इस नियम को लागू किया। • उनकी अपील का बिजली जैसे प्रभाव पड़ा और देश भर के कई घरों ने उनके आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। **एक दूरदर्शी व्यक्ति** • उनका मानवीय गुण एक अन्य उदाहरण में परिलक्षित हुआ। उत्तर प्रदेश के पुलिस और परिवहन मंत्री के रूप में, उन्होंने आदेश दिया कि अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठियों के बजाय पानी के जेट का उपयोग करना चाहिए। • यह तथ्य कि शास्त्री पहले परिवहनमंत्री थे, जिन्होंने महिलाओं के लिए बस कंडक्टरों का पद निकाला, यह दर्शाता है कि वह कितने दूरदर्शी थे। • उनका दूरदर्शी दृष्टिकोण 1964 में दिल्ली में ग्रामीण परियोजनाओं की बैठक में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों में परिलक्षित होता है। • उन्होंने कहा "हमें सेवाओं में नए तत्वों को शामिल करना चाहिए। आइए हम प्रोफेसरों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षकों, इंजीनियरों और अन्य लोगों, यहां तक कि बाहरी लोगों से भी परिचय कराएं, ताकि कुछ ताजगी हो, विचारों का वास्तविक आदान-प्रदान हो, विभिन्न दृष्टिकोणों का मिलन हो"। • शायद, लेटरल एंट्री के लिए 10 वरिष्ठ सिविल सेवा पदों को निकालने का सरकार का निर्णय इसी दर्शन के अनुरूप है। • चूंकि वह जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने एक युवा स्कूली छात्र के रूप में अपना उपनाम छोड़ दिया। काशी विद्यापीठ से स्नातक होने पर उन्हें "शास्त्री" की उपाधि विद्वतापूर्ण उपलब्धि के प्रतीक के रूप में प्रदान की गई थी। **क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं?** **1.** स्वतंत्र भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में लाल बहादुर शास्त्री का क्या योगदान है? क्या आपको लगता है कि वह आज के समय में प्रासंगिक हैं? चर्चा कीजिए।
लंगा मांगणियार (Langa Manganiyar) विरासत	**संदर्भ:** लंगा मांगणियार (Langa Manganiyar) कलाकारों के गाथागीत, लोककथाओं और गीतों को प्रलेखन और डिजिटलीकरण के लिए एक पहल के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। ● इस परियोजना का उद्देश्य इन समुदायों की तेजी से लुप्त हो रही कथा परंपराओं को बचाना है। ● जोधपुर स्थित रूपयान संस्थान ने अनुसंधान परियोजना में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज (AIIS) में

	आर्काइव्स एंड रिसर्च सेंटर फॉर एथनोम्यूजिकोलॉजी द्वारा की गई पहल को समर्थन दिया है। **लंगस और मांगणियार कौन हैं?** ● लंगा और मांगणियार मुस्लिम संगीतकारों के वंशानुगत समुदाय हैं जो ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में तथा पाकिस्तान के थारपारकर और सिंध में संघर जिलों में रहते हैं। ● प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित लोक कलाकार, COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ● महामारी के अलावा, इस महत्वपूर्ण विरासत को इन जिलों में संरक्षण में बदलाव और बढ़ते शहरीकरण से भी खतरा है। ● स्वतंत्रता से पहले धनी जमींदारों और व्यापारियों द्वारा समर्थित दो हाशिए के समुदायों का संगीत थार रेगिस्तान के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ब्रह्मपुत्र विरासत केंद्र	● 150 साल पहले, गुवाहाटी के इस प्रतिष्ठित बंगले का निर्माण कामरूप के ब्रिटिश उपायुक्त के निवास के रूप में किया गया था। ● यह बंगला अहोम शासकों का 17वीं सदी का सैन्य कार्यालय हुआ करता था। ● यह विरासत केंद्र बरफुकनार टीला के ऊपर स्थित है, जो एक छोटी सी पहाड़ी है जिसका नाम अहोम सेनानायक लचित बरफुकान (Lachit Barphukan) के नाम पर रखा गया है। ● बारपुखान अहोम राजा प्रताप सिम्हा या सुसेंगफा (1603-1641) द्वारा सृजित गवर्नर जनरल के समकक्ष पद था। ● ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी, जिसका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में मंद्राचल के रूप में किया गया है, जहां से अहोम जनरल लचित बरपुखान ने मुगलों को सबसे अधिक करारी हार देने के लिए मार्च 1671 में सरायघाट की लड़ाई शुरू की थी। ● सरायघाट को "नदी में लड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई" के रूप में माना जाता है।
श्यामजी कृष्ण वर्मा	**सुर्ख़ियों में:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। • एक भारतीय क्रांतिकारी सेनानी, वकील और पत्रकार, जिन्होंने लंदन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। • 1904 में लंदन में प्रसिद्ध इंडिया हाउस की स्थापना की जो वीर सावरकर, मैडम कामा, सरदार सिंह राणा, वीवीएस अय्यर, लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और मदनलाल ढींगरा जैसे भारत के क्रांतिकारियों के लिए केंद्र बन गया - वे वीर सावरकर, वीवीएस अय्यर और इस अवधि के कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी के राजनीतिक गुरु थे। • उन्होंने 'भारतीय समाजशास्त्री' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जो क्रांतिकारी विचारों का वाहन बन गया। फरवरी 1905 में, उन्होंने भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। मासिक भारतीय समाजशास्त्री राष्ट्रवादी विचारों के लिए एक आउटलेट बन गया और भारतीय होम रूल सोसाइटी के माध्यम से, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। • बाद में 1905 में, श्यामजी ने इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में होलबोर्न टाउन हॉल में आयोजित यूनाइटेड कांग्रेस ऑफ़ डेमोक्रेट्स में भाग लिया। • भारत पर उनके प्रस्ताव को पूरे सम्मेलन से उत्साहजनक प्रशंसा मिली। इंग्लैंड में श्यामजी की गतिविधियों ने ब्रिटिश सरकार की चिंता जगाई: • द इंडियन सोशियोलोजिस्ट में ब्रिटिश विरोधी लेख लिखने के कारण उन्हें इनर टेंपल से निकाल दिया गया और 30 अप्रैल 1909 को सदस्यता सूची से हटा दिया गया। • अधिकांश ब्रिटिश प्रेस श्यामजी विरोधी थे और उन्होंने उन पर तथा उनके अखबार के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए। उन्होंने साहसपूर्वक उनका बचाव किया। • द टाइम्स ने उन्हें "कुख्यात कृष्णवर्मा" के रूप में संदर्भित किया। कई समाचार पत्रों ने श्यामजी और उनके विचार का समर्थन करने वाले ब्रिटिश प्रगतिवादियों की आलोचना की। • उनकी गतिविधियों पर ब्रिटिश सीक्रेट सर्विसेज की नजर थी, इसलिए उन्होंने वीर सावरकर के प्रभारी इंडिया हाउस को छोड़कर अपना मुख्यालय पेरिस स्थानांतरित करने का फैसला किया। सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करने से पहले श्यामजी ने गुप्त रूप से ब्रिटेन छोड़ दिया। • यह श्यामजी ही थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए अहिंसक तरीकों की वकालत की और इस उद्देश्य के लिए सबसे प्रभावी हथियार के रूप में औपनिवेशिक प्रशासन के साथ सहयोग वापस लेने की वकालत की। गांधीजी ने इस पर निर्माण किया और सत्याग्रह को अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए एक उपकरण के रूप में

	विकसित किया। • श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ जिले में क्रांतिकारी के पैतृक शहर मांडवी में श्यामजी कृष्ण वर्मा को एक स्मारक 'क्रांति तीर्थ' समर्पित किया।
राम वन गमन पर्यटन सर्किट	**संदर्भ:** छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने "राम वन गमन" पर्यटन सर्किट का हिस्सा पुनर्विकसित प्राचीन माता कौशल्या मंदिर का उद्घाटन किया। ● उन्होंने रायपुर जिले के चंद्रखुरी गांव में परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। चांदखुरी को भगवान राम का मायका माना जाता है। **राम वन गमन पर्यटन सर्किट के बारे में** ● राज्य सरकार 137.45 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। ● पर्यटकों को सर्किट की ओर आकर्षित करने के लिए नौ स्थलों का विकास किया जा रहा है, ● सर्किट उस मार्ग को कवर करेगा जो माना जाता है कि भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास के दौरान लिया था। ● सीतामढ़ी-हरचिका (कोरिया), रामगढ़ (अंबिकापुर), शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलोदा बाजार), चांदखुरी, राजिम (गरियाबंद), सिहावा-सप्तर्षि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर) और रामाराम (सुकमा) नौ स्थल हैं। **माता कौशल्या मंदिर के बारे में** ● माता कौशल्या मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान राम की माता कौशल्या को समर्पित है। ● यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो माता कौशल्या को समर्पित है। ● यह छत्तीसगढ़ में रायपुर से 27 किमी दूर चांदखुरी गांव में स्थित है। ● माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था।
अभिधम्म दिवस	**सुर्ख़ियों में:** अभिधम्म दिवस अभिधम्म दिवस (Abhidhamma Day) 20 अक्टूबर 2021 को मनाया जा रहा है। यह दिन बौद्ध भिक्षुओं और ननों के लिए तीन महीने की वर्षा वापसी - वर्षावास या वासा के अंत का प्रतीक है, जिसके दौरान वे विहार और मठ में एक स्थान पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। ● श्रीलंका के वास्काडुवा श्री सुबुद्धि राजविहार मंदिर से लाए जा रहे पवित्र बुद्ध अवशेष का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में होगा। ● इन अवशेषों को वास्तविक अवशेष (हड्डी के टुकड़े, राख, बुद्ध के गहनों के टुकड़े) के रूप में स्वीकार किया जाता है। ● अजंता फ्रेस्कोस की पेंटिंग, बौद्ध सूत्र सुलेख, वडनगर और गुजरात के अन्य स्थलों से खुदाई की गई बौद्ध कलाकृतियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। ● उत्तर प्रदेश राज्य में प्राचीन शहर कुशीनगर गौतम बुद्ध का अंतिम विश्राम स्थल है, जहां उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। यह प्राचीन काल से बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ● तीन महीने के लंबे वर्षा के बाद की अवधि जिसे भिक्षुओं और ननों द्वारा वर्षा के मौसम में विहार में रहने के रूप में मनाया जाता है संघ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, देने का समय है। बौद्ध लोग मंदिरों में दान लाते हैं विशेष रूप से भिक्षुओं और ननों के लिए नए वस्त्र।
आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ	**सुर्ख़ियों में:** अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 21 अक्टूबर तक और उसके बाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ● आजाद हिंद सरकार के अस्तित्व ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम को अधिक वैधता प्रदान की। प्रासंगिक रूप से, आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) की भूमिका स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को एक बहुत ही आवश्यक प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण रही है। ● **स्थापना:** 21 अक्टूबर, 1943 ● **गठित:** स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार, या, अधिक सरलता से, स्वतंत्र भारत (आजाद हिंद), 1943 में कब्जे

	वाले सिंगापुर में स्थापित एक भारतीय अस्थायी सरकार थी और इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, फासीवादी इटली और उनके सहयोगियों द्वारा समर्थित थी। • अर्ज़ी हुकुमत-ए-आज़ाद हिंद के रूप में जाना जाता है, इसे इंपीरियल जापान, नाजी जर्मनी, इतालवी सामाजिक गणराज्य और उनके सहयोगियों की धुरी शक्तियों द्वारा समर्थित किया गया था। **फौज के गठन की ओर ले जाने वाली घटनाएँ:** • द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास आजाद हिंद फौज का गठन और गतिविधियां थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA के रूप में भी जाना जाता है। • रास बिहारी बोस (सर्वोच्च सलाहकार), एक भारतीय क्रांतिकारी जो भारत से भाग कर कई वर्षों से जापान में रह रहे थे, उसने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले भारतीयों के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। • जब जापान ने ब्रिटिश सेनाओं को हराया और दक्षिण-पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया, तो लीग ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के उद्देश्य से युद्ध के भारतीय कैदियों में से भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। • एशिया में जापान के युद्ध में अपनी भूमिका को लेकर INA नेतृत्व (मोहन सिंह) और जापानी सेना के बीच मतभेदों के बाद उस वर्ष दिसंबर में यह पहला INA ढह गया और भंग कर दिया गया। 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया में उनके आगमन के बाद सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसे पुनर्जीवित किया गया था।

IAS BABA

TLP Connect 2022

Integrated Prelims & Mains Test Series cum Mentorship Program

- **Comprehensive Program** (Prelims +Mains+ Interview)
- **1:1 Mentorship**
- **30 Mains Tests** (14 Sectional + 6 Essay + 10 FLT's)
- **Detailed Synopsis Along With Strategy Classes**
- **50 Prelims Tests** (40 GS + 10 CSAT)
- **Discussion Classes /Videos after Test**
- **Babapedia** (Prelimspedia + Mainspedia)

Toppers Recommended

Available Online and Offline (Delhi, BANGALORE and Lucknow)

REGISTER NOW

Scan here to know more

नासा का लुसी मिशन बृहस्पति के रहस्यमय ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की जांच करेगा	**संदर्भ :** नासा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के गठन में नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजने के लिए तैयार है। • ज्ञातव्य हो कि ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का एक ऐसा बड़ा समूह है जो सूर्य के चारों और बृहस्पति ग्रह की कक्षा साझा करते हुए परिक्रमा करते हैं। **अन्य सम्बंधित तथ्य** • मानव प्रजातियों के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले एक प्राचीन जीवाश्म के बाद लुसी नामक जांच, 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च होगी। • **मिशन:** इसका मिशन दो झुंडों में सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी पिंडों के समूह की जांच करना है, एक बृहस्पति से पहले उसके कक्षीय पथ में और दूसरा उसके पीछे पीछे। • पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से वृद्धि प्राप्त करने के बाद, लुसी आठ अलग-अलग क्षुद्रग्रहों के लिए 12 साल की यात्रा शुरू करेगी - एक मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में और फिर सात ट्रोजन। • ट्रोजन अंतरिक्ष के बहुत छोटे क्षेत्र में हैं, वे शारीरिक रूप से एक दूसरे से बहुत अलग हैं। "उदाहरण के लिए, उनके पास बहुत अलग रंग हैं, कुछ ग्रे हैं, कुछ लाल हैं," अंतर यह इंगित करते हैं कि वे अपने वर्तमान प्रक्षेपवक्र को संभालने से पहले सूर्य से कितनी दूर बने होंगे। • ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की संख्या कुल 7,000 से अधिक है। • यह सूर्य से इतनी दूर उद्यम करने वाला पहला सौर-संचालित अंतरिक्ष यान होगा, और इससे पहले किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान की तुलना में अधिक क्षुद्रग्रहों का निरीक्षण करेगा। 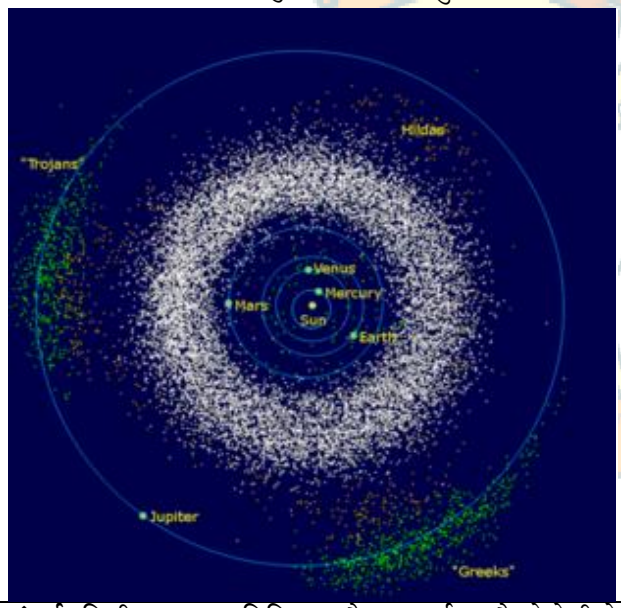
डिजी सक्षम का शुभारंभ	**संदर्भ:** डिजी सक्षम एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है जो तेजी से प्रौद्योगिकी संचालित युग में आवश्यक डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए है। • माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ यह संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को समर्थन देने के लिए सरकार के चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार है। • डिजी सक्षम पहल के माध्यम से, प्रथम वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ-साथ अग्रिम कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। • मूल रूप से तीन प्रकार के प्रशिक्षण होंगे अर्थात-डिजिटल कौशल - स्व गति से सीखने, VILT मोड प्रशिक्षण (वर्चुअल इंस्ट्रक्टर के नेतृत्व में) और ILT मोड प्रशिक्षण (प्रशिक्षक के नेतृत्व में)।
मधुमेह (डायबिटीज)	**प्रसंग :** भारत से टाइप 1 मधुमेह (T1D) के लंबे समय तक जीवित बचे लोगों की अपनी तरह की पहली रिपोर्ट, एक बहु-केंद्रित अध्ययन सहकर्मी की समीक्षा की गई पत्रिका मधुमेह प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान में प्रकाशित किया गया था। **मधुमेह क्या है?** • जब हमारे शरीर में पैक्रियाज (अग्नाश्य) इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कम कर देता है या बंद कर देता है तब हमारे

	ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। अगर इस स्तर को कंट्रोल ना किया जाए तो हम शुगर के रोगी बन जाते हैं। • **टाइप-1 डायबिटीज :** यह ज्यादातर 14-16 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। यह तब होती है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में विफल रहती है। जिंदा रहने के लिए उन्हें रोजाना कृत्रिम इंसुलिन लेना चाहिए। • **टाइप-2 डायबिटीज:** इसका एक कारण शरीर में इंसुलिन कम बनना भी होता है। ऐसा कुछ शारीरिक कारणों या गलत खान-पान के कारण भी हो सकता है। 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या इससे सबसे अधिक प्रभावित है। • यह डायबिटीज का सबसे आम प्रकार है और इसका मोटापे से ज्यादा संबंध है। • डायबिटीज पांच प्रमुख अंगों - किडनी, हृदय, रक्त वाहिकाओं, तंत्रिका तंत्र और आंखों (रेटिना) को प्रभावित करती है। • **प्रमुख कारक :** Unhealthy diet, शारीरिक गतिविधि की कमी, शराब का हानिकारक उपयोग, अधिक वजन/मोटापा, तंबाकू का उपयोग आदि। **क्या आप जानते हैं?** • T1D वाले व्यक्तियों में मधुमेह के बिना लोगों की तुलना में रुग्णता और अधिक समय से पहले मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। • जीवन रक्षक इंसुलिन की सहायता से भी उनकी जीवन प्रत्याशा अनुमानित 15-20 वर्ष कम हो जाती है। • 9वें इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस (Atlas) के अनुसार, भारत में T1D वाले 95,000 से अधिक बच्चे हैं, जिन्हें विश्व में सबसे ज्यादा बताया गया है।
मेनिन्जाइटिस शोथ	**सन्दर्भ :** विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मेनिन्जाइटिस को समाप्त करने के लिये पहली वैश्विक रणनीति- ''वर्ष 2030 तक मेनिन्जाइटिस को हराने के लिये वैश्विक रोडमैप'' (Global Roadmap to Defeat Meningitis by 2030) जारी किया गया है। • मैनिंजाइटिस को समाप्त करने के लिये यह अब तक की पहली वैश्विक रणनीति है। • बैक्टीरियल मेनिन्जाइटिस (Bacterial Meningitis) महामारी को समाप्त करना। वैक्सीन-प्रेवेंटेबल बैक्टीरियल मेनिन्जाइटिस (Vaccine-Preventable Bacterial Meningitis) के मामलों में 50% और मौतों में 70% की कमी लाना। • **महत्व:** यह रणनीति सालाना 200,000 से अधिक लोगों की जान बचा सकती है और बीमारी के कारण होने वाली विकलांगता को काफी कम कर सकती है। **मेनिन्जाइटिस के बारे में** • मेनिन्जाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों की सूजन (सूजन) है। • यह मुख्य रूप से बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण के कारण होता है। • जीवाणु संक्रमण के कारण होने वाला मेनिन्जाइटिस एक वर्ष में लगभग 2,50,000 मौतों का कारण बनता है जो तेज़ी से फैलने वाली महामारी का रूप ले सकती है। • इससे प्रभावित प्रत्येक दस में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और प्रत्येक पाँचवाँ व्यक्ति दृष्टि हानि, तंत्रिका संबंधी क्षति, संज्ञानात्मक हानि जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है।

	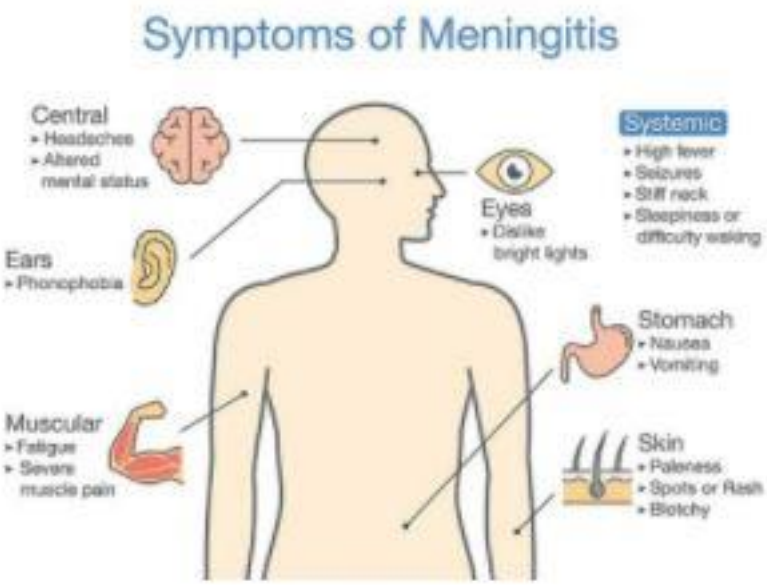
विक्रांत दूसरे चरण के परीक्षणों के लिए रवाना होंगे	**प्रसंग :** स्वदेशी विमानवाहक पोत (IAC) विक्रांत के पहले समुद्री परीक्षणों में बहुत अच्छी प्रगति हुई है और दूसरे चरण के परीक्षण अक्टूबर के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है, तीसरे चरण की योजना दिसंबर में है। • विक्रांत को अप्रैल में नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है और अगस्त 2022 में चालू होने की संभावना है। **विक्रांत के बारे में** • विक्रांत भारत का सबसे जटिल युद्धपोत (विमान वाहक) है जिसे भारतीय नौसेना के लिए कोचीन शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। • कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा शिपयार्ड और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एकमात्र शिपयार्ड है। • विक्रांत में 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। • यह देश में पहली बार है कि किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के आकार का जहाज पूरी तरह से 3डी में तैयार किया गया है और 3डी मॉडल से प्रोडक्शन ड्रॉइंग निकाला गया है। • IACदेश का सबसे बड़ा युद्धपोत है जिसका विस्थापन लगभग 40,000 टन है। • एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटा तैरता हुआ शहर है, जिसमें दो फ़ुटबॉल मैदानों के आकार को कवर करने वाला फ़्लाइट डेक क्षेत्र है। • नौसेना के सेवामुक्त प्रथम वाहक के नाम पर पोत का नाम विक्रांत रखा गया है। • इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक होगा, जिसमें स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों के अलावा मिग-29के लड़ाकू जेट, कामोव-31 हवाई पूर्व चेतावनी वाले हेलीकॉप्टर और जल्द ही शामिल किए जाने वाले MH-60R बहु-भूमिका हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। • जहाज से चलने वाले हथियारों में बराक LR SAM और AK-630 शामिल हैं, जबकि इसमें सेंसर के रूप में MFSTAR और RAN-40L 3D रडार हैं। • वर्तमान में, भारत के पास केवल एक रूसी मूल का आईएनएस विक्रमादित्य विमानवाहक पोत है। **महत्व** • विमानवाहक पोत की युद्धक क्षमता, पहुंच और बहुमुखी प्रतिभा रक्षा में जबरदस्त क्षमताएं जोड़ेगी और समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों को सुरक्षित रखने में मदद करेगी। • यह लंबी दूरी पर वायु शक्ति को प्रक्षेपित करने की क्षमता के साथ एक अतुलनीय सैन्य उपकरण की पेशकश करेगा।
तापमान और स्पर्श पर काम के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार	**संदर्भ :** अमेरिकी वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और आर्डम पातापुतियन को तापमान और स्पर्श के लिए 'रिसेप्टर' की खोज के लिए यह सम्मान दिया गया है। • अभूतपूर्व खोजों ने हमें यह समझने की अनुमति दी है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को शुरू कर सकते हैं जो हमें दुनिया को देखने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। • इस जोड़ी के शोध का उपयोग पुराने दर्द सहित बीमारियों और स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपचार

	विकसित करने के लिए किया जा रहा है। **क्या आप जानते हैं?** ● मिस्टर जूलियस (65) ने तंत्रिका सेंसर की पहचान करने के लिए मिर्च के घटक कैप्साइसिन का इस्तेमाल किया, तंत्रिका सेंसर से त्वचा पर तापमान की प्रतिक्रिया होती है।
एक्स मिलन: भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास	**प्रसंग :** भारत अगले साल की शुरुआत में अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास, एक्स मिलन (Ex Milan) की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसके लिए 46 देशों को आमंत्रित किया गया है। ● इस अभ्यास में सभी क्वाड देशों (Quad countries) की भागीदारी दिखाई देगी, जिसमें यू.एस. को पहली बार आमंत्रित किया जाएगा। ● मिलन, जो 1995 में शुरू हुआ, द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इस क्षेत्र के सभी देशों की नौसेनाओं को एक साथ लाता है। यह अब तक पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया है लेकिन अब इसे विशाखापत्तनम में स्थानांतरित किया जा रहा है जो अधिक स्थान और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। ● आमंत्रित लोगों में हिंद महासागर के सभी तटवर्ती राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के देश शामिल हैं।
आई-ड्रोन (i-Drone)	**सुर्ख़ियों में:** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल 'आई-ड्रोन (I-Drone)' लॉन्च किया। आई-ड्रोन को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research - ICMR) द्वारा विकसित किया गया है। आई-ड्रोन का मतलब आईसीएमआर का ड्रोन रिस्पांस और नॉर्थ ईस्ट में आउटरीच (Drone Response and Outreach in North East) है। ● दक्षिण एशिया में पहली बार ड्रोन का कॉमर्शियल फ्लाइंग हुआ है, मणिपुर में बिश्नुपुर से करंग स्वास्थ्य केंद्र, लोकटक लेक, मणिपुर ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई गई। केवल 15 मिनट में ये दूरी तय की गई। इस दूरी में आमतौर पर 3-4 घंटे लगते हैं। ● यह सुनिश्चित करने के लिए एक डिलीवरी मॉडल है कि जीवन रक्षक टीके सभी तक पहुंचें। ● यह तकनीक स्वास्थ्य देखभाल वितरण, विशेष रूप से कठिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपूर्ति में चुनौतियों का समाधान करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ● यह स्वास्थ्य में 'अंत्योदय' के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है; देश के अंतिम व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाना।
आयुष्मान भारत संशोधित	**संदर्भ :** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज (HBP) मास्टर में बदलाव किए हैं। **स्वास्थ्य लाभ पैकेज (HBP 2.2)** ● कुछ पैकेजों की दरों में 20% से 400% की वृद्धि की गई है। ● लगभग 400 प्रक्रियाओं की दरों में संशोधन किया गया है। ● और ब्लैक फंगस से संबंधित एक नया अतिरिक्त चिकित्सा प्रबंधन पैकेज भी जोड़ा गया है। ● ऑन्कोलॉजी के लिए संशोधित पैकेज देश में कैंसर के रोगियों की देखभाल को और बेहतर बनाएगा। **लाभ:** युक्तिसंगत HBP निजी अस्पतालों में योजनाओं की गति में सुधार करेगा जिससे जेब खर्च में कमी आएगी। **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) क्या है?** ● PM-JAY को लागू करने के लिए NHA की स्थापना की गई है। ● मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ● इसे पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है। ● NHA केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी बोर्ड द्वारा शासित होता है। ● इसका नेतृत्व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) करता है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी है, जो इसके मामलों का प्रबंधन करता है। ● CEO गवर्निंग बोर्ड के पूर्व-कार्यालय सदस्य सचिव हैं। **आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के बारे में** ● यह योजना कुछ केंद्रीय क्षेत्र के घटकों के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ● PM-JAY माध्यमिक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल के लिए

	प्रति परिवार 5 लाख की बीमा राशि प्रदान करता है। लाभार्थियों के लिए यह नि:शुल्क योजना है। ● यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति। ● जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है। ● बीमा लागत केंद्र और राज्य द्वारा ज्यादातर 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है। 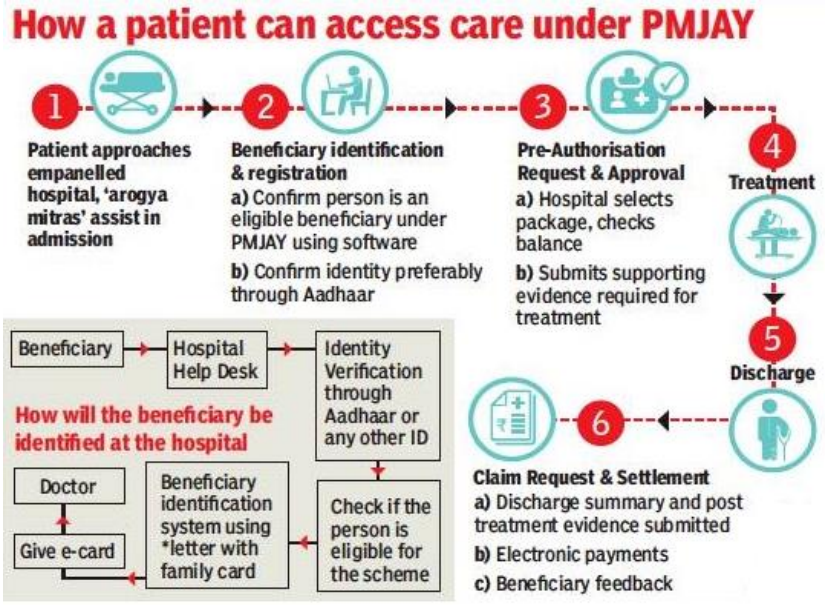
इंटरपोल ने ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया	**संदर्भ :** हाल ही में, इंटरपोल (Interpol) द्वारा साइबर अपराधियों से अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करने में मदद करने हेतु लोगों को प्रमुख साइबर-खतरों से अवगत कराने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। ● तीन सप्ताह का अभियान, 4 से 22 अक्टूबर तक, मुख्य रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जाएगा। **इंटरपोल क्या है?** ● 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन' (International Criminal Police Organisation– Interpol) अथवा 'इंटरपोल', 194 सदस्यीय अंतरसरकारी संगठन है। ● प्रत्येक सदस्य देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) की मेजबानी करता है। ● केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। ● इसका मुख्यालय फ्राँस के 'लियोन' (Lyon) शहर में है। ● भारत वर्ष 1949 में इस संगठन में शामिल हुआ था और इसके सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। ● इसकी स्थापना वर्ष 1923 में 'अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग' के रूप में की गई थी, और वर्ष 1956 से इसे 'इंटरपोल' कहा जाने लगा।
भौतिकी नोबेल पुरस्कार 2021	**संदर्भ :** यू.एस.-जापानी वैज्ञानिक स्यूकुरो मानेबे (Syukuro Manabe), जर्मनी के क्लॉस हासेलमैन (Klaus Hasselmann) और इटली के जियोर्जियो पेरिस (Giorgio Parisi) ने जटिल भौतिक प्रणालियों की समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए भौतिकी

	में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता। **वैज्ञानिकों का सराहनीय कार्य** ● 1960 के दशक में डॉ मनबे ने दिखाया कि कैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि के अनुरूप है। ○ वह पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलों को विकसित करने में प्रभावशाली थे और उन्होंने इस बात पर काम किया कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली उष्ण ऊर्जा (heat energy) वापस वायुमंडल में कैसे पहुंचती है। ● डॉ. हैसलमैन को यह पता लगाने का श्रेय दिया जाता है कि कैसे मौसम के रुझान में कभी-कभी अराजक बदलाव के बावजूद जलवायु मॉडल विश्वसनीय बने रह सकते हैं। ○ समिति ने प्राकृतिक और मानवीय दोनों गतिविधियों के कारण जलवायु "उंगलियों के निशान" की उनकी पहचान की प्रशंसा की और मानव निर्मित उत्सर्जन के लिए जलवायु परिवर्तन को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ● डॉ. पेरिसी को 1980 के दशक में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया था, उन्हें यह पुरस्कार 'एटॉमिक स्केल से लेकर प्लेनेटरी स्केल तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार-चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज' हेतु दिया गया है। ○ उन्होंने 'एक जटिल भौतिक और गणितीय मॉडल विकसित किया है, जिसने गणित, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस तथा मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में जटिल प्रणालियों को समझना संभव बना दिया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की सिफारिश की	**संदर्भ :** विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले मलेरिया रोधी टीके की अनुमतिदी है। ● डब्ल्यूएचओ ने उप-सहारा अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में बच्चों को मलेरिया रोधी टीका दिए जाने की सिफारिश किया। **अन्य सम्बंधित तथ्य** ● तीन अफ्रीकी देशों में एक सफल पायलट कार्यक्रम के बाद RTS, S वैक्सीन को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। ● RTS,S वैक्सीन, जिसे Mosquirix के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश दवा कंपनी GlaxoSmithKline (GSK) द्वारा विकसित किया गया था, और 2019 में पायलट कार्यक्रम शुरू होने के बाद से घाना, केन्या और मलावी में 800,000 से अधिक बच्चों को प्रशासित किया गया है। ● एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि जब छोटे बच्चों को RTS, S और मलेरिया-रोधी दोनों दवाएं दी गईं तो अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु में 70% की कमी आई। **मलेरिया के बारे में** ● मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लास्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ● यह मुख्य रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलते हैं। ● ये 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं। इनमें से 2 प्रजातियां - प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लास्मोडियम वाइवैक्स - सबसे बड़ा खतरा हैं। ● **लक्षण:** बुखार और फ्लू जैसी बीमारी, जिसमें कंपकंपी ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है। ● यह रोकथाम योग्य होने के साथ-साथ इलाज योग्य भी है। ● यह रोग प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों के संक्रमण का कारण बनता है, जीवन और आजीविका को खतरे में डालता है। **भारत की स्थिति** ● भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने 2018 की तुलना में 2019 में 17.6% की गिरावट दर्ज की है। ● मलेरिया उन्मूलन के लिए भारत की राष्ट्रीय रणनीतिक योजना ने मलेरिया नियंत्रण से हटाकर उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया और 2022 तक भारत के 678 जिलों में से 571 जिलों में मलेरिया को समाप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रदान किया। ● भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने हाल ही में 'मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-भारत)' की स्थापना की है जो मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों का एक समूह है।
रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार	**संदर्भ :** जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका स्थित डेविड मैकमिलन ने अणुओं के निर्माण के लिए एक उपकरण विकसित करने के लिए नोबेल रसायन पुरस्कार जीता जिसने रसायन विज्ञान को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद की है। **अन्य सम्बंधित तथ्य**

2021 की घोषणा	● वर्ष 2000 में उन्होंने एक-दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कटैलिसीस (catalysis) का विकास किया। इसे असममित ऑर्गेनोकैटलिसिस कहा जाता है और ये छोटे कार्बनिक अणुओं से बनते हैं। ● अपने काम से पहले, वैज्ञानिकों का मानना था कि उत्प्रेरक केवल दो प्रकार के होते हैं - धातु और एंजाइम। ○ उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ हैं जो अंतिम उत्पाद का हिस्सा बने बिना रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित और तेज करते हैं। ● इसका व्यापक रूप से फार्मास्यूटिकल्स में उपयोग किया जाता है, जिससे दवा निर्माताओं को अवसाद और श्वसन संक्रमण के लिए दवाओं के उत्पादन को कारगर बनाने की अनुमति मिलती है। ● ऑर्गेनोकैटलिसिस एक उत्पादन प्रक्रिया में कई चरणों को एक अखंड अनुक्रम में निष्पादित करने की अनुमति देते हैं, रासायनिक निर्माण में कचरे को काफी कम करते हैं।
हरा-भरा अभियान	**संदर्भ :** हाल ही में तेलंगाना सरकार ने 'हारा भरा' नाम से ड्रोन आधारित वनीकरण परियोजना शुरू की है। **अभियान के बारे में** ● अभिनेता राणा दग्गुबाती इस परियोजना के ब्रांड एंबेसडर हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से हैदराबाद के केबीआर पार्क में सीडकॉप्टर ड्रोन द्वारा भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान शुरू किया। ● एरियल सीडिंग, रोपण की एक तकनीक है जिसमें बीजों को मिट्टी, खाद, चारकोल और अन्य घटकों के मिश्रण में लपेटकर एक गेंद का आकार दिया जाता है, इसके बाद हवाई उपकरणों जैसे- विमानों, हेलीकाप्टरों या ड्रोन आदि का उपयोग करके इन गेंदों को लक्षित क्षेत्रों में फेंका जाता है/छिड़काव किया जाता है। ● पर्याप्त बारिश होने पर ये बीज अंकुरित होते हैं, इनमें मौजूद पोषक तत्त्व इनकी प्रारंभिक वृद्धि में मदद करते हैं। ● राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार विभाग और वन विभाग ने भारत में अपनी तरह की इस पहली परियोजना के लिए हैदराबाद स्थित ड्रोन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मारुत ड्रोन के साथ भागीदारी की है। ● यह परियोजना ड्रोन का उपयोग करके पतली, बंजर और खाली वन भूमि पर बीज के गोले को पेड़ों के हरे भरे निवास में बदलने के लिए तितर-बितर करती है। ● ड्रोन द्वारा तेजी से वनरोपण के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में जंगलों में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में 50 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। ● इस अभियान से 'हरित हरम' कार्यक्रम के तहत हरित तेलंगाना के मिशन में तेजी आने की उम्मीद है। पारिस्थितिकी तंत्र को समझने और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और इलाके के मानचित्रण के साथ प्रक्रिया शुरू होती है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)	**सुर्ख़ियों में:** प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) ने सरकार द्वारा दिए गए डेडलाइन से पहले ही 8,300 जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendras) खोलने का लक्ष्य पूरा कर लिया है, इस प्रकार वित्त वर्ष 2021-22 के लक्ष्य को केवल 6 महीनों में प्राप्त कर लिया है। ● देश के सभी जिलों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत कवर किया गया है। ● सभी दुकानों पर दवाओं का वास्तविक समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी IT-सक्षम रसद और आपूर्ति-श्रृंखला प्रणाली भी शुरू की गई है। ● PMBJP के उत्पाद समूह में वर्तमान में 1,451 दवाएं और 240 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, ग्लूकोमीटर, प्रोटीन पाउडर, माल्ट आधारित खाद्य पूरक, प्रोटीन बार, इम्युनिटी बार आदि जैसी नई दवाएं और न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)** ● यह औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है ● **विजन:** "सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं" प्रदान करके भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य देखभाल बजट को कम करना। ● प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र योजना के अंतर्गत खोला गया एक मेडिकल आउटलेट है जो सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराता है। ● जनऔषधि सुगम प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो

	जनता को अपनी उंगलियों की नोक पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके सुविधा प्रदान करता है।
भारतीय सेना यूके के साथ अभ्यास करेगी	**संदर्भ:** भारत के सशस्त्र बल इस महीने (अक्टूबर) के अंत में यूके के क्वीन एलिजाबेथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ एक अभ्यास करने वाले हैं। ● प्रशिक्षण के भाग के रूप में, दोनों सेनाएं संयुक्त सैन्य अभियानों को अंजाम देने के लिए एक-दूसरे के हथियारों, उपकरणों, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित होंगी। **भारत और ब्रिटेन के बीच अन्य घटनाक्रम** ● यह भारत-U.K. की दूसरी बैठक होगी। साइबर क्षमता निर्माण पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) हाल ही में वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। ● सेना ने यह भी कहा कि भारत-U.K. संयुक्त कंपनी-स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण, अभ्यास अजय योद्धा (Exercise Ajeya Warrior), उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ था और 20 अक्टूबर को समाप्त होगा। ● भारत और U.K. एक द्विपक्षीय लोजिस्टिक्स सहायता समझौते के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। **क्या आप जानते हैं?** ● जुलाई में, भारत और यूके ने बंगाल की खाड़ी में रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप (CSG-21) के साथ दो दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज अभ्यास (PASSEX) में भाग लिया, जिसका नेतृत्व HMS क्वीन एलिजाबेथ ने बंगाल की खाड़ी में किया था।
पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली: भारत, क्रोएशिया सहयोग करेंगे	**सुर्ख़ियों में:** भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अकादमिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करते हुए, विशेष रूप से आयुर्वेद के क्षेत्र में, दोनों देशों के बीच, आयुष मंत्रालय ने क्रोएशिया के साथ एक समझौता किया है। ● दोनों पक्ष पहचान किए गए संस्थानों के सहयोग से आयुर्वेद के क्षेत्र में अकादमिक गतिविधियां शुरू करेंगे। ● अनुसंधान पर घनिष्ठ सहयोग और सहयोग होगा, जिसमें अध्ययन डिजाइन और निष्पादन, आयुर्वेदिक सिद्धांतों और प्रथाओं को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने के लिए साक्ष्य-आधारित दिशानिर्देश विकसित करना, व्याख्यान, कार्यशालाएं, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना तथा आयुर्वेद पर ऐसी अन्य गतिविधियां शामिल हैं। ● दोनों पक्ष संस्थान, अंतिम उपयोगकर्ताओं और हितधारकों की जरूरतों के अनुसार शैक्षणिक मानकों और पाठ्यक्रमों का विकास करेंगे तथा क्रोएशिया में आयुर्वेद शिक्षा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा दिशानिर्देश विकसित करेंगे। ● यह अकादमिक अनुसंधान, क्लीनिकल और शैक्षिक गतिविधियों, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और योग्यता निर्माण को बढ़ावा देगा।
आर्यभट्ट पुरस्कार	**सुर्ख़ियों में:** सचिव DDR & D और अध्यक्ष DRDO, डॉ जी सतीश रेड्डी को सम्मानित किया गया। ● उन्नत वैमानिकी, नौवहन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी। ● डॉ रेड्डी एक संस्था निर्माता हैं और उन्होंने मजबूत रक्षा विकास तथा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए तंत्र स्थापित किया है।
भारतीय अंतरिक्ष संघ	**सुर्ख़ियों में:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर, 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA) का शुभारंभ करेंगे। ● ISpA अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनने की आकांक्षा रखता है। ● यह नीति की हिमायत करेगा और सरकार तथा इसकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी हितधारकों के साथ जुड़ेगा। ● ISpA भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी प्लेयर बनाने में मदद करेगा। ● SpA का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताओं वाले प्रमुख घरेलू और वैश्विक निगमों द्वारा किया जाता है।
वन हेल्थ कंसोर्टियम (One Health Consortium)	**संदर्भ :** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने 'वन हेल्थ' पर एक मेगा कंसोर्टियम का समर्थन किया और DBT की पहली 'वन हेल्थ' परियोजना शुरू की। **महत्वपूर्ण तथ्य** ● इस संघ में DBT-राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद के नेतृत्व में 27 संगठन शामिल हैं। ● यह COVID के बाद के समय में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है।

	• इस कार्यक्रम में भारत में जूनोटिक के साथ-साथ सीमापार रोगजनकों के महत्वपूर्ण जीवाणु, वायरल और परजीवी संक्रमणों की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है। • मौजूदा क्लीनिकल परीक्षणों का उपयोग और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पद्धतियों का विकास निगरानी और उभरती बीमारियों के प्रसार को समझने के लिए अनिवार्य है।
यूफिल (UFill)	**संदर्भ:** भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) - पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम ने "UFill" लॉन्च करने की घोषणा की है। • यह एक डिजिटल ग्राहक अनुभव है जो यह सुनिश्चित करता है कि उनके ग्राहकों का ईंधन भरने के अनुभव के हिस्से के रूप में समय, प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता पर पूर्ण नियंत्रण है। **अन्य संबंधित तथ्य** • UFill प्रस्ताव को देशभर के 65 शहरों में लॉन्च किया गया है और जल्द ही इसे पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। • प्रौद्योगिकी ग्राहक को ईंधन के नियंत्रण के साथ-साथ स्पर्श रहित पूर्व-भुगतान समाधान प्रदान करती है। • वितरण इकाई को उसके द्वारा अग्रिम रूप से भुगतान किए गए ईंधन के मूल्य के लिए स्वचालित रूप से पूर्व निर्धारित किया जा सकता है और बिक्री के बिंदु पर किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप को समाप्त कर सकता है।
व्यायाम युद्ध अभ्यास 2021	**संदर्भ:** भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास "पूर्व युद्ध अभ्यास 2021" का 17 वां संस्करण, संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का के संयुक्त बेस एल्मेंडॉर्फ रिचर्डसन में 15 से 29 अक्टूबर, 2021 तक होने वाला है। • युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा चल रहा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है। • यह संयुक्त अभ्यास का 17वां संस्करण होगा जो दोनों देशों के बीच बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। • इस अभ्यास का पिछला संस्करण फरवरी 2021 में राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था।
1000 मेगावाट घंटे की परियोजना के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)	**सुर्ख़ियों में:** सरकार 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) की स्थापना करेगी। इसके लिए टेंडर मांगा गया है। यह भंडारण सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्युअल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy) व मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर (ministry of Power) के संयुक्त प्रयास से स्थापित किया जाएगा। दोनों मंत्रालय इसके रोडमैप पर काम कर रहे हैं। • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का टारगेट फिक्स किया है। इससे ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र आदि) की स्थापना में काफी मदद मिलेगी। • संतुलन सेवाओं और लचीले संचालन के लिए एक परिसंपत्ति के रूप में भंडारण। • सिस्टम ऑपरेटर यानी लोड डिस्पैचर्स (RLDCs और SLDCs) अन-जेनरेशन के कारण लोड में अंतर्निहित अनिश्चितता/भिन्नताओं को प्रबंधित करने के लिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और बैलेंसिंग सेवाओं के लिए स्टोरेज सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। • वितरण प्रणाली के लिए भंडारण यानी इसे अपने भार और अन्य दायित्वों के प्रबंधन के लिए लोड सेंटर पर रखा जा सकता है। • ऊर्जा भंडारण प्रणाली डेवलपर द्वारा एक व्यापारी क्षमता के रूप में पॉवर मार्किट में बेचते हैं। • उपरोक्त के संयोजन के रूप में भविष्य का कोई अन्य व्यावसायिक मॉडल।
2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट: WHO	**संदर्भ :** हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार, एक दशक से अधिक समय में पहली बार वैश्विक स्तर पर तपेदिक (TB) से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। • WHO मॉडलिंग अनुमानों से पता चलता है कि 2021-2022 में टीबी विकसित करने वाले और बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष** • **कम की गई सूचनाएं:** भारत (41%) उन शीर्ष देशों में शामिल था, जिन्होंने 2019- 2020 के बीच टीबी अधिसूचनाओं में वैश्विक कमी में सबसे अधिक योगदान दिया, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। • भारत, इंडोनेशिया (14%), फिलीपींस (12%), चीन (8%) और 12 अन्य देशों के साथ, अधिसूचनाओं में कुल

	वैश्विक गिरावट का 93% हिस्सा है। ● **मामलों में वृद्धि:** डब्ल्यूएचओ ने अनुमान लगाया कि वर्तमान में लगभग 4.1 मिलियन लोग टीबी से पीड़ित हैं, लेकिन इसका निदान नहीं किया गया था या आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई थी। यह आंकड़ा 2019 में 2.9 मिलियन से ऊपर है। ● **प्रावधान कम किया गया:** टीबी की रोकथाम के लिये उपचार पाने वाले लोगों की संख्या में भी कमी आई है। वर्ष 2020 में 28 लाख लोगों में बीमारी की रोकथाम के लिये उपचार हुआ, जो कि 2019 से 21 फ़ीसदी की गिरावट है। ● **ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी:** ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी के इलाज वाले लोगों की संख्या में 15% की गिरावट आई है। ● **बढ़ी हुई मौतें:** 2020 में टीबी से ज्यादा लोगों की मौत हुई। **मौतों में वृद्धि के कारण:** ● टीबी से निपटने से लेकर COVID-19 तक मानव, वित्तीय और अन्य संसाधनों का पुन: आवंटन, आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को सीमित करना। ● लोग लॉकडाउन के दौरान देखभाल करने के लिए संघर्ष करते रहे। **क्षय रोग (टीबी) क्या है?** ● टीबी बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होता है जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है। ● **संचरण:** टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब टीबी से पीड़ित लोग खांसते, छींकते या थूकते हैं, तो वे टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देते हैं। ● **लक्षण:** कभी-कभी बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात को पसीना आना। ● टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। ● मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB) बैक्टीरिया के कारण होने वाली टीबी का एक रूप है जो आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन, 2 सबसे शक्तिशाली, प्रथम-पंक्ति एंटी-टीबी दवाओं का जवाब न दें। यह दूसरी पंक्ति की दवाओं का उपयोग करके उपचार और इलाज योग्य है। ● व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी (XDR-TB) MDR-TB का एक अधिक गंभीर रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है जो सबसे प्रभावी दूसरी-पंक्ति एंटी-टीबी दवाओं का जवाब नहीं देते हैं, अक्सर रोगियों को बिना किसी और उपचार के विकल्प के छोड़ देते हैं। ● **2025 तक टीबी का उन्मूलन:** भारत 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले, 2025 तक तपेदिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। ● **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम:** महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए, कार्यक्रम का नाम संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) से बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) कर दिया गया है।
सुपारी (Arecanut)	**संदर्भ :** एक किताब जिसका शीर्षक है सुपारी, जिसमें कहा गया है कि सुपारी का एक प्रमुख सक्रिय सिद्धांत, ऐकोलिन हाइड्रोब्रोमाइड, कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए पाया जाता है। ● इस पुस्तक ने इसे यू.एस. अटलांटा के एमोरी विश्वविद्यालय के विनशिप कैंसर संस्थान में हाल ही में किए गए एक अध्ययन से उद्धृत किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● विनशिप कैंसर संस्थान में हाल के एक अध्ययन में, कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए एस्कोलीन हाइड्रोब्रोमाइड पाया गया है। ● यह बताया गया था कि ऐकोलिन हाइड्रोब्रोमाइड एंजाइम ACAT1 (एसिटाइल-सी0ए एसिटाइलट्रांसफेरेज़) की गतिविधि को रोकता है जिससे कैंसर कोशिका प्रसार और चूहों में ट्यूमर के विकास में कमी आती है। ● सुपारी की एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि कैंसर कोशिकाओं में डीएनए क्षति की मरम्मत में सक्रिय भूमिका निभाती है। ● पुस्तक के अनुसार, सुपारी अपने शुद्ध रूप में खतरनाक नहीं है, लेकिन इसमें अल्सर, घाव और यहां तक कि कैंसर को ठीक करने सहित औषधीय गुणों की अधिकता है।

	सुपारी क्या है? ● सुपारी आम चबाने वाले अखरोट का स्रोत है, जिसे सुपारी के नाम से जाना जाता है। ● भारत में इसका व्यापक रूप से लोगों में उपयोग किया जाता है और यह धार्मिक प्रथाओं से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। ● भारत सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ● इस फसल की खेती करने वाले प्रमुख राज्य कर्नाटक (40%), केरल (25%), असम (20%), तमिलनाडु, मेघालय और पश्चिम बंगाल हैं। **क्या आप जानते हैं?** ● सुपारी को कथित तौर पर मानव स्वास्थ्य के दुष्प्रभावों से जोड़ा गया है। इसे कार्सिनोजेनिक (एक जो कैंसर का कारण बनता है) माना जाता है।
ई-संजीवनी	**सुर्खियों में:** केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत की अग्रणी टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 1.4 करोड़ परामर्श दर्ज किए। ● ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी और ई-संजीवनी ओपीडी जैसे दो रूपों में संचालित, इस पहल ने समय के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं देने में सक्षम होने के कारण अपार लोकप्रियता हासिल की है। **ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी, एक डॉक्टर-टू-डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन सिस्टम** ● स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करने के इरादे से शुरू किया गया। ● यह हब-एंड-स्पोक मॉडल (Hub-and-Spoke Model) पर काम करता है। ● राज्य स्तर पर स्थापित 'आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र' (HWCs) प्रवक्ता के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय स्तर पर हब (एमबीबीएस/स्पेशलिटी/सुपर-स्पेशलिटी डॉक्टरों सहित) के साथ मैप किया जाता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले रोगी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। **ई-संजीवनी ओपीडी** ● इसे 2021 में लॉन्च किया गया। ● सुरक्षित डॉक्टर-से-रोगी परामर्श प्रदान करने का लक्ष्य। ● इसकी मांग में वृद्धि जारी है क्योंकि यह नागरिकों को प्रतीक्षा समय, यात्रा, संक्रमण के जोखिम आदि को दरकिनार करते हुए आराम से अपने घरों में डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति देता है। **महत्व** ● जमीनी स्तर पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की कमी को दूर करना। ● माध्यमिक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों पर बोझ कम करना। ● देश के डिजिटल स्वास्थ्य ढांचे में लगातार सुधार करने का लक्ष्य।
पहली बार मानव शरीर में लगाया गया सूअर का गुर्दा	**संदर्भ :** अमेरिका में दुनिया में पहली बार सूअर की किडनी को इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया है। यह कारनामा न्यूयॉर्क शहर के एनवाईयू लैंगोन हेल्थ मेडिकल सेंटर के सर्जनों ने किया है। ● यह एक संभावित प्रमुख प्रगति है जो अंततः प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों की भारी कमी को दूर करने में मदद कर सकती है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● यह प्रक्रिया न्यूयॉर्क शहर में NYU लैंगोन हेल्थ में की गई थी। ● इसमें एक सुअर का उपयोग शामिल था जिसके जीन को बदल दिया गया था ताकि उसके ऊतकों में अब एक अणु न हो जो लगभग तत्काल अस्वीकृति को ट्रिगर करने के लिए जाना जाता है। ○ आनुवंशिक रूप से परिवर्तित सुअर, जिसे गैलसेफ कहा जाता है, को दाता के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ● प्राप्तकर्ता एक ब्रेन-डेड रोगी था जिसमें गुर्दे की शिथिलता के लक्षण थे, जिनके परिवार ने जीवन समर्थन से हटाए जाने से पहले प्रयोग के लिए सहमति दी थी। ● **खोज:** टीम ने सिद्धांत दिया कि अस्वीकृति को ट्रिगर करने वाले कार्बोहाइड्रेट के लिए सुअर के जीन को हटाने से - एक चीनी अणु, या ग्लाइकेन, जिसे अल्फा-गैल कहा जाता है इस समस्या को रोक देगा।

	• **भविष्य की संभावना:** NYU गुर्दा प्रत्यारोपण प्रयोग अंतिम चरण के गुर्दे की विफलता वाले रोगियों में परीक्षण के लिए संभवतः अगले एक या दो साल में मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
MES का वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल (WBPMP)	**संदर्भ:** हाल ही में, रक्षा मंत्री ने सैन्य अभियंता सेवाओं (MES) के लिए वेब आधारित परियोजना निगरानी पोर्टल (WBPMP) का शुभारंभ किया। **पोर्टल के बारे में** • इस पोर्टल की अवधारणा केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के अनुसार की गई थी। • इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-G) द्वारा विकसित किया गया है। • नए लॉन्च किये गए एकीकृत पोर्टल MES द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला यह पहला परियोजना प्रबंधन ई-गवर्नेंस है। • यह परियोजनाओं की स्थापना से लेकर पूरा होने तक की वास्तविक समय निगरानी में सक्षम होगा। • सभी हितधारक न केवल MES से बल्कि सशस्त्र बलों के उपयोगकर्ता भी परियोजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मास्टिटिस रोग	**संदर्भ:** गुजरात के एक किसान द्वारा साझा की गई स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों का उपयोग करते हुए, मास्टिटिस रोग के इलाज के लिए एक पॉली-हर्बल और लागत प्रभावी दवा विकसित की गई है। **मस्तिरक जेल का महत्व** • नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF) ने गुजरात के एक किसान द्वारा कृषि पशुओं में मास्टिटिस के नियंत्रण के लिए साझा की गई अनूठी हर्बल संरचना की पहचान की है। • प्रभावित थन सतह पर सामयिक अनुप्रयोग के लिए एक जेल की तैयारी विकसित की गई है, और इस संरचना के लिए एक पेटेंट दायर किया गया है यह पाया गया कि दवा थन स्वास्थ्य में सुधार करती है। • धारु पशुओं की संक्रमित दुग्ध ग्रंथियों की सतह पर इस जेल के अनुप्रयोग से उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है। • यह जेल थन के हानिकारक सूजन को कम करने में सहायक है। • यह एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के साथ ही कम लागत पर बीमारी के प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। • संक्रमित जानवरों का उपचार एंटीबायोटिक दवाओं से करना वर्तमान समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा बन गया है। • देश के आठ राज्यों - गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में डेयरी मालिकों ने मसिरक-विरोधी मास्टिटिस हर्बल दवा को अपनाकर लाभान्वित किया है। • इसने एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम किया है और बीमारी के लागत प्रभावी प्रबंधन में मदद की है। **मास्टिटिस रोग के बारे में** • मास्टिटिस या दुग्ध ग्रंथियों की सूजन दुनिया भर में डेयरी मवेशियों की सबसे आम और सबसे खर्चीली बीमारी है। • कई प्रकार के बैक्टीरिया अलग-अलग मास्टिटिस संक्रमण का कारण बनते हैं। • मास्टिटिस के इलाज में एंटीबायोटिक दवाएँ केवल नैदानिक उपचार प्रदान करती हैं लेकिन जीवाणु के संक्रमण को समाप्त नहीं कर सकती हैं। • क्लिनिकल मास्टिटिस के सबसे स्पष्ट लक्षण इसमें असामान्यताएं हैं: थन जैसे सूजन, गर्मी, कठोरता, लालिमा या दर्द। • दूध में पानी जैसा रूप, गुच्छे, थक्के या मवाद होता है।
अटल इनोवेशन मिशन डिजी-बुक इनोवेशन फॉर यू	**सुर्ख़ियों में:** नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने का प्रयास - "इनोवेशन फॉर यू" लॉन्च किया है। • इन स्टार्टअप ने नए, विघटनकारी और अभिनव उत्पादों, सेवाओं तथा समाधानों को बनाने के लिए काम किया है जो एक स्थायी भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। • इस पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित है - एनीमिया, मलेरिया, दंत चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, नवजात और बच्चे की देखभाल तथा मानव जीवन की निगरानी।
पिनाका और स्मर्च	**संदर्भ :** भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के नजदीक अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में पिनाका और स्मर्च

रॉकेट सिस्टम	लंबी दूरी की, मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के साथ-साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को तैनात किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● रूस से मिली स्मर्च, 90 किमी की अधिकतम सीमा के साथ सेना की सूची में सबसे लंबी दूरी की पारंपरिक रॉकेट प्रणाली है। ● रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा विकसित पिनाका की सीमा 38 किमी है। **ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के बारे में** ● द्वारा किया गया: ओडिशा के बालासोर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)। ● ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ-साथ कई अन्य 'मेड इन इंडिया' सब-सिस्टम हैं। ● ब्रह्मोस लैंड-अटैक क्रूज मिसाइल मच (Mach) 2.8 की शीर्ष गति से परिभ्रमण कर रही थी।
इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF)	**संदर्भ:** इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IIGF) इवेंट का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, NIXI तथा मल्टीस्टेकहोल्डर ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से 8 से 11 नवंबर, 2021 तक किया जाएगा। **अन्य संबंधित तथ्य** ● IIGF 2021 का विषय 'इंटरनेट की शक्ति के माध्यम से भारत को सशक्त बनाना' है। यह आयोजन भारत में डिजिटलीकरण की राह पर चर्चा का गवाह बनेगा। ● यह यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (UN-IGF) से जुड़ी एक पहल है। ● इसका गठन यूएन-आधारित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) के ट्यूनिस एजेंडा के IGF-पैराग्राफ 72 के अनुरूप किया गया है। ● यह एक बहु-हितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। ● एक खुली और समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से, IIGF सरकार उद्योग, नागरिक समाज, शिक्षा जगत सहित वैश्विक इंटरनेट गवर्नेंस पारिस्थितिकी तंत्र में सभी हितधारकों को एक साथ लाता है - बड़े इंटरनेट गवर्नेंस प्रवचन के समान प्रतिभागियों के रूप में।
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)	**संदर्भ:** 24 अक्टूबर, 2021 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने व्यापार को आसान बनाकर, निर्यात को सहारा प्रदान कर और रोजगार को बढ़ावा देकर भारतीय वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Amended Technology Up-gradation Fund Scheme: ATUFS) की समीक्षा की। **अन्य संबंधित तथ्य** ● कपड़ा मंत्रालय ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के रूप में 1999 में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (TUFS) शुरू की थी। **उद्देश्य:** ● भारतीय कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, ● व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, ● रोजगार पैदा करना और निर्यात को बढ़ावा देना। ● तब से, इस योजना को विभिन्न संस्करणों में लागू किया गया है। ● चल रहे ATUFS को 2016 में अनुमोदित किया गया है और वेब आधारित TUFS प्लेटफॉर्म के माध्यम से लागू किया गया। ● भौतिक सत्यापन के बाद वस्त्र उद्योग द्वारा स्थापित चिन्हित मशीनरी को पूंजी निवेश से संबंधित सब्सिडी प्रदान की जाती है। ● ATUFS को 2015-16 से 2021-22 की अवधि के लिए 17,822 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ अनुमोदित किया गया था। ● इस योजना को तकनीकी सलाहकार-सह-निगरानी समिति और अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा दो चरणों वाले निगरानी तंत्र के साथ प्रशासित किया जा रहा है।

	• 2018 में योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। • 2019 में, अंतर मंत्रालयी संचालन समिति ने योजना के पिछले संस्करणों के तहत प्रतिबद्ध देयता जारी करने से पहले मशीनरी का भौतिक सत्यापन और सब्सिडी की गणना शुरू करने का निर्णय लिया।
स्पंदित सफेद बौना (Pulsating White Dwarf)	**संदर्भ:** नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) का उपयोग करते हुए खगोलविदों की एक टीम ने पृथ्वी से लगभग 1,400 प्रकाश वर्ष दूर एक सफेद बौने में एक अनोखी घटना की सूचना दी। • उन्होंने देखा कि सफेद बौना 30 मिनट में अपनी चमक खो देता है। **सफेद बौने के बारे में** • एक सफेद बौना वह है जो सूर्य जैसे तारे अपने परमाणु ईंधन को समाप्त करने के बाद बनते हैं। • अपने परमाणु जलने की अवस्था के अंत में, इस प्रकार का तारा अपनी अधिकांश बाहरी सामग्री को बाहर निकाल देता है, जिससे एक ग्रह नीहारिका का निर्माण होता है। • तारे का केवल तप्त क्रोड ही रहता है। • यह कोर एक बहुत गर्म सफेद बौना बन जाता है, जिसका तापमान 100,000 केल्विन से अधिक होता है। • सफेद बौना अगले अरब वर्षों में ठंडा हो जाता है। • एक स्पंदित सफेद बौना, सफेद बौना तारा है जिसकी चमक अपने भीतर गैर-रेडियल गुरुत्वाकर्षण तरंग स्पंदन के कारण भिन्न होती है। • यह स्विच ऑन और ऑफ मोड है। • वैज्ञानिकों के अनुसार, इस प्रणाली में सफेद बौने के चारों ओर कक्षा में दाता तारा अभिवृद्धि डिस्क को फीडिंग करता है। • अभिवृद्धि डिस्क एक विशाल केंद्रीय पिंड के चारों ओर कक्षीय गति में विसरित सामग्री द्वारा बनाई गई संरचना है। केंद्रीय निकाय आमतौर पर एक तारा होता है। • जैसे-जैसे अभिवृद्धि डिस्क सामग्री धीरे-धीरे सफेद बौने के करीब जाती है, यह आम तौर पर उज्जवल (मोड पर) हो जाती है। • 'चालू' मोड के दौरान, सफेद बौना अभिवृद्धि डिस्क को सामान्य रूप से फीड करता है। • अचानक सिस्टम 'बंद' होकर उसकी चमक कम हो जाती है। • जब ऐसा होता है तो चुंबकीय क्षेत्र इतनी तेजी से घूमता है कि एक केन्द्रापसारक अवरोध सफेद बौने पर लगातार गिरने वाली अभिवृद्धि डिस्क से ईंधन को रोकता है। • नई खोज से खगोलविदों को अभिवृद्धि के पीछे की भौतिकी को समझने में मदद मिलेगी - ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे अपने आस-पास के तारों से सामग्री कैसे प्राप्त करते हैं। **ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS) के बारे में** • TESS NASA के खोजकर्ता कार्यक्रम के लिए एक अंतरिक्ष दूरबीन है, जिसे केपलर मिशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से 400 गुना बड़े क्षेत्र में पारगमन विधि का उपयोग करके एक्सोप्लैनेट की खोज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • इसे 2018 में फाल्कन रॉकेट सिस्टम द्वारा लॉन्च किया गया था। • हबल स्पेस टेलीस्कोप और TESS का उपयोग करते हुए, खगोलविदों ने पिछले कुछ वर्षों में कई सफेद बौनों की पहचान की है।
निपुण भारत मिशन	**सुर्खियों में:** शिक्षा मंत्रालय ने 'बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल- निपुण' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy- NIPUN) भारत मिशन की शुरुआत की है। • **द्वारा:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। • **उद्देश्य:** आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिये एक सक्षम वातावरण बनाना ताकि ग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27 तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। **जिम्मेदारियां:**

	• मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की प्रगति की निगरानी करना तथा नीतिगत मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करना। • 2026-27 में राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य पर पहुंचने के लिए। • दिशानिर्देशों के रूप में वार्षिक प्रगति के मापन के लिए उपकरणों का प्रसार करना। • प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिए KRAs के साथ एक राष्ट्रीय कार्य योजना (राज्य की कार्य योजनाओं के आधार पर) तैयार करना और अनुमोदन करना, अंतराल के लिए जिम्मेदार कारकों (यानी, फंड की कमी, रिक्तियों, शिक्षकों, जनसांख्यिकी, स्थानीय मुद्दों, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता, पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र संबंधी)। • प्रोग्रामेटिक और वित्तीय मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। • प्रगति का विश्लेषण करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फीडबैक प्रदान करने के लिए मूल्यांकन की पद्धति विकसित करना।
पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत मोबाइल अस्पताल	**संदर्भ :** हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि हाल ही में शुरू किए गए पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत, जिला स्तर पर विभिन्न परीक्षण मुफ्त किए जाएंगे, जिससे गरीबों के लिए खर्च और अनावश्यक यात्रा में कमी आएगी। **अन्य संबंधित तथ्य** • एशिया में पहली बार, व्यापक चिकित्सा सुविधाओं से लैस दो कंटेनर-आधारित अस्पताल, चेन्नई और दिल्ली में तैनात किए जाएंगे तथा देश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए रेल या हवाई मार्ग से तेजी से जुटाए जाने के लिए तैयार रहेंगे। • **उद्देश्य:** सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने के लिए, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल में। • प्रवेश के बिंदुओं को मजबूत करने से भारत की सीमाओं को नए संक्रामक रोगों और रोगजनकों के आयात के खिलाफ घेरा जाएगा। • जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों के विकास से जिलों को संक्रामक रोगों के व्यापक उपचार उपलब्ध कराने में आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। • प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज भी होगा।
भारत का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम	**सुर्ख़ियों में:** WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (SEAR) उच्च स्तरीय बैठक भारत की सह-अध्यक्षता में नए सिरे से टीबी प्रतिक्रिया के लिए आयोजित की गई। **टीबी को खत्म करने में भारत का योगदान** • **2025 तक टीबी का उन्मूलन:** भारत 2030 के वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले, 2025 तक तपेदिक को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। • **राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम:** महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए, कार्यक्रम का नाम संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) से बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) कर दिया गया है। ○ सभी सह-रुग्णताओं को संबोधित करना और निदान तथा उपचार के लिए पहुंच बाधाओं को कम करते हुए टीबी के सामाजिक निर्धारकों से निपटने के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप से परे है। ○ निक्षय पोषण योजना के माध्यम से, सभी टीबी रोगियों को उनके उपचार की पूरी अवधि के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। ○ अस्पताल के वार्डों और आउट पेशेंट प्रतीक्षा क्षेत्रों में वायुजनित संक्रमण नियंत्रण की दिशा में सख्ती से काम करना। ○ टीबी रोगियों और PLHIV रोगियों के बाल चिकित्सा संपर्कों में टीबी रोग के खिलाफ कीमोप्रोफिलैक्सिस का प्रावधान है। ○ वयस्क संपर्कों के लिए भी टीबी निवारक उपचार के विस्तार के लिए प्रक्रिया जारी है।

	• भारत में टीबी उन्मूलन के लिए जन आंदोलन के रूप में 'टीबी मुक्त भारत अभियान' शुरू किया गया है। • भारत संभावित तकनीकी सहायता और अपने पड़ोस के देशों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। • भारत ने तपेदिक को समाप्त करने और टीबी को समाप्त करने की दिशा में निवेश बढ़ाने के लिए उच्चतम स्तर की राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र (SEAR) की सराहना की। **क्षय रोग (TB)** • क्षय रोग (TB) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। • **संचरण:** टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब टीबी से पीड़ित लोग खांसते, छींकते या थूकते हैं, तो वे टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देते हैं। • **लक्षण:** कभी-कभी बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन घटना, बुखार और रात को पसीना आना। • टीबी एक इलाज योग्य बीमारी है। • मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB) बैक्टीरिया के कारण होने वाली टीबी का एक रूप है जो आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन, 2 सबसे शक्तिशाली, प्रथम-पंक्ति एंटी-टीबी दवाओं का जवाब नहीं देता है। यह दूसरी पंक्ति की दवाओं का उपयोग करके उपचार योग्य इलाज है। • व्यापक रूप से दवा प्रतिरोधी टीबी (XDR-TB) MDR-TB का एक अधिक गंभीर रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि दूसरी पंक्ति की सबसे प्रभावी टीबी विरोधी दवाओं का जवाब नहीं देते हैं, अक्सर रोगियों को बिना किसी और उपचार के विकल्प के छोड़ देते हैं। **रिपोर्ट कहती है** • इंडिया टीबी रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में, 18.05 तपेदिक सूचनाएं थीं, जो 2019 से महामारी के कारण हुए व्यवधानों के कारण 24% की गिरावट थी। • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा हाल ही में जारी 2021 की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार, एक दशक से अधिक समय में पहली बार विश्व स्तर पर तपेदिक (TB) से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। WHO मॉडलिंग अनुमानों से पता चलता है कि 2021-2022 में टीबी बढ़ने और बीमारी से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है।
AY4.2 भारत में 'अनियमित': INSACOG	**संदर्भ :** भारत SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम की एक साप्ताहिक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोनावायरस संस्करण का नवीनतम उत्परिवर्तन, AY4.2, जिसे यूनाइटेड किंगडम के मामलों में वृद्धि से जोड़ा गया है, यह भारत में "बहुत कम" है। **AY4.2 क्या है?** • AY.4.2 COVID-19 के डेल्टा संस्करण का वंशज है। डेल्टा संस्करण, जिसे B.1.617.2 के नाम से भी जाना जाता है, को पहली बार भारत में अक्टूबर 2020 में पहचाना गया था। • AY.4.2 उप-वंश (sub-lineage) में इसके स्पाइक प्रोटीन में 2 उत्परिवर्तन होते हैं - A222V और Y145H। • इसे "डेल्टा प्लस" करार दिया गया है और अब यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (UKHSA) द्वारा इसका नाम VUI-21OCT-01 रखा गया है)। • भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया (INSACOG) क्या है? • **द्वारा समन्वित:** MoH&FW, ICMR और CSIR के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)। • संघ देश में SARS-CoV-2 के नए संस्करण की स्थिति का पता लगाएगा। • INSACOG में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी। • इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा। • **उद्देश्य:** बहु-प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से नियमित आधार पर SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करना। • यह महत्वपूर्ण अनुसंधान संघ भविष्य में संभावित टीकों को विकसित करने में भी सहायता करेगा। • संघ सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थ के साथ जीनोमिक वेरिएंट का शीघ्र पता लगाने के लिए एक प्रहरी निगरानी भी स्थापित करेगा और असामान्य घटनाओं / प्रवृत्तियों (सुपर-स्प्रेडर घटनाओं, उच्च मृत्यु दर / रुग्णता प्रवृत्ति क्षेत्रों आदि)

	में जीनोमिक वेरिएंट का निर्धारण करेगा।
भारत ने ADB, AIIB से वैक्सीन ऋण मांगा	**संदर्भ :** भारत सरकार ने ADB और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से COVID-19 टीकों की 667 मिलियन खुराक की खरीद के लिए ऋण के लिए आवेदन किया है। **अन्य संबंधित तथ्य** ● ADB से 1.5 अरब डॉलर और AIIB से करीब 500 मिलियन डॉलर उधार देने की उम्मीद है। ● 667 मिलियन खुराकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा योग्य टीके लगाने होंगे। ● AIIB वैक्सीन खरीद का सह-वित्तपोषण करेगा। ● भारत सरकार द्वारा वैक्सीन की खरीद ADB की एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी (APVAX) पहल के तहत की गई है। **APVAX पहल क्या है?** ● इसे दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। ● यह अपने विकासशील सदस्य देशों को "तेजी से और समान समर्थन प्रदान करता है क्योंकि वे प्रभावी और सुरक्षित COVID-19 टीके खरीदते और वितरित करते हैं"। **एशियाई विकास बैंक (ADB)** ● यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। ● इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ● **मुख्यालय:** मंडलुयोंग, फिलीपींस। इसकी स्थापना एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ● आदर्श वाक्य (Motto): एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ● पांच सबसे बड़े उधार लेने वाले देश चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश हैं। **एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB)** ● यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। ● यह एक विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार करना है। ● इसमें 103 स्वीकृत सदस्य हैं। ● यह स्थायी अवसंरचना और विकासात्मक परियोजनाओं में निवेश पर केंद्रित है। ● बैंक की सदस्यता एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली है।
अग्नि-5	**सुर्ख़ियों में:** अग्नि -5, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ● यह बहुत उच्च सटीकता के साथ 5,000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम। ● तीन चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करता है। ● 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' की भारत की नीति के अनुरूप सफल प्रक्षेपण जो 'पहले उपयोग न करने' की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
न्यूमोकोकल 13-वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV) ड्राइव लॉन्च	**संदर्भ:** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत न्यूमोकोकल 13-वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV) के राष्ट्रव्यापी विस्तार का शुभारंभ किया। ● यह देश में पहली बार था कि PCV सार्वभौमिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। ● निमोनिया विश्व स्तर पर भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण था। **निमोनिया के बारे में** ● बैक्टीरिया, वायरस और कवक सहित विभिन्न प्रकार के जीव निमोनिया का कारण बनते हैं। ● न्यूमोकोकस के कारण होने वाला निमोनिया बच्चों में गंभीर रोग का सबसे आम कारण है। ● भारत में लगभग 16% बच्चों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। ● PCV के राष्ट्रव्यापी रोल-आउट से बाल मृत्यु दर में लगभग 60% की कमी आएगी।

	• **निमोनिया के लक्षण:** सांस लेने या खांसने पर सीने में दर्द, मानसिक जागरूकता में बदलाव, खांसी, कफ, थकान, बुखार, ठंड लगना आदि उत्पन्न करती है। • उपचार में एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटी फंगल दवाएं शामिल हैं। • स्वस्थ आहार, स्वच्छता, टीकाकरण निमोनिया से बचाव के कुछ उपाय हैं।

क्वाड पहल में शामिल हो सकता है चीन	**संदर्भ:** हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड पहल के माध्यम से एक स्वतंत्र और खुला इंडो-पैसिफिक सुनिश्चित करने के उद्देश्य में योगदान करने के लिए चीन का स्वागत है। **क्वाड** • **पूर्ण रूप:** चतुर्भजी सुरक्षा संवाद। • **देश:** यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। • **उद्देश्य:** मुख्य उद्देश्य एक नियम-आधारित व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला को सक्षम करना है। यह एक 'उभरते चीन' को रोकना चाहता है और अपने व्यापार और आर्थिक नीतियों के खिलाफ काम करता है।
CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार	**संदर्भ:** हाल ही में, पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के बहु-अरब डॉलर के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने पर चर्चा की है। • चीन ने अफगानिस्तान में CPEC के विस्तार के रूप में पेशावर-काबुल मोटरवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा** • CPEC पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। • इसका उद्देश्य संपूर्ण पाकिस्तान में राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों के नेटवर्क के साथ ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। • इसका उद्देश्य चीन के पश्चिमी भाग (शिनजियांग प्रांत) को पाकिस्तान के उत्तरी भागों में खुंजेरब दर्रे के माध्यम से बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह से जोड़ना है। • यह चीन के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका को ग्वादर पोर्ट से एक्सेस करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे चीन हिंद महासागर तक पहुंच सकेगा। • CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। 2013 में शुरू किए गए BRI का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है। • भारत CPEC की गंभीर रूप से आलोचना करता रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है।
भारत अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्थन देता है	**सुर्खियों में:** भारत ने अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिये और पूर्वी अंटार्कटिक एवं वेडेल सागर को समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) के रूप में नामित करने के यूरोपीय संघ के प्रस्ताव को सह-प्रायोजित करने के लिये अपना समर्थन दिया है। • गैर-सूचित और गैर-विनियमित मछली पकड़ने को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य। • MPA प्रस्ताव संरक्षण और सतत् उपयोग सिद्धांतों द्वारा संचालित होते हैं तथा वैश्विक सहयोग ढाँचे (जैसे सतत् विकास लक्ष्य, महासागरों का संयुक्त राष्ट्र दशक, जैव विविधता पर सम्मेलन आदि) का अनुपालन करते हैं। भारत इन सम्मेलनों या समझौतों का हस्ताक्षरकर्त्ता है। • भारत ने 1981 में दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र के माध्यम से अंटार्कटिक अभियान शुरू किया था। अब तक, भारत ने 2021-22 में 41वें अभियान की योजना के साथ 40 अभियान पूरे किए थे। भारत ने अपने अंटार्कटिक विजन को कायम रखने में अपने हितों को मजबूत किया है। **अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोग (CCAMLR) के बारे में**

	• CCAMLR संपूर्ण अंटार्कटिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की प्रजातियों की विविधता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए अंटार्कटिक मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। • CCAMLR अप्रैल 1982 में लागू हुआ। • भारत 1986 से CCAMLR का स्थायी सदस्य रहा है। **समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) के बारे में** • MPA एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है जो अपने सभी या उसके प्राकृतिक संसाधनों के हिस्से के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। • MPA के भीतर कुछ गतिविधियां विशिष्ट संरक्षण, आवास संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी या मत्स्य प्रबंधन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सीमित या प्रतिबंधित हैं। **वेडेल सागर के बारे में:** दक्षिणी महासागर का हिस्सा है और इसमें वेडेल गायरे शामिल हैं। इसकी भूमि सीमाओं को कोट भूमि और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के तटों से बनी खाड़ी द्वारा परिभाषित किया गया है। **क्या आप जानते हैं?** • भारतीय अंटार्कटिक अभियान 1981 में शुरू हुआ। • भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम को अब अंटार्कटिका में तीन स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय दिया गया है- दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। • आज की स्थिति में, भारत के अंटार्कटिका में मैत्री और भारती नामक दो परिचालन अनुसंधान केंद्र हैं। • राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR), गोवा, पूरे भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन करता है।
भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक सुरक्षा	**संदर्भ:** भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच औद्योगिक सुरक्षा समझौता (ISA) शिखर सम्मेलन दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए आयोजित किया गया था। **दिसंबर 2019 में ISA पर हस्ताक्षर किए गए थे** • दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाना। • यह ISA को लागू करने के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए आयोजित किया गया था। • यह संयुक्त कार्य समूह नीतियों और प्रक्रियाओं को संरेखित करने के लिए समय-समय पर बैठक करेगा जो रक्षा उद्योगों को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने की अनुमति देगा।
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट: यूनिसेफ	**संदर्भ:** यूनिसेफ (UNICEF) के ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन में "द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021; ऑन माई माइंड: बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना और उसकी देखभाल करना" रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। ग्लोबली लांच की गई रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर COVID-19 महामारी के महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण देता है। • रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15 से 24 साल के लगभग 14 प्रतिशत या उनमें से 7 में से 1 ने अक्सर उदास महसूस करने या काम करने में कम दिलचस्पी होने की सूचना दी। • लगभग 46,000 किशोर हर साल आत्महत्या से मर जाते हैं, जो उनके आयु वर्ग के लिए मृत्यु के शीर्ष पांच कारणों में से एक है। • 1.6 अरब से अधिक बच्चों को शिक्षा का कुछ नुकसान हुआ है। • इस बीच, मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और मानसिक स्वास्थ्य निधिकरण के बीच व्यापक अंतर बना हुआ है। रिपोर्ट में पाया गया है कि सरकारी स्वास्थ्य बजट का लगभग 2 प्रतिशत वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य खर्च के लिए आवंटित किया जाता है। **आगे की राह:** यह प्रत्येक बच्चे के लिए अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, कमजोर बच्चों की रक्षा करने और सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में प्रतिबद्धता, संचार और कार्रवाई की मांग करता है। • रोकथाम, प्रोत्साहन और देखभाल के लिए पूरे समाज के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, न केवल स्वास्थ्य में, बल्कि सभी क्षेत्रों में बच्चे और किशोर मानसिक स्वास्थ्य में तत्काल निवेश। • स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों में साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों को एकीकृत करना और बढ़ाना - जिसमें माता-पिता के कार्यक्रम शामिल हैं जो उत्तरदायी, देखभाल करने वाले को बढ़ावा देते हैं और माता-पिता तथा देखभाल

	करने वाले मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं; और यह सुनिश्चित करना कि स्कूल गुणवत्तापूर्ण सेवाओं और सकारात्मक संबंधों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। • मानसिक बीमारी के बारे में चुप्पी को तोड़ना, कलंक को दूर करके और मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर समझ को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के अनुभवों को गंभीरता से लेना।
भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन (HAC) में शामिल हुआ	**सुर्खियों में:** भारत प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है, 70 से अधिक देशों के एक समूह ने 30x30 की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने को प्रोत्साहित किया है। • जनवरी 2021 में पेरिस में "वन प्लैनेट समिट" में शुरू किए गए इस गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना है। • HAC सदस्यों में वर्तमान में वैश्विक उत्तर और दक्षिण के देशों का मिश्रण शामिल है; यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी, अफ्रीका और एशिया के देश इसके सदस्य हैं। • भारत HAC में शामिल होने वाली प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के ब्रिक्स ब्लॉक में पहला है।
समझौता ज्ञापन: कपड़ा मंत्रालय और GIZ	**सुर्खियों में:** डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (GIZ) और कपड़ा मंत्रालय सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। • भारत की 'कपास अर्थव्यवस्था में स्थिरता और मूल्य वर्धित' पर इंडो जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना के कार्यान्वयन समझौते पर। • इस परियोजना का उद्देश्य स्थायी कपास पर ध्यान केंद्रित और डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण को मजबूत करके भारत में स्थायी कपास उत्पादन से मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। • यह 4 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। • भारत में उपभोक्ताओं को कपास उत्पादकों से जोड़ने और पूरी आपूर्ति श्रृंखला के साथ काम करने की रणनीति के साथ "शेल्फ से फील्ड तक" दृष्टिकोण का पालन करता है। • किसानों द्वारा उनकी स्थायी रूप से उगाई जाने वाली कपास के लिए बेहतर बाजार पहुंच के लिए "पुल" कारक बनाने के लिए - अच्छी कृषि प्रथाओं के कार्यान्वयन पर जोर देते हुए स्थायी कपास की खेती के तरीकों को बढ़ावा देना। • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त/स्वीकृत स्थिरता मानकों के प्रसार और अनुप्रयोग के बारे में पारदर्शिता के सृजन और प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना और कपास उत्पादन में पानी के पदचिह्न को कम करने वाले उपायों को बढ़ावा देना। इससे कपास क्षेत्र की जलवायु अनिश्चितताओं के कारण लगातार बढ़ रहे जल-तनाव के प्रति संवेदनशीलता को कम करने में मदद मिलेगी। **GIZ परियोजना का उद्देश्य है-** • कम से कम 90,000 हेक्टेयर पर कपास उत्पादन की मात्रा बढ़ाना। • उपज में 10% की वृद्धि के साथ 1.50 लाख कपास किसानों की भागीदारी होना। • इससे 1.50 लाख किसानों और उद्यमियों का क्षमता निर्माण हो सकेगा, जिनमें से लगभग 30% महिला लाभार्थी होंगी। • भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है और दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जिसकी अनुमानित खपत 303 लाख गांठ (5.15 मिलियन मीट्रिक टन अर्थात 1505 लाख गांठ (25.59 मिलियन मीट्रिक टन) की विश्व कपास खपत का 20% है। यह अनुमानित 6 मिलियन कपास किसानों और कपास प्रसंस्करण तथा व्यापार जैसी संबंधित गतिविधियों में लगे लगभग 50 मिलियन लोगों की आजीविका को बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
प्रतिबंध अधिनियम (CAATSA) के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला	**संदर्भ:** नई दिल्ली को इस तरह के पहले संकेत में, अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने संकेत दिया है कि वाशिंगटन भारत सरकार पर प्रतिबंध लगाने पर पुनर्विचार कर सकता है जब भारत यूएस $ 5.5 में पांच रूसी निर्मित एस-400 ट्रायम्फ एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी लेता है। इस साल के अंत में अरबों का सौदा होगा। **CAATSA क्या है?** • प्रतिबंध अधिनियम (CAATSA) के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला करना मुख्य उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया का मुकाबला करना है।

	• यह 2017 में अधिनियमित किया गया। • रूस के रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन करने वाले देशों के खिलाफ प्रतिबंध शामिल हैं। **S-400 Triumpf विमान भेदी मिसाइल प्रणाली क्या है?** **1.** S-400 Triumf रूस द्वारा डिजाइन की गई एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है। **2.** यह दुनिया में सबसे खतरनाक परिचालन रूप से तैनात आधुनिक लंबी दूरी की SAM (MLR SAM) है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम (THAAD) से काफी आगे माना जाता है।
परमाणु नियामक आयोग (NRC)	**संदर्भ:** हाल ही में परमाणु नियामक आयोग (NRC) ने विकिरण सुरक्षा मानकों को निर्धारित करने के लिए रैखिक नो-थ्रेशोल्ड (LNT) मॉडल को बरकरार रखा, इस विषय पर लंबे विवाद को समाप्त किया। **पृष्ठभूमि** • छह साल पहले, फरवरी 2015 के दौरान, NRC से अनुरोध करते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं, "अपने सबूतों के आधार पर अपने नियमों में संशोधन करने के लिए जो रैखिक नो-थ्रेसहोल्ड (LNT) खुराक-प्रभाव मॉडल के विपरीत हैं। • याचिकाकर्ता "रेडिएशन हार्मेसिस (radiation hormesis)" का समर्थन करते हैं, एक अवधारणा जो प्रस्तावित करती है कि आयनकारी विकिरण की कम खुराक विकिरण की उच्च खुराक के हानिकारक प्रभावों से रक्षा करती है और इसके परिणामस्वरूप मनुष्यों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। NRC ने इसका खंडन किया था। **LNT मॉडल के बारे में** • लीनियर नो-थ्रेशोल्ड मॉडल (LNT) एक खुराक-प्रतिक्रिया मॉडल है जिसका उपयोग विकिरण संरक्षण में संभावित स्वास्थ्य प्रभावों जैसे कि विकिरण-प्रेरित कैंसर, मानव शरीर पर आयनकारी विकिरण के संपर्क के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। • LNT मॉडल एजेंसियों को वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से लेकर व्यक्तिगत औद्योगिक रेडियोग्राफरों और परमाणु चिकित्सा पद्धतियों तक विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंसधारियों को विकिरण जोखिम को विनियमित करने में मदद करता है। **परमाणु नियामक आयोग (NRC) क्या है?** • यह संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसे परमाणु ऊर्जा से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। • यह 1974 के ऊर्जा पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। • कार्य: रिएक्टर सुरक्षा और सुरक्षा की देखरेख करना। • रिएक्टर लाइसेंसिंग और नवीनीकरण का प्रशासन करना। • खर्च किए गए ईंधन के भंडारण, सुरक्षा, पुनर्चक्रण और निपटान का प्रबंधन करने वाली रेडियोधर्मी सामग्री को लाइसेंस देना।
रोहिंग्या संकट	**संदर्भ :** बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते पर मुहर लगाने के बाद 80,000 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में एक दूरस्थ द्वीप- भासन चर में भेजने की योजना बना रहा है। • सहायता समूहों द्वारा उठाए गए संदेह के बावजूद, म्यांमार के लगभग 19,000 मुस्लिम शरणार्थी पहले ही द्वीप पर स्थानांतरित हो चुके हैं। **पृष्ठभूमि** • भासन चार एक ऐसा द्वीप है जिसे विशेष रूप से पड़ोसी म्यांमार से भागे 10 लाख रोहिंग्याओं में से 1,00,000 को समायोजित करने के लिए विकसित किया गया है। • मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की आलोचना की है। **रोहिंग्या कौन हैं?** • वे एक जातीय समूह हैं, जिनमें ज्यादातर मुसलमान हैं। उन्हें म्यांमार द्वारा पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई थी। • उन्हें "विदेशी निवासी या सहयोगी नागरिक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। • जातीय रूप से वे म्यांमार के चीन-तिब्बती लोगों की तुलना में भारत और बांग्लादेश के इंडो-आर्यन लोगों के अधिक करीब हैं। • संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा वर्णित "दुनिया में सबसे अधिक भेदभाव वाले लोगों में से एक, यदि नहीं तो"।

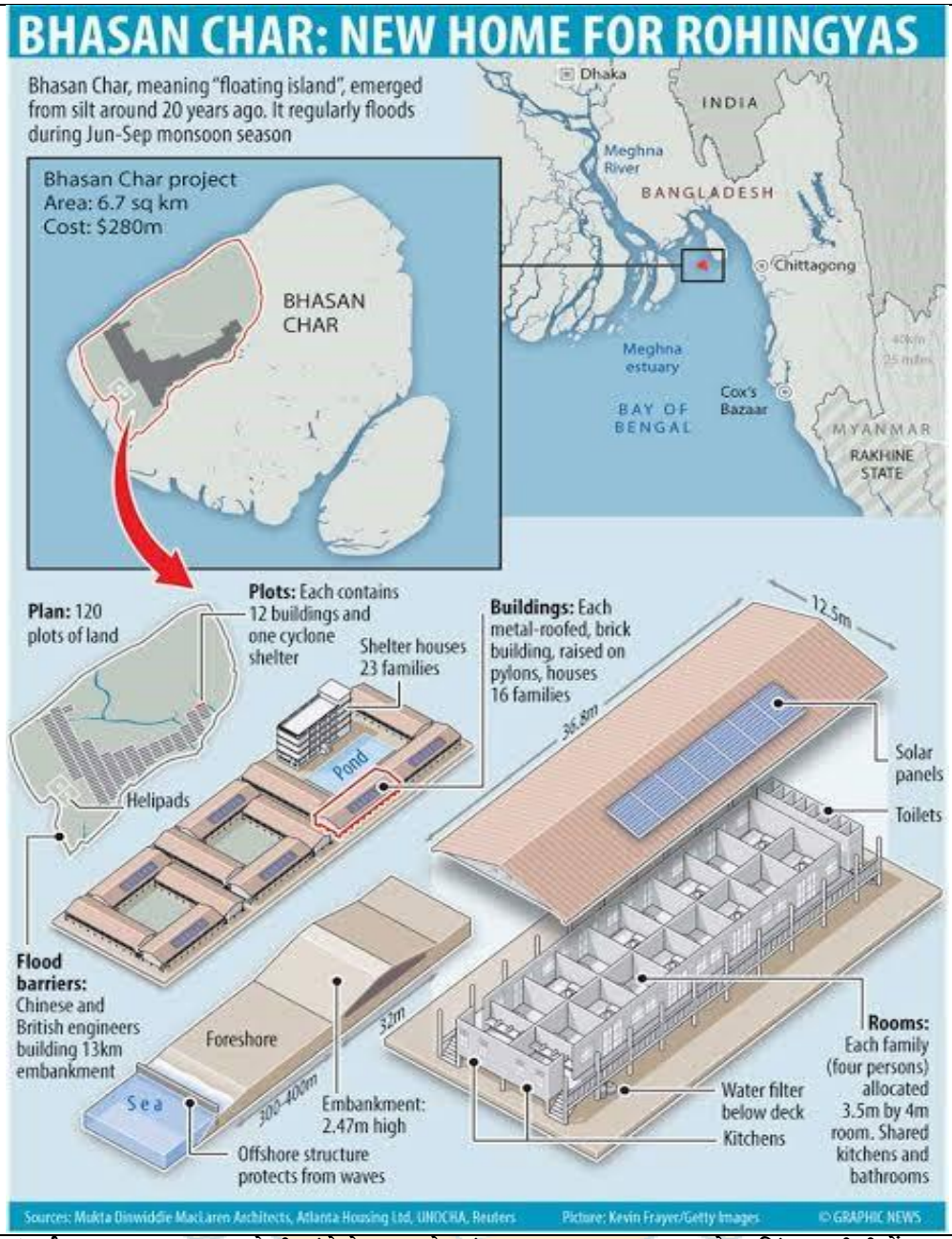

OECD/G20 समावेशी फ्रेमवर्क टैक्स डील

संदर्भ: OECD/G20 समावेशी ढांचे के तहत दो-स्तंभ समाधान 13 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में, फिर महीने के अंत में रोम में G20 लीडर्स समिट में दिया जाएगा।

- देश 2023 में प्रभावी कार्यान्वयन के साथ, 2022 के दौरान एक बहुपक्षीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य बना रहे हैं।
- भारत पहले ही G20-OECD समावेशी ढांचे के सौदे में शामिल हो चुका है।
- यह अंतरराष्ट्रीय कर नियमों में सुधार करना चाहता है और यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय उद्यम जहां कहीं भी काम करते हैं, उनके उचित हिस्से का भुगतान करें।
- 130 देशों और क्षेत्राधिकारों, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ढांचे के दो स्तंभ

- **अंतरराष्ट्रीय और डिजिटल कंपनियों से निपटना:** यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल कंपनियों सहित बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यम, जहां वे काम करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और कर का भुगतान करते हैं।
- **सीमा पार लाभ स्थानांतरण और संधि खरीदारी को संबोधित करने के लिए कम कर क्षेत्राधिकार से निपटना:** यह वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर के माध्यम से देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के तहत एक मंजिल रखना चाहता है, जो वर्तमान में 15% पर प्रस्तावित है।

3rd इंडिया - यूके एनर्जी फॉर ग्रोथ पार्टनरशिप - मंत्रिस्तरीय ऊर्जा वार्ता	**सुर्ख़ियों में:** ऊर्जा संक्रमण वार्ता में चर्चा का एक प्रमुख क्षेत्र था और ऊर्जा मंत्रियों ने सौर, अपतटीय पवन, भंडारण, ईवी, वैकल्पिक ईंधन आदि सहित अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ अपने-अपने देशों में चल रही ऊर्जा संक्रमण गतिविधियों पर विस्तार से बात की। • यूके पक्ष ने द्विपक्षीय सहयोग की छत्रछाया में पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों और पिछले कार्यों का एक विस्तृत सारांश प्रस्तुत किया। • मई में भारत-यूके वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा शुरू किए गए भारत-यूके भविष्य के संबंधों के लिए रोडमैप 2030 का स्वागत किया और रोडमैप 2030 के अनुरूप सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की। • रोडमैप 2030 के हिस्से के रूप में बिजली और स्वच्छ परिवहन, नवीकरणीय, ग्रीन फाइनेंस और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पर आगे की कार्य योजना पर विचार-विमर्श और सहमति हुई, जिसमें स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, ग्रीन हाइड्रोजन, चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी भंडारण सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। बहुपक्षीय सहयोग के तहत अन्य प्रस्तावों के साथ अक्षय ऊर्जा में निवेश जुटाने की आवश्यकता। • दोनों पक्षों के साथ बातचीत समाप्त हुई, जिसमें बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए ठोस कार्य योजनाओं की स्थापना करते हुए दुनिया के लिए सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा को असुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया।
उत्तर पश्चिमी यूरोप सहकारी आयोजन	**सुर्ख़ियों में:** भारत ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव-वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (GGI-OSOWOG) नॉर्थवेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट के मंत्रिस्तरीय सत्र में भाग लिया, जिसमें अक्षय बिजली के सीमा पार व्यापार को विकसित करने के लिए एक बहुस्तरीय संवाद देखा गया। **भारत** • पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा तथा ऊर्जा संक्रमण के कारण अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। • वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य पर प्रकाश डाला। • रेखांकित किया कि भारत लक्ष्य तिथि से काफी पहले स्वच्छ ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी से संबंधित अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को प्राप्त करने की राह पर है। • भंडारण की आवश्यकता को कम करने और वास्तव में ऊर्जा संक्रमण की लागत को कम करने के लिए एक संभावित समाधान के रूप में GGI-OSOWOG पहल को प्रस्तुत किया। • सतत विकास और जलवायु परिवर्तन शमन GGI-OSOWOG पहल के केंद्र में हैं, और यह परियोजना का पैमाना बहुत अच्छी तरह से इसे अगला सबसे बड़ा आधुनिक इंजीनियरिंग चमत्कार बना सकता है। **पृष्ठभूमि** • वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG) पहल का विचार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की पहली सभा में रखा गया था। उन्होंने सौर ऊर्जा को सीमाओं के पार ऊर्जा आपूर्ति जोड़ने का आह्वान किया था। • मई 2021 में, यूनाइटेड किंगडम और भारत ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव तथा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की ताकतों को संयोजित करने और नवंबर 2021 में यूके द्वारा ग्लासगो में आयोजित होने वाले COP26 शिखर सम्मेलन में GGI-OSOWOG को संयुक्त रूप से लॉन्च करने पर सहमति व्यक्त की।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स: भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर	**संदर्भ:** भारत 116 देशों के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2021 में फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया है. इस मामले में वह अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है. वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था। • भारत भी उन 31 देशों में शामिल है जहां भूख को गंभीर के रूप में पहचाना गया है। • पिछले साल जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) में 107 देशों में भारत 94वें स्थान पर है। **अन्य संबंधित तथ्य** • पापुआ न्यू गिनी (102), अफगानिस्तान (103), नाइजीरिया (103), कांगो (105), मोजाम्बिक (106), सिएरा लियोन (106), तिमोर-लेस्ते (108) आदि जैसे देशों में भारत से केवल 15 देशों की स्थिति खराब है)। • भारत भी अधिकांश पड़ोसी देशों से पीछे है। पाकिस्तान को 92वें, नेपाल को 76वें और बांग्लादेश को भी 76वें स्थान पर रखा गया है।

- 2021 GHI रैंकिंग के अनुसार सोमालिया में भूख का स्तर उच्चतम है।
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) पर आधारित वर्तमान अनुमानों से पता चलता है कि पूरी दुनिया और विशेष रूप से 47 देश - 2030 तक कम भूख को भी हासिल करने में विफल हो जाएंगे।
- दशकों की गिरावट के बाद, अल्पपोषण का वैश्विक प्रसार बढ़ रहा है। यह बदलाव भूख के अन्य उपायों में उलटफेर का संकेत हो सकता है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है?

- GHI कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फ़ द्वारा एक वार्षिक सहकर्मी-समीक्षा प्रकाशन है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को ट्रैक करना है।
- यह अपने अंकों की गणना के लिए चार मापदंडों का उपयोग करता है -
  - अल्पपोषण
  - बर्बाद बच्चे (child wasting)
  - बच्चे का स्टंटिंग और
  - बाल मृत्यु दर
- इन मापदंडों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र से जानकारी ली जाती है।
- ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय डेटा से प्राप्त करते हैं, जिसमें भारत के मामले में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) शामिल है।

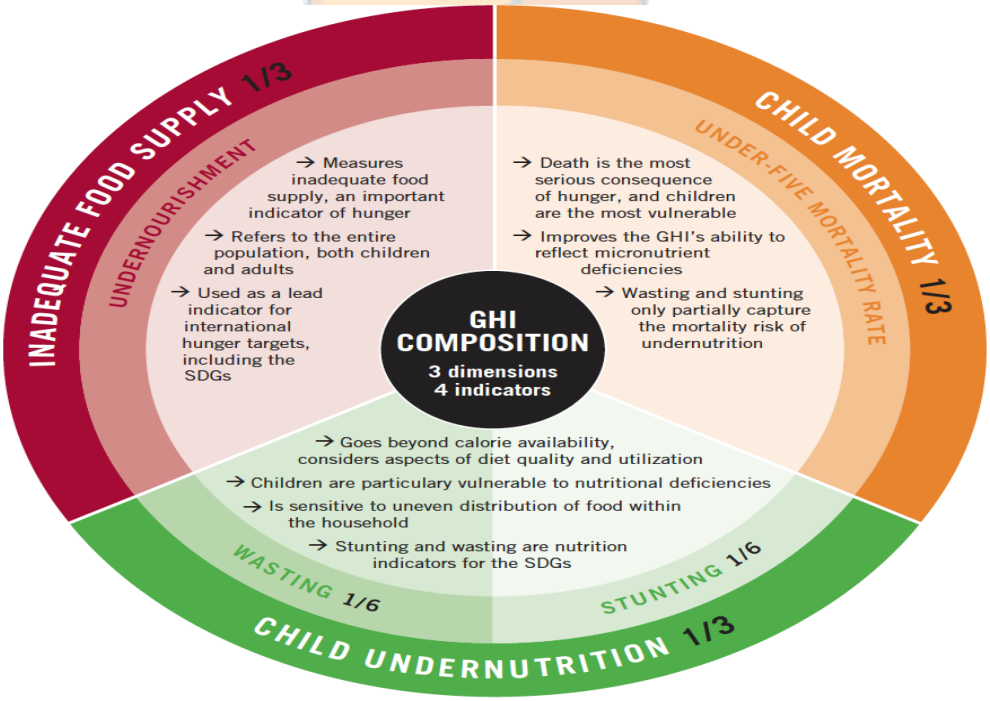

सीमा संबंधी वार्ता में तेजी लाने के लिए चीन और भूटान के बीच समझौता

संदर्भ : अपने सीमा विवादों को हल करने की दिशा में, भूटान और चीन ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में वार्ता को गति देने में मदद करने के लिए तीन-चरणीय रोडमैप पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- अप्रैल 2021 में कुनमिंग में विशेषज्ञ समूह की 10वीं बैठक के दौरान रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया था, जो क्रमशः थिम्पू और बीजिंग में उनकी सरकारों को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था।
- रोडमैप "भूटान-चीन सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए", से सीमा वार्ता प्रक्रिया पर प्रगति की शुरुआत होने की उम्मीद है, जो पांच साल से विलंबित है, पहले 2017 में डोकलाम गतिरोध और फिर महामारी के कारण।
- समझौते का समय भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उनके 17 महीने पुराने गतिरोध पर सीमा वार्ता इस सप्ताह गतिरोध पर आ गई है।
- तीन चरणों वाले रोडमैप पर [भूटान-चीन] समझौता ज्ञापन सीमा वार्ता को एक नई गति प्रदान करेगा।

	• यह आशा की जाती है कि सद्भावना, समझ और सामंजस्य की भावना से इस रोडमैप के कार्यान्वयन से सीमा वार्ता एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेगी जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य है।
भारत-इजरायल के बीच व्यापार वार्ता फिर से शुरू	**संदर्भ:** भारत और इज़राइल एक मुक्त व्यापार समझौते पर लंबे समय से लंबित वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। • FTA वार्ता नवंबर में शुरू होगी और जून 2022 तक समाप्त होगी। **अन्य संबंधित तथ्य** • इस बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने लगभग 200 वस्तुओं के लिए एक सीमित व्यापार सौदे या एक तरजीही व्यापार समझौते की संभावना का पता लगाया था, जो समाप्त नहीं हो सका। • भारत सरकार कई व्यापार वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए भी काम कर रही है। • सरकार अब तक यू.के., ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। • भारत और इज़राइल एक दूसरे की टीकाकरण प्रक्रिया को "सैद्धांतिक रूप से" मान्यता देने के लिए भी सहमत हुए। • इज़राइल ने यह भी घोषणा की कि वह नवंबर 2021 में ग्लासगो में अगले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 शिखर सम्मेलन से पहले भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल होगा। **क्या आप जानते हैं?** • दोनों अमेरिकी विदेश मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री के साथ एक आभासी चतुर्भुजी बैठक में भी शामिल हुए। • चतुर्भुजी बैठक को पिछले साल के अब्राहम समझौते के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें यू.एस. द्वारा दलाली की गई थी और यूएई तथा इज़राइल ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे।
लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज (LMDC)	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वस्तुतः समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसका शीर्षक था 'जलवायु परिवर्तन पर COP 26 की तैयारी - अपेक्षाएँ और चुनौतियाँ'। • ग्लासगो में होने वाले 26वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले इस बैठक की मेजबानी बोलीविया ने की है। • इस बैठक के दौरान LMDC मंत्रियों द्वारा एक मंत्रिस्तरीय बयान का समर्थन किया गया, जिसमें COP 26 प्रेसीडेंसी के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। **समान विचारधारा वाले विकासशील देश (LMDC) समूह क्या है?** • LMDC में एशिया और अन्य क्षेत्रों के लगभग 25 विकासशील देश शामिल हैं। • यह खुद को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में वार्ताकारों के एक ब्लॉक के रूप में संगठित करता है। • वे दुनिया की 50% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। • **इसके सदस्य देश:** अल्जीरिया, बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान, चीन, क्यूबा, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, वियतनाम और जिम्बाब्वे। **पार्टियों का 26वां सम्मेलन (COP26) क्या है?** • COP26 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। • यह यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में 31 अक्टूबर और 12 नवंबर 2021 के बीच आयोजित होने वाला है। • जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा आने वाले दशकों में गर्मी की लहरों, सूखे, अत्यधिक वर्षा और समुद्र के स्तर में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए, पृथ्वी की जलवायु पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करने के महीनों बाद यह सम्मेलन आता है। • COP, 1994 में गठित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत आता है। ○ UNFCCC की स्थापना "वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के स्थिरीकरण" की दिशा में काम करने के लिए की गई थी। **COP26 के चार लक्ष्य** • सदी के मध्य तक वैश्विक नेट-शून्य सुरक्षित करना और पहुंच के भीतर 1.5 डिग्री रखें। • समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूल।

	• राशि जुटाना। • वितरित करने के लिए मिलकर काम करना।
पाकिस्तान फिर से FATF की 'ग्रेलिस्ट' पर बरकरार	**संदर्भ:** FATF पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल यानी एफएटीएफ (Financial Action Task Force) ने एक बार फिर से पाकिस्तान को 'ग्रे सूची' रखा है। • FATF ने पाया कि पाकिस्तान को यह दिखाने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और तालिबान शामिल हैं। **फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) क्या है?** • FATF 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है। • **उद्देश्य:** अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए। • वर्तमान में, इसमें 39 सदस्य हैं। • पाकिस्तान जून 2018 से ग्रे लिस्ट में है।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, 2021	**संदर्भ:** हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को 71वें स्थान पर रखा गया है। **शीर्ष रैंकिंग वाले देश** • आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ़िनलैंड, स्विटज़रलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका ने सूचकांक पर 77.8 और 80 अंकों की सीमा में समग्र GFS स्कोर के साथ शीर्ष स्थान साझा किया। **निचले पायदान के पांच देश हैं-** • मलावी (109 वां), सूडान (110), मोजाम्बिक (111), यमन (112) और बुरुंडी (113)। • भारत और उसके पड़ोसियों का प्रदर्शन। • भारत GFS सूचकांक पर 57.2 अंकों के समग्र स्कोर के साथ 71वें स्थान पर रहा। • इसने पाकिस्तान (75वें), श्रीलंका (77वें), नेपाल (79वें) और बांग्लादेश (84वें) से बेहतर प्रदर्शन किया। • लेकिन चीन (34वें स्थान) से काफी पीछे है। • खाद्य सामर्थ्य की श्रेणी में पाकिस्तान (52.6 अंक) और श्रीलंका (62.9 अंक) ने भारत (50.2 अंक) से बेहतर स्कोर किया। • पिछले 10 वर्षों में, समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर में भारत का वृद्धिशील लाभ पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से पिछड़ रहा था। **वैश्विक खाद्य सुरक्षा (GFS) सूचकांक के बारे में** • GFS इंडेक्स को लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था और यह कोर्टेवा एग्रीसाइंस द्वारा प्रायोजित है। • यह सामर्थ्य, उपलब्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों और लचीलेपन के कारकों के आधार पर 113 देशों में खाद्य सुरक्षा के अंतर्निहित चालकों को मापता है।
अफगानिस्तान में 'पीपुल्स इकोनॉमी' के लिए यूएन फंड	**संदर्भ:** संयुक्त राष्ट्र ने पिछले अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से जमे हुए दाता धन में टैपिंग सिस्टम के माध्यम से सीधे अफगानों को तत्काल आवश्यक नकदी प्रदान करने के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है। **अन्य संबंधित तथ्य** • वैश्विक एजेंसी ने कहा कि युद्धग्रस्त देश की स्थानीय अर्थव्यवस्था के फटने के साथ, फंड का उद्देश्य अफगान परिवारों में तरलता को इंजेक्ट करना है ताकि उन्हें इस सर्दी में जीवित रहने और अपनी मातृभूमि में रहने की अनुमति मिल सके। • अफगान कामगारों को सूखा और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों तथा सूक्ष्म उद्यमों को दिए जाने वाले अनुदान जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों में नकद प्रदान किया जाएगा। • कमजोर बुजुर्गों और विकलांगों को अस्थायी मूल आय का भुगतान किया जाएगा। • पहले योगदानकर्ता जर्मनी ने इस कोष में €50 मिलियन ($58 मिलियन) का वचन दिया था। **इस फंड की जरूरत क्या है?**

	• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को 2021 में 30% तक अनुबंधित करने के लिए निर्धारित किया गया था और इससे शरणार्थी संकट को और बढ़ावा मिलने की संभावना थी जो पड़ोसी देशों, तुर्की और यूरोप को प्रभावित करेगा। • अगस्त 2021 में तालिबान के अधिग्रहण में अरबों की केंद्रीय संपत्ति जमी हुई थी और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने धन तक पहुंच को निलंबित कर दिया था, हालांकि, मानवीय सहायता जारी है। • बैंकों के पास पैसे खत्म हो रहे हैं, नौकरशाहों को भुगतान नहीं किया गया है और खाने की कीमतें बढ़ गई हैं। • फंड अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पर्याप्त आश्वस्त होने की अनुमति देगा कि ये फंड सरकार-से-सरकारी फंडिंग के रूप में नहीं हैं। • संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पहले 12 महीनों में लगभग 667 मिलियन डॉलर की गतिविधियों को कवर किया था।
इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (IPRD)	**संदर्भ:** पहली बार 2018 में आयोजित, इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (IPRD) भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतरराष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है, और यह सामरिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी का प्रमुख अभिव्यक्ति है। **उद्देश्य:** इंडो-पैसिफिक के अंदर उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियों दोनों की समीक्षा करना। **थीम:** 21 वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति में विकास: अनिवार्यताएं, चुनौतियां आगे की राह • भारत-प्रशांत के अंदर विकसित समुद्री रणनीतियां: अभिसरण, विचलन, अपेक्षाएं और आशंकाएं। • समुद्री सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए अनुकूली रणनीतियाँ। • बंदरगाह के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय समुद्री संपर्क और विकास रणनीतियाँ। • सहकारी समुद्री डोमेन जागरूकता रणनीतियाँ। • नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम ऑर्डर पर कानून के बढ़ते सहारा का प्रभाव। • क्षेत्रीय सार्वजनिक-निजी समुद्री भागीदारी को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ। • ऊर्जा-असुरक्षा और न्यूनीकरण रणनीतियाँ। • समुद्र में मानव रहित पहेली को संबोधित करने की रणनीतियाँ।
अफ्रीकी संघ	**संदर्भ :** अफ्रीकी संघ ने देश में नागरिक शासन बहाल होने तक सूडान को निलंबित कर दिया है, यह कहते हुए कि उसने सूडान में सैन्य अधिग्रहण को सत्ता की "असंवैधानिक" जब्ती के रूप में खारिज कर दिया। • साथ ही, विश्व बैंक ने सैन्य तख्तापलट के बाद सूडान को सहायता निलंबित कर दी है। **अफ्रीकी संघ के बारे में** • यह एक महाद्वीपीय संघ है जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। • 2017 में, AU ने मोरक्को को एक सदस्य राज्य के रूप में स्वीकार किया। AU की घोषणा 1999 में सिरते (Sirte), लीबिया में सिरते घोषणा में की गई थी। • इसकी स्थापना 2001 में अदीस अबाबा, इथियोपिया में हुई थी। • इसे 2002 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था। • AU का सचिवालय, अफ्रीकी संघ आयोग, अदीस अबाबा में स्थित है।
डेटा प्रकटीकरण ढांचा	**संदर्भ:** ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और सुरक्षा परिषद आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय ने डेटा प्रकटीकरण ढांचा शुरू किया है। • यह एक उपकरण है जो आतंकवाद विरोधी जांच के लिए विदेशी आपराधिक न्याय अधिकारियों से डेटा अनुरोधों का जवाब देने के लिए विकसित प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करता है। **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में** • यह 1997 में स्थापित किया गया था और 2002 में इसे ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के रूप में नामित किया गया था। • यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम (UNDCP) और वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अपराध निवारण तथा आपराधिक न्याय प्रभाग को मिलाकर ड्रग नियंत्रण और अपराध रोकथाम कार्यालय के रूप में कार्य करता है।
15वां भारत-	**संदर्भ:** द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भारत-इजराइल संयुक्त कार्य समूह (JWG) ने साथ मिलकर काम करने के नए क्षेत्रों की पहचान

इजरायल संयुक्त कार्य समूह	हेतु व्यापक दस वर्षीय रोडमैप तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की है। ● अभ्यास और उद्योग सहयोग सहित सैन्य कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा की। ● रक्षा खरीद और उत्पादन तथा अनुसंधान और विकास पर उप कार्य समूहों (SWG) द्वारा की गई प्रगति पर मूल्यांकन किया गया। ● रक्षा उद्योग सहयोग पर एक SWG बनाने का भी निर्णय लिया गया - यह द्विपक्षीय संसाधनों के कुशल उपयोग, प्रौद्योगिकियों के प्रभावी प्रवाह और औद्योगिक क्षमताओं को साझा करने में सक्षम होगा। **भारत-इजरायल संयुक्त कार्य समूह (JWG) के बारे में:** JWG भारत के रक्षा मंत्रालय और इजरायल के रक्षा मंत्रालय के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए शीर्ष निकाय है।
ताजिकिस्तान में 'सैन्य अड्डे' का निर्माण करेगा चीन	**संदर्भ:** चीन ताजिकिस्तान में एक सैन्य अड्डे का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने जा रहा है। चीन लंबे समय से चुपचाप इस अड्डे का इस्तेमाल कई साल से कर रहा था। यही नहीं चीन ताजिक सेनाओं के लिए एक नया सैन्य अड्डा बनाएगा। **अन्य संबंधित तथ्य** ● ताजिकिस्तान की संसद ने चीन के पैसे से नए सैन्य अड्डे को बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। ● चीन ताजिकिस्तान के विशेष बलों के लिए इस सैन्य अड्डे का निर्माण करेगा। यह सैन्य अड्डा ताजिकिस्तान के उत्तरी गोर्नो-बदख्शान प्रांत में बनाया जाएगा जो पामीर के पहाड़ों से घिरा हुआ है। ● समझौते पर चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, न कि चीनी सेना द्वारा, जो पड़ोसी अफगानिस्तान में अस्थिरता पर बढ़ती चिंताओं के बीच आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। ● नया बेस ताजिकिस्तान के रैपिड रिएक्शन ग्रुप के स्वामित्व में होगा और 10 मिलियन डॉलर की लागत से चीन द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। ● यह पूर्वी गोर्नो-बदख्शां स्वायत्त प्रांत में पामीर पहाड़ों के पास स्थित होगा, और वहां चीनी सैनिक तैनात नहीं होंगे। ● ताजिकिस्तान सरकार चीन-ताजिकिस्तान-अफगानिस्तान ट्राई-जंक्शन और वखान कॉरिडोर के पास एक पूर्व सोवियत बेस को पूर्ण नियंत्रण हस्तांतरित करने पर भी सहमत हो गई है, जहां चीन अफगानिस्तान के साथ 100 किमी से कम की सीमा साझा करता है। **क्या आप जानते हैं?** ● रूस और भारत उन देशों में शामिल हैं जिनकी पहले से ही ताजिकिस्तान में सैन्य उपस्थिति है।
18वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आसियान के वर्तमान अध्यक्ष ब्रुनेई के महामहिम सुल्तान हाजी हसनल बोल्कैया के निमंत्रण पर 18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। **भारत-** ● भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक इंडो-पैसिफिक विजन के लिए भारत के विजन में आसियान की केंद्रीयता को रेखांकित किया। ● COVID-19 पर, इस क्षेत्र में महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला और इस संबंध में आसियान की पहल के लिए समर्थन भी दोहराया। ● भारत ने म्यांमार के लिए आसियान की मानवीय पहल के लिए 200,000 अमरीकी डालर और आसियान के कोविड - 19 प्रतिक्रिया कोष के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की चिकित्सा आपूर्ति का योगदान दिया है। ● भारत-आसियान सांस्कृतिक संपर्क को और मजबूत करने के लिए: भारत आसियान सांस्कृतिक विरासत सूची की स्थापना का समर्थन करेगा। ● व्यापार और निवेश पर, कोविड के बाद आर्थिक सुधार के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और लचीलेपन के महत्व को रेखांकित किया और इस संबंध में, भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया। **भारत और आसियान** ● भारत-आसियान साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के मील के पत्थर पर प्रकाश डालते हुए, नेताओं ने वर्ष 2022 को भारत-आसियान मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया। ● इंडो-पैसिफिक (AOIP) और भारत के इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI) के लिए आसियान आउटलुक के

	बीच तालमेल पर निर्माण करते हुए, पीएम और आसियान नेताओं ने शांति, स्थिरता और समृद्धि क्षेत्र में भारत-आसियान संयुक्त वक्तव्य को अपनाने का स्वागत किया। ● भौतिक, डिजिटल और लोगों के बीच व्यापक रूप से भारत-आसियान संपर्क बढ़ाने पर विचारों का आदान-प्रदान किया। ● इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की, विशेष रूप से वर्तमान कोविड -19 महामारी के दौरान टीके की आपूर्ति के साथ। ● भारत-प्रशांत में आसियान केंद्रीयता के लिए भारत के समर्थन का स्वागत किया और संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक भारत-आसियान सहयोग की आशा की। **अन्य बिंदु** ● दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित साझा हित और चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कवर किया। ● अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से UNCLOS के पालन को बनाए रखने सहित क्षेत्र में नियम-आधारित आदेश को बढ़ावा देने के महत्व को नोट किया। ● दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखने और नेविगेशन तथा ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की।

IAS BABA

TLP+ Mains Answer Writing Program - 2022

Mains Test - Based Mentorship Program.

- **30 UPSC Level Mocks**
  (14 Sectional, 6 Essay, 10 FLT's)
- **1:1 Mentorship**
- **Discussion Classes After Test**
- **Detailed Synopsis**
- **Flexible Tests**

Toppers Recommended

Scan here to know more

REGISTER NOW

विविध

01 अक्टूबर : अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	**द्वारा:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय • बुजुर्ग लाइन 14567 राष्ट्र को समर्पित • वरिष्ठ सक्षम नागरिक पुनर्रोजगार इन डिग्निटी (SACRED) पोर्टल लॉन्च करना • सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल लॉन्च करना **वरिष्ठ सक्षम नागरिकों के बारे में डिग्निटी (SACRED) पोर्टल में रोजगार** • रोजगार चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और रोजगार प्रदाताओं को एक मंच पर लाने के लिए एक आईटी पोर्टल विकसित किया जाएगा • इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक स्वस्थ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीना। **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल के बारे में** • यह ऐसे व्यक्तियों की मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिये सेवाएँ मुहैया कराने संबंधी क्षेत्र में रुचि रखने वाले उद्यमियों को सहयोग प्रदान करते हो। • बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (EEC) की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित • सेज पोर्टल (SAGE Portal) विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला 'वन-स्टॉप एक्सेस' होगा।
'राज्य पोषण प्रोफाइल' (एसएनपी)	**सुर्ख़ियों में:** नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई), भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) के साथ संयुक्त प्रयास में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 'राज्य पोषण प्रोफाइल' लॉन्च किया। • 'स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल' (एसएनपी) एनएफएचएस-राउंड 3, 4 और 5 पर आधारित पोषण परिणामों, तत्काल और अंतर्निहित निर्धारकों तथा हस्तक्षेपों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। • एसएनपी में महत्वपूर्ण डेटा का एक व्यापक संकलन शामिल है जो नीतिगत निर्णयों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और क्षेत्र में अनुसंधान की सुविधा प्रदान कर सकता है। वेस्टिंग, स्टंटिंग, एनीमिया, कम वजन और अधिक वजन और एनसीडी (मधुमेह और उच्च रक्तचाप) जैसे प्रमुख संकेतकों का प्रवृत्ति विश्लेषण जिलों में प्रदर्शन की परिवर्तनशीलता को प्रदर्शित करता है। • यह रिपोर्ट में देश के सबसे अच्छे और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों, सबसे अधिक बोझ वाले जिलों और शीर्ष कवरेज वाले जिलों को उजागर किया गया है। • एसएनपी हेडकाउंट-आधारित विश्लेषण और एनएफएचएस-5 के डेटा के उपयोग पर आधारित हैं, जो डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता वाले राज्य में प्राथमिकता वाले जिलों और जिलों की संख्या की पहचान करने में मदद करते हैं। प्रत्येक एसएनपी ने बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण बातों को शामिल किया है तथा उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां राज्य में और सुधार करने की क्षमता है।
वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार	**संदर्भ:** उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ गेरिएट्रिशन (senior geriatrician) विशेषज्ञ वी.एस. नटराजन को वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। • पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने उद्यम (डॉ वी एस नटराजन जराचिकित्सा फाउंडेशन) के माध्यम से बड़ों के स्वस्थ कल्याण के लिए विभिन्न पहल कर रहे हैं। • वयोश्रेष्ठ सम्मान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित पुरस्कारों की एक योजना है। • यह धीरे-धीरे राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थिति में बढ़ गया, बुजुर्गों के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान करने में शामिल संस्थानों के लिए, विशेष रूप से गरीब वरिष्ठ नागरिकों और प्रतिष्ठित नागरिकों को उनकी सेवा/उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए।
गेमिंग विकार और रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण	• डब्ल्यूएचओ के अनुसार, गेमिंग डिसऑर्डर को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ऑफ डिजीज (ICD-11) के 11 वें संशोधन में परिभाषित किया गया है, जो गेमिंग पर बिगड़े हुए नियंत्रण की विशेषता है। • गेमिंग से लेकर अन्य गतिविधियों तक गेमिंग को दी गई प्राथमिकता, गेमिंग को इस हद तक नकारात्मक परिणामों की घटना

(ICD)	के बावजूद अन्य रुचियों और दैनिक गतिविधियों, और गेमिंग की निरंतरता या वृद्धि पर वरीयता लेता है। ● गेमिंग विकार "लगातार और आवर्ती गेमिंग व्यवहार के एक पैटर्न की विशेषता है" जहां एक खिलाड़ी अन्य दैनिक गतिविधियों और उस बिंदु पर रुचि के लिए गेमिंग को प्राथमिकता देना शुरू करता है। ● यह उनके रिश्तों, काम और शिक्षा को प्रभावित करना शुरू कर देता है जिसके कारण भारत के चिकित्सकों को बैठकर गहराई से ध्यान देना पड़ेगा। ● WHO द्वारा जून में ज़ारी रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के 11वें पुनरीक्षण के मसौदे में इसे "विकार" के रूप में शामिल किया गया है। जबकि वर्गीकरण का उद्देश्य दिशा निर्देशों के एक समूह के रूप में कार्य करना है, ऐसे में ICD -11 कई देशों में स्वास्थ्य देखभाल नीतियों, निदान और उपचार विकल्पों के निर्धारण को प्रभावित करता है। ● इसका उपयोग दुनिया भर के चिकित्सकों द्वारा स्थितियों का निदान करने के लिए और शोधकर्ताओं द्वारा स्थितियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। ● ICD में एक विकार को शामिल करना एक विचार है जिसे देश सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों की योजना बनाते समय और विकारों के रुझानों की निगरानी करते समय ध्यान में रखते हैं।
मिहिदाना	**सुर्ख़ियों में:** स्वदेशी तथा भौगोलिक पहचान (GI) टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के एक प्रयत्न के रूप में, पश्चिम बंगाल के बर्धमान से सोर्स की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात कर दी गई है। ● जयनगरर मोआ (Jaynagarer Moa): हाल ही में, पश्चिम बंगाल के जयनगर में पोप्ड-राइस बॉल तथा ताजे खजूर के गुड़ से तैयार एक सदी पुराने मीठे पकवान-जयनगर मोआ की ऐतिहासिक विरासत का समारोह मनाने के लिए इंडिया पोस्ट ने एपीडा के सहयोग से एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया लिफाफा जारी किया था। ● पश्चिम बंगाल के बर्धमान को 2017 में एक सदी पुराने मीठे पकवानों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ था। **GI टैग क्या है?** ● GI टैग एक विशिष्ट भौगोलिक मूल को उल्लेखित करने वाला एक प्रतीक है और इसमें वैसी गुणवत्ता होती है या उस मूल के कारण वह विख्यात होता है। ● GI एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) होता है जो आईपीआर के अन्य रूपों से भिन्न होता है क्योंकि यह एक विशेष रूप से निर्धारित स्थान में समुदाय की विशिष्टता को श्रेय देता है, बजाये किसी व्यक्ति विशेष के जैसाकि ट्रेडमार्क या पैटेंटों के मामले में होता है।
गुडूची (Guduchi)	**संदर्भ :** आयुष मंत्रालय ने हाल ही में गुडुची (टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया) के उपयोग को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर ध्यान दिया है। यह परामर्श यह पुष्टि करने के लिए जारी किया जा रहा है कि गुडुची (टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया) उपयोग करने के लिहाज से सुरक्षित है लेकिन कुछ समान दिखने वाले पौधे जैसे टिनोस्पोरा क्रिस्पा हानिकारक हो सकते हैं। **गुडुची क्या है?** ● गुडूची एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है और आयुष प्रणालियों में लंबे समय से चिकित्सीय में इसका उपयोग होता रहा है। ● यह पूरे भारत में पाए जाने वाले कमजोर और मांसल तने की एक बड़ी, चमकदार, बारहमासी, पर्णपाती चढ़ने वाली झाड़ी है। ● यह लोक और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला पौधा है। ● संभावित औषधीय गुणों में मधुमेह विरोधी, गठिया विरोधी, एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-एलर्जी, तनाव-विरोधी, मलेरिया-रोधी

	आदि शामिल हैं।
साहित्य में नोबेल पुरस्कार	• साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुलराजक गुरनाह को दिया गया है। अब्दुलराजक गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर काफी कुछ लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। • श्री गुरनाह 2007 में जिम्बाब्वे डोरिस लेसिंग के बाद पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी लेखक हैं, और नाइजीरिया के वोले सोयिंका के बाद उप-सहारा अफ्रीका से रंग के दूसरे लेखक हैं, जिन्होंने 1986 में जीत हासिल की थी। • उनके उपन्यासों में पैराडाइज शामिल है, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औपनिवेशिक पूर्वी अफ्रीका में स्थापित है और इसे फिक्शन तथा डेजर्टन के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम	**सुर्खियों में:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। **10 लाख रुपये का कोष :** • इनमें से प्रत्येक बच्चे को PM CARES फंड से 10 लाख रुपये का एक कोष आवंटित किए जाएंगे। • यह 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा प्रदान करेगा। • 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, उसे कॉर्पस राशि (corpus amount) मिल जाएगी। **बच्चों को शिक्षा (10 वर्ष से कम):** • केन्द्रीय विद्यालयों/निजी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करना। • समान पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक्स के लिए PM CARES भुगतान करेगा। • यदि बच्चे का प्रवेश किसी निजी स्कूल में होता है तो आरटीई के मानदंडों के अनुसार शुल्क प्रदान किया जाएगा। **बच्चों को शिक्षा (11-18 वर्ष):** • बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। • यदि बच्चे को अभिभावक की देखरेख में जारी रखना है, तो उसे नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। **उच्च शिक्षा:** • ट्यूशन फीस/शैक्षिक ऋण के बराबर छात्रवृत्ति का प्रावधान। • PM-CARES फंड द्वारा ऋण पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। **स्वास्थ्य बीमा:** • आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी बच्चों को लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। • बच्चे के 18 साल के होने तक प्रीमियम राशि का भुगतान PM-CARES द्वारा किया जाएगा।
नोबेल शांति पुरस्कार 2021	• फिलीपींस के पत्रकार मारिया रसा और रूस के दिमित्री मुराटोव ने उन देशों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई के लिए 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता, जहां पत्रकारों को लगातार हमलों, उत्पीड़न और हत्या का सामना करना पड़ा है। • 2012 में सुश्री रेसा ने एक समाचार वेबसाइट रैपर की सह-स्थापना की, जिसने फिलीपींस में राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के "विवादास्पद, जानलेवा एंटी-ड्रग अभियान" पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया है।

	• श्री मुराटोव 1993 में स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र नोवाया गज़ेटा के संस्थापकों में से एक थे, जिसे नोबेल समिति ने "आज रूस में सबसे स्वतंत्र समाचार पत्र, सत्ता के प्रति मौलिक रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ" कहा।
डॉ. तीजन बाई ने 'गोल' कार्यक्रम के मेंटर्स और मेंटीज़ को प्रेरित किया	• पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉ. तीजन बाई ने गोल कार्यक्रम पर प्रेरणा मास्टरक्लास के हिस्से के रूप में 9 अक्टूबर, 2021 को इस कार्यक्रम के मेंटर्स और मेंटीज को संबोधित किया। • एक प्रसिद्ध पांडवानी लोक गायिका। **लीडर्स (GOAL) प्रोग्राम ऑनलाइन होने के बारे में** • जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) और फेसबुक इंडिया द्वारा। • जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक इंडिया द्वारा 'गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स' (GOAL) कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को उनके पेशेवर-आर्थिक उत्थान को कौशल विकास के जरिए गति देना है। साथ ही डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने पर भी इस कार्यक्रम का खास ध्यान है। • इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 5,000 आदिवासी युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे व्यवसाय करने के नए तरीके सीखने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बतौर एक टूल उसकी पूरी क्षमता के साथ उपयोग कर सकें। • यह आदिवासी युवाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से परामर्श प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभा का पता लगाने के एक माध्यम के रूप में तैयार किया गया है। यह उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा और साथ ही उनके समाज के सर्वांगीण उत्थान में योगदान देगा।
177 संभावित जनजातीय उत्पादों के लिए जीआई टैग	**सुर्ख़ियों में:** 56 जीआई उत्पादों के विपणन के अलावा ट्राइफेड उन 177 संभावित उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए भी काम कर रहा है, जिनकी देश के पूर्वोत्तर, दक्षिण और उत्तर भाग में स्थित संचालन क्षेत्रों के तहत पहचान की गई है। ट्राइफेड के जीआई हस्तक्षेप और विदेशों में भारतीय मिशनों में आत्मानिर्भर कोने की स्थापना का उद्देश्य है: • मूल उत्पादकों के साथ-साथ उनके उत्पादों के हितों की भी रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उत्पादक को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य में उनके उत्तम माल के लिए अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो। • स्वदेशी उत्पादों की भारत और वैश्विक बाजार में मान्यता सुनिश्चित करना। • जनजातीय विशिष्ट भौगोलिक स्थिति से विलुप्त हो रही कला और शिल्प को पुनर्जीवित करना। **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED)** • एक राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च संगठन, 1987 में अस्तित्व में आया। • उद्देश्य: देश की जनजातियों द्वारा एकत्रित 'लघु वनोपज (MFP) का अच्छा मूल्य प्रदान करना। • यह जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। • ट्राइफेड का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क है।
डाक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	• अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में रामेश्वरम के तीर्थस्थल पम्बन द्वीप पर, फिर मद्रास प्रेसीडेंसी और अब तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उन्होंने 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक किया। • डॉ. कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV-3) के प्रोजेक्ट हेड थे। यह भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था जिसने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। • DRDO के निदेशक के रूप में, उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) और पांच परियोजनाओं का संचालन किया। उसके अधीन पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि का विकास हुआ। • एपीजे अब्दुल कलाम को बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास में उनके योगदान के लिए "भारत के मिसाइल मैन" के रूप में जाना जाता है। • 'कपिल (KAPILA)' (बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम) अभियान • इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अपने आविष्कार के पेटेंट के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली की जानकारी मिलेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। • 15 से 23 अक्टूबर: बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह

	K मिसाइलों का परिवार ● दिवंगत डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर कोडनेम ● मिसाइलों का K परिवार मुख्य रूप से सबमरीन लॉन्चेड बैलिस्टिक मिसाइल (SLBMs) है। ● इन मिसाइलों को भारत के अरिहंत श्रेणी के परमाणु संचालित प्लेटफार्मों से पनडुब्बियों से दागा जाता है। ● **स्वदेशी रूप से विकसित:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ● इन नौसैनिक मंच से प्रक्षेपित मिसाइलों का विकास 1990 के दशक के अंत में भारत के परमाणु त्रय (nuclear triad) को पूरा करने की दिशा में एक कदम के रूप में शुरू हुआ - भूमि, समुद्र और वायु आधारित संपत्तियों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता। ● ये मिसाइलें अपने भूमि आधारित समकक्षों की तुलना में हल्की, छोटी और अधिक गुप्त हैं। ● अग्नि शृंखला की मिसाइलें भूमि आधारित हैं जो मध्यम और अंतरमहाद्वीपीय दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ● "अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और सुंदर दिमाग का देश बनना है, तो मुझे दृढ़ता से लगता है कि तीन प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो फर्क कर सकते हैं। वे पिता, माता और शिक्षक हैं। " - डाक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
केरावन केरल परियोजना	**प्रसंग :** केरल ने हाल ही में कारवां पर अपनी पर्यटन परियोजना शुरू की है - केरावन केरल। ● हितधारकों के अनुकूल कारवां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह एक अनूठी पहल है। **इस परियोजना की विशेषताएं** ● कारवां पार्क प्राकृतिक वातावरण में स्थित होंगे। ● पर्यटकों की सुरक्षा पर जोर। ● कारवां पार्क बनाने में स्थानीय संसाधनों का सतत उपयोग। ● प्रत्येक कारवां पार्क में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। ● इस परियोजना का मूल विषय कारवां की विलासिता को पार्क के प्राकृतिक स्वरूप के साथ जोड़ना है। ● कारवां वाहनों की खरीद के लिए निवेश सब्सिडी सहित आकर्षक प्रोत्साहन। ● कारवां पार्क निजी, सार्वजनिक या संयुक्त क्षेत्र में विकसित किए जा सकते हैं। ● पर्यटन सीजन के दौरान 24x7 परिचालन। ● यह मुख्य सड़क से सुहावने मौसम वाली सड़कों से जुड़ा हुआ है।
भारत ने 100 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक को पार किया	**संदर्भ :** भारत ने अभियान शुरू होने के लगभग नौ महीनों में गुरुवार को COVID-19 टीकों की 100 करोड़ खुराक पूरी की। ● इसने योग्य आबादी के लगभग 30% (291 मिलियन) को पूरी तरह से टीका लगाया है और 707 मिलियन ने पहली खुराक ली है। ● भारत का लक्ष्य 2021 के अंत तक लगभग एक अरब लोगों को पूरी तरह से टीकाकरण करना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभियान को और गति देने की जरूरत है। ● यह मील का पत्थर भारत को एक अरब के आंकड़े तक पहुंचने वाला दूसरा देश होगा है, चीन ने इसे जून में पार किया। **भारत में टीकाकरण अभियान के लिए प्रारंभिक चुनौतियाँ** ● तार्किक समस्याएं ● आपूर्ति की बाधाएं ● वैक्सीन हिचकिचाहट (hesitancy) ● कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर **भारत किस टीके का उपयोग कर रहा है?** ● भारत तीन टीकों का उपयोग कर रहा है - ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका जैब, जिसे स्थानीय रूप से कोविशील्ड के रूप में जाना जाता है; भारतीय फर्म भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सिन; और रूसी द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी (Sputnik V)। ● भारत ने 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अपने पहले टीके को भी मंजूरी दे दी है। तीन खुराक वाली ZyCoV-D वैक्सीन कोविद -19 के खिलाफ दुनिया की पहली DNA वैक्सीन है। इसके कुछ हफ्तों में रोल आउट होने की उम्मीद है।

	• ZyCov-D को जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से विकसित किया गया है। • सरकार ने भारतीय फार्मा कंपनी सिप्ला को मॉडर्न के टीके के आयात के लिए भी अधिकृत किया है, जिसने कोविड -19 के खिलाफ लगभग 95% प्रभावकारिता दिखाई है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत को कितनी खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। • कई और टीके अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं। **100 स्मारक रोशन (100 monuments illuminated)** • भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भी 100 करोड़ COVID-19 वैक्सीन खुराक के मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए तिरंगे में 100 स्मारकों को रोशन किया। • इन स्मारकों में शामिल हैं: ○ **दिल्ली:** लाल किला, हुमायूँ का मकबरा और कुतुब मीनार। ○ **उत्तर प्रदेश:** आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। ○ **तमिलनाडु:** ओडिशा में कोणार्क मंदिर और मामल्लापुरम रथ मंदिर।
सक्षम केंद्र	**संदर्भ:** आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत 13 राज्यों के 77 जिलों में 4-8 अक्टूबर, 2021 के दौरान कुल 152 वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र (सक्षम केंद्र) शुरू किए गए। • वित्तीय साक्षरता और सेवा वितरण केंद्र (CFL & SD) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (SHG) परिवारों की बुनियादी वित्तीय जरूरतों के लिए एक जगह सभी वित्तीय समाधन सेवा/सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। • इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को वित्तीय सेवाओं (बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि) की पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। • इन केंद्रों का प्रबंधन मुख्यत क्लस्टर स्तर संघों (CLFs) के स्तर पर एसएचजी नेटवर्क द्वारा प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) की मदद से किया जाएगा। • इन प्रशिक्षित सीआरपी को जिले के अग्रणी बैंक द्वारा स्थापित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETIs) में छह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। • इन सभी संसाधन व्यक्तियों, जिन्हें लोकप्रिय रूप से वित्तीय साक्षरता समुदाय संसाधन व्यक्ति (FL CRPs) के रूप में जाना जाता है, ने स्थानीय भाषाओं में एक प्रशिक्षण टूल किट भी प्रदान की। • ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने "सक्षम" नामक एक मोबाइल और वेब-आधारित एप्लिकेशन भी विकसित किया है। ○ इसका उपयोग केंद्र के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति द्वारा प्रत्येक SHG और गांव के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं की पहुंच जानने, प्रमुख अंतराल की पहचान करने और तदनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने तथा आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ○ यह एप्लिकेशन रणनीति में मध्य-पाठ्यक्रम सुधार के लिए नियमित अंतराल पर कार्यक्रम के प्रभाव को भी मापेगा, यदि कोई हो।
ढोल (Dhole)	• हाल के एक अध्ययन ने 114 प्राथमिकता वाले तालुकों / तहसीलों की पहचान की है जहां ढोल या एशियाई जंगली कुत्ते (Cuon alpinus) के लिए जनसंख्या कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आवासों को समेकित किया जा सकता है। • यह मध्य, दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करने वाला एक शीर्ष सामाजिक मांसाहारी जीव है। • भारत शायद सबसे बड़ी संख्या में ढोले का समर्थन करता है, जिसकी प्रमुख आबादी तीन परिदृश्यों - पश्चिमी घाट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। • IUCN - लुप्तप्राय (Endangered) • बाघ के अलावा भारत में ढोल एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जिसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। • इसे CITES की परिशिष्ट II में और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 [Wildlife (Protection) Act] के तहत

अनुसूची II में सूचीबद्ध किया गया है।

- इस गिरावट में योगदान देने वाले कारक: निवास स्थान की हानि, शिकार की हानि, अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा, पशुधन के शिकार के कारण उत्पीड़न और घरेलू कुत्तों से रोग हस्तांतरण।
- 2014 में, भारत सरकार ने विशाखापत्तनम में इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान (IGZP) में अपने पहले ढोल संरक्षण प्रजनन केंद्र

को मंजूरी दी।

IAS BABA

UPSC OPTIONAL

Mains Test Series

- History Optional
- Public Administration Optional
- Anthropology Optional
- Geography Optional
- Kannada Optional

REGISTER NOW

Scan here to know more

पार्टियों को संवैधानिक बनाना

एक राजनीतिक दल क्या है?

- राजनीतिक दल नागरिकों का एक संगठित समूह है जो शासन पर समान विचार रखता है। वे एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं जो उनके द्वारा घोषित एजेंडा और नीति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से सरकार का नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है।
- वे लोगों और सरकार के प्रतिनिधि तंत्र के बीच अपरिहार्य कड़ी हैं।
- राजनीतिक दल लोगों और सरकार या विपक्ष में उनका प्रतिनिधित्व करने वालों के बीच एक सतत संबंध बनाए रखते हैं।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय संविधान, दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक, सहकारी समितियों से संबंधित है, लेकिन राजनीतिक दलों पर नहीं।
- सहकारी समितियां बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, लेकिन राजनीतिक दल बनाने का अधिकार नहीं है।

राजनीतिक दलों की कानूनी स्थिति क्या है?

- लगभग हर लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का गैर-कानूनी विकास होता है।
- अमेरिकी संविधान राजनीतिक दलों के अस्तित्व को नहीं मानता है। ब्रिटेन में भी, राजनीतिक दल अभी भी कानून से अनजान हैं।
- इसी तरह, भारत में राजनीतिक दल गैर-संवैधानिक हैं, लेकिन वे राजनीतिक व्यवस्था की सांस लेने वाली हवा हैं।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A(5) भारत में राजनीतिक दलों से संबंधित एकमात्र प्रमुख वैधानिक प्रावधान है।
  - यह आदेश देता है कि एक राजनीतिक दल भारत के संविधान के अनुसार स्थापित कानून और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा।

जर्मन मॉडल क्या है?

- जर्मनी के संघीय गणराज्य का मूल कानून (1949) राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा देता है।
- जर्मनी के मूल कानून का अनुच्छेद 21 उनकी स्थिति, अधिकारों, कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। यह प्रावधान:
  - राजनीतिक दल लोगों की राजनीतिक इच्छा के निर्माण में भाग लेंगे। उन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जा सकता है। उनका आंतरिक संगठन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। उन्हें अपनी संपत्ति और फंड के स्रोतों और उपयोग के लिए सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए।
  - जो पार्टियां स्वतंत्र लोकतांत्रिक बुनियादी व्यवस्था को कमजोर करने या समाप्त करने या जर्मनी के संघीय गणराज्य के अस्तित्व को खतरे में डालने की कोशिश करती हैं, वे असंवैधानिक होंगी। संघीय संवैधानिक न्यायालय असंवैधानिकता के प्रश्न पर शासन करेगा।
  - राजनीतिक दलों के विनियमन का विवरण संघीय कानूनों द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- राजनीतिक दलों को संवैधानिक बनाने का जर्मन मॉडल यू.एस. और यू.के. मॉडल की तुलना में भारत के लिए अधिक वांछनीय है।

भारतीय राजनीतिक दलों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?

- विकसित देशों में राजनीतिक दल आंतरिक लोकतंत्र के उच्च स्तर को बनाए रखते हैं लेकिन भारत में इसका अभाव है।
  - अधिकांश भारतीय पार्टियों में समय-समय पर चुनाव नहीं होते हैं।
  - अधिकांश राजनीतिक दल पारिवारिक जागीर हैं, जहां आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है।
- अधिकांश दल खुले तौर पर जाति- या धार्मिक-आधारित हैं।
- लगभग सभी राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति संदिग्ध और अपारदर्शी है।

आगे की राह

- राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र और सुरक्षा वाल्व के एजेंट हैं। उन्हें सुधार की सख्त जरूरत है।
- इसलिए, राजनीतिक दलों को पार्टी में लोकतंत्र सुनिश्चित करने, उनके वित्त में पारदर्शिता प्रदान करने और उन्हें सांप्रदायिक बनाने के लिए संवैधानिक बनाने का समय आ गया है।

गांधी जी एक दार्शनिक के रूप में

दर्शन और नैतिकता

- दर्शनशास्त्र शुरू में केवल तीन सभ्यताओं - चीनी, ग्रीक और भारतीय में प्रचलित था।
- इन सभ्यताओं में, दर्शन ने जीवन के अन्य तरीकों से अलग जीवन के तरीके के रूप में कार्य किया जो अलौकिक शक्तियों में विश्वास में निहित थे।
- लेकिन उन प्राचीन काल में प्रचलित जीवन के दार्शनिक तरीकों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है - एक तत्वमीमांसा-आधारित दार्शनिक जीवन शैली और एक नैतिकता-आधारित दार्शनिक जीवन शैली।
- बुद्ध, सुकरात और कन्फ्यूशियस द्वारा दिए गए दर्शन को छोड़कर अन्य सभी दर्शनों ने जीवन के तत्वमीमांसा के नेतृत्व वाले तरीकों का प्रचार किया।
- नैतिकता के नेतृत्व वाले दर्शन में, व्यक्ति को उसके अस्तित्व की स्थिति से नैतिक रूप से उच्च स्थिति में बदलने और इस प्रक्रिया में उसे मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है।
- तत्वमीमांसा के नेतृत्व वाले जीवन के दार्शनिक तरीके में, एक उच्च नैतिक स्थिति के बजाय, दार्शनिक समझ की एक उच्च स्थिति (अंतर्दृष्टि) "परम" के साथ एक संवाद प्राप्त करने का प्रयास करता है। यहाँ, नैतिकता की केवल एक गौण भूमिका है।
- 529CE में एक बार ईसाई धर्म ने यूरोप में जीवन के सभी गैर-ईसाई तरीकों पर प्रतिबंध लगा दिया, तो दर्शन 17वीं शताब्दी में यूरोप में जीवन प्रथाओं की वकालत किए बिना केवल सैद्धांतिक अनुशासन के रूप में फिर से उभरा। इसके साथ ही, "जीवन के दार्शनिक तरीके" का विचार यूरोप में विलुप्त हो गया।
- जीवन के एक तरीके के रूप में दर्शनशास्त्र से एक सैद्धांतिक अनुशासन के रूप में दर्शनशास्त्र में बदलाव को आधुनिक पश्चिमी दर्शन के जन्म के रूप में मनाया जाता है।

गांधी और दर्शन

- गांधी आध्यात्मिक थे, अगर अध्यात्म का मतलब आत्मकेंद्रितता में कमी है। 1929 में "ईश्वर सत्य है" से "सत्य ही ईश्वर है" में उनकी पारी का उद्देश्य नैतिकता को उनके दर्शन का "पहला सिद्धांत" बनाना था।
- गांधी' ने 1907 में बहुत पहले कहा था कि "नैतिकता को एक धर्म के रूप में देखा जाना चाहिए"।
- गांधी, बुद्ध की तरह, एक नैतिक परिणामवादी थे कि उनके नैतिक तरीके का उद्देश्य आत्म-केंद्रितता को कम करना और सभी (सर्वोदय) की भलाई के लिए एक चिंता को बढ़ावा देना था।
- जो बात गांधी को बुद्ध से अलग बनाती है, वह है कि गांधी व्यक्तिगत मोक्ष (बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा) के अलावा, संपूर्ण मानवता के लिए स्वतंत्रता (अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से) का विकास करना चाहते थे। केवल राजनीतिक कार्रवाई के माध्यम से, गांधीवादी नैतिकता के अनुसार, हम इस रचनात्मक कार्यक्रम को लागू कर सकते हैं।
- इसलिए, गांधी का दार्शनिक जीवन एक समाजवादी समाज के लिए एक स्पष्ट इच्छा है - क्योंकि स्वार्थ की कमी पर आधारित नैतिकता तार्किक कारणों से केवल समाजवादी जीवन शैली को स्वीकार कर सकती है।
- भले ही "साधारण जीवन" के विचार जैसे समाजवादी विषय उपमहाद्वीप के सभी दार्शनिक स्कूलों का हिस्सा थे, यह केवल गांधी में था कि उन्होंने एक स्पष्ट राजनीतिक/वैचारिक आयाम हासिल किया - गांधी के आश्रम ऐसे समाजवादी कम्यून्स (communes) थे।
- कई मौकों पर गांधी ने कहा था कि वह "शून्य को कम करने" की आकांक्षा रखते हैं, अर्थात स्वार्थ/आत्मकेंद्रितता को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। बुद्ध के लिए भी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि जैसे गुणों की खेती के माध्यम से आत्म-केंद्रितता की कमी, सर्वोदय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण थी।

निष्कर्ष

- गांधी द्वारा प्रचारित राजनीतिक रूप से आरोपित, अहिंसक और नैतिक शैली का दर्शन एक आध्यात्मिक बनाने के लिए है - एक अभ्यासी को अन्य सभी प्राणियों के कल्याण के लिए गुरुत्वाकर्षण और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) को भंग किया गया

संदर्भ: आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB), जिसका पहला औद्योगिक प्रतिष्ठान 1801 में स्थापित किया गया था, 1 अक्टूबर से समाप्त हो जाएगा और इसके 41 फैक्ट्रियों को सात नई कॉरपोरेट इकाइयों में बांटा जाएगा। आयुध निर्माणी बोर्ड भारत में हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रमुख उत्पादक है।

निगमीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क

- यह तर्क दिया गया है कि OFB के एकाधिकार ने कम उत्पादकता, उत्पादन की उच्च लागत और उच्च प्रबंधकीय स्तरों पर लचीलेपन की कमी के अलावा, नवाचार को समाप्त कर दिया है।
- OFB का निगमीकरण: पिछले दो दशकों में स्थापित रक्षा सुधारों पर कम से कम तीन विशेषज्ञ समितियों द्वारा OFB को

कॉरपोरेट संस्थाओं (सरकार के स्वामित्व वाली यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के स्वामित्व वाली) में पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी -

- TKS नायर समिति (2000)
- विजय केलकर समिति (2005)
- वाइस एडमिरल रमन पुरी समिति (2015)
- पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा गठित और लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकातकर की अध्यक्षता में चौथी समिति ने निगमीकरण का सुझाव नहीं दिया, लेकिन पिछले प्रदर्शन को देखते हुए सभी आयुध इकाइयों के नियमित ऑडिट की सिफारिश की।

- केंद्रीय तर्क यह रहा है कि निगमीकरण, जो इन संस्थाओं को कंपनी अधिनियम के दायरे में लाएगा, को बढ़ावा मिलेगा।
- **दक्षता में सुधार**
  - उत्पादों को लागत-प्रतिस्पर्धी बनाना
  - उनकी गुणवत्ता बढ़ाना
- कर्मचारियों ने तर्क दिया कि निगमीकरण "निजीकरण की दिशा में एक कदम" था। उन्होंने नौकरी छूटने की आशंका व्यक्त की, और कहा कि एक कॉर्पोरेट इकाई अपनी अस्थिर मांग-आपूर्ति की गतिशीलता के साथ रक्षा उत्पादों के अद्वितीय बाजार वातावरण से बचने में सक्षम नहीं होगी।

OFB के निगमीकरण की प्रगति क्या रही है?

- मई 2020 में, आत्मानिर्भर भारत पहल के चौथे दौर के दौरान, वित्त मंत्री ने "आयुध आपूर्तिकर्ताओं में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार" के लिए OFB को निगमित करने के निर्णय की घोषणा की।
- निगमीकरण के लिए मंत्रियों का एक अधिकार प्राप्त समूह (EGoM) का गठन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अध्यक्ष के रूप में किया गया था, जो "उनके वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा करते हुए कर्मचारियों के संक्रमण समर्थन और पुनर्नियोजन योजना सहित पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करने के लिए" थे।
- अक्टूबर 2020 में, सरकार ने श्रमिक संघों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को "अमान्य और अवैध" घोषित किया।
- जैसा कि सरकार और विरोध कर रहे श्रमिकों के बीच कोई सुलह नहीं हो सका, सरकार ने इस जून में घोषणा की कि EGoM को सात DPSUs - मुनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड में विभाजित किया जाएगा।
- इनमें से प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम समान श्रेणी के उत्पादों के निर्माण में शामिल आयुध कारखानों के समूह चलाएंगे। OFB का हिस्सा रहे प्रशिक्षण और विपणन प्रतिष्ठानों को भी सात सार्वजनिक उपक्रमों में विभाजित किया जाएगा।

MSP मांग और संभावित समाधान

संदर्भ: पिछले 10 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए किसानों की स्पष्ट मांगें हैं:

- तीन कृषि कानूनों को रद्द करना
- सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी आश्वासन
- गेहूं और धान के लिए चल रही MSP योजना को जारी रखना।

सरकार की स्थिति क्या है?

- ऐसे संकेत हैं कि सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस लेने या रद्द करने की ओर झुक रही थी।
- हालांकि, सरकार सभी फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

- MSP सरकार द्वारा किसानों से फसल खरीदने के लिए निर्धारित मूल्य है, चाहे फसलों का बाजार मूल्य कुछ भी हो।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर बुवाई के समय से पहले आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP की घोषणा की जाती है।
- CACP कोई वैधानिक निकाय नहीं है बल्कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह MSP की सिफारिश कर सकता है, लेकिन फिक्सिंग (या यहां तक कि फिक्सिंग नहीं) और प्रवर्तन पर निर्णय अंततः सरकार के पास है।
- समर्थन मूल्य आम तौर पर किसानों के निर्णयों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे फसलों के लिए भूमि आवंटन, उत्पादित होने वाली फसलों की मात्रा आदि
- एमएसपी बाजार को स्पष्ट मूल्य संकेत प्रदान करने के अलावा किसानों की कृषि आय का आश्वासन देता है।
- प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से समर्थन देना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना है।
- सरकार फसलों के लिए MSPs की घोषणा करती है, लेकिन उनके कार्यान्वयन को अनिवार्य करने वाला कोई कानून नहीं है।
- MSP किसी भी कानूनी समर्थन से रहित है। MSP तक पहुंच किसानों के लिए एक अधिकार नहीं है। वे इसे अधिकार के रूप में मांग नहीं सकते।

- केंद्र वर्तमान में CACP's की सिफारिशों के आधार पर 23 कृषि फर्मों के लिए MSPs तय करता है -
  - 7 अनाज - धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ।
  - 5 दालें - चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर।
  - 7 तिलहन - रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और नाइजरसीड।
  - 4 व्यावसायिक फसलें - कपास, गन्ना, खोपरा और कच्चा जूट।

MSP का क्या है?

- जिन 23 फसलों के लिए MSP की घोषणा की गई है, उनमें से अधिकांश निजी कंपनियों द्वारा खरीदी जाती हैं और कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है।
- कभी ये फसलें MSP से काफी कम बिकती हैं और कभी MSP से थोड़ा ज्यादा मिलता है।
- इसलिए किसान कानूनी गारंटी चाहते हैं कि फसलों को केवल MSP या उससे अधिक पर बेचा जा सके।
- लेकिन सरकार इस समय कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय कई बार मौखिक रूप से दोहराए जाने के कि वह अपने वर्तमान MSP शासन को जारी रखेगी, जिसमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, एमपी और यूपी के कुछ हिस्सों में गेहूं और धान शामिल हैं। हालांकि किसानों ने झुकने से इंकार कर दिया है।

क्या राज्य स्तरीय नीतियां किसानों को उनकी फसलों के लिए MSP सुनिश्चित करने का आश्वासन दे सकती हैं?

- कुछ राज्यों ने अपनी राज्य-स्तरीय नीतियों के तहत किसानों को MSP दरों से नीचे बेचने वाली फसलों के लिए मुआवजा देना शुरू कर दिया है।
- पिछले वर्षों में, भावांतर भरपायी योजना (Bhavantar Bharpayi Yojna) के तहत मध्य प्रदेश (एमपी) जैसे कुछ राज्य, हरियाणा, केरल अपनी राज्य मूल्य निर्धारित करते हैं और यदि कवर की गई फसलें उस कीमत से कम पर बेचीं जाती है तो राज्य सरकार पंजीकृत किसानों को उनके संबंधित पोर्टल पर अंतर का भुगतान करती है।
- मध्य प्रदेश सरकार ने जहां अनाज, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को अपनी योजना के तहत कवर किया है, वहीं हरियाणा और केरल ने केवल बागवानी फसलों को कवर किया है। हाल ही में हरियाणा राज्य ने बाजरा को अपनी योजना में शामिल किया है।
- ये योजनाएं अच्छी हैं लेकिन राज्य सरकारों के पास ऐसी नीतियों को बनाए रखने और लंबे समय में सभी फसलों को कवर करने के लिए संसाधन नहीं हैं।

उपाय क्या है?

- वर्तमान MSP शासन के साथ, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) जैसे निगमों को केंद्र सरकार द्वारा अनाज के लिए गठित किया जाना चाहिए, जिनमें से कुछ केंद्र के वर्तमान MSP शासन के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- CCI बाजार में तब प्रवेश करता है जब 'कपास' (बिना कच्चा कपास) की कीमत CACP द्वारा निर्धारित MSP से कम हो जाती है। CCI फिर MSP पर कपास खरीदता है, जो बदले में निजी खिलाड़ियों को भी MSP के बराबर कीमतों की पेशकश करने के लिए मजबूर करता है ताकि CCI को बाजार से सभी कपास खरीदने से रोका जा सके।
- पिछले साल बासमती के मामले में, निजी व्यापारियों पर निर्भरता के कारण किसानों को बहुत कम मिला। यहीं पर CCI जैसा निगम कदम उठा कर किसानों को शोषण से रोकने के लिए एक निवारक की भूमिका निभा सकता है।
- जिस तरह गेहूं और धान के MSP, जिसे सरकार आरबीआई से कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) लेकर भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से खरीदती है, ऐसे निगम भी उसी नीति का पालन कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश में तिलहन और दालों का बहुत बड़ा बाजार है।
- कुछ किसान नेताओं ने सुझाव दिया कि यदि किसानों की फसल की कीमत निश्चित दर से कम हो जाती है, तो उन्हें मुआवजा देने के लिए एक राज्य-केंद्र संयुक्त "भावांतर योजना" भी शुरू की जा सकती है।

पटाखा निर्माताओं पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु सहित पटाखा उद्योग में सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच में बेरियम और इसके लवण जैसे जहरीले तत्वों के उपयोग पर प्रतिबंध के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का पता चला है।

तीन साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था?

- तीन साल पहले, कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया और आदेश जारी किया कि केवल कम उत्सर्जन और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए, सही समय पर टाइट रेस्ट्रिक्शन के साथ जब वे फट सके।
- SC ने बेरियम साल्ट जैसे रसायनों और कानून के अनुपालन में पटाखों पर लेबल लगाने पर भी रोक लगा दी।
- यह याचिका तीन बच्चों अर्जुन गोपाल, आरव भंडारी और ज़ोया राव भसीन की ओर से कोर्ट में साल 2015 में दायर की गई थी। इन बच्चों की उम्र अब तीन से चार साल के बीच है। बच्चों की तरफ से वकील गोपाल संकरानारायण ने पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाने की अपील की थी।

विवाद क्या है?

- पटाखे एक दहन प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइज़र का उपयोग करते हैं, और परिणामी विस्फोट, ऊर्जा जारी करते हुए, सामग्री को अत्यधिक गर्म अवस्था में फैलाता है। विस्फोटक मिश्रण में धातु के लवण 'उत्तेजित' होकर प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।
- मिश्रण में धातुएं, जिनके नाभिक (अलग-अलग द्रव्यमान संख्या) के बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉनों की एक अलग अरेंजमेंट होता है, इस प्रतिक्रिया में प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य उत्पन्न कर प्रभावशाली रंग उत्पन्न करते हैं।
- उदाहरण के लिए बेरियम यौगिक ग्रीन लाइट तथा स्ट्रोंटियम और लिथियम लवण, लाल रंग उत्पन्न करते हैं।
- लेकिन जैसा कि कई अध्ययनों से पता चलता है, पटाखों का जलना प्रदूषण का एक असामान्य और चरम स्रोत है, जो कणों और गैसों से बनता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2016 में दिल्ली में एक अध्ययन किया जिसमें उसने यह पाया की दीपावली के समय में एल्युमिनियम, बेरियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन और स्ट्रोंटियम का स्तर निम्न से अत्यधिक उच्च तक तेजी से बढ़ा।
- उदाहरण के लिए, बेरियम 0.268 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से बढ़कर 95.954 mcg/m3 हो गया।
- पटाखों से होने वाला प्रदूषण लोगों और जानवरों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और भारतीय शहरों में पहले से ही खराब परिवेशी वायु गुणवत्ता को बढ़ाता है।
- इसके परिणामस्वरूप अदालती मामलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया है, और अदालत ने अंततः उपयोग किए जाने वाले रसायनों के प्रकार के साथ-साथ उनकी मात्रा को भी प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है।
- गौरतलब है कि SC द्वारा नए फॉर्मूलेशन का पालन अधिकांश पटाखा निर्माताओं द्वारा किया जाता है। इसके आदेश के अनुसार, पटाखों पर कानूनी अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की जानकारी का लेबल नहीं लगाया जाता है।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि लगभग 2,000 निर्माताओं में से केवल 120 में पटाखों को ग्रीन करने के लिए अदालत के साथ काम करने की क्षमता और झुकाव था। इसलिए उद्योग हल्के नियमन की मांग कर रहा है क्योंकि कई नौकरियां इस पर निर्भर हैं।

ग्रीन पटाखों से क्या फर्क पड़ता है?

- केंद्र सरकार का कहना है कि नागपुर के माध्यम से राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CSIR-NEERI) पटाखों के साथ बाहर आया है जिसमें " प्रकाश उत्सर्जन और ध्वनि कम" है तथा पोटेशियम नाइट्रेट को ऑक्सीडेंट के रूप में 30% कम कण पदार्थ का उपयोग करते हैं।
- इन पटाखों के नाम हैं
  - सुरक्षित जल रिलीजर, जो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के उपयोग को कम करता है, लेकिन पारंपरिक पटाखों की ध्वनि तीव्रता से मेल खाता है
  - सुरक्षित न्यूनतम एल्युमिनियम, जहाँ एल्युमीनियम का उपयोग कम है
  - कम सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ सुरक्षित थर्माइट पटाखे।
- उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए इन पटाखों की पहचान अद्वितीय क्यूआर कोड का उपयोग करके जानकारी मिली है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया था कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को यह आश्वासन देने के बाद ही पटाखों की संरचना को प्रमाणित करना चाहिए कि वे प्रतिबंधित रसायनों से नहीं बने हैं।

निष्कर्ष

हाल की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेशों का "घोर उल्लंघन" हुआ था। इसने लगभग हर दिन बड़ी मात्रा में पटाखों को जलाने पर ध्यान दिया और यह जिम्मेदारी तय करने के लिए इच्छुक महसूस किया। "अगर पुलिस आयुक्त पर दायित्व तय है, तभी ऐसा हो सकता है," यह टिप्पणी की।

शहरों द्वारा जलवायु कार्रवाई को अपनाना

संदर्भ: हाल ही में, महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की कि राज्य भर के 43 शहर संयुक्त राष्ट्र समर्थित 'रेस टू जीरो' वैश्विक अभियान में सम्मिलित होंगे, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करते हुए रोजगार सृजित करना है।

क्या शहर पर्याप्त कर रहे हैं?

- दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 भारतीय शहरों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार –इनमें से लगभग आधे शहर जलवायु योजनाओं की रिपोर्ट करते हैं, अर्थात, उनके पास जलवायु प्रतिस्कंदी योजना या परियोजनाओं का एक समुच्चय है। तथा 18 शहर कार्यान्वयन के उद्देश्य से आगे बढ़ चुके हैं।
- ये आंकड़े उत्साहजनक पहले कदम को उजागर करते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि शहरी विकास नीति में बाढ़, पानी की कमी, चक्रवात और तूफान के आवर्तक अनुभवों को शामिल किया जा रहा है।
- अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान (एचएपी): इसे 2010 से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गर्मी से मृत्यु दर में कमी आई है। इसे देश भर के 17 शहरों में भी बढ़ाया गया है।
- अन्य सफल परियोजनाओं में प्रकृति आधारित समाधान जैसे तटीय तमिलनाडु में मैंग्रोव बहाली और बेंगलुरु में शहरी आर्द्रभूमि प्रबंधन (शहरी बाढ़ को नियंत्रित करना) शामिल हैं।

बाधाएं

- किंतु इनमें से बहुत से अंतःक्षेप विशेष रूप से अलग-अलग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- उदाहरण के लिए, भारत की लंबी तट रेखा एवं अत्यधिक संवेदनशील तटीय शहरों तथा आधारिक अवसंरचना के बावजूद तटीय बाढ़, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि एवं चक्रवातों पर कम चर्चा की जाती है।
- यह ध्यान इस बात को नजरअंदाज करने की ओर प्रवृत्त होता है कि कितने जोखिम एक-दूसरे को अभिसरित करते हैं एवं एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं- उदाहरण के लिए, चेन्नई में बाढ़ एवं जल के अभाव का मौसमी चक्र।
- शहर के पैमाने पर अपर्याप्त वित्त और राजनीतिक इच्छाशक्ति स्थायी भारतीय शहरों के विकास में बाधक है।
- मौजूदा सरकारी विभागों में काम करने के तरीकों को बदलने के लिए अपर्याप्त संस्थागत क्षमता।

आगे की राह

- अलगाव में जोखिमों को देखने से दूर जाना और कई प्रतिच्छेदन जोखिमों की योजना बनाना।
- सरकार को सीधा और क्षैतिज ज्ञान साझा करने को सक्षम करने के लिए हर लाइन विभाग के साथ-साथ विभागों में संचार चैनलों में लचीलापन योजनाकारों के साथ दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है।
- बदलते व्यवहार और जीवन शैली पर ध्यान दें। एक उभरता हुआ व्यवहार परिवर्तन शहरी खेती जैसे निचले स्तर की स्थायी प्रथाएं हैं जहां नागरिक स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर स्थिरता की व्याख्या कर रहे हैं।
- छतों पर अपना भोजन उगाना और साथ ही साथ स्थानीय जैव विविधता को बढ़ाना;
- जैविक कचरे का खाद बनाना और लैंडफिल दबाव को कम करना;
- एक पड़ोसी के साथ कृषि उपज साझा करना,
- समुदायों को पास में लाना और भोजन उगाने के बारे में जागरूकता पैदा करना।

कोयला संकट

संदर्भ: भारत के ताप विद्युत संयंत्र (Thermal Power Plant) कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि थर्मल स्टेशनों की बढ़ती संख्या के कारण कोयले का स्टॉक औसतन चार दिनों के लिये बचा है।

- 4 अक्टूबर को, 17,475 मेगावाट (मेगा वाट) की बिजली उत्पादन क्षमता वाले 16 ताप विद्युत संयंत्रों में शून्य दिनों (zero days) का कोयला भंडार था।
- 59,790 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाले अतिरिक्त 45 ताप विद्युत संयंत्रों के पास केवल दो दिनों के उत्पादन के लिए पर्याप्त कोयला भंडार था।
- कुल मिलाकर, 132 गीगावाट (1GW 1,000 MW) की बिजली उत्पादन क्षमता वाले संयंत्रों की प्रतिदिन निगरानी की जाने वाली 165 GW क्षमता में कोयला स्टॉक का महत्वपूर्ण या सुपर क्रिटिकल स्तर था।
- गैर-पिथेड (non-pithead) संयंत्रों में कोयले की कमी अधिक होती है, जो कोयला खदानों के पास स्थित नहीं होते हैं, ऐसे संयंत्रों में 108 में से 98 संयंत्रों में स्टॉक का महत्वपूर्ण स्तर यानी आठ दिनों के भीतर देखा जाता है।
- भारत के कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्र 208.8 GW या भारत की 388 GW स्थापित उत्पादन क्षमता का 54 प्रतिशत हैं।
- सरकार ने कहा है कि आपूर्ति की कमी के कारण अभी तक देश में कोई बिजली कटौती नहीं हुई है, कोयले की आपूर्ति की स्थिति छह महीने तक "असहज" रहने की संभावना है।

भारत में कोयले की कमी का क्या कारण है?

- आपूर्ति संबंधी मुद्दों के साथ युग्मित कोविड-19 महामारी से उबरने वाली अर्थव्यवस्था ने मौजूदा कोयले की कमी को जन्म दिया है।
- भारत बिजली की मांग में तेज़ उछाल, घरेलू खदान उत्पादन पर दबाव और समुद्री कोयले की बढ़ती कीमतों के प्रभावों से परेशान है।
- भारत ने अगस्त 2019 में 106 बिलियन यूनिट बिजली की तुलना में अगस्त 2021 में 124 बिलियन यूनिट बिजली की खपत की, जो महामारी से प्रभावित नहीं थी।
- कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों ने भी मांग में वृद्धि के उच्च अनुपात की आपूर्ति की है, जिससे भारत के उर्जा मिश्रण में थर्मल पावर की हिस्सेदारी वर्ष 2019 के 61.9% से बढ़कर 66.4% हो गई है।
- सरकार ने अतिरिक्त 28.2 मिलियन घरों को जोड़ा है और ये परिवार बिजली की मांग में वृद्धि के कारण रोशनी, पंखे और टेलीविजन सेट खरीद रहे हैं।
- आपूर्ति की कमी के अन्य प्रमुख कारणों में अगस्त और सितंबर में कोयला असर वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कम उत्पादन और कोयला खदानों से कोयले का कम प्रेषण शामिल है।
- कोयले की उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ-साथ कम आयात के लिए लगातार कदम ने भी संयंत्रों को आयात में कटौती करने के लिए प्रेरित किया है।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

- बिजली और रेल मंत्रालयों, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन के

प्रतिनिधियों सहित एक अंतर-मंत्रालयी टीम थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति की निगरानी कर रही है।

- सरकार अपने कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैप्टिव कोयला खदानों वाले थर्मल प्लांटों पर दबाव डाल रही है ताकि वे अपनी अधिक मांग को पूरा कर सकें।
- सरकार निम्न स्तर के स्टॉक वाले ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति को भी प्राथमिकता दे रही है।
- बिजली मंत्रालय कई खदानों से उत्पादन शुरू करने में तेजी लाकर कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, जिनके पास पहले से ही सभी आवश्यक मंजूरी है।
- सरकार ने 248 रेक से कोयला खदानों से भेजे गए 263 रेक कोयले के साथ प्रतिदिन ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के रेक की संख्या में भी वृद्धि की है।

डीप ब्रेन स्टिमुलेशन

संदर्भ: कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को (UCSF) के चिकित्सकों ने अवसादग्रस्त मस्तिष्क पैटर्न (depressive brain patterns) से जुड़े मस्तिष्क सर्किटों को पहचानकर और उनका दोहन करके गंभीर अवसाद के रोगी का सफलतापूर्वक इलाज किया है।

- चिकित्सकों ने इन पैटर्न को रीसेट करने का प्रयास किया है, जो उन्होंने कहा है कि हृदय के लिए पेसमेकर का उपयोग करने के बराबर है।
- डॉक्टरों ने इस मरीज के मामले के लिए इसे अनुकूलित करते हुए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) नामक एक मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल किया।

डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) क्या है?

- डीप ब्रेन स्टिम्यूलेशन (DBS) एक न्यूरोसर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें न्यूरोस्टिम्यूलेटर चिकित्सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण को ब्रेन पेसमेकर के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में मस्तिष्क में प्रत्यारोपित इलेक्ट्रोड के माध्यम से उत्पन्न विद्युत आवेग का उपयोग असामान्य मस्तिष्क गतिविधि को नियंत्रित करने के लिये किया जाता है।
- यह विद्युत आवेग मस्तिष्क के भीतर रासायनिक असंतुलन के लिये समायोजन का कार्य भी करता है, जो विभिन्न असामान्य स्थितियों का कारण होता है।

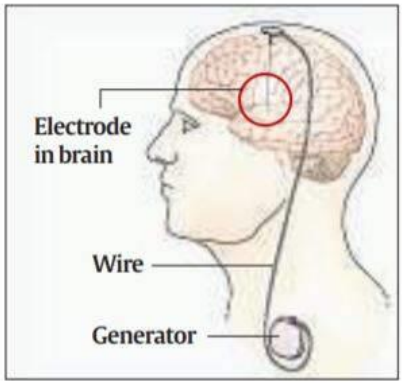

डीबीएस में तीन घटक होते हैं (ऊपर चित्र देखें):

इलेक्ट्रोड या लीड, यह एक पतला कुचालक तार है जिसे मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र (मस्तिष्क नाभिक) में प्रत्यारोपित किया जाता है।

- एक्सटेंशन वायर का उपयोग इलेक्ट्रोड को इस प्रणाली के तीसरे घटक से जोड़ने के लिये किया जाता है, जो सिर, गर्दन व कंधे की त्वचा के नीचे से गुज़रता है।
- आंतरिक पल्स जनरेटर इस प्रणाली का तीसरा घटक है, जिसे सामान्यतः ऊपरी वक्ष में स्थापित किया जाता है।

DBS से किन बीमारियों का इलाज किया जाता है?

- परंपरागत डी.बी.एस. प्रणाली का उपयोग डायस्टोनिया, मिर्गी, आरंभिक ट्यूमर, नियंत्रित-बाध्यकारी विकार तथा पार्किंसंस जैसे रोगों के उपचार में किया जाता है।
- अवसाद के उपचार में डी.बी.एस. के माध्यम से किये गए नैदानिक परीक्षणों में सीमित सफलता प्राप्त हुई है, क्योंकि अधिकांश उपकरण केवल मस्तिष्क के एक निश्चित क्षेत्र में निरंतर विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करने में सक्षम हैं।
- नवीनतम शोध और उपचार के दौरान, वैज्ञानिकों ने एक नए डी.बी.एस. उपकरण को अनुकूलित किया, जो अवसादग्रस्त पैटर्न को पहचानने पर मस्तिष्क को उत्तेजित करेगा।
- इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिकों को एक न्यूरल बायोमार्कर भी मिला है जो लक्षणों की शुरुआत का संकेत देता है। अनुकूलित डीबीएस डिवाइस का उपयोग करके, वे मस्तिष्क के एक अलग क्षेत्र को उत्तेजित करने में सक्षम थे, जिसने बदले में मस्तिष्क के लिए तत्काल चिकित्सा का निर्माण किया।

भारतीय कृषि में डेटा क्रांति

संदर्भ: भारतीय कृषि क्षेत्र से संबंधित दो महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किए गए।

परामर्श पत्र: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) की ओर से इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर (IDEA)

भारतीय कृषि: एक निजी संगठन, बैन एंड कंपनी से व्यवधान के लिए परिपक्व।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- बैन रिपोर्ट कृषि-व्यवसाय परिदृश्यों पर डेटा-आधारित भविष्यवाणी है।
- इसमें वैकल्पिक प्रोटीन के उत्पादन को लक्षित करना, और खाद्य सेल-आधारित भोजन / सामग्री और समुद्री खेती शुरू करना आदि शामिल हैं।
- कृषि क्षेत्र (वर्तमान में 370 अरब डॉलर मूल्य के) को 35 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश मिलने का अनुमान है।
- इस तरह के निवेश के अवसरों के लिए दो सक्षम शर्तें हैं:
  - नियामक ढांचे में परिवर्तन, विशेष रूप से फार्म अधिनियमों में हाल के बदलाव
  - IDEA की सरकारी पहल के माध्यम से डिजिटल व्यवधान- 'कृषि के लिए भारत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र'।
- भारतीय कृषि क्षेत्र भविष्य में खेत से टेबल तक शामिल होगा और उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध के साथ एक राष्ट्रीय मंच के साथ एकल राष्ट्रीय बाजार का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- रिपोर्ट ने खेत से कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडी और मंडी के बीच ग्राहक को आपूर्ति श्रृंखला में उपलब्ध व्यापार अवसर का प्रदर्शन किया है, जिसे डिजिटल व्यवधान और नवीनतम कृषि सुधारों के समर्थन से महसूस किया जा सकता है।
- रिपोर्ट का तर्क है कि कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र में भारी निवेश से लाभान्वित होकर, निकट भविष्य में किसानों की आय के लक्ष्य को दोगुना किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में गेम-चेंजर के रूप में घोषित कृषि सुधारों को दर्शाया गया है।

चिंताएं या चुनौतियां

- आईटी उद्योग का मुख्य रूप से आधार संख्या के आधार पर एक विशिष्ट किसान आईडी बनाने की नैतिकता और डेटा के दुरुपयोग की संभावना के कारण आईडिया का विरोध है।
- एक सामान्य धारणा है कि कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश से किसानों को लाभ होगा; रिपोर्ट में 'लेकिन कैसे' का पुख्ता जवाब नहीं दिया गया है।
- अधिकांश छोटे और सीमांत किसान कम पढ़े-लिखे हैं न कि तकनीक की समझ रखने वाले। हालांकि, इन महत्वाकांक्षी विकासों के बीच किसानों की क्षमता निर्माण की अनदेखी की जाती है।
- सुधारों के खिलाफ किसानों का विरोध एक बाधा या जोखिम कारक के रूप में कार्य कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप इन नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जा सकता है।

आगे की राह

- इस तथ्य पर सहमत होते हुए कि कृषि क्षेत्र में डेटा क्रांति अपरिहार्य है, इसकी सामाजिक-राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए, हम किसानों की आजीविका में सुधार के लिए केवल प्रौद्योगिकी सुधार और कृषि-व्यवसाय निवेश पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
- FPOs और अन्य किसान संघों के माध्यम से समर्थन प्रणाली स्थापित करके, किसानों की क्षमता में सुधार के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।
- देश के कृषि क्षेत्र के आकार को ध्यान में रखते हुए यह एक आसान काम नहीं होने जा रहा है, लेकिन देश भर में काफी निवेश के साथ एक अलग कार्यक्रम की आवश्यकता होगी।

PRIs और आपदा प्रबंधन

संदर्भ: पंचायती राज, जिसे पहली बार 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान में नागौर द्वारा अपनाया गया था, का व्यापक रूप से विस्तार हुआ है। अब पूरे भारत में लगभग 31 लाख निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व 2,60,512 पंचायती राज संस्थान (PRIs) हैं।

- इस साल शुरू किए गए पीपुल्स प्लान कैंपेन और वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड, ग्राम सभाओं को और अधिक जीवंत बनाकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की आकांक्षा रखते हैं।
- लोक योजना अभियान या "सबकी योजना सबका विकास" का उद्देश्य देश में ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDPs) तैयार करके एक वेबसाइट पर रखना है, जहां कोई भी सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं की स्थिति देख सकता है।
- वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड साल भर ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति की बैठक, निर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों की बैठक के माध्यम से पंचायतों की अधिकतम भागीदारी बढ़ाने में मदद करेगा।
- महामारी के दौरान पंचायत राज संस्थाओं (PRI) द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।
- जब महामारी के ख़राब महीनों के दौरान पारंपरिक टॉप-डाउन आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली से समझौता किया गया था, यह PRI थे जिन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी।
- उन्होंने जोखिमों को कम करने में मदद कर जल्दी से प्रतिक्रिया दी और इस तरह लोगों को जल्द ठीक होने में मदद की। पंचायती राज संस्थाओं ने स्थानीय स्तर पर आवश्यक नेतृत्व प्रदान किया।
- उन्होंने नियामक और कल्याणकारी दोनों कार्य किए।
- उदाहरण के लिए, देशव्यापी तालाबंदी के दौरान, PRI ने नियंत्रण क्षेत्र स्थापित किए, परिवहन की व्यवस्था की, लोगों को छोड़ने के

लिए इमारतों की पहचान की और आने वाले प्रवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था की।

- इसके अलावा, मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन ने कमजोर आबादी को समर्थन सुनिश्चित करते हुए वसूली की गति तेज कर दी।
- समितियों के माध्यम से अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं जैसे आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ नियमित जुड़ाव ने समुदाय तथा अधिकारियों के बीच विश्वास की खाई को पाट दिया।
- हाल ही में, COVID-19 टीकाकरण के लिए नागरिकों को जुटाने में PRI की भूमिका अनुकरणीय है, जिससे भारत को वर्ष के अंत तक सार्वभौमिक टीकाकरण की ओर बढ़ने में मदद मिली है।

आपदाओं (जैसे महामारी) के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- योकोहामा रणनीति (Yokohama strategy), 1994 ने इस बात पर जोर दिया कि भेद्यता को कम करने के लिए अकेले आपदा प्रतिक्रिया के बजाय आपदा रोकथाम, शमन और तैयारियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए कुछ पहल की जा सकती है।
- **कानूनी मान्यता:** पंचायत राज अधिनियमों में आपदा प्रबंधन अध्यायों को शामिल करना, आपदा योजना तथा व्यय को पंचायती राज विकास योजनाओं और स्थानीय स्तर की समितियों का हिस्सा बनाना महत्वपूर्ण है। यह नागरिक केंद्रित मानचित्रण और संसाधनों की योजना सुनिश्चित करेगा।
- **क्षमताओं को मजबूत करना:** समुदाय के लिए नियमित स्थान-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने से व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताएं मजबूत होंगी।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, व्यक्तिगत सदस्यों को भूमिकाएँ सौंपना और उन्हें आवश्यक कौशल प्रदान करना ऐसे कार्यक्रमों को और अधिक सार्थक बना सकता है।
- **आपदा प्रबंधन योजनाएं:** चूंकि आपदा के मामले में समुदाय आमतौर पर सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजनाएं मदद करेंगी।
- ये आपदा के दौरान संसाधन उपयोग और रखरखाव के लिए एक रणनीति प्रदान करेंगे।
- ऐसी योजनाओं को स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान का दोहन करना चाहिए जो आधुनिक प्रथाओं का पूरक होगा।
- **राशि जुटाना:** सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक आपदा कोष की स्थापना के माध्यम से समुदाय से वित्तीय योगदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

आपदा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को पहले से कहीं अधिक अब सामुदायिक संस्कृति का एक अंतर्निहित हिस्सा बनाना अनिवार्य है।

जलवायु विज्ञान के लिए पहला नोबेल

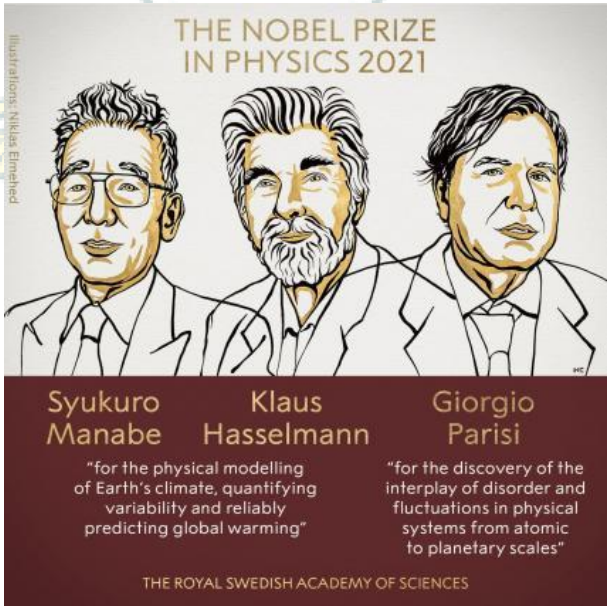

संदर्भ: स्यूकुरो मानेबे और रिचर्ड वेदरल्ड ने 1967 में पहली बार अपने प्रकाशित पत्रों में ग्लोबल वार्मिंग पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के प्रभाव का वर्णन किया था।

- 90 वर्षीय स्यूकुरो मनाबे और 89 वर्षीय क्लॉस हासेलमैन को "पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी" में उनके काम के लिए दिया गया है।
- बाकि पुरस्कार का दूसरा भाग 73 वर्षीय जियोर्जियो परिसी को "परमाणु से ग्रहों के पैमाने में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार-चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज" के लिए दिया गया है।

नोबेल पुरस्कार पैनल ने कहा कि मनाबे और हासेलमैन ने "पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारे ज्ञान की नींव रखी और बताया कि मानवता इसे कैसे प्रभावित करती है।"

पहली पहचान (First recognition)

- यह पहली बार है जब जलवायु वैज्ञानिकों को भौतिकी के नोबेल से सम्मानित किया गया है।
- IPCC ने 2007 में शांति नोबेल जीता था, जो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई के लिए जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयासों की एक स्वीकृति है, जबकि 1995 में पॉल क्रुट्ज़न को ओजोन परत पर उनके काम के लिए रसायन विज्ञान नोबेल, केवल दूसरी बार माना जाता है वायुमंडलीय विज्ञान से यह सम्मान जीता है।
- इसलिए, मनाबे और हैसलमैन की मान्यता को आज दुनिया में जलवायु विज्ञान के महत्व की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है।

मनाबे का कार्य

- आज हम जो परिष्कृत जलवायु मॉडल चला रहे हैं, जो जलवायु विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके वंश का पता उस मॉडल से लगाया जाता है जिसे मानाबे ने बनाया था।
- मनाबे ने पहले युग्मित मॉडल को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें 1970 के दशक में महासागर और वायुमंडलीय बातचीत को एक साथ मॉडल किया गया था।

हैसलमैन का कार्य

- हासेलमैन, एक जर्मन, जो अब 90 वर्ष के है, एक समुद्र वैज्ञानिक (oceanographer) है जिसने जलवायु विज्ञान में कदम रखा है। उन्हें जलवायु परिघटनाओं में विशिष्ट हस्ताक्षरों की पहचान करने के लिए उनको जाना जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिली कि क्या ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानवीय गतिविधियों के कारण थे।
- 1990 के दशक में, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर बहुत बहस हुई थी - क्या ये मानवीय गतिविधियों से प्रेरित थे या प्राकृतिक परिवर्तनशीलता का हिस्सा थे।
- इन उंगलियों के निशान की पहचान करने के हैसलमैन के काम ने अब उस बहस को बंद कर दिया है। IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट जो 2021 में आई थी, यह कहने में स्पष्ट है कि मानवीय गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
- मनाबे और हैसलमैन भी पिछली IPCC रिपोर्टों के लेखक रहे हैं। उन दोनों ने पहली और तीसरी मूल्यांकन रिपोर्ट में योगदान दिया, जबकि हासेलमैन दूसरी मूल्यांकन रिपोर्ट में एक लेखक थे।

इस नोबेल पुरस्कार का महत्व

- कई वैज्ञानिकों ने कहा कि जलवायु विज्ञान को देर से मान्यता देने से अधिक उपयुक्त समय नहीं आ सकता था।
- उम्मीद है कि यह नोबेल पुरस्कार जलवायु विज्ञान में विश्वास करने वाले अधिक लोगों की मदद करेगा।
- कुछ समय पहले तक, जलवायु विज्ञान को वैज्ञानिक हलकों में भी महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मौसम के पूर्वानुमान बहुत सटीक नहीं थे। सभी ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि यह विज्ञान स्वयं अनिश्चित और अराजक था।
- लेकिन वह धारणा अब बदल रही है। मौसम के पूर्वानुमान कहीं अधिक सटीक हो गए हैं, जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मनाबे और हैसलमैन जैसे विभिन्न वैज्ञानिकों के कार्यों के कारण सम्मोहक रहे हैं।
- यह नोबेल पुरस्कार संभवत: जलवायु विज्ञान को मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा।

शरणार्थी कानून

संदर्भ: हर साल, लाखों लोग अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपना घर छोड़ने को मजबूर होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2020 में 82.4 मिलियन से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उनमें से 20 मिलियन से अधिक शरणार्थी हैं। इनमें से 200,000 से अधिक शरणार्थी वर्तमान में भारत में हैं।

भारत और शरणार्थी

- अपने इतिहास के माध्यम से, भारत ने कई बार युद्ध, संघर्ष और उत्पीड़न से भागे लोगों की मेजबानी की है - ईरान से पारसी, 1971 बांग्लादेश मुक्ति के दौरान बंगाली, 1980 के दशक में श्रीलंकाई या विस्थापन की विभिन्न लहरों के दौरान अफगान।
- शरणार्थियों का स्वागत भारत के धर्मनिरपेक्ष, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के मूल में है।
- भारत ने 49 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें 195,000 से अधिक सैनिकों और बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने संघर्ष-ग्रस्त भूमि में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की सहायता की है।
- शरण की तलाश करने वाले शरणार्थियों के विचार चाहे जो भी हों - आर्थिक, जनसांख्यिकीय, सुरक्षा, या राजनीतिक - भारत ऐसी स्थितियों से उत्पन्न जटिलताओं के प्रबंधन में माहिर रहा है।

मुद्दे

- **शरणार्थी ढांचे की कमी:** एक स्वागत योग्य देश होने के बावजूद, भारत के पास राष्ट्रीय शरणार्थी ढांचा नहीं है।
- तदर्थ उपाय (Ad-Hoc Measures): भारत में शरणार्थी सहायता पर हस्तक्षेप काफी हद तक अंतरिम नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर है।
- परिणामस्वरूप, शरणार्थियों के कुछ समूहों को समग्र समर्थन और समाधान से लाभ हुआ है, जबकि अन्य पिछड़ गए हैं।

- **सॉफ्ट पावर की कमी:** भारत ने शरण प्रबंधन में हमारे हस्तक्षेप को संहिताबद्ध नहीं किया है, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया जा सके।
- **नौकरशाही की कवायद नहीं (Not a bureaucratic Exercise) :** शरणार्थियों के साथ व्यवहार एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा विचार है जिसे नौकरशाही की कवायद में नहीं बदला जा सकता जैसा कि यह वर्तमान में है।

शरणार्थी कानून की आवश्यकता

- एक स्थायी शरणार्थी नीति जनसंख्या आंदोलनों को समझदारी से प्रबंधित करने और हमारे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता तथा पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम है।
- एक राष्ट्रीय शरणार्थी प्रबंधन कानून इस क्षेत्र में और विकासशील देशों के बीच भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को ध्यान में रखते हुए होगा।
- यह कानून शरणार्थी संरक्षण में शामिल विभिन्न एजेंसियों - सरकारी, न्यायिक, संयुक्त राष्ट्र की भूमिकाओं को स्पष्ट करेगा और उनके बीच समन्वय की प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा।
- यह मेजबान देश और मूल देश के बीच संघर्ष से बचने में भी मदद करेगा।
- अन्य राज्य शरण देने के कदम को शांतिपूर्ण, मानवीय और कानूनी कृत्य के रूप में स्वीकार करेंगे, न कि एक मनमाना राजनीतिक इशारा।
- यह जिम्मेदारी साझा करने पर बातचीत के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा और शरणार्थी समस्या के मूल कारणों के स्थायी समाधान की खोज में सहायता करेगा।
- कुछ देश शरणार्थियों को प्रारंभिक सहायता प्रदान करते हैं, जिसके बाद उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं की रक्षा करें। कुछ देशों ने शरणार्थियों के साथ धर्मार्थ मामलों की तरह व्यवहार किया है। दोनों के बीच सही संतुलन ढूँढना वही है जो एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून हासिल करने में मदद कर सकता है।

आगे की राह

- भारत जैसे प्रगतिशील देश और आर्थिक महाशक्तियाँ, पारंपरिक अनुभव और मूल्यों के साथ, वैश्विक मानवीय कार्रवाई तथा शरण प्रबंधन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं।
- वर्तमान वैश्विक शरणार्थी और आर्थिक संकट भारत के लिए एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाकर अपने शरण प्रबंधन को बेहतर ढंग से जांचने का अवसर प्रदान करते हैं।

'अर्ध-संघीय' लोकतंत्र पर विचार

संदर्भ: भारत के संविधान की संघीय संरचना बहु-सांस्कृतिक भारत की लोकतांत्रिक आवश्यकता है, जहां घटक इकाइयां (राज्य) जाति, जनजाति या धर्म जैसी प्रतिस्पर्धी पहचान के खिलाफ भाषा पर आधारित हैं।

इसलिए लोकतांत्रिक संरचना और राष्ट्रीय अखंडता आंतरिक रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं।

- हालांकि, लोकतंत्र के परिचालन दोष उदारवादी संस्थानों को तेजी से नुकसान पहुंचा रहे हैं, संघीय लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि हाल की घटनाओं ने रेखांकित किया है।

कुछ फॉल्ट लाइन

- हालांकि, सदन ने रिकॉर्ड संख्या में स्थगन के बीच रिकॉर्ड संख्या में बिल पारित किए, जो बिना किसी विचार-विमर्श के बिलों को जल्दी से पारित करने की ओर इशारा करते हैं।
- हाल ही में, एक घटक राज्य द्वारा दूसरे के खिलाफ सीमा पार पुलिस फायरिंग, घातक परिणाम देना और संघवाद पर दबाव डालना।
- भारत के लोकतंत्र में अधिक अपराधीकरण, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड वाले 30% से अधिक विधायक शामिल हैं,
- लोकतांत्रिक संघवाद संस्थानों को इकाइयों और केंद्र के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए मानता है ताकि वे एक-दूसरे के साथ समन्वय कर सकें, संविधान के अधीन हों और उनके विवाद एक स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा त्रुटिहीन पेशेवर और नैतिक विश्वसनीयता के साथ तय किए गए हों। लेकिन भारत की संघीय संरचना संवैधानिक रूप से इन सभी मामलों में कमियों से प्रभावित है।
- संस्थागत प्राथमिकताएं या तो जातीय या रिश्तेदारी नेटवर्क, या सत्ता विरोधी लहर पर आधारित होती हैं।
- प्राथमिकता के रूप में 'राष्ट्र-निर्माण' के साथ सत्ता और संसाधनों का संवैधानिक विभाजन केंद्र के पक्ष में भारी रूप से इसकी तरफ (skewed) बना हुआ है।
- भारत के संविधान में राज्यों के अधिकारों, यहां तक कि उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के बारे में कुछ भी नहीं है। इसने केंद्र को राज्य की सीमाओं को एकतरफा रूप से बदलने और नए राज्य बनाने में सक्षम बनाया है।
- न्यायपालिका को संघीय इकाइयों के बीच संघर्षों पर निर्णय लेने का अधिकार है, हालांकि उच्च न्यायिक नियुक्तियों (अनुमानित 41% खाली पड़ी हुई) के साथ, पदोन्नति और स्थानान्तरण एक केंद्रीय अधिकार बन गया है, उनके संचालन तेजी से विवादास्पद होते जा रहे हैं।
- "अखिल भारतीय सेवाओं" और राज्यपालों की भूमिका विकृत है - संघीय "लिंक" के इन संवैधानिक प्राधिकरणों को राज्यों में केंद्रीय "एजेंट" में से एक में बदलना।

- राज्य सभा अप्रत्यक्ष रूप से उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके विधायक इसे चुनते हैं, लेकिन राज्य के हितों की कीमत पर राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं।
- इस प्रकार, राष्ट्रीय शासन के महत्वपूर्ण उपकरण या तो केंद्र द्वारा सौंपे गए हैं या विनियोजित किए गए हैं, राज्यों के पास कानून और व्यवस्था तथा भूमि सुधार जैसे राजनीतिक रूप से विवादास्पद विषयों के साथ छोड़ दिया गया है।
- इस प्रकार, भारत के अधिकांश संघीय संघर्ष संरचनात्मक हैं, जो परिचालन दुर्व्यवहारों द्वारा प्रबलित हैं।

निष्कर्ष

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी निष्क्रिय "अर्ध-संघीय" संरचना के लिए एक कार्यात्मक लोकतांत्रिक संघीय विकल्प की हकदार है, जो न तो संघीय है और न ही लोकतांत्रिक बल्कि एक संवैधानिक "बुनियादी संरचना" है।

इंडो-पैसिफिक में एक 'ताइवान फ्लैशप्वाइंट'

संदर्भ: पिछले हफ्ते एक नई घटना में, दक्षिण चीन सागर में एक अमेरिकी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी कथित तौर पर एक "अज्ञात वस्तु" से टकरा गई। अमेरिका की इन कार्रवाइयां का चीन ने आपत्ति जताई है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता टकराव हथियारों के टकराव में बदल जाता है, संभावित क्षेत्र ताइवान जलडमरूमध्य हो सकता है।

ताइवान की संक्षिप्त पृष्ठभूमि:

- 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) के तहत ताइवान चीन की मुक्ति का अधूरा बिज़नेस है।
- च्यांग काई-शेक के तहत गुओमिनडांग (KMT) सेना 1945-49 के गृहयुद्ध में माओत्से तुंग के तहत CCP फ़ोर्स से हार गई।
- च्यांग ताइवान द्वीप पर पीछे हट गया और एक शासन स्थापित किया जिसने पूरे चीन पर अधिकार का दावा किया और अंततः मुख्य भूमि को पुनर्प्राप्त करने का वचन दिया।
- CCP ने बदले में इसे "पाखण्डी" प्रांत के रूप में पुनः प्राप्त करने और चीन के अंतिम पुनर्मिलन को प्राप्त करने का वचन दिया।
- ताइवान को नव स्थापित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) द्वारा सैन्य रूप से कब्जा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह 1950-53 के कोरियाई युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य का सैन्य सहयोगी बन गया था।
- इसके सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए इसे "अकल्पनीय विमानवाहक पोत" के रूप में वर्णित किया गया था।
- यह चरण 1979 में चीन की वैध सरकार के रूप में PRC को मान्यता देने, ताइवान के साथ अपने आधिकारिक संबंधों को समाप्त करने और द्वीप के साथ अपनी पारस्परिक रक्षा संधि को निरस्त करने के साथ समाप्त हुआ।

ताइवान के साथ अमेरिका और चीन की सामरिक अस्पष्टता

- अमेरिका ने घोषणा की है कि वह ऐसा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध नहीं करते हुए "ताइवान की रक्षा में आने की क्षमता बनाए रखेगा"। यह USA की "रणनीतिक अस्पष्टता" की नीति है।
- दूसरी ओर, चीन शांतिपूर्ण एकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग का अधिकार बरकरार रखता है। यह चीन की रणनीतिक अस्पष्टता का संस्करण है।

ताइवान के प्रति चीन की क्या नीति रही है?

- मुख्य भूमि के साथ ताइवान के पुनर्मिलन को प्राप्त करने के लिए चीन ने एक टिपिकल कार्रोट (typical carrot) और स्टिक पॉलिसी अपनाई है।
- 1997 में चीनी संप्रभुता के उल्टा होने के बाद पहली बार हांगकांग पर लागू "एक देश दो सिस्टम" फॉर्मूला के तहत द्वीप को उच्च स्तर की स्वायत्तता का वादा करके, शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए संभावना, वास्तव में वरीयता का आयोजन किया गया है।
- इस फॉर्मूले के अनुसार, हांगकांग 50 वर्षों की अवधि के लिए अपनी मुक्त बाजार प्रणाली, अपने राजनीतिक, न्यायिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को बनाए रखेगा, इस प्रकार एक विस्तारित और क्रमिक संक्रमण को सक्षम करेगा।
- ताइवान से भी यही वादा किया गया था, लेकिन इस अतिरिक्त आश्वासन के साथ कि वह संक्रमण काल के दौरान अपने सशस्त्र बलों को भी बरकरार रखता है।

चीन और ताइवान के बीच आर्थिक संबंध

- 1978 के बाद से चीन ने खुद बाजार-उन्मुख सुधारों को अपनाया और विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक और वाणिज्यिक अवसर बन गया, ताइवान की व्यापारिक संस्थाओं ने मुख्य भूमि चीन में भारी निवेश किया है और दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से एकीकृत हो गई हैं।
- 1991 और 2020 के बीच, चीन में निवेश की गई ताइवानी पूंजी का स्टॉक 188.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो ताइवान के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% था।
- इसके विपरीत ताइवान में निवेश की गई चीनी पूंजी का स्टॉक मुश्किल से यूएस $2.4 बिलियन है।
- चीन को उम्मीद है कि ताइवान के साथ बढ़ते आर्थिक संबंध एकीकरण के विरोध को कमजोर करेंगे।
- साथ ही, ताइवान को एक स्वतंत्र स्थिति की ओर बढ़ते हुए देखा जाता है, तो चीन जबरदस्त आर्थिक नीतियों के माध्यम से ताइवान को गंभीर आर्थिक कमजोर करने में सक्षम है।

हांगकांग और ताइवान पर प्रभाव

- हाल ही में, चीन ने 'वन कंट्री टू सिस्टम्स' फॉर्मूले को छोड़कर हांगकांग में कई कठोर नीतियां अपनाई।
- परिणामस्वरूप , ताइवान में जनता की राय द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) के पक्ष में आ गई, जो द्वीप की स्वदेशी आबादी का अधिक प्रतिनिधि है, और स्वतंत्रता का पक्षधर है।
- इस विकास का एक महत्वपूर्ण निहितार्थ यह है कि शांतिपूर्ण एकीकरण की संभावनाएं कम हो गई हैं।

क्या चीन ताइवान पर आक्रमण और कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान चलाने के लिए तैयार है?

- मार्च 2021 में, यूएस पैसिफिक कमांडर ने चेतावनी दी कि एशिया में अमेरिकी शक्ति को विस्थापित करने की अपनी रणनीति के तहत चीन अगले छह वर्षों के अंदर ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चीनी सैन्य क्षमताओं को विकसित किया गया था।
- क्वाड (Quad) और औकस (AUKUS) की हालिया पहल ताइवान पर चीनी चालों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य कर सकती है।
- लेकिन वे हिंद-प्रशांत में संतुलन बदलने से पहले चीन को एकीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान रूप से प्रेरित कर सकते हैं।
- इन कारणों से, ताइवान अमेरिका और चीन के बीच हथियारों के टकराव के संभावित ट्रिगर बिंदु के रूप में उभर रहा है।

निष्कर्ष

अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति को आगे बढ़ाते हुए, भारत इन संभावित परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए अच्छा करेगा।

वन संरक्षण अधिनियम और प्रस्तावित संशोधन

संदर्भ: वनों की कटाई को संबोधित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू हुआ।

- हालांकि भारतीय वन अधिनियम 1927 से लागू है, यह औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन को लकड़ी के निष्कर्षण को नियंत्रित करने की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया था, न कि वनों को संरक्षित करने या वनों की कटाई को संबोधित करने के उद्देश्य से।
- जबकि राज्यों ने पहले ही वन भूमि को अधिसूचित कर दिया था, FCA ने "गैर वानिकी उद्देश्यों" के लिए ऐसी वन भूमि का उपयोग करने और इस तरह के पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समिति के निर्माण के लिए केंद्र की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक बना दिया।

क्या FCA में कभी संशोधन किया गया है?

- FCA में कम से कम दो बड़े संशोधन हुए हैं - 1988 और 1996 में।
- 1996 तक, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य स्थानीय कानून के तहत अधिसूचित वनों पर लागू करती थी।
- हालाँकि, गोदावर्मन थिरुमुलपाद द्वारा दायर एक याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद "जंगल" का गठन नाटकीय रूप से किया गया था।

  अब, "जंगल" भी शामिल है

  स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण के बावजूद, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में "वन" के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र; सभी क्षेत्र जो "वन" के "शब्दकोश" अर्थ के अनुरूप हैं
- 1996 के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा "वन" के रूप में पहचाने जाने वाले सभी क्षेत्र।

  इस फैसले ने भी मार्ग प्रशस्त किया

  परियोजना के प्रस्तावकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए नष्ट किए जा रहे जंगल के हिस्से के शुद्ध वर्तमान मूल्य या आर्थिक मूल्य की गणना करना;

  प्रतिपूरक वनीकरण कोष का निर्माण;

  डायवर्टेड वन के बदले गैर वानिकी भूमि उपलब्ध कराना।

फिर से FCA में संशोधन क्यों किया जा रहा है?

- FCA में आवश्यक तनाव यह है कि राज्य वन क्षेत्र को बढ़ाने के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है, और इससे राज्यों और निजी संस्थाओं द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि तक पहुंच कठिन हो जाती है।

- भारत का लक्ष्य भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% हिस्सा वन और वृक्षों से आच्छादित करना है, और बाद वाले को बढ़ाना एक प्रमुख जोर है।
- अब तक, वन आवरण लगभग 22% है क्योंकि मुख्य वन भूमि में वृद्धि करना कठिन होता जा रहा है, विस्तार के तरीके में इस धारणा का विस्तार शामिल है कि वन भूमि क्या है।
- इस प्रकार, निम्नीकृत भूमि भी, यदि उन्हें भूमि अभिलेखों में कहीं भी "जंगल" के रूप में दर्ज किया गया है, और यहां तक कि वाणिज्यिक वृक्षारोपण या एक निश्चित कैनोपी कवर (canopy cover) और घनत्व वाले पेड़ों वाले क्षेत्रों को "वन" के रूप में गिना जाता है।
- दूसरी ओर, "वन" की परिभाषा के तहत आने वाली अधिक भूमि के साथ, राज्य सरकारों या निजी उद्योग के लिए "वन" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली भूमि का उपयोग करना कठिन होता जा रहा है।
- वर्षों से, इसने मुकदमेबाजी के कई उदाहरणों को जन्म दिया है, साथ ही साथ "वन" की कानूनी परिभाषा पर भी सवाल उठाए हैं।
- राज्यों से कहा गया है कि वे इस बात की परिभाषा दें कि जंगल क्या होता है, लेकिन कई ने उन्हें नहीं दिया क्योंकि इसके राजनीतिक परिणाम होते हैं। इन सभी ने वर्षों से FCA की परस्पर विरोधी व्याख्याओं को जन्म दिया है।

नवीनतम संशोधन किस बारे में है?

- हाल ही में, पर्यावरण मंत्रालय ने एक "परामर्शी पत्र" जारी किया है जो प्रस्तावित परिवर्तनों को बताता है। यह सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुला है।
- मोटे तौर पर, यह कुछ श्रेणियों के बुनियादी ढांचा परियोजना डेवलपर्स को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति के लिए केंद्र से संपर्क करने से छूट देने का प्रस्ताव करता है।
- उदाहरण के लिए, इसने राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं, सीमा अवसंरचना परियोजनाओं, रेलवे या सड़क परिवहन मंत्रालय के स्वामित्व वाली भूमि जो 1980 से पहले या अधिनियम के लागू होने से पहले अधिग्रहित की गई थी, में शामिल एजेंसियों को छूट देने का प्रस्ताव किया है।
- भारत, अपनी जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के हिस्से के रूप में, 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 को बंद करने के लिए कार्बन सिंक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह केवल निजी भूमि पर पेड़ लगाने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और वर्तमान कानून एक बाधा उत्पन्न करते हैं। निजी जमींदारों को अधिक से अधिक पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- मंत्रालय ने कुछ प्रावधानों का प्रस्ताव किया है जहां गैर-अनुपालन के दंड में जेल की सजा शामिल हो सकती है, लेकिन प्रस्ताव का समग्र कार्यकाल गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करना थोड़ा आसान बनाना है। हालाँकि, इसके लिए अभी भी कैबिनेट और संभवतः संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता है।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण

सुर्खियों में: पीएम ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

- लोकनायक जय प्रकाश नारायण के जन्मदिन (11 अक्टूबर, 1902) को 1975-76 के दौरान आपातकाल विरोधी आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान के लिए "लोकतंत्र बचाओ दिवस" के रूप में मनाया जाता है।
- उनका पूरा जीवन सर्वोच्च बलिदान और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता में से एक है।
- 1921 में वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे।
- बाद में वे अमेरिका चले गए, जहां वे मार्क्सवादी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। हालाँकि, उन्होंने मार्क्सवादियों द्वारा वकालत की जा रही पूंजीवाद को नीचे लाने के लिए "क्रांति" के अंतिम समाधान को खारिज कर दिया। इसके विपरीत, उन्होंने समाजवाद की वकालत की।
- 1929 में वह जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर INC में शामिल हुए।
- 1934 में उन्होंने निम्नलिखित सदस्यों के साथ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया:
  महासचिव: जेपी नारायण
  विचारधारा: लोकतांत्रिक समाजवाद
- उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। अविद्या और अहिंसा की वकालत की।
- 1975 से शुरू हुए आपातकाल की अवधि के दौरान, उन्होंने समाज को पूरी तरह से बदलने के लिए "संपूर्ण क्रांति" का आह्वान किया।
  उन्होंने वकालत की
  पार्टी रहित लोकतंत्र
  सर्वोदय
  संसदीय लोकतंत्र की अस्वीकृति
- जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, जेपी जल्द ही राष्ट्रीय राजनीति में शामिल हो गए।
- 1960 के दशक के उत्तरार्ध के दौरान, वह कश्मीर में विवादों को सुलझाने में शामिल रहे।
- उन्होंने 1960 के दशक में नागालैंड के मुद्दे में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

- बांग्लादेश संकट के दौरान, यह जेपी ही थे जो भारत के उद्देश्य की सत्यता के बारे में समझाने के लिए भारत के राजदूत बने।
- मानवाधिकारों के पक्ष में जेपी की आवाज को उनके समय में हंगरी, चेक गणराज्य और तिब्बती संकट में प्रासंगिकता मिली।
- 1999 में, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) का हिस्सा

- जयप्रकाश नारायण (जेपी), जिनकी 117 वीं जयंती 11 अक्टूबर को पड़ती है, महात्मा के बारह प्रेरितों में से थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक फ्रंट-सिपाही थे। इस लड़ाई में, जेपी ने अहिंसा और आक्रामकता के संयोजन को आत्मसात किया।
- 1974 में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थानों के व्यवस्थित रूप से कमजोर होने और उसके बाद की घटनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए 'संपूर्ण क्रांति' या पूर्ण क्रांति का उनका आह्वान, प्रसिद्ध आपातकाल को लागू करने के लिए प्रेरित हुआ। इसने अंततः देश में राजनीतिक ताकतों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया और दूरगामी प्रभाव के साथ देश की राजनीति को एक नई दिशा दी।
- उनका दृढ़ विश्वास था कि व्यवस्था को बदलने में युवाओं को सबसे आगे होना चाहिए। सत्ता में बैठे लोग, यथास्थितिवादी, स्वाभाविक रूप से किसी भी परिवर्तन का विरोध करेंगे, लेकिन केवल युवाओं की ऊर्जा और शक्ति ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है - यह उनका दृढ़ विश्वास था।
- और ठीक ऐसा ही सत्तर के दशक में हुआ था। गुजरात में नव निर्माण आंदोलन को आशीर्वाद देने के बाद, जहां लोग भ्रष्ट राज्य सरकार के खिलाफ उठे थे, जेपी ने बिहार में छात्रों को सत्तावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जुटाया । राजनीतिक परिदृश्य पर उनका इतना प्रभाव था कि उनकी सलाह के तहत कांग्रेस (O), जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी जैसे कांग्रेस के कई अलग-अलग दलों और अन्य समाजवादियों ने जनता पार्टी बनाने के लिए एक साथ आए। वह जनता शासन के दौरान आसानी से शीर्ष पद पर आसीन हो सकते थे। हालांकि लोगों ने उनके नेतृत्व के लिए शोर मचाया, लेकिन उन्होंने कहा कि सत्ता उनका लक्ष्य नहीं है।
- उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और 1942 में वरिष्ठ नेताओं की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। आजादी के बाद वे चुनावी राजनीति से अलग रहे, लेकिन राजनीति के प्रति वे उदासीन नहीं रहे। उन्होंने विनोबा में भी सक्रिय भाग लिया।

  भावे का भूदान आंदोलन।

जेपी की विरासत महात्मा के समान है और गांधी के बाद के युग में सामने आए मुद्दों पर उन्हें प्रतिध्वनित करती है।

आजादी

"स्वतंत्रता मेरे जीवन की रोशनी में से एक बन गई और यह तब से बनी हुई है ... इसका मतलब मानव व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, दिमाग की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता थी। यह स्वतंत्रता मेरे जीवन का जुनून बन गया है और मैं इसे भोजन, सुरक्षा, समृद्धि, राज्य की महिमा के लिए या किसी और चीज के लिए समझौता नहीं देखूंगा।"

लोकतंत्र

"भारत का लोकतंत्र नींव से मंजिला ऊपर उठना है, जिसमें स्वशासी, आत्मनिर्भर, कृषि-औद्योगिक, शहरी-ग्रामीण स्थानीय समुदाय - ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं - जो विधानसभाओं का आधार बनेगी। ये राजनीतिक-आर्थिक संस्थान समुदाय और राष्ट्र की भलाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करेंगे।

विकास

- "विकास का विचार स्वतंत्र भारत की कल्पना करता है, जो कि किसी भी अन्य के विपरीत एक समाज है, जो अपने स्वयं के वर्ग में है जो मेगा औद्योगीकरण, शहरीकरण और व्यक्तिगतकरण के पश्चिमी पैटर्न का पालन नहीं करेगा। भारत कृषि आधारित लोगों की अर्थव्यवस्था होगी जो आर्थिक विकास में एक अलग पाठ्यक्रम तैयार करेगी, जो प्रकृति तथा आजीविका के संरक्षण के दौरान आवश्यकता-आधारित, मानव-पैमाने और संतुलित होगी।
- ऐसी 'विकास' प्रक्रिया लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत होगी। भारत के लिए सबसे अच्छा विकास मॉडल विविध, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत और मूल के रूप में मूल्य वर्धित कृषि है, छोटे / मध्यम उद्योगों को ट्रंक और शाखाओं के रूप में तथा व्यापक सेवा क्षेत्र को छत के रूप में बनाना है। एक केंद्रीकृत राजनीतिक, आर्थिक मॉडल और सामाजिक व्यवस्था के लिए लगभग सार्वभौमिक प्रवृत्ति जो इन दोनों से जुड़ी है, को छोड़ दिया जाना चाहिए। "

सांप्रदायिकता

"यद्यपि लगभग हर धार्मिक समुदाय के पास सांप्रदायिकता का अपना ब्रांड था, हिंदू सांप्रदायिकता दूसरों की तुलना में अधिक घातक थी क्योंकि हिंदू सांप्रदायिकता आसानी से भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में सामने आ सकती है और इसके सभी विरोधों को राष्ट्र-विरोधी बता सकती है।"

जलवायु संकट से निपटना

संदर्भ: हाल ही में प्रकाशित इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) वर्किंग ग्रुप-I की छठी आकलन रिपोर्ट में जलवायु कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया गया है।

- इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक (2011-2020) 1850 से 1900 की अवधि की तुलना में 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था, और 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग सीमा जल्द ही उल्लंघन होने की संभावना है

क्या आप जानते हैं?

- ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (2021) ने भारत को मौसम की चरम सीमा से सातवां सबसे अधिक प्रभावित देश का दर्जा दिया।

- IPCC की रिपोर्ट भारत को और अधिक तीव्र गर्मी की लहरों, भारी मानसून तथा भविष्य में चरम मौसम में वृद्धि के प्रति आगाह करती है।

अनुकूलन का महत्व

- देश भर में उत्पादन प्रणालियों, कृषि-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में अंतर होने के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रियाएं अलग-अलग जगहों पर भिन्न होती हैं। इसलिए, देश विशिष्ट अनुकूलन रणनीतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।
- भारत में अनुकूलन की दिशा में कुछ समर्पित पहलें हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय अनुकूलन कोष।
- हालांकि, अनुकूलन योजना को हमेशा की तरह व्यापार दृष्टिकोण से आगे जाने की जरूरत है।
- एक विकास-केंद्रित दृष्टिकोण जो जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के दृष्टिकोण को संरेखित करके क्षेत्रीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखता है, गरीबी और संकट प्रवासन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- इसके अलावा, अनुकूलन योजना को समझने, योजना बनाने, समन्वय करने, एकीकृत करने और भेद्यता तथा जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शासन की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत निम्नलिखित कार्य कर सकता है।

- **इम्प्रोवाइज्ड प्रेडिक्शन मॉडल:** पहला, यह उच्च गुणवत्ता वाले मौसम संबंधी डेटा के साथ जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक तैयार होता है। बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली और पूर्वानुमान के साथ, हम संकट से अच्छी तरीके से निपट सकते हैं। मजबूत जोखिम आकलन के लिए क्षेत्रीय जलवायु अनुमान विकसित करने के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को शामिल किया जाता है।
- **पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देना:** दूसरा, स्थायी उत्पादन प्रणालियों के लिए, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए अच्छी तरह से काम करने वाले बाजारों को विकसित करना और वांछित व्यवहार परिवर्तन के लिए उनका प्रसार करना आवश्यक है।
- **निजी क्षेत्र को शामिल करना :** तीसरा, अनुकूलन प्रौद्योगिकियों में निवेश के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, बीमा और जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नवीन जलवायु सेवाओं और समाधानों को डिजाइन और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है।
- **पारंपरिक ज्ञान का दोहन:** चौथा, हमें पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सम्मिश्रण करके जलवायु से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिए मैंग्रोव और जंगलों की रक्षा करने और स्थानीय तथा गैर-राज्य अभिनेताओं को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना:** पांचवां, निरंतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए, मध्य-पाठ्यक्रम सुधार के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। उपयुक्त प्रतिक्रियाओं और उचित संसाधन आवंटन को डिजाइन करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजनाओं के आवधिक सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- सक्रिय और समय पर आवश्यकता-आधारित अनुकूलन महत्वपूर्ण है। इसके बिना, भविष्य में एक बड़ा वित्तीय भार होगा।
- जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के प्रति अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है।
- अगली पीढ़ी के सुधार कई क्षेत्रों में नए व्यापार और जलवायु सेवा के अवसरों को बढ़ावा देंगे और इस प्रकार एक स्थायी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पर विवाद

संदर्भ: हाल ही में, विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में चीन के पक्ष में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा (पूर्व WB प्रमुख और वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एमडी) द्वारा डेटा छेड़छाड़ (tampering) के आरोप लगाए गए थे।

जॉर्जीवा के आसपास क्या विवाद है?

- जॉर्जीवा एक बल्गेरियाई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने यूरोपीय राजनीति में कई उच्च पदों पर कार्य किया। जनवरी 2017 में, उन्हें विश्व बैंक समूह का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया था।
- जनवरी 2019 में, उन्होंने WB समूह के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला।
- अक्टूबर 2019 में, उन्होंने IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला।
- परेशानी तब शुरू हुई जब जनवरी 2018 में, विश्व बैंक के तत्कालीन मुख्य अर्थशास्त्री पॉल रोमर ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) रैंकिंग को राजनीतिक कारणों से बदल दिया गया था।
- जल्द ही रोमर ने इस्तीफा दे दिया। संयोगवश, रोमर को उस वर्ष के अंत में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह दिखाने के लिए कि ज्ञान दीर्घकालिक विकास के चालक के रूप में कैसे कार्य करता है।
- रोमर की टिप्पणियों और इस्तीफे ने विश्व बैंक के अंदर और बाहर EoDB रैंकिंग की अखंडता के बारे में प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर दी।
- विशेष रूप से, यह आरोप लगाया गया था कि EoDB रैंकिंग को चीन (EoDB 2018 में) और सऊदी अरब, यूएई और अजरबैजान (EoDB 2020) के लिए रैंक बढ़ाने के लिए बदल दिया गया था।

विवाद शुरू होने के बाद से क्या हुआ है?

- अगस्त 2020 में, विश्व बैंक ने कुछ "डेटा अनियमितताओं" का पता लगाने के बाद अपनी EoDB रैंकिंग को निलंबित कर दिया।
- विश्व बैंक ने एक पूर्ण समीक्षा और एक स्वतंत्र जांच शुरू की। ऐसा ही एक प्रयास जनवरी 2021 में एक कानूनी फर्म विल्मरहेल (WilmerHale) को शामिल करना था।
- सितंबर 2021 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, विल्मरहेल की जांच में पाया गया कि विश्व बैंक के कर्मचारियों ने वास्तव में चीन की रैंकिंग में मदद करने के लिए डेटा में हेरफेर किया और उन्होंने जॉर्जीवा के दबाव में ऐसा किया।
- विल्मरहेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक समय पर, जब जॉर्जीवा ने चीन की रैंकिंग पर सीधा नियंत्रण कर लिया था और इसे बढ़ाने के तरीकों की तलाश कर रहा था, तो यह सुझाव दिया गया था कि केवल दो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों - बीजिंग और शंघाई का औसत लिया जाए - जैसा कि वे कई वर्षों से करते हैं।
- कई शहरों का भारित औसत लेने के बजाय अन्य देश (जैसे भारत)। शीर्ष दो शहरों को चुनकर चीन की रैंकिंग ऊपर जाएगी।
- ये निष्कर्ष विशेष रूप से हानिकारक हैं क्योंकि चीन अमेरिका और जापान के बाद विश्व बैंक में तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, और इसे उच्च रैंकिंग के लिए अपने तरीके से छेड़छाड़ के रूप में देखा जा रहा है।
- जांच रिपोर्ट में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान की रैंकिंग के संबंध में गलत काम करने का कोई सबूत नहीं मिला।

EoDB रैंकिंग क्या हैं, और वे क्यों मायने रखती हैं?

- EoDB रैंकिंग 2002 में शुरू की गई थी ताकि देशों को कई मापदंडों पर रैंक किया जा सके ताकि यह इंगित किया जा सके कि किसी देश में व्यापार करना कितना आसान या कठिन है।
- रैंकिंग की स्पष्ट रूप से व्यापक प्रकृति को देखते हुए और विश्व बैंक यह कर रहा था, EoDB जल्द ही अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए दुनिया भर में जोखिम और अवसर का आकलन करने के लिए जाने-माने मीट्रिक बन गया।
- अरबों डॉलर का निवेश इस बात पर निर्भर होने लगा कि कोई देश EoDB पर कहां है और इसमें सुधार हो रहा है या बिगड़ रहा है।
- इसने बड़े पैमाने पर राजनीतिक महत्व भी हासिल कर लिया क्योंकि विभिन्न देशों के नेताओं ने अपनी नीतियों का सफल दावा करने के लिए EoDB रैंकिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया।

रैंकिंग पद्धति में सुधार कैसे किया जा सकता है?

- 1 सितंबर को, विश्व बैंक ने अपनी EoDB पद्धति की बाहरी पैनल समीक्षा के निष्कर्ष भी प्रकाशित किए। इसमें कहा गया है कि "वर्तमान पद्धति को महत्वपूर्ण रूप से संशोधित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि परियोजना का एक बड़ा ओवरहाल (overhaul)।

कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं:

- इतने छोटे नमूने के आधार पर किसी भी रैंकिंग ने देश के अन्य शहरों और क्षेत्रों में व्यापार करने में आसानी को नजरअंदाज कर दिया। इस प्रकार, "वास्तविक" व्यापार मालिकों और ऑपरेटरों के बड़े प्रतिनिधि नमूनों से डेटा संग्रह को व्यापक आधार देने की आवश्यकता है।
- निजी क्षेत्र को आवश्यक सार्वजनिक सामान प्रदान करने वाले सरकारी कार्यों की उपेक्षा न करें: परिवहन और संचार अवसंरचना, एक कुशल कार्यबल, कानून और व्यवस्था आदि।
- देशों को उनकी कर दरों पर रैंक न करें। सामाजिक दृष्टिकोण से, कर एकत्र करना आवश्यक है, और इस प्रकार कम कर दरें जरूरी नहीं कि बेहतर हों।

  "अल्पसंख्यक शेयरधारकों की रक्षा" और "दिवालियापन का समाधान" संकेतकों को हटा दें।

  "सरकार के साथ अनुबंध" संकेतक को अधिक प्रासंगिक बनाएं।

  "एम्प्लॉयिंग वर्कर्स" संकेतक को पुनर्स्थापित और सुधारें, लेकिन इस जानकारी के आधार पर देशों को रैंक न करें।

- डूइंग बिजनेस की पारदर्शिता और निगरानी में सुधार करना।

क्या यह पहली बार है जब IMF या विश्व बैंक प्रमुख विवाद में हैं?

नहीं। हाल के वर्षों में, विश्व बैंक और IMF के कई प्रमुखों को किसी न किसी गलत काम का दोषी पाया गया है।

- 2011 में, IMF के तत्कालीन MD डोमिनिक-स्ट्रॉस कान को यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अमेरिका में गिरफ्तार किए जाने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था।
- 2004 और 2007 के बीच IMF के MD रॉड्रिगो राटो को 2017 में क्रेडिट कार्ड स्कैंडल के लिए स्पेन के जेल में डाल दिया गया था।
- क्रिस्टीन लेगार्ड, जो 2011 और 2017 के बीच IMF की MD थीं, को 2011 के एक मामले के लिए 2016 में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की अनुमति देने में लापरवाही का दोषी पाया गया।
- 2005 और 2007 के बीच विश्व बैंक के अध्यक्ष पॉल वोल्फोविट्ज़ को नैतिक उल्लंघन और विश्व बैंक के एक कर्मचारी के साथ उनके रोमांटिक्स लिंक्स (romantic links) के कारण इस्तीफा देना पड़ा।
- 2005 और 2007 के बीच विश्व बैंक के अध्यक्ष पॉल वोल्फोविट्ज़ को नैतिक उल्लंघन और विश्व बैंक के एक कर्मचारी के साथ उनके रोमांटिक्स लिंक्स (romantic links) के कारण इस्तीफा देना पड़ा।
- 2019 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष रहे जिम योंग किम की भूमिका पर भी रैंकिंग विवाद में सवाल उठ रहे हैं.

पैंडोरा पेपर्स (Pandora Papers)

पेंडोरा पेपर्स क्या है?

- पेंडोरा पेपर्स लगभग 12 मिलियन दस्तावेजों और फाइलों का लीक है जो छिपी हुई संपत्ति, कर से बचाव और कुछ मामलों में, दुनिया के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करता है।
- डेटा वाशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स द्वारा प्राप्त किया गया था, जो 140 से अधिक मीडिया संगठनों और 117 देशों के 600 से अधिक पत्रकारों के साथ अपनी अब तक की सबसे बड़ी वैश्विक जांच पर काम कर रहा है।
- ICIJ ने यह भी कहा है कि "डेटा ट्रोव में 330 से अधिक राजनेता और 130 फोर्ब्स अरबपति, साथ ही मशहूर हस्तियां, ड्रग डीलर, शाही परिवार के सदस्य और दुनिया भर के धार्मिक समूहों के नेता शामिल हैं"।

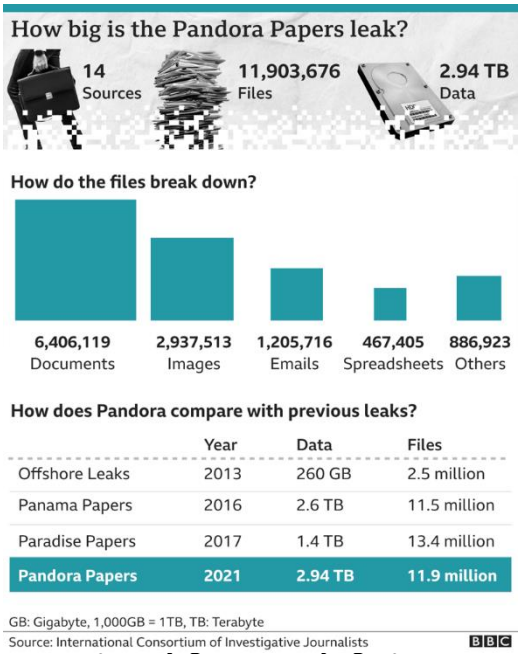

क्या यह पहली बार है कि इस तरह के वित्तीय कागजात लीक हुए हैं?

- कम से कम 2008 के बाद से, वित्तीय संस्थानों से अमीरों द्वारा जोड़तोड़ का संकेत देने वाली फाइलें चोरी हो गई हैं।
- 2008 में, LGT बैंक ऑफ लिकटेंस्टीन के एक पूर्व कर्मचारी ने कर अधिकारियों को जानकारी की पेशकश की।
- 2008 में फिर से, Herv Falciani ने दूरस्थ सर्वर से HSBC बैंक खातों पर गोपनीय डेटा प्राप्त किया और डेटा को तत्कालीन फ्रांसीसी वित्त मंत्री क्रिस्टीन लेगार्ड को दिया, जिन्होंने इसे भारत सहित विभिन्न सरकारों को दिया।
- 2017 में, पैराडाइज पेपर्स ज्यादातर 100 साल से अधिक पुरानी ऑफशोर लॉ फर्म, Appleby से लीक हो गए थे, जो विश्व स्तर पर संचालित होती है।
- 2016 में, पनामा पेपर्स को पनामा की वित्तीय फर्म, मोसैक फोन्सेका के सर्वर को हैक करके प्राप्त किया गया था।
- लक्ज़मबर्ग से लीक हुए दस्तावेज़, "लक्ज़मबर्ग लीक्स", 2014 में सामने आए।

कार्यप्रणाली

- अभी और पहले भी लीक हुए कागजात ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना और अवैध वित्तीय प्रवाह को उजागर कर दिया है।
- उदाहरण के लिए, पनामा पेपर्स ने अन्य टैक्स हेवन में इस्तेमाल किए गए टेम्पलेट पर प्रकाश डाला। पैंडोरा पेपर्स एक बार फिर इस पैटर्न की पुष्टि करते हैं।
- टैक्स हेवन (havens) अमीरों को ट्रस्ट, शेल कंपनियों और 'लेयरिंग' की प्रक्रिया का उपयोग करके संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को छिपाने में सक्षम बनाता है।
- लेयरिंग की प्रक्रिया में एक शेल-कंपनी से एक टैक्स हेवन से दूसरे टैक्स हेवन में फंड ले जाना और पिछली कंपनी को लिक्विड करना

शामिल है। इस तरह, पैसा कई टैक्स हेवन के माध्यम से अंतिम गंतव्य तक ले जाया जाता है।

- चूंकि हर कदम पर निशान छिप जाता है, इसलिए अधिकारियों के लिए धन के प्रवाह को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।
- वित्तीय फर्म अमीरों के लिए इसे काम करने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं।
- वे तैयार मुखौटा कंपनियों को निदेशक प्रदान करते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और धन की आवाजाही को 'लेयर' करते हैं। केवल पैसे वाले ही इन सेवाओं को वहन कर सकते हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया के अधिकांश अमीर अपनी कर देयता को कम करने के लिए इस तरह के जोड़तोड़ का उपयोग करते हैं, भले ही उनकी आय कानूनी रूप से अर्जित की गई हो। कम कर दरों वाले देशों के नागरिक भी टैक्स हैवन का उपयोग करते हैं।

आशय

- **टैक्स हेवन का उदय:** तीन दशकों में, टैक्स हेवन ने पूंजी को अत्यधिक मोबाइल (mobile) बनने में सक्षम बनाया है, जिससे राष्ट्रों को पूंजी आकर्षित करने के लिए कर दरों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसने 'रेस टू द बॉटम' को जन्म दिया है,
- **सरकार के कल्याणकारी प्रावधान को प्रभावित करता है:** टैक्स हेवन के माध्यम से धन की लेयरिंग के परिणामस्वरूप सरकारों के पास सार्वजनिक सामान आदि उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों की कमी होती है, जो बदले में गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- **कानूनी रूप से सही लेकिन नैतिक रूप से गलत:** कड़ाई से बोलते हुए, पेंडोरा पेपर्स द्वारा उजागर की जा रही सभी गतिविधि अवैध नहीं हो सकती हैं, हालांकि, अमीरों के लिए करों से बचना नैतिक रूप से गलत है जो अन्यथा गरीब लोग हो सकते थे।
- **जटिल कानूनी प्रक्रिया:** अधिकारियों को यह साबित करना होगा कि इनमें से प्रत्येक खुलासे में भूमि के कानून का उल्लंघन किया गया है या नहीं। प्रत्येक देश को अपनी जांच करनी होगी और यह साबित करना होगा कि गतिविधि के किस हिस्से ने उनके किसी भी कानून को तोड़ा है।
  यूनाइटेड किंगडम में, वित्तीय लेनदेन के संबंध में कानून अमीरों और उनके जोड़तोड़ के लिए बहुत अनुकूल हैं।
- **असंगठित क्षेत्र पर गलत फोकस:** ब्लैक आय के स्रोत के रूप में असंगठित क्षेत्र पर भारत सरकार का ध्यान भी गलत है क्योंकि आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह संगठित क्षेत्र है जो वास्तविक अपराधी रहा है और कर के माध्यम से हेवन और लेयरिंग अपनी ब्लैक आय का एक हिस्सा निकालता है।

निष्कर्ष

- एक दिलचस्प हालिया विकास (8 अक्टूबर) लगभग 140 देशों के बीच कॉरपोरेट्स पर 15% न्यूनतम कर दर लगाने का समझौता रहा है। हालांकि यह एक लंबा शॉट है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सेंध लगाती है।
- अवैध वित्तीय प्रवाह के अभिशाप से निपटने के लिए आवश्यक अन्य कदम बैंकिंग गोपनीयता को समाप्त कर रहे हैं और लेनदेन पर एक टोबिन कर (Tobin tax) है।

गति शक्ति योजना

संदर्भ: अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, पीएम ने 100 लाख करोड़ रुपए की "गति शक्ति" बुनियादी ढांचा योजना की घोषणा की है।

गति शक्ति मास्टर प्लान क्या है?

- यह 'समग्र बुनियादी ढांचे' के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की एक एक परियोजना है।
- इस योजना का उद्देश्य सड़क, रेल, हवाई और जलमार्गों के बीच आसान अंतर्संबंध यात्रा के समय को कम करना, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार करना और अधिक सामंजस्यपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में तालमेल विकसित करना है।
- बुनियादी ढांचे पर बल, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।

महत्व

- **लोजिस्टिक्स ग्रिड:** गति शक्ति के साथ, भारत एकीकृत, सामंजस्यपूर्ण परिवहन और लोजिस्टिक्स ग्रिड का निर्माण करने में सक्षम होगा। ऐसा ग्रिड भारत की लोजिस्टिक्स और आपूर्ति लागत को कम करने में मदद करेगा।
- **आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ाता है:** यह नई आपूर्ति-पक्ष क्षमता बनाने में मदद करता है और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता को बढ़ाता है जो गति में विकास के पहियों को स्थापित करता है और $ 5-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी मिशन की ओर बढ़ सकता है।
- **समन्वित शासन:** एक छत्र ढांचे के तहत सभी उपयोगिता और बुनियादी ढांचे की योजना बनाने से समन्वित योजना सुनिश्चित होगी, मंत्रिस्तरीय देरी में कमी आएगी और तेजी से निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
- **FDI आकर्षित करता है:** गति शक्ति के तहत एक व्यापक ढांचा होने से निवेशकों को स्पष्टता और स्थिरता मिलती है जिससे बुनियादी ढांचा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होता है।
- **नए आर्थिक गलियारों के लिए दायरा:** नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए घरेलू और विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश में वृद्धि से भविष्य के नए आर्थिक क्षेत्रों के द्वार खुलते हैं।
- **कनेक्टिविटी में सुधार:** यह निश्चित समय सीमा में आर्थिक क्षेत्रों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा।

- **निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएं उत्पाद की लागत में इजाफा करती हैं, और इस प्रकार, हमारे निर्यात को अन्य अंतरराष्ट्रीय निर्यात खिलाड़ियों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी बनाने का जोखिम उठाती हैं। गति शक्ति के तहत समर्पित बुनियादी ढांचा विकास और वैश्विक निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार करता है।
- **नीति निर्माण के लिए डेटा :** गति शक्ति के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म मंत्रालयों के लिए उपयोगी डेटा प्रदान करेगा - जिसमें एक क्षेत्र की स्थलाकृति, उपग्रह चित्र, भौतिक विशेषताएं, मौजूदा सुविधाओं के नक्शे आदि शामिल हैं, इस प्रकार उनकी मदद करना अनुमोदन के लिए धन और समय की बचत करना।
- **कार्गो व्यवसाय (cargo business) में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाता है:** अंतर्राष्ट्रीय कार्गो व्यवसाय में भारत की हिस्सेदारी 2019-20 में 1,686 करोड़ रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 2,644 करोड़ रुपए हो गई (57% की वृद्धि)। सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब होने से इस शेयर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

- इस प्रकार, गति शक्ति बहुरूपता की संस्कृति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जहां समुद्र, सड़क, रेल और हवाई परिवहन के साधन एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।

प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतें

संदर्भ: यह एक ऑफ सीजन माना जाता है। सर्दी अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में प्राकृतिक गैस की कीमतें बढ़ी हैं, खासकर यूरोप में। यूरोप में प्राकृतिक गैस की कीमत अब पिछले साल की तुलना में छह गुना अधिक है। पूरे महाद्वीप में, प्राकृतिक गैस की सूची गिर रही है।

क्या कीमतें बढ़ा रहा है?

1. आपूर्ति की बाधाएं

- वैश्विक ऊर्जा मांग 2020 में गिर गई जब अर्थव्यवस्थाएं COVID-प्रेरित लॉकडाउन में फिसल गईं।
- जब इस साल विकास वापस आया, विशेष रूप से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में, मांग बढ़ी और ऊर्जा उत्पादकों को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, कीमतों में बढ़ोतरी हुई।
- यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस उत्पादक अमेरिका में भी, कीमतें 31 मार्च को 1.7 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट से बढ़कर 5 अक्टूबर को 6.3 डॉलर प्रति एमबीटीयू हो गईं।
- यूरोप, जो अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुआ।
- स्वच्छ ऊर्जा की ओर यूरोप के बदलाव के हिस्से के रूप में, कई देश बिजली उत्पादन के लिए कोयले से गैस की ओर चले गए थे। इससे यूरोप की गैस पर निर्भरता बढ़ गई।
- दूसरी ओर, महाद्वीप के प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में कम हो गया है, क्योंकि कई देशों ने पर्यावरणीय चिंताओं पर उत्पादन क्षेत्रों को बंद कर दिया है।
- यदि यूरोप का प्राकृतिक गैस उत्पादन (रूस को छोड़कर) 2005 में लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर था, तो यह 2021 में 200 bcm से कम हो गया, यूरोप के प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक ने 2015 में 117.6 bcm से घटकर 2021 में 105.3 bcm हो गया है। इससे यूरोप काफी हद तक रूस पर निर्भर हो गया है।

2. ऊर्जा भू-राजनीति

- जैसा कि दुनिया भर में बढ़ती मांग और यूरोप में गिरते उत्पादन के बीच जैसे-जैसे कीमतें बढ़ीं, रूस से आपूर्ति यूक्रेन और पोलैंड से गुजरने वाली एक पाइपलाइन के माध्यम से भी कम हो गई, जिससे स्थिति और खराब हो गई।
- रूस ने एक और गैस पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम-2 का निर्माण किया है, जो यूक्रेन और पोलैंड (जो पुतिन के आलोचक हैं) को दरकिनार करते हुए रूसी गैस को सीधे जर्मनी ले जाएगी। लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 के माध्यम से यूरोप को आपूर्ति अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि पाइपलाइन को यूरोपीय अधिकारियों से मंजूरी का इंतजार है।
- अमेरिका और यूरोप के कई देश नॉर्ड स्ट्रीम-2 पाइपलाइन के आलोचक हैं, जो कहते हैं कि रूस को महाद्वीप पर अपना लाभ बढ़ाने में मदद करेगा और रूस को यूक्रेन और पोलैंड को आर्थिक रूप से दंडित करने की अनुमति देगा।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि इस सप्ताह यूरोप में रूसी निर्यात 2019 की तुलना में कम था।
- इसने अटकलों को हवा दी है कि श्री पुतिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के लिए यूरोपीय संघ से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यूरोप में ऊर्जा की कमी का उपयोग कर रहे हैं। रूस ने इस तरह की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि ऊर्जा संकट में रूस की कोई भूमिका नहीं है।

आगे की राह

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूरोप को आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन दिए जाने के बाद स्थिति शांत हुई है।
- लेकिन श्री पुतिन ने यह नहीं बताया कि रूस मौजूदा पाइपलाइन या नॉर्ड स्ट्रीम 2 के माध्यम से अपनी आपूर्ति कैसे बढ़ाने जा रहा है?
- यह देखा जाना है कि क्या अतिरिक्त आपूर्ति नॉर्ड स्ट्रीम- 2 पाइपलाइन के लिए त्वरित अनुमोदन से जुड़ी होगी।

- इसके अलावा, रूसी घरेलू गैस बाजार भी तंग बना हुआ है। सूची का कम चल रहा है, और सर्दी आ रही है, जो रूस की निर्यात क्षमता को बाधित करने वाली मांग को बढ़ाएगी।
- और न केवल यूरोप और अमेरिका में बल्कि एशिया में भी मांग बढ़ रही है। भारत और चीन में कोयले की कमी से प्राकृतिक गैस की कीमतें और बढ़ सकती हैं।

भारत-श्रीलंका: कोलंबो पोर्ट

संदर्भ: 30 सितंबर, 2021 को, गुजरात-मुख्यालय अदानी समूह ने कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (CWICT) को रणनीतिक रूप से लाभप्रद कोलंबो पोर्ट संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए श्रीलंकाई कंपनी जॉन कील्स होल्डिंग्स और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (SLPA) के साथ एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (BOT) समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- तीनों पक्षों द्वारा किए गए 35 साल के BOT समझौते के अनुसार, अदानी समूह के पास बहुमत, 51%, हिस्सेदारी होगी, जबकि जॉन कील्स के पास 34% और SLPA के पास 15% हिस्सेदारी होगी।
- कहा जाता है कि 700 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश द्वीप राष्ट्र के बंदरगाह क्षेत्र में सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।
- कोलंबो बंदरगाह दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक के बीच स्थित है।
- मुख्य रूप से एक कंटेनर पोर्ट, कोलंबो पोर्ट ने कंटेनरीकृत कार्गो के 5 मिलियन से अधिक TEU को संभाला है। इसके पांच कार्यात्मक टर्मिनल हैं।

बैकस्टोरी (backstory) क्या है?

- विभिन्न सरकारों के नेतृत्व में श्रीलंका अपने बंदरगाह को विकसित करने और एक भयंकर क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभरने का इच्छुक है, लेकिन निजी विदेशी निवेशक अदानी समूह को सीधे तौर पर शामिल करना कोलंबो की पहली पसंद नहीं था।
- मई 2019 में, मैत्रीपाला सिरिसेना-रानिल विक्रमसिंघे सरकार ने भारत और जापान की सरकारों के साथ एक ही बंदरगाह पर आंशिक रूप से कार्यात्मक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ECT) को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत के लिए, सौदे का मतलब व्यावसायिक और रणनीतिक दोनों तरह से संभावित लाभ था, विशेष रूप से चीन समर्थित कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (CICT) के बगल में, जहां चीन के पास 35 साल के BOT समझौते में 85% हिस्सेदारी है।
- बंदरगाह पर भारतीय उपस्थिति का मामला बनाने वालों का तर्क है कि कोलंबो बंदरगाह पर 70% से अधिक ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय भारत से जुड़ा हुआ है।

2019 के समझौते का क्या हुआ?

- 1 फरवरी, 2021 को एक कैबिनेट निर्णय में, श्रीलंका ने एकतरफा भारत और जापान को समझौते से बाहर कर दिया, इसके बजाय अपने स्वयं के निवेश के साथ ECT को विकसित करने का विकल्प चुना, बंदरगाह श्रमिक संघों, राष्ट्रवादी समूहों और बौद्ध भिक्षुओं के लगातार विरोध का हवाला देते हुए किसी भी विदेशी का जोरदार विरोध किया।
- श्रीलंकाई सरकार के इस कदम ने नई दिल्ली को सदमे में डाल दिया, क्योंकि कोलंबो के सौदे से पीछे हटने का कोई पूर्व संकेत नहीं था।
- ECT सौदे को रद्द करने से तीनों देशों के बीच काफी कूटनीतिक तनाव पैदा हो गया

WCT सौदा कैसे हुआ?

- इसके तुरंत बाद, मार्च 2021 की शुरुआत में, भारत और जापान के साथ कोलंबो बंदरगाह पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (WCT) को विकसित करने के लिए एक कैबिनेट निर्णय लिया गया।
- भारत ने अदानी पोर्ट्स को "नामांकित" किया था और इस सौदे को "समझौता" के रूप में पेश किया गया था।
- हाल ही में, अदानी समूह ने विकास कार्य शुरू करने के लिए जॉन कील्स और SLPA के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- राजनयिक सूत्रों के अनुसार, जापान ने अभी तक WCT परियोजना में अपनी भागीदारी पर फैसला नहीं किया है।
- चाहे वह पूर्व ECT सौदा हो या वर्तमान WCT समझौता, यह स्पष्ट नहीं है कि अडानी समूह भारत का चुना हुआ निवेशक कैसे बना।
- अब तक, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया का कोई संकेत नहीं है। या निवेशक का चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तर्क।
- कोलंबो ने बार-बार अदानी समूह को भारत सरकार के "नामित" के रूप में संदर्भित किया है, हालांकि भारत ने इनकार करने की मांग की थी कि उसने परियोजना के लिए किसी को नामित किया था।

विरोध

- हालांकि कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सौदे पर सवाल उठाया है, लेकिन WCT का विरोध ECT के विरोध से तुलनीय नहीं है।
- खास बात यह है कि अदानी समूह के पास अब अपने स्थानीय साझेदार जॉन कील्स के साथ बहुमत हिस्सेदारी है, जबकि SLPA के पास WCT परियोजना में सिर्फ 15% हिस्सेदारी है, ECT सौदे के विपरीत जब SLPA के पास 51% नियंत्रण हिस्सेदारी थी।

विकास का विश्लेषण

- कोलंबो के नंबर-1 ग्राहक भारतीय शिपर्स और कैरियर हैं जो कोलंबो के माध्यम से क्षेत्र और दुनिया को कनेक्टिविटी देते हैं। इसलिए, भारत का एक भागीदार समुद्री और लोजिस्टिक्स क्षेत्र में

नए संबंध बनाने के लिए श्रीलंका के लिए एक स्वागत योग्य विकास है।

- श्रीलंकाई बंदरगाहों में कई वैश्विक खिलाड़ियों की मौजूदगी से विभिन्न भू-राजनीतिक कारकों को संतुलित करने और मौजूदा तनाव को कम करने में मदद मिलेगी।
- हालांकि, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या श्रीलंकाई सरकार ने ठेकेदार के चयन में उचित प्रक्रिया का पालन किया - चाहे वह चीनी, अमेरिकी या भारतीय हो। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से "विचलन", पारदर्शिता की कमी और ध्वनि डेटा-संचालित निर्णय लेने की कमी के आरोप हैं।

COP26 जलवायु सम्मेलन

संदर्भ: यूके 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक COP 26 UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

- इस आयोजन में 190 से अधिक देशों के नेता, हजारों वार्ताकार, शोधकर्ता और नागरिक जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक साथ आएंगे।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा आने वाले दशकों में गर्मी की लहरों, सूखे, अत्यधिक वर्षा और समुद्र के स्तर में वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए, पृथ्वी की जलवायु पर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करने के महीनों बाद यह सम्मेलन होता है।

COP26 क्या है?

- पार्टियों का सम्मेलन (COP) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया था।
- 2021 पार्टियों का 26वां सम्मेलन (इस प्रकार COP26 नाम) को चिह्नित करता है और ग्लासगो में स्कॉटिश इवेंट कैंपस में आयोजित किया जाएगा।
- UNFCCC की स्थापना "वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के स्थिरीकरण" की दिशा में काम करने के लिए की गई थी।
- इसने सदस्य राज्यों के लिए जिम्मेदारियों की एक सूची तैयार की जिसमें शामिल हैं:
- जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय तैयार करना
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अनुकूलन की तैयारी में सहयोग करना
- जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना
- भारत ने 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2002 तक नई दिल्ली में आठवें COP की मेजबानी की। सम्मेलन में सात उपायों को शामिल किया गया, जिनमें 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करना ... ऊर्जा, परिवहन सहित सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में ... और अनुसंधान तथा विकास के माध्यम से तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना ... और सतत विकास के लिए संस्थानों को मजबूत करना' शामिल है।
- सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक, COP21 2015 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। सदस्य देश 'पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने' के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।

COP26 लक्ष्य क्या हैं?

- UNFCCC के अनुसार, COP26 चार लक्ष्यों की दिशा में काम करेगा:
- सदी के मध्य तक वैश्विक नेट-शून्य सुरक्षित करना और पहुंच के भीतर 1.5 डिग्री रखना
- समुदायों और प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए अनुकूल
- **राशि जुटाना:** पहले दो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, विकसित देशों को प्रति वर्ष जलवायु वित्त में कम से कम $ 100bn जुटाने के अपने वादे को पूरा करना चाहिए।
- **वितरित करने के लिए एक साथ काम करना :** COP26 में एक महत्वपूर्ण कार्य 'पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप देना' है। नेता विस्तृत नियमों की एक सूची तैयार करने के लिए मिलकर काम करेंगे जो पेरिस समझौते को पूरा करने में मदद करेंगे।

भारत अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या कर सकता है?

- यह भारत के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDCs को अद्यतन करने का समय है। (NDCs राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का विवरण देता है)
- विकास लाने के लिए सेक्टर दर सेक्टर योजनाओं की जरूरत है। हमें बिजली, परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करना होगा और प्रति यात्री मील कार्बन को देखकर शुरू करना होगा।
- आक्रामक तरीके से समझें कि हमारे कोयला क्षेत्र को कैसे परिवर्तित किया जाए
- भारत को जलवायु परिवर्तन के कानूनी और संस्थागत ढांचे में भी तेजी लाने की जरूरत है।

भवन जल सुरक्षा

संदर्भ: पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप के हालिया लॉन्च पर दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता की बात कही।

भारत में जल संकट

- भूजल संसाधन आकलन समिति की रिपोर्ट (2015 से) के अनुसार, देश के 6,607 ब्लॉकों में से 1,071 का अत्यधिक दोहन किया गया है; यह वर्षों से खराब होने की संभावना है।
- देश की एक तिहाई से अधिक आबादी पानी की कमी वाले क्षेत्रों में रहती है, और यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

- देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2011 तक 1950 के स्तर के एक तिहाई से भी कम हो गई थी, बढ़ती आबादी और निरंतर उपयोग में वृद्धि के कारण।
- भारत में 82 फीसदी ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की आपूर्ति नहीं है और 163 मिलियन घरों के पास स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पाता हैं।

भारत में जल संकट के कारण

कृषि:

- देश में हर साल इस्तेमाल होने वाले मीठे पानी का 78% हिस्सा कृषि के लिए होता है, जिसमें से 64% हिस्सा भूजल से होता है।
- ट्यूबवेल-सिंचाई में तेजी से वृद्धि और गन्ना तथा धान जैसी पानी की कमी वाली फसलों के रकबे ने भारत को गंभीर भूजल संकट में डाल दिया है।
- भारत की आधी से अधिक खेती योग्य भूमि जल प्रधान फसलों के अधीन है। भारत की 141.4 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 54 प्रतिशत पानी-गहन फसलों-चावल, गेहूं, गन्ना और कपास के अधीन है।

खराब जल दक्षता: भारत तुलनीय देशों की तुलना में भोजन की एक इकाई विकसित करने के लिए पानी की मात्रा का कम से कम दोगुना उपयोग करता है।

बढ़ती हुई जनसंख्या: 2030 तक, भारत की पानी की मांग आपूर्ति से दो गुना अधिक हो जाएगी, जो देश में गंभीर पानी की कमी को दर्शाता है।

- वास्तव में, 12 नदी घाटियों में रहने वाले 820 मिलियन भारतीयों के पास प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1,000 क्यूबिक मीटर के करीब या उससे कम है।
- 2025 तक औसत अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 1,341 क्यूबिक मीटर होने की उम्मीद है, और आधिकारिक पानी की कमी की सीमा के करीब 2050 तक 1,140 क्यूबिक मीटर के निचले स्तर को छूने की उम्मीद है।

योजनाओं का धीमा कार्यान्वयन:

- अटल बहुजल योजना (ABY) के डैशबोर्ड से पता चलता है कि विभिन्न मदों के तहत निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध खर्च, साथ ही धन जारी करना, पिछले और वर्तमान वर्ष के लिए खतरनाक रूप से कम रहा है।
- अन्य कारकों में जागरूकता की कमी के कारण पानी की बर्बादी, उद्योगों में जल संरक्षण के तरीकों की कमी, खराब जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल का अपर्याप्त उपयोग शामिल हैं।

आगे की राह

- राष्ट्रीय जल नीति 2020 "सहभागी भूजल प्रबंधन (PGWM)" दृष्टिकोण के माध्यम से "भूजल शासन और प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता" देती है। सभी हितधारकों को इस नीति को सही भावना से लागू करना होगा।
- सरकार को जल-गहन फसलों की खेती (MSP के नेतृत्व वाली खरीद, SAP/FRPs के माध्यम से) को प्रोत्साहित करना बंद करने की जरूरत है; फसल विविधीकरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- 2018 PM-आशा (PM-AASHA) (अन्नदाता आय संरक्षण अभियान) में उन फसलों की 40% तक खरीद का प्रस्ताव है जो पानी की अधिकता (बाजरा, पोषक तत्व) के रूप में नहीं हैं।
- पानी के मूल्य निर्धारण, उपयोग/उपलब्धता/कमी आदि समय पर डेटा पर भी नीतिगत ध्यान देने की आवश्यकता है।

हंगर: GHI का विश्लेषण

संदर्भ: हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) रैंकिंग में, भारत कुल 116 देशों में से 101वें स्थान पर है (भारत की 2020 रैंक 94 थी)।

- रैंक में इस वर्ष की स्लाइड विशेष रूप से COVID-19 के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
- अधिकांश पड़ोसी देशों से भी भारत पीछे है। इस सूची में पाकिस्तान को 92वें, नेपाल को 76वें और बांग्लादेश को भी 76वें स्थान पर रखा गया है।

GHI के घटक क्या हैं?

GHI के चार घटक हैं।

	अवयव	प्रयोज्यता	महत्व	डेटा स्रोत

- सरकार ने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और दावा किया कि रैंकिंग जमीनी स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

इसके लिए कार्यप्रणाली, विशेष रूप से GHI के घटकों की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

1.	**अल्पपोषण** (अपर्याप्त कैलोरी सेवन)	सभी आयु वर्ग	33.3%	खाद्य और कृषि संगठन के खाद्य सुरक्षा संकेतकों का सूट (Suite) (2021)
2.	**वेस्टिंग** (ऊंचाई के लिए कम वजन)	पांच साल से कम उम्र के बच्चे	16.6%	WHO, UNICEF और विश्व बैंक, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के पूरक हैं।
3.	**स्टंटिंग** (उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना)	पांच साल से कम उम्र के बच्चे	16.6%	WHO, UNICEF और विश्व बैंक, जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के नवीनतम आंकड़ों के पूरक हैं।
4.	मृत्यु-दर	पांच साल से कम उम्र के बच्चे	33.3%	बाल मृत्यु दर आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी समूह।

- भारत की बर्बादी की व्यापकता (17.3%) दुनिया में सबसे ज्यादा है।
- भारत में बाल स्टंटिंग 1998-2002 में 54.2% से घटकर 2016-2020 में 34.7% हो गई,
- 21वीं सदी के दो दशकों के दौरान बाल अपव्यय लगभग 17% रहता है।
- यदि GHI का अनुमान कैलोरी सेवन पर नवीनतम डेटा का उपयोग करके लगाया जाता है, जो आमतौर पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, तो चीजें और भी बदतर दिख सकती हैं, क्योंकि 2019 की लीक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि भारत में खपत व्यय 2011-12 और 2017-18 के बीच 4% (ग्रामीण भारत में 10%) घट गया।

GHI के साथ मुद्दे

- संकल्पनात्मक रूप से, GHI बड़े पैमाने पर बच्चों पर केंद्रित है, जिसमें भूख और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी सहित इसके छिपे हुए रूपों की तुलना में कुपोषण पर अधिक जोर दिया जाता है।
- पहला घटक - कैलोरी की कमी - कई कारणों से समस्याग्रस्त है।
- कम कैलोरी का सेवन, जिसका मतलब जरूरी नहीं कि कमी है, कम शारीरिक गतिविधि, बेहतर सामाजिक बुनियादी ढांचे (सड़क, परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल) और घर पर ऊर्जा-बचत करने वाले उपकरणों तक पहुंच से भी हो सकता है।
- भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए, कमी की व्यापकता पर पहुंचने के लिए एक समान कैलोरी मानदंड का उपयोग करने का अर्थ है क्षेत्रीय कारकों को पहचानने में विफल होना।
- उदाहरण के लिए: केरल और तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों में जनसंख्या के बड़े हिस्से को अर्थव्यवस्था के उच्च स्तर के मशीनीकरण के कारण कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए, उन्हें गलत तरीके से कुपोषित के रूप में गिना जाता है।

स्टंटिंग (Stunting) और वेस्टिंग (Wasting) के बीच संबंध

- बौनापन अल्पपोषण का एक दीर्घकालिक उपाय है, जबकि अपव्यय एक तीव्र, अल्पकालिक उपाय है।
- पोषक तत्वों की कमी और संक्रामक वातावरण के अचानक संपर्क में आने के कारण बच्चे की बर्बादी होती है।
- संभवतः, ठीक होने में अधिक समय के बिना बर्बाद करने के कई एपिसोड स्टंटिंग में तब्दील होते हैं।
- स्टंटिंग को प्राथमिकता का एक उच्च क्रम दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक स्थिर संकेतक है और परिस्थितियों में मामूली बदलाव के साथ दोलन (oscillate) नहीं करता है, जबकि बर्बादी करता है।
- यदि भारत सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की प्रभावी निगरानी करके बर्बादी से निपट सकता है, तो यह संभवतः एक साथ बर्बादी और स्टंटिंग में सुधार कर सकता है।
- ऐसा लगता है कि बर्बादी को दूर किए बिना स्टंटिंग में सुधार का कोई शॉर्ट-कट तरीका नहीं है।

भारत में बाल मृत्यु दर से बेहतर तरीके से निपटना

- अध्ययनों से पता चलता है कि बाल अल्पपोषण और मृत्यु दर आमतौर पर निकट से संबंधित हैं, क्योंकि बाल अल्पपोषण बाल मृत्यु दर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- बाल मृत्यु दर में भारत का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन एक उल्लेख के योग्य है।
- स्टंटिंग के उच्च स्तर होने के बावजूद भारत की बाल मृत्यु दर कम रही है
- इसका तात्पर्य यह है कि भारत पांच साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए बेहतर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं था, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच के कारण यह कई लोगों की जान बचाने में सक्षम था।

निष्कर्ष

- इस रैंकिंग से हमें अपने नीतिगत फोकस और हस्तक्षेपों को देखने के लिए प्रेरित करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे GHI द्वारा उठाई गई चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं, विशेष रूप से महामारी से प्रेरित पोषण असुरक्षा के खिलाफ।

अक्टूबर में असामान्य भारी बारिश

संदर्भ: मानसून खत्म हो गया है लेकिन देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। उदाहरण के लिए, दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत अधिक वर्षा हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर जान-माल का नुकसान हुआ है।

- वैज्ञानिकों का कहना है कि कई जगहों पर बारिश में देरी और कई स्थानों पर कम दबाव वाले क्षेत्रों के विकास जैसे कारकों के संयोजन के कारण कई जगहों पर बारिश हुई है।

क्या अक्टूबर की बारिश असामान्य है?

- अक्टूबर में बारिश असामान्य नहीं है।
- अक्टूबर को परिवर्तनकाल के लिए एक महीना माना जाता है, जिसके दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून वापस आते है और उत्तर-पूर्वी मानसून को रास्ता देता है जो मुख्य रूप से पूर्वी हिस्से में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित करता है।
- पश्चिमी विक्षोभ, जो भारत के उत्तरी भागों में स्थानीय मौसम में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं, आमतौर पर बारिश या बर्फबारी का कारण बनते हैं।
- अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से, लद्दाख, कश्मीर और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी होती है।
- हालांकि, कम दबाव वाली दो प्रणालियां एक साथ सक्रिय थीं, जिनमें से एक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में एक-एक थी। सामूहिक रूप से, इनसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंभीर मौसम की घटनाएं हुईं।

विलंबित मानसून वापसी

- चार महीने का दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम आम तौर पर अक्टूबर की शुरुआत तक पूरी तरह से वापस आ जाता है। वापसी के चरण के दौरान, यह गरज और स्थानीय रूप से भारी वर्षा का कारण बनता है।
- इस साल, हालांकि, निकासी केवल 6 अक्टूबर को शुरू हुई, जबकि सामान्य 17 सितंबर थी।
- अब तक पश्चिमी, उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों से मानसून पूरी तरह से वापस आ गया है। लेकिन यह दक्षिणी प्रायद्वीप पर सक्रिय रहता है। इस प्रकार, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पिछले 10 दिनों के दौरान महत्वपूर्ण वर्षा हुई है।
- आम तौर पर, अक्टूबर के मध्य तक, मानसूनी हवाएँ अपने प्रवाह की दिशा दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर विपरीत होती हैं।
- "भले ही पूरब पछुआ हवाओं की जगह लेने लगे हैं, पूर्व अभी भी मजबूत और पूरी तरह से स्थापित है। पूर्वी हवाएं उत्तर-पूर्वी मानसून के आगमन का संकेत देती हैं।
- इस साल, पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत के लिए स्थितियां 25 अक्टूबर के आसपास विकसित होने की उम्मीद है।
- जलवायु परिवर्तन के कारण, निश्चित रूप से वर्ष भर मौसम की घटनाओं में वृद्धि होती है। लेकिन भारी से भारी बारिश की ये विशिष्ट घटनाएं जो हम अभी देख रहे हैं, उन्हें निम्न दबाव प्रणालियों के गठन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- जब भी कम दबाव की प्रणाली होती है, परिणामस्वरूप भारी से भारी वर्षा होती है। इसके अलावा, जब एक कम दबाव प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ के साथ परस्पर क्रिया करती है, तो और अधिक तीव्र वर्षा होती है।

अन्य क्वाड

संदर्भ: हाल ही में, भारत, अमेरिका, इज़राइल और यूएई के विदेश मंत्रियों ने सहयोग के क्षेत्रों की खोज पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल बैठक किया।

- नई चतुर्भुजी बैठक का महत्व (भारत, इज़राइल, यूएई और यूएसए)
- यह पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में बदलाव का एक मजबूत अभिव्यक्ति है।
- यदि एक साल पहले इजरायल और यूएई के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे, तो अब्राहम समझौते के बाद से उनका बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग भारत सहित अन्य शक्तियों के लिए अवसर खोल रहा है।
- चार देशों की यह बैठक अपने द्विपक्षीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए पश्चिम एशिया की ओर एक क्षेत्रीय विदेश नीति रणनीति अपनाने की भारत की रणनीतिक इच्छा की ओर भी इशारा करती है।
- इन वर्षों में, भारत ने समूह के सभी देशों के साथ जीवंत द्विपक्षीय संबंध बनाए हैं।
- इसलिए भारत का क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना इस जीवंतता का स्वाभाविक विकास है, यह देखते हुए कि अरब राज्यों के प्रति इजरायल की नीति में नरमी है।
- इज़राइल भारत के शीर्ष रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।
- यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और लाखों भारतीय कामगारों की मेजबानी करता है।
- भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को गहरा किया है जैसा कि मूलभूत रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करके और एक अन्य क्वाड समूह का हिस्सा बनकर देखा गया था।
- हालांकि इस तरह के समूह के रणनीतिक महत्व के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां यह अपने जुड़ाव कर

सकता है - व्यापार, ऊर्जा संबंध, जलवायु परिवर्तन से लड़ना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना।

आगे की चुनौतियां

- अमेरिका स्पष्ट रूप से चीन के उदय से निपटने के लिए पूर्वी एशिया में अपनी धुरी के हिस्से के रूप में अपने पदचिह्न को कम करने की मांग कर रहा है, जो पश्चिम एशिया के पारंपरिक समीकरणों को फिर से तैयार कर रहा है। भारत को सावधान रहना चाहिए कि वह पश्चिम एशिया के अनेक संघर्षों में न फंस जाए।
- जबकि अब्राहम समझौते ने भारत के लिए इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आम रास्ता खोजना आसान बना दिया, इज़राइल और ईरान के बीच विरोधाभास हमेशा की तरह तीव्र बना हुआ है। भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए।
- अमेरिका के अफगानिस्तान से हटने के साथ, भारत को इस क्षेत्र में कम अमेरिकी उपस्थिति से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए ईरान जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा।
- इसलिए नई दिल्ली के सामने चुनौती ईरान के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखने की है, भले ही वह यू.एस.-इज़राइल-यूएई ब्लॉक के साथ एक मजबूत क्षेत्रीय साझेदारी का निर्माण करना चाहता है।

COP26 पर कार्बन मार्केट्स पहेली

संदर्भ: ग्लासगो में COP26 की सफलता, जो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक होगी, कार्बन बाजारों की चर्चा के समापन पर काफी हद तक निर्भर करती है।

- पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 देशों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की पूर्ति की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारों का उपयोग करने के प्रावधानों का परिचय देता है।

भारत के लिए कार्बन बाजार महत्वपूर्ण क्यों है?

- विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत, चीन और ब्राजील ने क्योटो प्रोटोकॉल के स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) के अंतर्गत कार्बन बाजार से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया।
- भारत ने CDM के तहत 1,703 परियोजनाएं पंजीकृत कीं जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। इन परियोजनाओं के लिए जारी किए गए प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (CERs) के रूप में पहचाने जाने वाला कुल कार्बन क्रेडिट लगभग 255 मिलियन है जबकि यूएस $ 2.55 बिलियन है।
- इसलिए, तार्किक रूप से, भारत को एक संपन्न कार्बन बाजार से बहुत कुछ हासिल करना है। हालाँकि, पेरिस समझौते के अनुसमर्थन के साथ, गेम के नियम बदल गए हैं।
- क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत, अब विकासशील देशों को भी शमन लक्ष्य रखने की आवश्यकता है।
- विकासशील देशों को आकर्षक विदेशी निवेश प्रवाह के बदले में अपने कार्बन क्रेडिट बेचने या अपने स्वयं के शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन क्रेडिट का उपयोग करने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
- इसने अनुच्छेद 6 को एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा बना दिया है जिसके लिए हितों और अपेक्षाओं के सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता है।
- जबकि 50% से अधिक देशों ने NDC लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाजार तंत्र का उपयोग अपने इरादे को संप्रेषित किया है, भारत उनमें से नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य अपने NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए घरेलू शमन प्रयासों पर भरोसा करना है।
- यह विकसित देश हैं जो अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाजार तंत्र पर अधिक भरोसा करेंगे क्योंकि वे तुलनात्मक रूप से कम लागत वाले विकल्प होंगे।

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं?

- अनुच्छेद 6 वार्ता कक्षों में जिन तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर गरमागरम बहस होगी, वे हैं स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) संक्रमण, लेखा नियम और अनुकूलन कोष में आय का हिस्सा। आइए एक-एक करके उनकी जांच करें।

CDM संक्रमण:

- स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) परियोजनाएं उचित परिश्रम से गुजरी हैं और UNFCCC की निगरानी में क्रेडिट जारी किए गए हैं। इसलिए, अनुच्छेद 6 तंत्र को पिछले निर्णयों का सम्मान करना चाहिए।
- हालांकि, कुछ देशों ने इन क्रेडिटों की पर्यावरणीय अखंडता पर संदेह जताया है जबकि परियोजनाओं/गतिविधियों के संक्रमण के लिए अधिक स्वीकृति है, क्रेडिट के संक्रमण के मामले में ऐसा नहीं है।
- यदि सीडीएम के संक्रमण के संबंध में निर्णय अनुकूल नहीं है, तो इससे अकेले भारत को अरबों डॉलर के संभावित राजस्व का नुकसान हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप पेरिस समझौते के तहत नए पर्यवेक्षी निकाय का गठन हो सकता है जो ऐसे क्रेडिट की वैधता और कठोरता की फिर से जांच कर सकता है।

लेखांकन नियम:

- अनुच्छेद 6.4 तंत्र का उद्देश्य निजी क्षेत्र और सार्वजनिक संस्थाओं को सतत विकास के लिए शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस तंत्र के तहत, एक देश मेजबान देश की सार्वजनिक और निजी संस्थाओं से उत्सर्जन में कमी खरीद सकता है और इसका उपयोग अपने NDC लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर सकता है।
- हालांकि, इसका स्वचालित रूप से यह अर्थ नहीं है कि एक मेजबान देश से स्थानांतरित उत्सर्जन कटौती को उसके NDC लक्ष्यों के विरुद्ध समायोजित किया जाए।

- यह सराहना की जानी चाहिए कि ये कटौती ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए निजी क्षेत्र या सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है, और वास्तव में वैश्विक जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है।
- यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.5 के प्रावधान के अनुरूप है जिसमें मेजबान देश को अपने NDC के बाहर परियोजनाओं के लिए इसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
- इसलिए, इस तरह के प्रयास NDC में किए गए प्रयासों के अतिरिक्त होंगे।
- मजबूत लेखांकन यह सुनिश्चित करेगा कि उत्सर्जन में कमी की दोहरी गणना नहीं होगी।

अनुकूलन कोष में आय का हिस्सा (SOP):

- विकासशील देशों के लिए अनुकूलन एक आवश्यकता है।
- हालांकि, यह शमन गतिविधियों के लिए वित्तपोषण की तुलना में गंभीर रूप से कम है।
- जबकि विकासशील देश इस बात पर जोर देते हैं कि अनुकूलन को निधि देने के लिए SOP को समान रूप से अनुच्छेद 6.2 और 6.4 पर लागू किया जाना चाहिए, विकसित देश इसके आवेदन को अनुच्छेद 6.4 तक सीमित रखना चाहते हैं।
- यह अनुच्छेद 6.4 तंत्र को हतोत्साहित करेगा और विकसित देशों द्वारा समर्थित अनुच्छेद 6.2 के तहत सहकारी दृष्टिकोण के लिए स्वैच्छिक सहयोग को सीमित करेगा।

निष्कर्ष

- एक तरह से कार्बन बाजार विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन जारी रखने की अनुमति देते हैं जबकि विकासशील देशों को अपने कार्बन क्रेडिट की बिक्री से होने वाले राजस्व से लाभ होता है।
- अनुच्छेद 6 पर चर्चा का केंद्र कार्बन और विकासात्मक स्थान का समान बंटवारा है। जलवायु न्याय की मांग है कि विकासशील देशों को वैश्विक कार्बन स्पेस के अपने उचित हिस्से तक पहुंच प्राप्त हो।
- चूंकि विकासशील देशों को अधिक से अधिक शमन जिम्मेदारियों को लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, एक सुविधाजनक कार्बन बाजार तंत्र जो UNFCCC में निहित सिद्धांतों का सम्मान करता है, और तेजी से मदद करेगा।

लिथियम सुरक्षित करने के लिए भारत की रेस

संदर्भ: हाल ही में लिथियम के पहचान भारत में कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में खोजे गए।

- इस खोज को सरकार के उच्चतम स्तर पर महत्व दिया जा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि लिथियम आने वाले वर्षों में कितना प्रयास और निवेश हो सकता है।

लिथियम भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

- **जलवायु परिवर्तन शमन:** लिथियम-आयन बैटरी जैसी प्रौद्योगिकियां 2030 तक 2005 के स्तर से अपने कार्बन पदचिह्न को 33-35% तक कम करने की भारत की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
- **ऊर्जा संक्रमण:** एक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन से एक इलेक्ट्रिक वाहन में संक्रमण में बैटरी शामिल होती है, जो वाहन की लागत का कम से कम 30% हिस्सा लेती है।
- **इलेक्ट्रिक मोबिलिटी:** 2030 तक, लगभग तीन-चौथाई भारतीय दोपहिया और सभी नई कारों के EVs होने की उम्मीद है और उनमें से अधिकांश को निकट भविष्य में लिथियम-आधारित (बैटरी पैक) द्वारा संचालित किया जाएगा।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, देश को 2030 तक 27 GW ग्रिड-स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए भारी मात्रा में लिथियम की आवश्यकता होगी।

लिथियम के संबंध में भारत के सामने कौन से मुद्दे और चुनौतियाँ हैं?

- **भारत में नगण्य लिथियम संसाधन आधार:** चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोलीविया और चीन के पास लगभग सभी लिथियम भंडार हैं जो अब तक विश्व स्तर पर खोजे गए हैं।
- **भारत की उच्च आयात निर्भरता:** देश में लगभग सभी इलेक्ट्रिक वाहन आयातित बैटरी पर चलते हैं, ज्यादातर चीन से। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, 2016 और 2019 के बीच, लिथियम बैटरी के आयात पर विदेशी मुद्रा की राशि तीन गुना हो गई है।
- **चीन के साथ भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** चीन बड़े लिथियम भंडार रखने के लिए जाना जाता है और लिथियम तथा कोबाल्ट दोनों के लिए आपूर्ति के स्थिर स्रोत सुनिश्चित करने के लिए कई देशों में लिथियम खानों को सुरक्षित किया है।
- इसलिए, एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी द्वारा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की खोज को आसानी से पटरी से उतार दिया जा सकता है।

लिथियम को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

- हाल ही में भारत ने बैटरी स्टोरेज इकोसिस्टम विकसित करने की अपनी रणनीति का खुलासा किया था। इसमें उन्नत रसायन सेल बैटरी के लिए कम से कम 50-गीगावाट घंटे की निर्माण क्षमता स्थापित करना शामिल है।
- देश के भीतर लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए 18,100 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना शुरू की गई है। सरकार की PLI योजना के साथ, लिथियम की मांग बढ़ना तय है और यह घरेलू अन्वेषण के नए अवसर खोलती है।

- सरकार ने खनिज बिदेश (Bidesh) इंडिया लिमिटेड (KABIL) का गठन किया - नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम। यह विदेशों में कोबाल्ट और लिथियम खदानों का अधिग्रहण करना चाहता है। काबिल भी कोबाल्ट और लिथियम की सीधी खरीद की संभावनाएं तलाश रहा है।
- गवर्नमेंट, सरकार से सरकार (G2G) सौदों को सुरक्षित करने का भी प्रयास कर रही है। उदाहरण के लिए, सामरिक खनिजों को हासिल करने के लिए अर्जेंटीना के साथ भारत का द्विपक्षीय समझौता।
- **लिथियम अन्वेषण:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में सात अन्य लिथियम अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की हैं।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका:** कई ऑटोमोबाइल प्रमुख संयुक्त रूप से गुजरात में एक विनिर्माण सुविधा विकसित करने की योजना बना रहे हैं, जो अंततः लिथियम-आयन कोशिकाओं के लिए वैश्विक निर्यात केंद्र में बदल सकती है।
- भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्रिड-स्केल बैटरी स्टोरेज प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसमें लद्दाख में 13 गीगावाट-घंटे (GWh) की सुविधा और कच्छ में 14 GWh सिस्टम शामिल है।

आगे की राह

- **अन्य उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना :** चूंकि चीन लिथियम-आयन सेल निर्माण के क्षेत्र में हावी है, इसलिए भारत को सौर उपकरण निर्माण के साथ चीजों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने होंगे।
- विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के एक वर्ग का मानना है कि लिथियम पहेली और संभावित चीनी जाल से बचने का एक अन्य तरीका उन्नत बैटरी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **एल्युमिनियम-आधारित बैटरी तकनीक:** एल्युमीनियम-आधारित बैटरी तकनीक में काफी संभावनाएं हैं। भारत के पास बॉक्साइट का विशाल भंडार है, जो उसे सस्ते दाम पर एल्युमीनियम उपलब्ध कराता है। यह तकनीक, जब व्यावसायिक रूप से परिपक्व होगी, भारत को वैश्विक आयात पर निर्भरता से बचाएगी।
- **अन्य बैटरी प्रौद्योगिकियों को जल्द अपनाना:** इसके अलावा, भारत को अन्य बैटरी प्रौद्योगिकियों जैसे हाइड्रोजन ईंधन सेल और सॉलिड-स्टेट बैटरी को भी जल्द अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
- एल्युमिनियम जैसी धातुओं का उपयोग करके सॉलिड-स्टेट बैटरियों का पता लगाया जा रहा है। विभिन्न सामग्रियों की उपलब्धता के संबंध में भारत का शीर्ष स्थान है। इस प्रकार, देश लिथियम की तुलना में इन वैकल्पिक तकनीकों को तेजी से अपना सकता है।
- भारत को भी अपने अंदर अन्वेषण को तेज करने का प्रयास करना चाहिए और उपयोग की गई लिथियम-आयन बैटरी के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण के अवसर का फायदा उठाना चाहिए।

भारत का मध्य एशियाई आउटरीच

संदर्भ: विदेश मंत्री (EAM) एस जयशंकर तीन देशों के यूरेशियन दौरे पर थे - किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया, जिसका उद्देश्य अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करना।

क्या आप जानते हैं?

- किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन सुरक्षा गठबंधन CSTO के सभी सदस्य हैं, जिन्होंने हाल के महीनों में अफगानिस्तान से आतंकवाद के किसी भी फैलाव को रोकने के लिए कई अभ्यास किए हैं।

यात्रा के मुख्य तथ्य

- किर्गिस्तान में, भारत ने विकास परियोजनाओं के समर्थन के लिए $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी और उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- कजाकिस्तान में, भारत के विदेश मंत्री ने एशिया में बातचीत और विश्वास-निर्माण उपायों (CICA) पर छठे विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया।
- CICA में, भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को निशाना बनाया। भारत ने कहा कि हालांकि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक संपर्क आवश्यक है, लेकिन इसे संकीर्ण हितों के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
- भारत ने सीमा पार आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान का भी सामना किया।
- अन्य मुद्दों के साथ CICA की बैठक में अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता प्रदान करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
- श्री जयशंकर अर्मेनिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बन गए हैं।
- भारत और आर्मेनिया द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ाने पर सहमत हुए।
- यात्रा के दौरान, श्री जयशंकर ने यूरोप के मिन्स्क समूह में सुरक्षा और सहयोग संगठन के तहत अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो-कराबाख संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों का भी समर्थन किया।

मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों का विकास

- सोवियत संघ के टूटने और मध्य एशिया में स्वतंत्र गणराज्यों के गठन के बाद, भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित किया।

- भारत ने इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की और राजनयिक संबंध स्थापित किए।
- भारत ने रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित और व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते (SPA) पर हस्ताक्षर किए।
- 2012 में, भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना था।
- हालाँकि, भारत के प्रयासों को पाकिस्तान द्वारा भारत को अपने क्षेत्र से गुजरने की इच्छा की कमी के कारण रोक दिया गया था। चीन ने स्थिति का फायदा उठाया और कजाकिस्तान में बहुप्रतीक्षित BRI का अनावरण किया।

चीन, भारत और मध्य एशिया

- BRI's के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के संबंध में बढ़ती भू-रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं तथा भारत की संप्रभुता के उल्लंघन ने भारत को इस क्षेत्र में अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया।
- पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों का दौरा किया।
- आखिरकार, मध्य एशिया वह कड़ी बन गया जिसने यूरेशिया को भारत के हित के क्षेत्र में रखा।
- भारत ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए 2015 में ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो 2003 से योजनाओं में था। अधिकांश मध्य एशियाई नेता भारत के चाबहार बंदरगाह को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और चीन की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के अवसर के रूप में देखते हैं।
- चीन के शिनजियांग प्रांत में अपने उइगर मुसलमानों के साथ चीन के दुर्व्यवहार ने मध्य एशियाई नेताओं (मुस्लिम बहुल देशों) में सामाजिक असंतोष पैदा कर दिया है।
- मध्य एशियाई देश भारत को एक भागीदार के रूप में लेने के इच्छुक हैं क्योंकि उन्होंने अपने रणनीतिक संबंधों में विविधता लाने की मांग की है।
- उन्होंने नई दिल्ली को अश्गाबात समझौते (Ashgabat Agreemen) में शामिल किया है, जिससे भारत को मध्य एशिया और यूरेशिया दोनों के साथ व्यापार तथा वाणिज्यिक बातचीत की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी नेटवर्क तक पहुंच की अनुमति मिलती है, और इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों तक भी पहुंच मिलती है।

निष्कर्ष

- इस क्षेत्र के अंदर चीन विरोधी भावनाओं में वृद्धि और तालिबान से सुरक्षा संबंधी खतरे भारत तथा मध्य एशिया को अपनी भागीदारी की फिर से कल्पना करने की अनुमति देते हैं। भारत को मध्य एशिया के साथ अपने संबंधों को फिर से जांचने में कोई समय नहीं गंवाना चाहिए।

भारत को नेट जीरो पर साइन ऑन क्यों नहीं करना चाहिए?

संदर्भ: दुनिया के शीर्ष तीन उत्सर्जक - चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ - अपनी शुद्ध शून्य प्रतिबद्धताओं और 2030 के लिए उनकी बढ़ी हुई उत्सर्जन में कमी प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, शुद्ध शून्य से पहले 500 बिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेंगे।

- इन प्रतिबद्ध उत्सर्जन के साथ, "1.5 डिग्री सेल्सियस को जीवित रखने" की कोई उम्मीद नहीं है। टारगेट डेड ऑन अर्रिवाल (dead-on-arrival) है।

भारत को नेट जीरो पर साइन क्यों नहीं करना चाहिए?

- **किसी भी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं:** न तो पेरिस समझौते और न ही जलवायु विज्ञान की आवश्यकता है कि 2050 तक देशों द्वारा व्यक्तिगत रूप से शुद्ध शून्य तक पहुंच जाए। पेरिस समझौते के लिए "सदी के उत्तरार्ध में" इस लक्ष्य की केवल वैश्विक उपलब्धि की आवश्यकता है।
- **नेट ज़ीरो ने इक्विटी की उपेक्षा की:** यह दावा है कि दुनिया को 2030 या 2050 तक विशिष्ट लक्ष्यों तक पहुंचना चाहिए, जलवायु कार्रवाई के लिए विशिष्ट आर्थिक मॉडल के उत्पाद हैं। इन्हें "सबसे कम लागत" विधियों, पूर्वगामी इक्विटी और जलवायु न्याय द्वारा पेरिस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **ऐतिहासिक जिम्मेदारी के विरुद्ध:** पिछले सभी संचयी उत्सर्जन के तीन-पांचवें हिस्से के लिए दुनिया के पांचवें हिस्से से भी कम जिम्मेदार रहा है, अकेले यू.एस. और यूरोपीय संघ ने 45% का योगदान दिया है। भारत के लिए अब शुद्ध शून्य घोषित करना वैश्विक कार्बन बजट के कुछ और अधिक विनियोग को स्वीकार करना है।
- **भारत की प्रतिबद्धता ज्यादा नहीं बदलेगी:** स्टॉक और प्रवाह दोनों में वैश्विक उत्सर्जन में भारत का योगदान इतना कम है कि उसकी ओर से कोई भी बलिदान दुनिया को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है।
- **पश्चिम की खराब प्राथमिकता:** 2020 से पहले के अपने दायित्वों को पूरा करने में विकसित दुनिया की विफलता के साथ-साथ इसे स्वीकार करने तथा पश्चिम द्वारा घोषित प्रतिबद्धताओं के संबंध में भारत के लिए थोड़ा विश्वास पैदा होता है।

भारत को क्या करना चाहिए

- भारत की उत्सर्जन कहानी को शीर्ष तीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। भारत पूर्व-औद्योगिक युग से कार्बन डाइऑक्साइड के 4.37% से अधिक संचयी उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार नहीं है, भले ही यह मानव जाति के छठे से अधिक का घर है।

- भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व औसत के आधे से भी कम है, अमेरिका के एक-आठवें से भी कम है, और चीन के 2000 के बाद की तरह कोई नाटकीय वृद्धि नहीं हुई है।
- संपत्ति के अधिकारों का आवंटन (कार्बन बजट), ग्रांडफॉदरिंग के बिना, किसी भी वैश्विक कॉमन्स के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
- वैश्विक कार्बन बजट इस तरह के किसी भी प्रतिबंध के अधीन नहीं है, जिससे विकसित देशों को अतीत और वर्तमान में इसका पूरी तरह से दोहन करने की अनुमति मिलती है।
- भारत को, प्रबुद्ध स्वार्थ में, अब वैश्विक कार्बन बजट के उचित हिस्से के लिए अपना दावा पेश करना चाहिए। इस तरह के दावे की अनुपस्थिति केवल कुछ लोगों द्वारा वैश्विक कॉमन्स के निरंतर अति-शोषण के लिए रास्ते को आसान बनाती है।
- भारत द्वारा इस तरह का दावा इसे अधिक से अधिक और बहुत आवश्यक दीर्घकालिक विकल्प प्रदान करता है। यह अच्छे के लिए गरीबी, भूख और कुपोषण के विकास, उन्मूलन के लिए कोयले, तेल और गैस के जिम्मेदार उपयोग को सक्षम बनाता है।
- भले ही भारत को पेरिस समझौते के तहत अपने अल्पकालिक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को बढ़ाना था, लेकिन उसे वैश्विक कॉमन्स के अपने हिस्से का दावा करते हुए ऐसा करना चाहिए।

चीन का नया भूमि सीमा कानून और भारतीय सरोकार

संदर्भ: 23 अक्टूबर को, चीन ने "देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण" के लिए एक नया भूमि कानून पारित किया, जो 1 जनवरी से लागू होगा।

- यह कानून विशेष रूप से भारतीय सीमा के लिए नहीं है; हालाँकि भारत के साथ चीन की 3,488 किलोमीटर सीमा विवादित है, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह 17 महीनों से सीमा पर जारी सैन्य गतिरोध और गहरा सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- चीन की भारत समेत 14 देशों के साथ 22,457 किलोमीटर लंबी ज़मीन से जुड़ी सीमा है, जो मंगोलिया और रूस के साथ सीमाओं के बाद तीसरी सबसे लंबी है।
- भारत की तरह रूस और मंगोलिया के चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं हैं।
- भारत के अलावा भूटान के साथ चीन की 477 किलोमीटर की सीमा विवादित है।

चीनी कानून

- इसमें कहा गया है कि "चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पवित्र और अहिंसक है", और राज्य को "प्रादेशिक अखंडता और भूमि की सीमाओं की रक्षा के लिए उपाय करने और इसे कमजोर करने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ सुरक्षा और मुकाबला करने" के लिए कहता है।
- राज्य "सीमा रक्षा को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करने के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में खुलने, लोगों के जीवन को प्रोत्साहित और समर्थन करने तथा वहां काम करने, सीमा रक्षा और सामाजिक, सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक विकास के बीच समन्वय को बढ़ावा देने" के उपाय कर सकता है।
- वास्तव में, यह सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को बसाने के लिए एक प्रेरणा का सुझाव देता है।
- हालाँकि, कानून राज्य को "समानता, आपसी विश्वास और मैत्रीपूर्ण परामर्श के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है, विवादों और लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दों को ठीक से हल करने के लिए बातचीत के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ भूमि सीमा संबंधी मामलों को संभालता है"

भारत पर प्रभाव

- पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए लंबे समय से चल रही चर्चा के समय चीन की सीमाओं को "पवित्र और अहिंसक" बनाने वाले कानून की घोषणा, स्थायी समाधान पर पहुंचने में और बाधाएं पैदा कर सकती है।
- PLA अब "सीमा की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करने के लिए बाध्य है", और कह रही है कि "PLA A, B, C, D क्षेत्रों से बाहर निकलने जा रहा है, यह और अधिक कठिन बना देगा"।
- कुल मिलाकर, यह बातचीत को थोड़ा और कठिन बना देगा, शेष क्षेत्रों से हटने की संभावना कम होगी।
- चीन सभी क्षेत्रों में LAC के पार "अच्छी तरह से" सीमा रक्षा गांवों का निर्माण कर रहा है। चीन न केवल सैन्य बल्कि नागरिक उपस्थिति के जरिए भी जमीनी स्तर को बदलने की कोशिश कर रहा है। सीमावर्ती गांवों का "दोहरा नागरिक और सैन्य उपयोग" भारत के लिए चिंता का विषय है।
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कानून सिर्फ शब्द हैं - संबंधों को प्रभावित करने वाला घरेलू चीनी कानून नहीं है, बल्कि जमीन पर उनकी कार्रवाई है।

खरीद सुधार (Procurement Reforms)

संदर्भ: भारतीय खाद्य निगम (FCI) की वेबसाइट से पता चलता है कि अक्टूबर में FCI के पास 30 मिलियन टन की बफर (buffer) आवश्यकता (1 अक्टूबर) के मुकाबले 86 मिलियन टन अनाज (बिना धान सहित) था।

- पिछले साल की खरीद के कारण इस साल जून-जुलाई में FCI के पास रिकॉर्ड मात्रा में अनाज था।
- महामारी वर्ष के दौरान, सरकार ने खाद्यान्न का उठाव 65 मिलियन टन सालाना से बढ़ाकर 93 मिलियन टन कर दिया (पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत बढ़ा हुआ प्रावधान)।

FCI खरीद के साथ क्या मुद्दे हैं?

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरण के लिए सालाना 65 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता के मुकाबले, इतनी बड़ी खरीद न केवल बेकार (भंडारण क्षमता की कमी को देखते हुए) है, बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए भारत की खरीद को बाजार-विकृत बनाने का जोखिम भी है।
- भले ही FCI अपनी अतिरिक्त जोत के हिस्से के लिए खुले बाजार की नीलामी आयोजित करता रहा हो, लेकिन यह अतिरिक्त की समस्या से निपटने के लिए शायद ही पर्याप्त हो।
- निर्यात स्पष्ट रूप से अतिरिक्त स्टॉक को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बाजार-विरूपण के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन के मानदंड लागू होंगे।
- गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय परिणामों के साथ धान/चावल मुख्य दोषी-खासकर पंजाब से खरीद-के लिए जिम्मेदार है।
- अनाज देने की कमी, ऐसा लगता है कि बहुत कम किया जा सकता है - जब तक कि नीतिगत सुधार नहीं किया जाता है।

किस नीति सुधार की आवश्यकता है?

- सरकार दो या तीन राज्यों में मुट्ठी भर किसानों को खुश रखने के लिए खरीददारी कर सकती है और संभवत: स्थानीय और विदेशों में खाद्य कार्यक्रमों के लिए अधिशेष दान कर सकती है।
  या सरकार MSP's की अपील को कमजोर करती है और खुली खरीद को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाती है।
- FCI द्वारा किए जा रहे "राज्य-वार आवश्यकताओं और बफर मानदंडों का सूक्ष्म विश्लेषण" तेज किया जाना चाहिए।
- दंड को कम करने का एक और तरीका यह होगा कि व्यक्तिगत भूमि-जोत के आकार के अनुसार खरीद को सीमित करके, खुली खरीद को सीमित किया जाए।
- सरकार भी एक शुद्ध लागत-समर्थन व्यवस्था की ओर बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि अमीर और प्रभावशाली किसानों को मूल्य-समर्थन की लत है।
- केंद्र और पंजाब को राज्य के किसानों को धान से मक्का और यहां तक कि फल और सब्जियों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

निष्कर्ष

उपर्युक्त सुधारों के बिना, FCI का बोझ केवल बढ़ेगा।

आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन

संदर्भ: COVID-19 ने भारत की अल्प-वित्तपोषित स्वास्थ्य प्रणाली की कई कमजोरियों को उजागर किया।

भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के साथ प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- ग्रामीण प्राथमिक देखभाल कम है और देश के कई हिस्सों में कर्मचारियों, उपकरणों, दवाओं और बुनियादी ढांचे की कमी है।
- शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अभी भी कई राज्यों में एक सक्रिय कार्यक्रम के रूप में सामने नहीं आई है।
- जिला और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और सहयोगी स्टाफ की कमी है।
- निजी क्षेत्र बड़े शहरों में उन्नत तृतीयक देखभाल अस्पतालों से लेकर गांवों में अनौपचारिक और अक्सर अयोग्य देखभाल प्रदाताओं तक होता है।
- महामारी के दौरान, निजी क्षेत्र भारत के बड़े हिस्से में प्रभावी रूप से सस्ती देखभाल प्रदान नहीं कर सका या टीके नहीं दे सका।
- सार्वजनिक प्रणाली के अंदर देखभाल के विभिन्न स्तरों और एक अलग ब्रह्मांड में संचालित निजी प्रणाली के बीच संबंध है।
- अधिकांश सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में आउट पेशेंट देखभाल शामिल नहीं थी।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (ABHIM)

- यह सात उच्च-केंद्रित राज्यों और तीन उत्तर-पूर्वी राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करेगा।
- इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों के सहयोग से 11,044 शहरी HWCs की स्थापना की जाएगी।
- विभिन्न स्तरों पर देखभाल की निरंतरता प्रदान करने के लिए, सभी हकदार लाभार्थियों के लिए HWCs को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा।
- ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का हब-एंड-स्पोक मॉडल प्रभावी माइक्रोबियल निगरानी को सक्षम करेगा।
- इसके साथ ही, केंद्रों का नेटवर्क एक प्रशिक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल का निर्माण करेगा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का जवाब देते हुए नियमित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य कर सकता है।
- 11 उच्च फोकस वाले राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) के लिए सहायता।

- यह सभी 730 जिलों में एकीकृत जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए प्रदान करेगा जो सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम रोग निगरानी की क्षमता को मजबूत करेगा।
- माइक्रोबियल निगरानी, क्षमताओं को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय मंच स्थापित किया जाएगा।
- चार क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के तहत प्रयोगशाला की क्षमता को मजबूत किया जाएगा।
- 602 जिलों में 50-100 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे, ताकि अन्य सेवाओं को बाधित किए बिना गंभीर संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों की देखभाल की जा सके।
- आपदा प्रतिक्रिया तत्परता के स्तर को बढ़ाने के लिए, 15 स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र और दो कंटेनर आधारित मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे।
- राज्यों द्वारा आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार सेवा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को आमंत्रित किया जा सकता है।
- सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक योजना पर 64,180 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए ब्लॉक स्तर पर डेटा-संचालित विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने और लोगों की भागीदारी वाली प्राथमिक देखभाल को सक्षम कर सकता है।
    - इसलिए, योजना का उद्देश्य स्थापित करना है।
    - संक्रामक रोगों की व्यापक निगरानी।
    - व्यापक निदान और उपचार सुविधाएं।
    - व्यापक महामारी अनुसंधान।

आगे की राह

- एक बड़े और बेहतर कुशल स्वास्थ्य कार्यबल को प्रशिक्षित करने तथा तैनात करने की आवश्यकता है। उन्नत जिला अस्पताल नए प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं।
- स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई क्षेत्रों में कार्यक्रम के डिजाइन, वितरण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।
- कई स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कार्यक्रमों को एक सामान्य उद्देश्य के साथ काम करना होगा और इसके लिए नौकरशाही मानसिकता में बदलाव तथा केंद्र-राज्य संबंधों में सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है।

फ्रीबी कल्चर (Freebie Culture)

प्रसंग: कल्याणवाद और लोकलुभावनवाद के बीच की रेखा धुंधली हो गई है।

- कल्याणकारी पहलों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उचित रोजगार, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, सभ्य आवास और शोषण और हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।
- दूसरी ओर, किसी विशेष चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त उपहार दिए जाते हैं। वे रिसीवर के लिए सीमित निजी लाभ पैदा करते हैं और सार्वजनिक वस्तुओं/सुविधाओं को मजबूत करने में योगदान नहीं देते हैं।

फ्रीबी कल्चर की उत्पत्ति कैसे हुई?

- तमिलनाडु में मुफ्तखोरी की संस्कृति 1967 के विधानसभा चुनावों के दौरान शुरू हुई थी। तत्कालीन द्रमुक प्रमुख सी.एन. अन्नादुरई ने 1 रुपए में चावल के तीन उपाय पेश किए।
- मुफ्त उपहार देने की प्रथा का पालन बाद के मुख्यमंत्रियों ने किया, जिन्होंने मुफ्त टीवी सेट, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी, मुफ्त गैस सिलेंडर और स्टोव, गरीब किसानों के लिए एक बकरी और एक गाय आदि का वादा किया।
- राजनीतिक नेताओं ने सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए मुफ्तखोरी को जायज ठहराया है क्योंकि यह पिरामिड के नीचे वालों की सहायता करता है।

फ्रीबी कल्चर की आलोचनाएं क्या हैं?

- **निजी लाभ:** मुफ्त उपहार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लाभ देने के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन करते हैं और निजी लाभ उत्पन्न करते हैं। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मुफ्त सुविधाओं के मुख्य लाभार्थी सत्ताधारी पार्टी के मुख्य समर्थक और स्विंग वोटर थे जो आसानी से प्रभावित हो सकते थे।
- **गरीबों का राजनीतिकरण:** मुफ्त उपहार न केवल गरीब और हाशिए के समुदायों का राजनीतिकरण करेंगे, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें राज्य के संसाधनों के उचित हिस्से से वंचित करेंगे।
- **तर्कसंगत सोच को मिटाना:** फ्रीबी एक लोकतांत्रिक राजनीति में व्यक्तित्व दोषों को प्रोत्साहित करती है। लोकलुभावनवाद औसत दर्जे के राजनीतिक आलोचकों को प्रोत्साहित करता है और आलोचनात्मक तथा तर्कसंगत सोच को मिटाता है, जो सत्ता में लोगों से सवाल उठाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **संरक्षक-ग्राहक सिंड्रोम:** अवांछित मुफ्त उपहार एक संरक्षक-ग्राहक सिंड्रोम पैदा करते हैं। मुफ्त उपहार देना लोगों के साथ प्रजा जैसा व्यवहार करना है, जबकि नागरिक संवैधानिक गारंटी के हकदार हैं।
- ग्राहकवाद एक राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था है जो ग्राहक के साथ संरक्षक के संबंध पर आधारित है और कुछ विशेष विशेषाधिकार या लाभ (मुफ्त उपहार) के बदले में एक संरक्षक (वोट के रूप में) को राजनीतिक समर्थन देता है।

- **कल्याणकारी राजनीति के खिलाफ:** कल्याणकारी पहल नागरिक अधिकारों का एक अवतार है, जबकि अवांछित मुफ्त उपहार सत्ताधारी दलों द्वारा गरीबों के प्रति सबसे अच्छा और सबसे कम उदासीनता दिखाते हैं।
- **उत्पादकता में वृद्धि नहीं करना :** यह देखा गया है कि मुफ्त लैपटॉप वितरित करने से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। साथ ही, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, कृषि ऋण माफी आदि ने उत्पादकता बढ़ाने में योगदान नहीं दिया है।
- **राजकोषीय बोझ:** मुफ्त में मिलने वाली सुविधाएं राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोझ डालती हैं, जिससे भारी राजकोषीय कर्ज में योगदान होता है।
- **भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील:** मुफ्त की संस्कृति बिचौलियों की भागीदारी के कारण भ्रष्ट आचरण का मार्ग प्रशस्त करती है।
- **लंबे समय तक टिकाऊ नहीं:** मुफ्त उपहारों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिणाम बहुत ही अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं। साथ ही, उन्हें हमेशा के लिए मुफ्त प्रदान नहीं किया जाता है, किसी बिंदु पर इन सामानों को युक्तिसंगत बनाना होगा।

फ्रीबी कल्चर पर न्यायपालिका का विचार क्या था?

- सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त उपहार देने के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मुफ्त उपहार भ्रष्ट आचरण नहीं है जैसा कि चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है।
- एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम सरकार में। तमिलनाडु (2013) की अदालत ने कहा कि "चुनावी घोषणा पत्र में वादों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' के रूप में नहीं माना जा सकता है, मुफ्त का वितरण लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को हिलाकर प्रभावित करता है।"
- 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने जिस तरह से मुफ्त में वोट देकर वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उस पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

पेगासस केस

संदर्भ: SC में 12 याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया था जिसमें इजरायली NSO ग्रुप स्पाइवेयर पेगासस के कथित अवैध उपयोग की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाइवेयर का उपयोग करके अनधिकृत निगरानी के आरोपों की "पूरी तरह से जांच" करने का आदेश दिया।
- तीन सदस्यीय तकनीकी समिति द्वारा जांच की जाएगी जिसमें शामिल हैं
  डॉ नवीन कुमार चौधरी, गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के डीन;
  डॉ प्रभारन पी, केरल में अमृता विश्व विद्यापीठम में प्रोफेसर; तथा
  आईआईटी बॉम्बे के डॉ अश्विन अनिल गुमस्ते।
- समिति के कामकाज की देखरेख सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन करेंगे, जिनकी सहायता के लिए दो अन्य विशेषज्ञ होंगे।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

- न्यायालय ने स्वीकार किया कि यह "कानून की एक स्थापित स्थिति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है"। साथ ही, SC ने यह भी नोट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को हर बार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का खतरा उठने पर एक मुफ्त पास मिल जाता है।
- SC ने देखा कि "राज्य द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान मात्र न्यायालय को मूकदर्शक नहीं बना देता है"।
- कानून के शासन द्वारा शासित एक लोकतांत्रिक देश में, संविधान के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके, पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों के अलावा व्यक्तियों पर अंधाधुंध जासूसी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- SC ने कहा कि निगरानी और और यह ज्ञान कि किसी पर जासूसी किए जाने का खतरा है, परिणामस्वरूप सेल्फ-सेंसरशिप हो सकती है।
- SC ने उन मजबूर करने वाली (compelling) परिस्थितियों को सूचीबद्ध किया जिसने एक जांच समिति का गठन करने का आदेश पारित करने के लिए इसे बनाया।
- निजता का अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता पर कथित तौर पर प्रभाव पड़ा है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।
- संभावित द्रुतशीतन प्रभाव के कारण इस तरह के आरोपों से समस्त नागरिक प्रभावित है।
- इसके द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में भारत संघ कोई स्पष्ट रुख नहीं लिया।
- संभावना है कि इस देश के नागरिकों को निगरानीमें रखने में कोई विदेशी प्राधिकरण, एजेंसी या निजी संस्था शामिल है।
- आरोप है कि केंद्र या राज्य सरकारें नागरिकों के अधिकारों से वंचित करने की पक्षकार हैं।

समिति के संदर्भ की शर्तों में शामिल हैं:

- क्या स्पाइवेयर के पेगासस सूट का इस्तेमाल भारत के नागरिकों के फोन या अन्य उपकरणों पर संग्रहीत डेटा तक पहुंचने, बातचीत पर सुनने, इंटरसेप्ट जानकारी तक पहुंचने के लिए किया गया था?
- पीड़ितों और/या ऐसे स्पाइवेयर हमले से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण।

- क्या भारत के नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल के लिए भारत के संघ, या किसी राज्य सरकार, या किसी केंद्रीय या राज्य एजेंसी द्वारा स्पाइवेयर के पेगासस सूट का अधिग्रहण किया गया था?
- यदि किसी सरकारी एजेंसी ने इस देश के नागरिकों पर स्पाइवेयर के पेगासस सूट का इस्तेमाल किया है, तो किस कानून, नियम, दिशानिर्देश, प्रोटोकॉल या वैध प्रक्रिया के तहत ऐसी तैनाती की गई थी?

म्यांमार संकट

संदर्भ: हाल ही में, आसियान ने 26-28 अक्टूबर को आयोजित अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन से म्यांमार के सैन्य जुंटा (military junta) को बाहर कर दिया।

- यह जनरलों के अपने शासन के लिए क्षेत्रीय वैधता हासिल करने के प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है।

म्यांमार में क्या हो रहा है?

- जब से उसने फरवरी में आंग सान सू की की लोकतांत्रिक सरकार को गिराकर सत्ता पर कब्जा किया है, सैन्य सत्ता ने लगभग 1,000 लोगों की जान लेने का दावा करते हुए आतंक का शासन शुरू किया है।
- सुश्री सू की, जो 2015 से पांच साल तक अर्ध-लोकतांत्रिक सरकार का नेतृत्व कर रही थीं, तख्तापलट के बाद से नजरबंद हैं।
- वह देश के आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने, अवैध वॉकी-टॉकी रखने और ऐसी जानकारी प्रकाशित करने सहित विभिन्न आरोपों का सामना कर रही है जो "भय या अलार्म का कारण बन सकती हैं"।
- सत्ता की जब्ती के महीनों बाद, जनरल मिन आंग हलिंग के नेतृत्व में सैन्य जुंटा अभी भी व्यवस्था बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- यदि अतीत में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD), सुश्री सू की की पार्टी ने दमन के बावजूद भी अहिंसा को बरकरार रखा था, तो इस बार NLD नेताओं ने "क्रांति" का आह्वान किया है।
- शहरों में, विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच सशस्त्र लड़ाई में बदल गए, जबकि जंगलों में, सैन्य प्रशिक्षण के लिए विद्रोहियों के साथ विरोधी समूहों ने हाथ मिलाया।
- स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत (Envoy) ने इस महीने चेतावनी दी थी कि म्यांमार गृहयुद्ध में उतर गया है।
- अधिकांश हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि जुंटा राजनीतिक कैदियों को व्यवस्थित रूप से प्रताड़ित करता रहा है।
- शासन की हिंसा, राजनीतिक संकट और हड़तालों तथा प्रदर्शनकारियों के जवाबी हमलों ने म्यांमार को पतन के कगार पर धकेल दिया है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, "संघर्ष, खाद्य असुरक्षा, प्राकृतिक आपदाओं और COVID-19" के कारण लगभग 30 लाख लोगों को जीवन रक्षक सहायता की आवश्यकता है।

इस संकट की स्थिति में आसियान क्या भूमिका निभा रहा है?

- म्यांमार के सैन्य शासन पर कुछ उत्तोलन वाले क्षेत्रीय समूहों में से एक आसियान है।
- अप्रैल में, जनरल मिन आंग हलिंग को आसियान सदस्यों के साथ आपातकालीन वार्ता के लिए जकार्ता आमंत्रित किया गया था। ब्लॉक ने उनसे तुरंत हिंसा खत्म करने और सुलह प्रक्रिया शुरू करने को कहा।
- आसियान ने म्यांमार सैन्य जुंटा से एक क्षेत्रीय विशेष दूत को सुश्री सू की सहित सभी हितधारकों से मिलने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
- आसियान योजना के हिस्से के रूप में एक विशेष दूत नियुक्त किया गया, लेकिन उन्हें सुश्री सू की से मिलने की अनुमति नहीं थी।

- अपने शिखर सम्मेलन के दौरान म्यांमार जुंटा को स्वीकार नहीं करने का आसियान का हालिया निर्णय एक अनुस्मारक है कि निरंतर हिंसा शासन के क्षेत्रीय अलगाव का कारण बन सकती है, जो संकट को और खराब कर सकती है।

निष्कर्ष

- हिंसा म्यांमार की सेना को अभी सत्ता पर काबिज होने की अनुमति दे सकती है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जुंटा पर दबाव जारी रखना चाहिए और सुलह प्रक्रिया को तत्काल शुरू करना चाहिए।

प्रैक्टिस MCQs

Q.1 विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं:

1. अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी योगदान प्राप्त करने से रोकता है।
2. इसे विदेश मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

सही कथनों का चयन करें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.2 भारत में एकल नागरिकता किस देश से ग्रहण की गई है?

a) ब्रिटेन
b) कनाडा
c) दोनों 1 और 2
d) अमेरीका

Q.3 विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं:

1. यह भारत में पहली बार है कि एक विमान वाहक के आकार का जहाज पूरी तरह से 3D में तैयार किया गया है।
2. यह लगभग 40,000 टन के विस्थापन के साथ देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है।

सही कथनों का चयन करें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4 पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर कम वर्षा क्यों होती है?

a) स्ट्रैट पश्चिमी तट
b) शीतकालीन अवसाद की कमी
c) उनका लेवार्ड स्थान
d) घाटों की ऊंचाई

Q.5 NDMA के प्रमुख कौन हैं?

a) कैबिनेट सचिव
b) ग्रह मंत्री
c) प्रधानमंत्री
d) रक्षा मंत्री

Q.6 वन संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत के जंगलों में चल रहे वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
2. यह अधिनियम राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना पहले निर्णय लेने के लिए प्रतिबंधित करता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.7 हाल ही में नोबेल चिकित्सा पुरस्कार 2021 को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रदान किया गया?

a) तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स पर खोजें
b) जीनोम संपादन
c) हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज
d) कोशिकाएं कैसे समझती हैं और ऑक्सीजन की उपलब्धता के अनुकूल कैसे होती हैं, इस खोज के लिए

Q.8 इंटरपोल का रेड नोटिस क्या दर्शाता है?

a) मिसिंग व्यक्ति
b) वांछित व्यक्ति
c) आने वाला डर
d) समूह और व्यक्ति UNSC प्रतिबंधों के अधीन हैं

Q.9 राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. इसे पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है।
2. NHA केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी बोर्ड द्वारा शासित होता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.10 इस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसके लिए दिया गया है?

a) मिल्की वे गैलेक्सी (Milky Way Galaxy) के केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज
b) टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशन और मैटर के टोपोलॉजिकल फेज की सैद्धांतिक खोज
c) प्रकाशिकी के क्षेत्र में योगदान
d) जलवायु मॉडल और भौतिक प्रणालियों की समझ।

Q.11 हाल ही में खबरों में रहा Mosquirix निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) डेंगू के लिए टीका
b) मलेरिया के लिए टीका

c) रेबीज के लक्षणों के इलाज के लिए दवा
d) मच्छरों के जीन बदलने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक

Q.12 PM MITRA पार्क योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) औषधीय उपकरण
b) कपड़ा
c) निजी मंडियां
d) विदेश शिक्षा

Q.13 हरा भरा अभियान (Hara Bhara campaign) निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है?

a) तेलंगाना
b) उत्तर प्रदेश
c) मध्य प्रदेश
d) पंजाब

Q.14 गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में खबरों में था। यह कहाँ स्थित है?

a) छत्तीसगढ
b) झारखंड
c) गुजरात
d) मध्य प्रदेश

Q.15 निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है?

a) महानदी
b) गोदावरी
c) तापी
d) कावेरी

Q.16 राम वन गमन पर्यटन सर्किट निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है?

a) कर्नाटक
b) उत्तर प्रदेश
c) मध्य प्रदेश
d) छत्तीसगढ

Q.17 S-400 ट्रायम्फ एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. S-400 ट्रायम्फ एक मोबाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है।
2. इसे इजराइल ने डिजाइन किया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18 हाल ही में खबरों में रही गुडूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) झारखंड हस्तशिल्प जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है
b) एक आयुर्वेद जड़ी बूटी
c) छत्तीसगढ़ आदिवासी से संबंधित पेंटिंग
d) गुजरात से सम्बंधित आदिवासी नृत्य

Q.19 खबरों में रहा बाशान चार द्वीप (Bashan Char Island) किस देश में स्थित है?

a) ईरान
b) यमन
c) बांग्लादेश
d) श्री लंका

Q.20 PM-WANI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
2. इस योजना में सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के माध्यम से स्थानीय किराना और पड़ोस की दुकानों द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क तथा एक्सेस प्वाइंट स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

Q.21 लीनियर नो-थ्रेशोल्ड (LNT) मॉडल, जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) ब्लैक होल्स
b) विकिरण
c) कार्बन पृथक्करण
d) ओजोन छिद्र रिक्तीकरण

Q.22 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये गैर-बाध्यकारी राष्ट्रीय योजनाएं हैं, जो जलवायु परिवर्तन के जवाब में सरकार द्वारा लागू की जाने वाली जलवायु कार्रवाइयों को उजागर करती हैं।
2. ये योगदान नागोया प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) सी। दोनों 1 और 2
d) डी। न तो 1 और न ही 2

Q.23 निम्नलिखित में से कौन COVID-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी, पूर्ण-विषाणु, निष्क्रिय टीका है?

a) कोविशील्ड
b) कोवैक्सिन
c) कृत्रिम उपग्रह
d) भारत अभी तक कोई वैक्सीन विकसित नहीं कर पाया है

Q.24 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे 1973 के तेल संकट के मद्देनजर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ढांचे में 1974 में स्थापित किया गया था।

2. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कार्य करता है।
3. भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.25 कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) निम्नलिखित में से किस पर नहीं लगाया जाता है?

a) आयातित सेब
b) आयातित बियर
c) आयातित दालें
d) आयातित पाम तेल

Q.26 हुनर हाट का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत किया जाता है?

a) शिक्षा मंत्रालय
b) कौशल विकास मंत्रालय
c) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
d) विदेश मंत्रालय

Q.27 वन हेल्थ कंसोर्टियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया।
2. यह COVID के बाद के समय में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है।
3. इस कार्यक्रम में भारत में जूनोटिक के साथ-साथ ट्रांसबाउंड्री रोगजनकों के महत्वपूर्ण जीवाणु, वायरल और परजीवी संक्रमणों की निगरानी करने की परिकल्पना की गई है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.28 भारत का सम्मान, संवाद और सहयोग का अभियान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है?

a) नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स
b) मानवाधिकार
c) विवादित कर का निपटारा
d) विशेष आर्थिक क्षेत्र

Q.29 यह नीलगिरि जिले में स्थित है और कर्नाटक तथा केरल राज्यों के साथ सीमाएँ साझा करता है। यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और इसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का वर्णन ऊपर किया जा रहा है?

a) पेरियार टाइगर रिजर्व
b) नागरहोल टाइगर रिजर्व
c) भद्रा टाइगर रिजर्व
d) मुदुमलाई टाइगर रिजर्व

Q.30 सुपारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है।
2. इस फसल की खेती करने वाले प्रमुख राज्य कर्नाटक (40%), केरल (25%), असम (20%), तमिलनाडु, मेघालय और पश्चिम बंगाल हैं।
3. हाल के एक अध्ययन में, कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने के लिए अरेकोलिन हाइड्रोब्रोमाइड पाया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.31 अब्राहम समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच गोपनीय युद्धविराम समझौता
b) अफगानिस्तान में तनाव कम करने के लिए पांच सूत्री रणनीति
c) जम्मू-कश्मीर में प्रवासियों को निशाना बनाने के लिए नई आतंकवादी रणनीति
d) संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के बीच राजनयिक संबंध

Q.32 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था और कुशीनगर में 'महापरिनिर्वाण' या मोक्ष प्राप्त किया था।
2. गौतम बुद्ध ने अष्टांगिका मार्ग (आष्टांग मार्ग) के दर्शन का प्रतिपादन किया।
3. बिहार में लुंबिनी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.33 निम्नलिखित में से कौन -सा सत्य नहीं है?

a) धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान तब पेश किया गया था जब 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन किया गया था।
b) साधारण जमानत के विपरीत, अग्रिम जमानत में, गिरफ्तारी होने से पहले ही किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।
c) सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली के एनसीटी राज्य (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फैसला सुनाया कि अग्रिम जमानत देते समय एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
d) यह केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है।

Q.34 मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है?

a) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

b) UNICEF
c) WHO
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.35 निम्नलिखित में से कौन काला सागर का सीमावर्ती देश नहीं है?

a) रूस
b) यूक्रेन
c) जॉर्जिया
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.36 भारत में व्यक्तियों के विदेशी वित्त पोषण को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है?

a) वित्त मंत्रित्व
b) विदेश मंत्रालय
c) गृह मंत्रालय
d) इनमे से कोई भी नहीं

Q.37 मास्टिटिस रोग (Mastitis disease) निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है?

a) मुर्गी पालन
b) दुधारू पशु
c) बंगाल टाइगर
d) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

Q.38 पिनाका और स्मर्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

a) मालदीव से खोजे गए नए द्वीप
b) रॉकेट लॉन्च सिस्टम
c) जैव ईंधन
d) स्वदेशी जनजाति

Q.39 उइगरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्किक जातीय समूह हैं।
2. चीन समुदाय को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक और एक स्वदेशी समूह के रूप में मान्यता देता है।
3. वे सांस्कृतिक और जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब हैं

उपरोक्त में से कौन-सा कथन गलत है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) 1, 2, और 3
d) न तो 1 और न ही 2

Q.40 ट्यूनिस एजेंडा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

a) संयुक्त राष्ट्र आधारित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF)
b) पेरिस जलवायु 2015
c) रामसर सम्मेलन
d) जैविक विविधता का संरक्षण

Q.41 सेन्की, बाराप और पॉलिन निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियाँ हैं?

a) यमुना
b) बराक
c) गंगा
d) ब्रह्मपुत्र

Q.42 कोंकण शक्ति, पहला त्रि-सेवा अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है?

a) अमेरीका
b) यूनाइटेड किंगडम
c) जापान
d) रूस

Q.43 मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है?

a) कर्नाटक
b) तमिलनाडु
c) केरल
d) तेलंगाना

Q.44 पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एशिया में पहली बार, दो कंटेनर-आधारित अस्पताल मुंबई और दिल्ली में तैनात किए जाएंगे और देश में किसी भी आपदा से निपटने के लिए रेल या हवाई मार्ग से तेजी से जुटाए जाने के लिए तैयार रहेंगे।
2. योजना का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है।
3. प्रवेश के बिंदुओं को मजबूत किया जाएगा जो नए संक्रामक रोगों और रोगजनकों के आयात के खिलाफ भारत की सीमाओं को घेरे रहेंगे।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.45 निम्नलिखित में से कौन-सा देश G7 का हिस्सा नहीं है?

a) इटली
b) जापान
c) रूस
d) अमेरीका

Q.46 एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी (APVAX) पहल किसकी पहल है?

a) एशियाई विकास बैंक
b) एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक
c) विश्व स्वास्थ्य संगठन
d) नीति आयोग

Q.47 मुल्लापेरियार बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर बना एक चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है।
2. बांध तमिलनाडु में स्थित है।
3. यह केरल द्वारा संचालित है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.48 पेगासस क्या है?

a) स्पाइवेयर
b) तारामंडल
c) मिसाइल
d) दोनों (b) और (c)

Q.49 वखान कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है:

1. यह अफगानिस्तान में क्षेत्र की एक संकरी पट्टी है।
2. यह ताजिकिस्तान को चीन से अलग करता है।
3. कॉरिडोर का निर्माण ब्रिटिश साम्राज्य (ब्रिटिश भारत) और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्माण करते हुए 1893 के समझौते द्वारा किया गया था।

सही कोड चुनें?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.50 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नौकरी के लिए आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार के प्रावधान की विफलता के परिणामस्वरूप नौकरी चाहने वालों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
2. आवेदक के आवास के 5 किमी के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।
3. मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही है?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 2
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर कुंजी

1. A
2. A
3. C
4. C
5. C
6. C
7. A
8. B
9. C
10. D
11. B
12. B
13. A
14. A
15. C
16. D
17. A
18. B
19. C
20. B
21. B
22. A
23. B
24. B
25. B
26. C
27. C
28. B
29. D
30. D
31. D
32. A
33. C
34. A
35. D
36. C
37. B
38. B
39. B
40. A
41. D
42. B
43. B
44. C
45. C
46. A
47. B
48. A
49. B
50. D

IAS BABA

Available In English & हिन्दी

INTEGRATED LEARNING PROGRAM (S-ILP) – 2022

Road to Mussoorie...

- Detailed Study Plan With Daily Targets
- Essay Guidance
- 63 Prelims & 66 Mains Tests
- CSAT Tests
- Value Add Notes- For Prelims & Mains
- Strategy Classes
- Babapedia - One Stop Destination for Current Affairs - Prelims + Mains
- Mind Maps For GS Mains

ADD-ONS Mentorship, Mains Evaluation, Current Affairs Classes

The Program Begins On November 12th

ENROLL NOW

Scan here to know more